चतुर्थ सेमेस्टर

Fourth Semester

जनसांख्यिकी के मुद्दे **एम.ए.ई.सी. - 610**

Issues of Demographic **M.A.E.C. - 610**

विषय-सूची

खण्ड – 1 भारत में जनसंख्या (Population in India)	**पृष्ठ संख्या 1-60**
इकाई 1- भारत में जनसंख्या की विभिन्न वर्षो में प्रवृत्तियाँ (Trends of population in different years in India)	1-15
इकाई 2- जनसंख्या नीति एवं मूल्यांकन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (Population Policy and Evaluation, National Population Commission)	16-31
इकाई 3- परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं महिला सशक्तीकरण (Family Planning Programme and Women Education)	32-42
इकाई 4- स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण से सम्बन्धित नीतियाँ (Policies Related to Health, nutrition, Education and Training)	43-60
खण्ड – 2 विश्व जनसंख्या (World Population)	**पृष्ठ संख्या 61-128**
इकाई 5- विश्व जनसंख्या की विभिन्न वर्षो में प्रवृत्तियाँ (Trends of World population in various years)	61-73
इकाई 6- जनसंख्या विस्फोट -विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion- Population Growth and Explosion in Developed and Developing Countries)	74-87
इकाई 7- विकसित और विकासशील देशां में आयु और लिंग संरचना के प्रतिमान, विभिन्न वर्गो में जनसंख्या पिरामिड (Patterns of age and Gender Structure in Developed and Developing Countries)	88-102

इकाई 8- सूचकांक - जीवन गुणवत्ता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, गरीबी सूचकांक एवं लिंग समानता 103-128
(Index- Physical Quality Index, Human Development Index, Poverty Index and Gender Equality)

खण्ड – 3 प्रवासन और नगरीकरण (Migration and Urbanization) **पृष्ठ संख्या 129-223**

इकाई 9- प्रवासन और नगरीकरण अवधारणा और प्रारुप 129-153
(Migration and Urbanization- Concept and Models)
इकाई 10- जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रतिमान पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के प्रभाव, प्रवासन के प्रभावकारी कारक 154-178
(Impact of National and International Migration on Population Growth and Its Paradigm)
इकाई 11- आन्तरिक प्रवासन से सम्बन्धित प्रवासन के सिद्धान्त 179-194
(Theories of Internal Migration)
इकाई 12- नगरीकरण -विकसित और विकासशील देशों में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की वृद्धि एवं वितरण 195-223
(Urbanization-Population Growth and Distribution of Rural and Urban population in Developed or Developing Countries)

Suggested Readings:

1. Agarwal, S.N. (1972) ***India's population problem***, Tata Mcgraw Hill Co., Bombay.
2. Choubey, P.K. (2000) ***Population Policy in India***, Kanishk Publication, New Delhi.
3. Gulati, S.C. (1988) ***Fertility in India and Econometric Study of Metropolis***, Sage Publication, New Delhi**.**
4. Gulati, S.C. and Srinivasan, K. (1998) ***Basic Demographic Techniques and Applications***, Saga Publication, New Delhi.

इकाई 1- भारत में जनसंख्या की विभिन्न वर्षों में प्रवृत्तियाँ
(Trends of population in different years in India)

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 भारत में विभिन्न वर्षों जनसंख्या का आकार

1.4 जनसंख्या 2011 की प्रमुख विशेषताएं

1.5 भारत में विभिन्न वर्षों जनसंख्या की वृद्धि दर

1.6 भारत में विभिन्न वर्षों औसत जन्म व मृत्यु दर

1.7 भारत में विभिन्न वर्षों जनसंख्या घनत्व

1.8 भारत में विभिन्न वर्षों लिंगानुपात

1.9 अभ्यास प्रश्न

1.10 सांराश

1.11 शब्दावली

1.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.14 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1.15 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

इससे पहले की इकाइयों के अध्ययन के बाद आप बता सकते है कि जनांकिकी क्या है ? जनांकिकी के प्रमुख सिद्धांत क्या है? जनसंख्या की गुणवत्ता के प्रभावकारी कारक कौन-कौन से हैं। जनसंख्या मापन. कुल जन्म दर,प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर, पुर्न उत्पादकीय दरए सकल पुनःउत्पादकीय दर, शुद्ध पुनःउत्पादकीय दर एवं अन्तर्सम्बन्ध , कुल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा एवं अन्तर्सम्बन्ध को जाना। इस इकाई में आप भारत की आबादी के आकार को विभिन्न अवधियों में विभक्त कर उनका अध्ययन करेगें। भारत में विभिन्न वर्षों जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की वृद्धि दर, जन्म व मत्य दर, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात तथा साक्षरता दर को जान पायेगें।

1.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- ✓ भारत में विभिन्न वर्षों जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि दर को जान सकेंगे।
- ✓ भारत में विभिन्न वर्षों जन्म व मृत्यु दर के कारक और जनसंख्या घनत्व को समझ सकेंगे।
- ✓ भारत में विभिन्न वर्षों लिंगानुपात और साक्षरता दर को स्पष्ट कर सकेंगे।

1.3 भारत में जनसंख्या का आकार

किसी भी देश में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, सामाजिक आर्थिक विकास और जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय स्त्रोत है। जनसंख्या वृध्दि दर, जन्म दर, मृत्यु दर के आधार पर भविष्य में जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। परिवार नियोजन, मातृत्व एवं प्रजननता स्वास्थ्य, आदि से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु इन जनसांख्यिकीय आंकड़ों का स्वास्थ्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिये जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता महसूस की गई, चूंकि जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को प्रति दस वर्ष के अन्तराल से एकत्रित किया जाता है।

अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न प्रकार की न्यादर्श योजना का परीक्षण किया जाता है जिसमें एकल सर्वेक्षण एवं बहुल सर्वेक्षण पद्धतियां प्रमुख है। भारत में न्यादर्श पंजीयन योजना (एस.आर.एस.) दोहरी पंजीयन पद्धति पर आधारित है इस योजना के अन्तर्गत एक निश्चित चुने गये क्षेत्र के अन्तर्गत इस कार्य हेतु पदस्थ अंशकालिक प्रगणक जो कि सामान्यत अध्यापक होता है, के द्वारा निरंतर जन्म और मत्य की घटनाओं का संकलन कार्य किया जाता है तथा प्रत्येक छ: माह के पश्चात जनगणना निदेशालय के पर्यवेक्षक द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वतंत्र रुप से सर्वेक्षण कार्य संपन्न कर जन्म/मृत्यु घटनाओं को संकलित किया जाता है। प्रगणक एवं पर्यवेक्षक द्वारा संकलित जन्म/मृत्यु घटनाओं का मुख्यालय पर मिलान किया जाता है तथा मिलान न होने वाली घटनाओं की पुनः जांच करने के पश्चात जन्म-मृत्यु के आंकड़ों को अंतिम रुप दिया जाता है।

आज भारत के पास विश्व के कुल भू क्षेत्र का 2.42 प्रतिशत भाग है किन्तु उसे विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत का पालन पोषण करना पड़ता है। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ पर भारत की जनसंख्या 1901 में

23.6 करोड़ अनुमानित की गई और 1981 की जनगणना के अनुसार यह 68.3 करोड़ आंकी गई। 1991 तक भारत की जनसंख्या 84.4 करोड़, 2001 में 102.87 करोड़ और 2011 में 121.01करोड़ हो गयी। भारत विश्व का दसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है।

वर्ष	जनसंख्या (करोड़)	दशाब्दी अंतर (करोड़)	प्रतिदाशक वृद्धि (%)	औसत वार्षिक घातांक वृद्धि (%)
1901	23.83	-	-	-
1911	25.20	1.36	+5.75	0.56
1921	25.13	0.07	-0.31	-0.03
1931	27.89	2.76	+11.00	1.04
1941	31.86	3.96	+14.22	1.33
1951	36.10	4.24	+13.31	1.25
1961	43.92	7.81	+21.64	1.96
1971	54.81	10.89	+24.80	2.20
1981	68.33	13.51	+24.66	2.22
1991	84.64	16.30	+23.87	2.16
2001	102.87	18.23	+21.54	1.97
2011	121.01	18.14	+17.64	1.64

स्रोत- http://www.censusindia.gov.in

भारत की जनसंख्या की गणना 1901 के पश्चात हर दस साल बाद होती है। इसमें 1911-21 की अवधि को छोड़कर प्रत्येक दशक में आबादी में वृद्धि दर्ज की गई। 1971 के दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्वि 24.80 रही। जबकि 1981में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातांक वृद्धिदर 2.22 रही।

1.4 जनसंख्या 2011 की प्रमुख विशेषताएं

देश की 15वीं जनगणना के प्रारंभिक आँकड़े सामने आ गए। इसके मुताबिक देश की कुल आबादी बढ़कर 121.01 करोड़ हो गई है। पिछले 10 सालों में भारत की आबादी 18 करोड़ बढ़ी! यानी दस साल में देश की आबादी में उतनी वृद्धि हुई, जितनी ब्राजील की कुल आबादी है। आशय यह कि हम हर 10 साल में एक ब्राजील को जन्म दे रहे हैं।

इस बार के प्रारंभिक आँकड़े उम्मीद की हल्की सी किरण जगाते हैं। महिला शिक्षा की दर बढ़ती नजर आ रही है और महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर पिछली जनसंख्या के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन, बच्चों के मामले में लिंगानुपात की दर 3 फीसदी घटना एक खतरनाक संकेत है, जो बालिका भ्रूण हत्या बढ़ने की तरफ इशारा करता है।

- भारत की आबादी अब अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल आबादी के बराबर है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन और भारत के बीच का फासला

भी घटा है। 2001 में 23.8 करोड़ था, जो 2011 में 13 करोड़ हो गया। देश में महिलाओं की कुल आबादी 48 करोड़ 64 है।

- पुरुषों की कुल आबादी 62 करोड़ 37 लाख है। बीते दस वर्षों में भारत की जनसंख्या में 17.6 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कुल जनसंख्या में 18 करोड़ का इजाफा हुआ है।
- पुरुषों की आबादी में 17 फीसदी और महिलाओं की आबादी में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
- 6 साल तक के बच्चों की संख्या घटी है।
- पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ने का भी संकेत है।
- 14वीं जनसंख्या के प्रारंभिक आँकड़ों के मुताबिक पिछले दस वर्षों में भारत का कुल लिंगानुपात 933 से बढ़कर 940 हो गया, जो वर्ष 1961 के बाद सर्वाधिक है। लेकिन, बच्चों का लिंगानुपात 927 से घटकर 914 हो गया। ये अनुपात आजाद भारत का सबसे निचला स्तर है।
- आँकड़ों के मुताबिक साल 2001 में कुल जनसंख्या का करीब 16 फीसदी बच्चे थे, लेकिन साल 2011 में
- ये कम होकर करीब 13 फीसदी हैं। जनगणना आयुक्त सी. चंद्रमौली के मुताबिक ये भारत में घटती उर्वरता का सूचक है। जनसंख्या के आधार पर देश की राजधानी दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा आबादी, 11297 लोग रहते हैं।
- इसमें भी राजधानी के उत्तर-पूर्व जिले में सबसे ज्यादा 37,346 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं।
- दूसरी ओर सबसे कम घनत्व वाला जिला अरुणाचल प्रदेश का दिबांग है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर के
- हिसाब से सिर्फ 1 व्यक्ति रहता है। देश में अब 82.1 फीसदी पुरुष और 64.4 फीसदी महिलाएँ साक्षर हैं। पिछले दस वर्षों में ज्यादा महिलाएँ (4 फीसदी) साक्षर हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश और बिहार में सबसे कम साक्षरता है। हालाँकि, मध्य प्रदेश के आलीराजपुर और छत्तीसगढ़ के बीजापुर, देश के सबसे कम साक्षर जिले हैं। केरल और लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 93 और 92 प्रतिशत साक्षरता है।
- आँकडों के मताबिक उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ है। जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है।
- नागालैण्ड देश का एकमात्र राज्य है, जिसकी जनसंख्या में कमी आई है।
- मुंबई के नजदीक का ठाणे सबसे अधिक आबादी वाला जिला उभरकर सामने आया है।
- मध्यप्रदेश का आलीराजपुर और छत्तीसगढ़ का बीजापुर, देश के सबसे कम साक्षर जिले।

भारत की जनसंख्या बीते एक दशक में 18.1 करोड़ बढ़कर अब 1.21 अरब हो गई है। जनगणना के ताजा आँकड़ों के मुताबिक, देश में पुरुषों की संख्या अब 62.37 करोड़ और महिलाओं की संख्या 58.64 करोड़ है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे देश के लिए अच्छी खबर यह है कि आबादी की वृद्धि दर में कमी देखी गई है। वर्ष 1991 की गणना में आबादी में 23.87 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी, 2001 में

21.54 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बीते एक दशक में आबादी 17.64 फीसदी बढ़ी। इस तरह जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। बीते एक दशक में वृद्धि दर में 3.90 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई और भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त सी. चंद्रमौली द्वारा जारी जनगणना 2011 के अंतिम आँकड़ों के अनुसार, अब भारत की 1.21 अरब की आबादी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के आँकड़ों को मिला दिया जाए तो दोनों राज्यों की कुल आबादी अमेरिका की जनसंख्या से अधिक होगी। अंतिम आँकड़ों के अनुसार, लिंगानुपात में सुधार हुआ है। पिछली जनगणना के मुताबिक देश में प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 थी, जो एक दशक में बढ़कर अब 940 हो गई है। आबादी में पुरुषों की संख्या 51.54 फीसदी और महिलाओं की संख्या 48.46 फीसदी है। महापंजीयक कार्यालय के आँकड़ों के अनुसार, लिंगानुपात में सबसे अधिक फर्क संघ शासित प्रदेश दमन और दीयू में है जहाँ प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 615 है। दादरा और नागर हवेली में लिंगानुपात 775 है। वहीं, केरल में प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1,084 दर्ज की गई है। पुडुचेरी में लिंगानुपात 1,038 है।

बहरहाल, चिंताजनक तथ्य यह है कि छह वर्ष तक की उम्र के बच्चों में लिंगानुपात में आजादी के बाद से सर्वाधिक गिरावट देखी गयी है। पिछली गणना में यह लिंगानुपात 927 था जो अब घटकर 914 हो गया है। साक्षरता की बात करें तो अब देश में 74 फीसदी आबादी पढ़ना-लिखना जानती है। साक्षर लोगों की संख्या में बीते एक दशक में 38.8 फीसदी और साक्षरता की दर में 9.2 फीसदी का इजाफा हुआ है। साक्षर पुरुषों की संख्या 44.42 करोड़ और साक्षर महिलाओं की संख्या 33.42 करोड़ है।

दिलचस्प रूप से, बीते एक दशक में साक्षर पुरुषों की संख्या में 31 फीसदी, जबकि साक्षर महिलाओं की संख्या में 49 फीसदी का इजाफा हुआ है। उत्तरप्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा 19.95 करोड़ है, जबकि लक्षद्वीप में आबादी सबसे कम यानी 64,429 है। सर्वाधिक आबादी वाले पाँच राज्यों में उत्तरप्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र (11.23 करोड़), बिहार (10.38करोड़), पश्चिम बंगाल (9.13 करोड़) और आंध्रप्रदेश (8.46 करोड़) शामिल है। सबसे कम आबादी वाले पाँच राज्यों में संघ शासित लक्षद्वीप के साथ ही दमन और दीयू (2.42 लाख), दादर और नगर हवेली (3.42 लाख), अंडमान और निकोबार द्वीप (3.79 लाख) और सिक्किम (6.97 लाख) शामिल है। बीते एक दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 25.85 फीसदी से कम होकर 20 फीसदी. महाराष्ट की 22.73 फीसदी से कम होकर 16 फीसदी, बिहार की 28.62 फीसदी से कम होकर 25.07 फीसदी, पश्चिम बंगाल की 18 फीसदी से 14 फीसदी, आंध्र प्रदेश की 14.5 फीसदी से 11 फीसदी और मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 24 फीसदी से कम होकर 20.30 फीसदी हो गई है।

चंद्रमौली के अनुसार, पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आबादी वृद्धि दर में गिरावट आयी है। विश्व आबादी में भारत की हिस्सेदारी अब 17.5 फीसदी है। भारत से आगे चीन है, जिसकी जनसंख्या विश्व आबादी की 19.4 फीसदी है। दिलचस्प पहलू यह है कि बीते एक दशक में भारत की आबादी 18.1 करोड़ बढ़ी है जो ब्राजील की कुल आबादी से थोड़ी

ही कम है। ब्राजील विश्व का पाँचवाँ सर्वाधिक आबादी वाला देश है।। अब भारत की जनसंख्या बढ़कर 1 अरब 21 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 2001 में जहां भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 21.5 प्रतिशत थी, वहीं 2011 में यह 17.7 फीसदी तक ही सीमित रही। साथ ही अच्छी बात यह भी है कि इन दस वर्षों में पुरुषों (17.1 फीसदी) की तुलना में महिलाओं (18.3 फीसदी) की संख्या में ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई।

मंगलवार को गृहमंत्री **सुशील कुमार शिंदे** ने 1 मार्च, 2011 तक की जनगणना के अंतिम आंकड़ों को रिलीज किया। इसके मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 1,21,07,26,932 है। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में करीब 18 करोड़ लोगों की बढ़ोत्तरी हुई है, जिसमें 9.09 करोड़ पुरुष और 9.10 करोड़ महिलाएं हैं। राज्यों की बात करें तो जनसंख्या के मामले में बिहार (25.4 प्रतिशत) सबसे आगे है जबकि अन्य 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 20 फीसदी से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई। कहते हैं असली भारत तो गांव में ही बसता है। सरकारी आंकड़े भी इस बात के सुबूत हैं।

2011 जनगणना के मुताबिक भारत के 83.35 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो कि देश की दो तिहाई आबादी है। जबकि 37.71 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 1951 में शहरी अनुपात जहां 17.3 फीसदी था, वही अब बढ़कर 31.2 प्रतिशत हो चुका है। साक्षरता दर में हुई बढ़ोतरी पिछले दस साल में भारत में साक्षरता दर में भी काफी सुधार आया है। 2001 में जहां देश की साक्षरता दर 64.8 फीसदी थी, वहीं अब यह बढ़कर 73 प्रतिशत हो गई है। पुरुष साक्षरता दर 5.6 प्रतिशत बढ़कर 80.9 फीसदी जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 10.9 फीसदी की वद्धि के साथ 64.6 हो गई है। मिजोरम को छोडकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार हुआ है।

2001-11 के बीच दादर व नागर हवेली (18.6), बिहार (14.8) और त्रिपुरा (14.0) ने बेहतर साक्षरता दर हासिल की। लगभग हर राज्य में साक्षरता दर में लिंग अनुपात में भी गिरावट हुई है। सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर दिल्ली दिल्ली (11,320) अभी भी सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। जबकि अरुणाचल प्रदेश (17) एक बार फिर से सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र साबित हुआ है। देश का प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व भी 2001 (325) की तुलना में बढ़कर 382 पहुंच गया है। इस क्षेत्र में बिहार (1106) ने पश्चिम बंगाल को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। सबसे खराब लिंग अनुपात हरियाणा में हरियाणा लिंग अनुपात के मामले में देश के सबसे खराब राज्यों में सबसे ऊपर है।

2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 1000 लड़कों पर महज 879 लड़कियां ही हैं। इसके बाद जम्मू व कश्मीर (889) और पंजाब (895) का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश (912) और बिहार (918) में भी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। साक्षरता दर की तरह केरल (1084 लड़कियां) लिंग अनुपात के मामले में भी सबसे बेहतर साबित हुआ है। इसके बाद तमिलनाडु (996), आंध्र प्रदेश (993), छत्तीसगढ़ (991) और ओडिशा (979) हैं। देश में लिंग अनुपात की बात करें, तो प्रति एक हजार लड़कों पर 943 लड़कियां हैं। नंबर गेम 1,21,07,26,932 देश की कुल आबादी 17.7 प्रतिशत बढ़ी आबादी पिछले एक दशक में 8 फीसदी हुआ साक्षरता दर में सुधार 64.6 प्रतिशत तक पहुंच गई है महिला साक्षरता दर 94 फीसदी साक्षरता दर के साथ केरल पहले नंबर पर बरकरार 61.8 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ बिहार निचले पायदान पर है।

1.5 भारत में विभिन्न वर्षों जनसंख्या की वृद्धि दर

भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर की चार अवधियों में विभक्त किया जाता है -

1) 1891 - 1921 : अवरुद्ध जनसंख्या
2) 1921 - 1951 : मर्यादित वृद्धि
3) 1951 - 1981 : तीव्र ऊँची वृद्धि दर
4) 1981 - 2011 : उच्च वृद्धि परन्तु मन्द होने के स्पष्ट चिन्ह

वर्ष	जनसंख्या (करोड़)	प्रतिदाशक वृधिदर (%)	औसत वार्षिक घातांक वृधिदर(%)
1901	23.83	-	-
1911	25.20	+5.75	0.56
1921	25.13	-0.31	-0.03
1931	27.89	+11.00	1.04
1941	31.86	+14.22	1.33
1951	36.10	+13.31	1.25
1961	43.92	+21.64	1.96
1971	54.81	+24.80	2.20
1981	68.33	+24.66	2.22
1991	84.64	+23.87	2.16
2001	102.87	+21.54	1.97
2011	121.01	+17.64	1.64

स्रोत- http://www.censusindia.gov.in

1) **1891 - 1921 : अवरुद्ध जनसंख्या -** 30 वर्षों की पहली अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या जो 1891 में 23.6 करोड़ थी बढ़कर 1921 में 25.1 करोड हो गयी, अर्थात् इसमें केवल 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर नाममात्र थी अर्थात् 0.019 प्रतिशत। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए अधिक जन्मदर के विरुद्ध अधिक मृत्यु दर विद्यमान थी। इस काल के दौरान जन्म दर एवं मृत्यु दर लगभग बराबर थी। इस काल में भारत जनांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में था।
2) **1921-1951 : मर्यादित वृद्धि -** 30 वर्षों की दूसरी अवधि (1921 से 1951) के दौरान, भारत की जनसंख्या जो 1921 में 25.1 करोड़ थी बढ़कर 1951 में 36.1 करोड़ हो गई। दसरे शब्दों में इन 30 वर्षों में जनसंख्या मात्र 11 करोड़ की वृद्धि हई। इस अवधि में जनसंख्या चक्रवृद्धि दर 1.09 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जो पिछली अवस्था से कई गुनी अधिक थी। परिणामतः इस अवधि में जनसंख्या में मर्यादित वृद्धि प्रारम्भ हुई।

3) **1951-1981 : तीव्र ऊँची वृद्धि दर -** 30 वर्षों की तीसरी अवधि (1951 से 1981) के दौरान, भारत की जनसंख्या जो 1951 में 36.1 करोड़ थी बढ़कर 1981 में 68.3 करोड़ हो गई। दूसरे शब्दों में इन 30 वर्षों में जनसंख्या 32.2 करोड़ की वृद्धि का रिकार्ड कायम हो गया। इस अवधि में जनसंख्या चक्रवृद्धि दर 2.14 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जो पिछली अवस्था से लगभग दुगुनी थी। आयोजन के प्रारंभ के साथ अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया और मृत्यु दर नियंत्रण के उपायों ने मृत्यु दर को और तेजी से कम किया और यह 15 हजार होगयी, परन्तु जन्मदर बड़ी सुस्ती से 40 से 36 प्रति हजार ही कम हुई। परिणामतः इस अवधि में जनसंख्या विस्फोट हुआ।
4) **1981 - 2011 : उच्च वृद्धि परन्तु मन्द होने के स्पष्ट चिन्ह -** 1981 से 2011 के दौरान भारत जनसंख्या वृद्धि के चौथे चरण में प्रवेश कर गया। भारत की कुल जनसंख्या जो 1981 में 68.3 करोड़ थी बढ़कर 2011 में 121.01 करोड़ हो गयी जो 30 वर्षों की अवधि में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 1981 से 2011 के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.05 प्रतिशत थी। 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर कम होकर 1.93 प्रतिशत हो गयी। 2001 से 2011 के बीच यह दर घटकर 1.64 प्रतिशत प्रतिवर्ष ही रह गयी।

1.6 भारत में विभिन्न वर्षों औसत जन्म व मृत्यु दर

भारत में जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति की व्याख्या जन्म और मृत्यु दर के परिवर्तन के आधार पर की जा सकती है। भारत में जन्म दर और मृत्यु दर निम्नलिखित रही हैतलिका से स्पष्ट हो जाता है कि 1921 से पूर्व भारत में विद्यमान जन्म और मृत्यु की ऊँची दर के कारण जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित थी। 1901 - 1921 के बीच जन्म दर 46 औ 49 के बीच तथा मृत्यु दर 42 से 49 के बीच घटती बढ़ती थी। तदनुरुप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम या नगण्य रही। किन्तु 1921 के बाद मृत्यु दर में स्पष्ट गिरावट आयी। 1911 - 1921 में मृत्यु दर के विपरीत जन्म दर में बहुत थोड़ी कमी हुई है। परिणामतः समय के साथ साथ उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर के बीच अन्तर बढ़ गया। तो उच्च जीवित शेष दर के रुप में प्रकट हुआ। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की उंची दर की व्याख्या जन्म की निरन्तर उच्च दर किन्तु मृत्यु की अपेक्षाकृत तेजी से गिरती हुई दर के आधार पर की जा सकती है। परिवार नियोजन अभियोजन के फलस्वरुप जन्म दर सन् 20082009 तक गिर कर 22.8 प्रति हजार हो गयी। इस काल के दौरान मृत्यु दर गिरकर 22.8 प्रति हजार के स्तर पर पहुंच गयी।

परिणामतः समय के साथ साथ उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर के बीच अन्तर बढ़ गया और इसके फलस्वरुप जीवित शेष दर में उच्च वृद्धि हुइ। अत जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर की व्याख्या उच्च जन्म दर एंव गिरती हुई मृत्यु दर के रुप में की जा सकती है। चूंकि मृत्यु दर उन्नत सफाई व्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और हैजा प्लेग जैसी महामारियों के नियंत्रण आदि बाहिर्जात तत्वों पर निर्भर रहती है अतः इसका नियंत्रण अपेक्षाकृत सरलता से किया जा सकता है। किन्तु इसकी तुलना में जन्म दर अन्तर्जात तत्वों पर यथा विवाह विषयक दृष्टिकोण परिवार का आकार गर्भनिरोधकों का प्रयोग नौकरी में सन्तोष और यौन सम्बन्धों आदि पर निर्भर करती है। अतः परिवार नियोजन कठिन समस्या है तथा जन्म दर में कमी के लिए दीर्घ अवधि और निरन्तर प्रयत्न की आवश्यकता होती है।

अवधि	जन्म दर (प्रति हजार)	मृत्यु दर (प्रति हजार)
1989-1901	45.8	44.4
1901-1911	48.1	42.6
1911-1921	49.2	48.6
1921 -1931	46.4	36.3
1931-1941	45.2	31.2
1941-1951	39.9	27.4
1951-1961	74.0	18.0
1961-1971	41.2	19.2
1971-1980	37.2	15.0
1985-1986	32.6	11.1
2008-2009	22.8	7.4

स्रोत- http://www.censusindia.gov.in

अतः परिवार नियोजन कठिन समस्या है तथा जन्म दर में कमी के लिए दीर्घ अवधि और निरन्तर प्रयत्न की आवश्यकता होती है। 1921 से पूर्व भारत जनांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में था किन्तु 1921 के पश्चात भारत की जनांकिकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। इस अवस्था में जनसंख्या की उच्च वृद्धि की संभावना वास्तविक वृद्धि के रुप में प्रकट हो रही है। यह आशा की जा रही है कि थोड़े समय के पश्चात भारत जनांकिकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा।

राज्यों से सम्बन्धित जन्म दर तथा मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है कि केरल तमिलनाड़ आंध्र प्रदेश पश्चिमी बंगाल कर्नाटक महाराष्ट्र और गुजरात में जन्म दर 25 प्रति हजार से कम हो चुकी है।इस प्रकार से ये राज्य जनांकिकीय संक्रमण की ततीय अवस्था मं प्रेवश कर गए हैं। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश और बिहार में जन्म दर 31-34 प्रति हजार के उच्च स्तर पर कायम है। ये राज्य जनांकिकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में हैं परन्तु इसमें भारत की कुल जनसंख्या का 44 प्रतिशत निवास करता है। जब तक इन राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रभाव व्यक्त नही होता तब जक समग्र भारत जनांकिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश नही कर सकता। यह बड़ी अजीब बात है कि हरियाणा जो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से दो नम्बर पर है वह भी जन्म दर को कम करे में काफी पीछे है।

1.6.1 जन्म दर

जनन क्षमता तीन कारणों पर निर्भर करती है 1 स्त्रियों की विवाह की आयु 2 जनन क्षमता की अवधि और परिवार में वृद्धि की गति। भारत में पुरुषों और स्त्रियों दोनो की विवाह आयु कम है चाहे यह कहा जा सकता है कि 1971 और 191 की बीच इसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। 1921 में बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम जो साधारणतः शारदा कानून के नाम से प्रसिद्ध है के पास हो जाने के कारण बाल विवाह की संख्या में कमी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां 1891 - 1901 के दौरान 14 वर्ष से कम आयु वाली 27 प्रतिशत लड़कीयों का

विवाह हो चुका था वहां 1951 - 61 के दशक में यह अनुपात 20 प्रतिशत रह गया। भारत में स्त्रियों की विवाह की औसत आयु 1921 में 13.7 वर्ष थी जो 2001 में बढ़कर 18.3 वर्ष हो गयी। पुरुषों के सम्बन्ध में यह 1921 में 20.7 वर्ष थी जो 2001 में बढ़कर 22.6 वर्ष हो गयी। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि विवाह आयु में वृद्धि जनसंख्या को कम करती है। जिसके परिणामस्वरुप जन्म दर में कमी होती है। ईसाइयों में विवाह की औसत आयु सबसे अधिक है और उसके क्रमश बाद हैं सिक्ख, मुसलमान और हिन्दू। हिन्दुओं में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों की स्त्रियों में औसत विवाह आयु सबसे कम है।

इसके बाद क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आते है। जनगणना विश्लेषण से पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में ग्राम क्षेत्रों की तुलना औसत विवाह आयु 2 से 3 वर्ष अधिक है। औसत विवाह आयु में वृद्धि के परिणामस्वरुप 1988 और 1993 के दौरान सामान्य जन्म दर 171 प्रति हजार से कम होकर 154 होगयी है। परन्तु अभी भी 15-19 20-24 और 25-29 के आयु वर्ग में भी जनन दर घटी। आंकड़ों से पता चलता है कि जनन दर में कमी अधिकतर शिक्षित महिलाओं में अधिक तेजी से हुई है।

इस तथ्य में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं को शिक्षित करना नितान्त आवश्यक है। जनन क्षमता का माता के शिक्षा स्तर के साथ गहरा सम्बन्ध है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से पता चलता है कि अशिक्षित या प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं के औसत 4.4 जीवित बच्चे होते हैं जबकि मिडिल मैट्रिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त स्त्रियां क्रमशः औसत रुप से 3.8, 3.0 और 2.3 बच्चों को जन्म देती हैं। केरल राज्य जनांकिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश कर गया है। 1993 में केरल में जन्म दर के 17.3 प्रति हजार के निम्न स्तर पर पहुंच गयी है।

इस सम्बन्ध में टी.एन. कृष्णन लिखते है केरल में जन्मदर में गिरावट की व्याख्या विवाह दरों में परिवर्तन लगातार और तेजी से बढ़ती हुयी स्त्री शिक्षा की उंची दरों के परिणामस्वरुप विवाह की प्रभावी दरों में वृद्धि के रुप में की जाती है।

1.6.2 मृत्यु दर

19वी शताब्दी के प्रारम्भ में विश्व के उन्नत देशों में मृत्यु दर 35-40 प्रति हजार के बीच थी। यह अब कम होकर 2005 7.6 प्रति हजार हो गईहै। मृत्यु दर में तीव्र कमी अच्छे भोजन पीने के स्वच्छ पानी उन्नत चिकित्सा सुविधाओं अच्छी सफाई और भयानक महामारियों और अन्य बीमारियों के नियंत्रण का परिणाम है। 1891-1901 और 1911-1921 के दशकों के दौरान जनसंख्या की वृद्धि बहुत ही कम रही। इसके मुख्य कारण व्यापक अकाल एवं 19185 के इनफ्लुएंजा के प्रभावाधीन 10 लाख व्यक्तियों की मृत्यु थी। इस वर्ष के दौरान मृत्यु दर 63 प्रति हजार के आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गयी जबकि यह इससे पहले और बाद के वर्ष में 33 और 36 प्रति हजार थी। मृत्यु दर को कम करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारण शिशु मृत्यु दर में कमी है। जबकि 1916-18 में शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार थी, यह 1970 में शहरी क्षेत्रों के लिए 90 प्रति हजार और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 130 प्रति हजार हो गयी।

समग्र देश के लिए यह 1978 तक कम होकर 125 और फिर 2003 में पुरुषों के लिए 57 प्रति हजार और स्त्रियों के लिए 64 प्रति हजार हो गयी तथा समग्र देश के लिए 60 प्रति हजार हो गयी। शिशु मृत्यु दर के मुख्य

कारण है अपर्याप्त भोजन निमोनिया दस्त संक्रामक और परजीवी रोग। बार बार और शीघ्रताशीघ्र गर्भ ठहरने के फलस्वरुप शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। इन सभी कारणों को दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रजनन काल के दौरान स्त्रियों में अधिक मृत्यु दर पायी जाती है। 15-45 वर्ष की स्त्रियों के लिए यह 300-400 प्रति हजार हैं।

निर्धनता के कारण जन्म पूर्व और जन्मोपरान्त काल में अपर्याप्त सावधानी और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव इसके लिए उत्तरदायी है। भोजन चिकित्सालय औश्र प्रसूति सुविधाओं में उन्नति के साथ यह आशा की जा सकती है कि शिशु मृत्यु दर एवं सामान्य मृत्यु दर में और भी कमी व्यक्त होगी। इसके अतिरिक्त मलेरिया अन्य कई प्रकार के ज्वर है चेचक प्लेग दस्त पेचिश और श्वास सम्बन्धी बीमारियां भी मृत्यु दर को बढ़ाती हैं। इनमें से मलेरिया चेचक प्लेग और हैजा को लगभग समाप्त ही कर दिया गया है। आशा की जाती है कि मृत्यु दर जीवन स्तर में उन्नति और चिकित्सा सुविधाओं के विकास के कारण और भी कम हो जाएगी।

अतः पिछले 50 वर्षों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की कम हुई हैं परन्तु मृत्यु दर अधिक तेजी से गिरी है। मृत्यु दर अब बहुत ही नीचे स्तर पर पहुंच गयी है। और चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी भी उन्नत क्यों ने कर ली जाएं यह 7-8 प्रति हजार के नीचे नही गिर सकती। अतः भारत की जनसंख्या की भाषी वृद्धि जन्म दर के भावी स्तर पर निर्भर करेगा।

1.7 भारत में विभिन्न वर्षों जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या के घनत्व का अर्थ किसी देश में रहते वाले व्यक्तियों की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत संख्या से है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनघनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। परन्तु यह जनसंख्या असमान रुप में बंटी हुई है। 1961 की जनगणना क अनुसार भारत का औसत जनघनत्व 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था किन्तु 1971 में यह बढ़कर 177 और 1981 में यह 216 हो गया। 1991 में भारत में जनघनत्व और बढ़कर 267, 2001 में और बढ़कर 325 और 2011 में 382 हो गया।

निम्नांकित तालिका में भारत के विभिन्न राज्यों में जनघनत्व में पाए जाने वाले अन्तर दिए गए हैं। केरल, पश्चिमी बंगाल, बिहार तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश अधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं परन्तु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान हिमांचल प्रदेश और नागालैण्ड ऐसे राज्य है जिनमे जनघनत्व कम है।

भारत की जनसंख्या के घनत्व की तुलना कुछ अन्य देशों से करने से पता चलता है कि न तो भारत उन देशों में सेहै जिनमें मनुष्य भुमि अनुपात अधिक है और नहीं भारत उन देशों की श्रेणी में है जिसमें मनुष्य भुमि अनुपात कम है। भारत की स्थिति न तो जापान इंग्लैण्ड और इटली जितनी बुरी है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका और रुस जितनी अच्छी। जनघनत्व के आधार पर भारत का स्थान मध्यम जनघनत्व के आधार पर भारत का स्थान मध्यम जनघनत्व वाले देशों में है।

वर्ष	घनत्व	संख्या में वृद्वि या कमी	प्रतिशत वृद्वि या कमी
1901	77	-	-
1911	82	5	6-5
1921	81	-1	-1-2

1931	90	9	11.1
1941	103	13	14.4
1951	117	14	13.6
1961	142	25	21.4
1971	177	35	24.6
1981	216	39	22
1991	267	51	23.6
2001	325	58	21.7
2011	382	57	17.5

स्रोत- http://www.censusindia.gov.in

जनसंख्या का घनत्व किसी देश की अपने आश्रित व्यक्तियों का पालन पोषण करने के लिए क्षमता का उचित सूचक नहीं है। कोई देश कितने लोगों का पालन पोषण कर सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन कितने हैं और उसका उपयोग करने के लिए किस सीमा तक उन्नत तकनीक का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दो में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और औद्योगिकरण की मात्रा के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि किस सीमा तक जनसंख्याके उच्च घनत्व का निर्वाह संभव है।

उदाहरणतया जापान में जनसंख्या का घनत्व भारत की तुलना में लगभग दगुना है, किन्तु जापान अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या का उच्चतर जीवन स्तर पर पालन पोषण करता है। इसका प्रधान कारण है कि जापान का औद्योगिकरण हो चुका है जबकि भारत की 68 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन स्तर का बहुत उचा होना आंशिक रुप मं अत्यन्त अनुकूल मनुष्य भुमि अनुपात और प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि पर निर्भर है।

इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास की उच्च अवस्था प्राप्त करने के कारण भी अमेरिका में उच्च जीवन स्तर संभव हुआ है। संक्षेप में, जनसंख्या का घनत्व न तो किसी देश की निर्धनता का सूचक है और न ही सम्पन्नता का।

1.8 भारत में विभिन्न वर्षों लिंगानुपात

प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं संख्या लिंगानुपात को बताता है । वर्ष 1901 के दशक में लिंगानुपात 972 था वह इसके बाद वर्ष 1941 के दशक तक लगातार घटाता रहा,जो वर्ष 1941 के दशक में 945 से बढकर वर्ष 1951 के दशक में 946 हो गया। इसके बाद भी इसमें 1971 तक लगातार गिरावट रही। वर्ष 1971 के दशक में 930, वर्ष 1981 के दशक में बढकर 934 , वर्ष 1991 के दशक में पुन घटकर 927 , वर्ष 2001 के दशक में बढकर 933 और 2011 के दशक में 940 हो गया है। वर्ष 1901 से लेकर 2011 के बीच सबसे कम लिंगानुपात 1971 के दशक में 930 रहा। वर्ष 1971 के दशक में ही सबसे अधिक कमी 11 संख्या की हुई थी। वर्ष 1901 से लेकर 2011 के बीच संख्या के रूप में सबसे अधिक वृद्धि सात वर्ष 2011 के दशक में रही। संख्या के रूप में कमी 11 की वर्ष 1971 के दशक में हुई।

वर्ष	लिंगानुपात वृद्धि/कमी (1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)	वृद्धि / कमी
1901	972	-
1911	964	-8
1921	955	-9
1931	950	-5
1941	945	-5
1951	946	+1
1961	941	-5
1971	930	-11
1981	934	+4
1991	927	-7
2001	933	+6
2011	940	+7

स्रोत- http://www.censusindia.gov.in

1.9 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. जनसंख्या 2011 की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में बताइए।
2. जनसंख्या की मर्यादित वृद्धि से आप क्या समझते है।
3. 1951 – 2011 के दशकों में जनसंख्या वृद्धि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

सही विकल्प चुनें

1. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बीते एक दशक में जनसंख्या में कितनें फीसदी बढ़ी।

(अ) 17.64 (ब) 16.45

(स) 18.45 (द) 12.64

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में करीब ..... करोड़ लोगों की बढ़ोत्तरी हुई है। (18/21)
2. 2011 की जनगणना में केरल में प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या .....दर्ज की गई है। (1,084/1200)
3. 2011 की जनगणना उत्तरप्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा .....करोड़ है। (19.95 /21.45)
4. 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 1000 लड़कों पर ..... लड़कियां ही हैं। (879/911)
5. वर्तमान में भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या के ..... प्रतिशत है। (12.4/17.5)
6. 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर घटकर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष ही रह गयी। (1.64 /1.84)

1.10 सारांश (Summary)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् यह जान चुके हैं कि आज भारत के पास विश्व के कुल भू क्षेत्र का 2.42 प्रतिशत भाग है किन्तु उसे विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत का पालन पोषण करना पड़ता है। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ पर भारत की जनसंख्या 1901 में 23.6 करोड़ अनुमानित की गई और 1981 की जनगणना के अनुसार यह 68.3 करोड़ आंकी गई। 1991 तक भारत की जनसंख्या 84.4 करोड़ , 2001 में 102.87 करोड़ और 2011 में 121.01 करोड़ हो गयी। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है।

1981 से 2011 के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.05 प्रतिशत थी। 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर कम होकर 1.93 प्रतिशत हो गयी। 2001 से 2011 के बीच यह दर घटकर 1.64 प्रतिशत प्रतिवर्ष ही रह गयी। 1961 की जनगणना क अनुसार भारत का औसत जनघनत्व 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था किन्तु 1971 में यह बढ़कर 177 और 1981 में यह 216 हो गया। 1991 में भारत में जनघनत्व और बढ़कर 267, 2001 में और बढ़कर 325 और 2011 में 382 हो गया।

1.11 शब्दावली (Glossary)

- **जनसंख्या की प्रति दशक वृद्धि** – एक दशक में जनसंख्या में कुल वृद्धि को जनसंख्या की प्रति दशक वृद्धि कहते है। जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि - प्रति वर्ष जनसंख्या में कुल वृद्धि को जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि कहते है।
- **जनघनत्व -** किसी क्षेत्र के एक वर्ग किमी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो की संख्या को उस क्षेत्र का जन घनत्व कहते है।
- **साक्षर** – सात वर्ष आयु से अधिक का वह व्यक्ति जो किसी भाषा को लिख, पढ़ और बोल सकता है।
- **लिंगानुपात -** प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या।

1.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Questions)

सही विकल्प चुनें :

1. (अ) 17.64

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. 18, **2.** 1084, **3.** 19.95, **4.**879, **5.** 17.5, **6.** 1.64

1.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ. मिश्रा, जे. पी., जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा।
- डॉ. बघेल, डी. एस., जनांकिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।

- डॉ. पन्त, जीवन चन्द्र, जनांकिकी, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
- अशोक कुमार, जनसंख्या, एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रयाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

1.14 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

- Dr. Premi, M.K., Ramanamma, A., Bambawale, Usha,. An Introduction to social demography, Vikas Publishing House, New Delhi.
- Appleman, Philip (ed.) Thomos Robert Malthus : An Essay on the Principle of Population, New York : W.W. Norton and Co., Inc., 1976.
- Carr- Saunders, A.M., World Population : Past Growth and Present Trends, Oxford : Clarendon Press, 1936.
- Coale, Ansley J. and Edgar M. Hoover, Populationi Growth and Economic development in low income countries, Princeton University Press, 1958.

1.15 निबन्धात्मक प्रश्न

1. "1921 का वर्ष भारतीय जनसंख्या का एक महान विभाजक वर्ष है।" इस कथन को समझाते हुए भारत की जनसंख्या की विकास दर पर प्रकाश डालिए।
2. भारत में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान अवस्था का वर्णन कीजिए।
3. "भारत की जनसंख्या के आकार की वृद्धि का प्रमुख कारण घटती मृत्यु दर है।" क्या आप इस कथन से सहमत है।
4. भारतीय जनसंख्या के विकास पर निबन्ध लिखें।

इकाई 2- जनसंख्या नीति एवं मूल्यांकन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

(Population Policy and Evaluation, National Population Commission)

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 जनसंख्या नीति: एक परिचय

2.3.1 जनसंख्या नीति से आशय

2.3.2 जनसंख्या नीति के उद्देश्य

2.4 भारत में जनसंख्या नीति

2.4.1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जनसंख्या नीति

2.4.2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनसंख्या नीति

2.5 जनसंख्या नीति: एक मूल्यांकन

2.6 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

2.7 अभ्यास प्रश्न

2.8 सारांश

2.9 शब्दावली

2.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

2.12 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री

2.13 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

जनसंख्या नीति के माध्यम से एक देश में जनसंख्या का नियोजन किया जाता है। इसके अन्तर्गत देश की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या के परिमाण को नियन्त्रित करने एवं विद्यमान जनसंख्या के उत्पादक गुणों में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है।

वास्तव में, जनसंख्या नीति वह नीति जिसके द्वारा जनसंख्या को आर्थिक विकास के अनुरूप लाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रस्तुत इकाई में जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग एवं इससे सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप जनसंख्या नीति तथा एक राष्ट्र के लिए इसका महत्व, भारत में जनसंख्या नीति के क्रमिक विकास एवं इसका मूल्यांकन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग आदि को समझ सकेंगें और इसका विश्लेषण कर सकेंगे।

2.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- ✓ बता सकेंगे कि जनसंख्या नीति से क्या आशय है।
- ✓ समझा सकेंगे कि देश के विकास हेतु आवश्यक संसाधन 'जनसंख्या' के उचित नियोजन में जनसंख्या नीति की क्या भूमिका है।
- ✓ बता सकेंगे कि भारत में स्वतन्त्रता पूर्व एवं पश्चात् जनसंख्या नीति किस प्रकार की रहीं और समय के साथ इनमें क्या परिवर्तन आये।
- ✓ बता सकेंगे कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग क्यों महत्वपूर्ण है।

2.3 जनसंख्या नीति: एक परिचय

विश्व का प्रत्येक देश आर्थिक दृष्टि से उन्नति का आकांक्षी है। एक देश का आर्थिक विकास मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है: **प्रथम**, प्राकृतिक संसाधन एवं **द्वितीय**, मानवीय संसाधन। वास्तविक रूप में, आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान मानवीय संसाधन अर्थात् उस देश में उपलब्ध जनसंख्या का ही होता है। जनसंख्या के सक्रिय सहयोग के बिना आर्थिक उन्नति और विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक साधन एवं पूंजी आदि को उत्पादन कार्य में लगाने के लिए मानवीय प्रयत्नों की ही आवश्यकता होती है। मनुष्य अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक शक्ति से भौतिक साधनों का शोषण करता है, नवप्रवर्तनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को विकसित करता है और इस प्रकार आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है।

स्पष्टतः जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं वरन् साध्य भी है और यह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन समय में विभिन्न विचारक अधिक जनसंख्या को **'प्रगति एवं सम्पन्नता का सूचक'** मानते थे, परन्तु वर्तमान में जनसंख्या की समस्या मानव की सबसे जटिल समस्या बन गई है। मानव की अपनी संख्या ने उसके समक्ष अनेक प्रश्न खड़े कर दिये हैं। विशेषकर, अल्पविकसित एवं विकासशील देशों के लिए

जनसंख्या एक गम्भीर समस्या का रूप लेती जा रही है जो इन देशों के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। **हर्षमैन** के अनुसार, ***"जनसंख्या का दबाव विकास के लिए एक बेढंगा और निष्ठुर प्रोत्साहन है।"*** इस सन्दर्भ में जनसंख्या के उचित नियोजन हेतु जनसंख्या नीति अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है।

2.3.1 जनसंख्या नीति से आशय

जनसंख्या नीति से आशय उन समस्त गतिविधियों से है जो देश की आवश्यकता के अनुरूप जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी करने एवं विद्यमान जनसंख्या के उत्पादक गुणों में वृद्धि करने के लिए की जाती हैं। इस नीति के माध्यम से किसी देश में जनसंख्या का नियोजन किया जाता है। इसमें जनसंख्या के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या नीति के परिमाणात्मक पहलू के अन्तर्गत जनसंख्या के आकार एवं संरचना को देश के राष्ट्रीय साधनों के अनुपात में नियन्त्रित किया जाता है, जबकि गुणात्मक पहलू के अन्तर्गत जनसंख्या के गुणों (जैसे- स्वास्थ्य स्तर, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा आदि) में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में, जनसंख्या नीति वह नीति जिसके माध्यम से जनसंख्या को आर्थिक विकास के अनुरूप लाने का प्रयत्न किया जाता है।

जनसंख्या नीति के सम्बन्ध में विभिन्न विचार निम्न प्रकार हैं:

संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग के अनुसार, ***''जनसंख्या नीति के अन्तर्गत वे समस्त कार्यक्रम एवं कार्यवाहियां शामिल की जाती हैं जो जनसंख्या के आकार, उसके वितरण एवं विशेषताओं में परिवर्तन लाकर आर्थिक, सामाजिक जनांकिकी, राजनीति अथवा अन्य किसी सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है।''***

मिर्डल के अनुसार, ***''जनसंख्या नीति किसी भी प्रकार सामाजिक नीति से कम नहीं होती है। यदि व्यावहारिक समाज विज्ञान सजग नहीं है तब यह खतरा है कि जनसंख्या नीति अविवेकपूर्ण रूप से संकीर्ण हो जायेगी तथा वह निदानों का उपहास होगा। एक जनसंख्या कार्यक्रम को सम्पूर्ण सामाजिक जीवन के ताने-बाने से बुना जाना चाहिये तथा उसे समस्त सामाजिक परिवर्तनों द्वारा सामाजिक जीवन में प्रवेश करना चाहिये। यदि हमारी प्रतिक्रियाएं विवेकपूर्ण हैं, तब जनसंख्या संकट हमको सभी सामाजिक उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करने को बाध्य करता है।''***

एस. चन्द्रशेखर मत में, ***''जनसंख्या नीति किसी देश की सरकार द्वारा निर्मित वह नीति है जो जनसंख्या के आकार एवं संरचना में किसी सरकारी कानून अथवा निर्देश द्वारा जान-बूझकर परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लागू की जाती है।''***

उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट है कि जनसंख्या नीति का प्रत्यक्ष सम्बन्ध जनसंख्या के आकार, संरचना एवं वितरण में परिवर्तन लाने से है जो सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य से किये जाते हैं।

2.3.2 जनसंख्या नीति के उद्देश्य

एक जनसंख्या नीति के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं:

1. देश की आवश्यकता के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी कर इसे अनुकूलतम स्तर पर लाना,
2. आर्थिक विकास को प्रोत्साहन,
3. जनसंख्या के वितरण में संतुलन,
4. जनसंख्या में गुणात्मक सुधार, आदि।

2.4 भारत में जनसंख्या नीति

भारत में जनसंख्या नीति को दो प्रकार से देखा जा सकता है:

प्रथम, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जनसंख्या नीति

द्वितीय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनसंख्या नीति।

2.4.1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जनसंख्या नीति

ब्रिटिश काल में शासन जनसंख्या पर नियन्त्रण लगाने के विरूद्ध था परन्तु बुद्धिजीवियों द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही थी। सन् 1916 में प्रकाशित अपनी पुस्तक **'The population Problems in India'** में **प्यारे कृष्ण वाटल** ने जनसंख्या को नियोजित करने पर बल दिया। सन् 1925 में गणित के **प्रोफेसर आर. डी. कर्वे** ने महाराष्ट्र में *संतति निग्रह चिकित्सालय* (बर्थ कन्ट्रोल क्लीनिक) स्थापित किया। उस समय किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में संतति निग्रह को एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी। कुछ समय बाद मद्रास में **'नवमाल्थसवादी संघ'** की स्थापना की गयी। 11 जून, 1930 को मैसूर सरकार ने सरकारी बर्थ कन्ट्रोल क्लीनिक की स्थापना की। ऐसा करने वाला यह विश्व के पहला राज्य था। इसी वर्ष मद्रास सरकार ने गर्भ नियन्त्रण के सम्बन्ध में शिक्षा देने का कार्य प्रारम्भ किया तथा 1932 में संतति निग्रह के हेतु अनेक चिकित्सालयों की स्थापना की। इसी वर्ष लखनऊ में **'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन'** में संतति निग्रह चिकित्सालयों से महिलाओं एवं पुरूषों को जन्म-नियन्त्रण की सुविधायें एवं सूचनाएं दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया।

सन् 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने श्री जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में **'राष्ट्रीय नियोजन समिति'** का गठन किया। इस समिति ने भारत की जनसंख्या वृद्धि का जीवन स्तर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों, परिवार नियोजन को राज्य की नीति का अभिन्न अंग बनाने, परिवार के आकार को सीमित करने हेतु विवाह की आयु में वृद्धि करने एवं बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति करने, संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त लोगों की नसबन्दी किये जाने, जनांकिकी सर्वेक्षण द्वारा बार-बार सर्वे कर जनसंख्या समंकों के गुणों में सुधार किये जाने से सम्बन्धित सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

1935-36 में **'अखिल भारतीय महिला सभा'** के आमंत्रण पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की विशेषज्ञ अमेरिका की **श्रीमती मार्गरेट सेंगर** भारत आयीं। उन्होंने इस क्षेत्र में अपने अनुभवों के आधार पर भारत की जनसंख्या नीति

में परिवार कल्याण कार्यक्रम को शामिल किये जाने की सलाह दी। सन् 1935 में श्रीमती कोवास जी जहांगीर की अध्यक्षता में परिवार स्वास्थ्य उत्थान अध्ययन समिति गठित की गयी। सन् 1936 में संतति निग्रह के प्रबल समर्थक **डॉ. ए. पी. पिल्लै** ने संतति निग्रह के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न स्थानों पर केन्द्रों की स्थापना की। 1938 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चन्द बोस ने परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया। 1939 से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में संतति निग्रह अर्थात् जन्म-नियन्त्रण चिकित्सालयों की स्थापना की गयी। सन् 1940 में **पी. एन. सपूर** ने Council of State में **'संतति नियमन चिकित्सालयों'** की स्थापना का प्रस्ताव रखा जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। सन् 1945 में **जोज़ेफ भोर** की अध्यक्षता में **'स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति'** की स्थापना की गयी जिसने जन्म-नियन्त्रण सेवाओं के विकास की संस्तुति की। महात्मा गांधी भी भारत में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं को हल करने हेतु जन्म-नियन्त्रण के पक्षधर थे किन्तु वे कृत्रिम विधियों के स्थान पर ब्रह्मचर्य को उचित ठहराते थे। उनका कहना था कि ***'वर्तमान भारत में गुलामों की संख्या में वृद्धि पर रोक लगा देना हमारा परम कर्तव्य है।'*** सन् 1938 में भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने आर्थिक प्रगति में तीव्रता लाने एवं आम जनता को खुशहाल बनाने हेतु जन्म-नियन्त्रण को अपनाने का सुझाव दिया था। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी लिखा कि परिवार नियोजन स्त्रियों को अनावश्यक मातृत्व से बचाता है। देश को अनावश्यक जनसंख्या से बचाता है तथा भुखमरी से बचाता है। भारत जैसे भूखग्रस्त देश में और बच्चे पैदा करना न केवल बेकसूर बच्चों की मौत बुलाना है वरन् सम्पूर्ण परिवार व देश को निकृष्ट जीवन में डालना है। इस अन्याय को नहीं होने देना चाहिये। भारत के सन्दर्भ में **गुन्नार मिर्डल** के शब्द भी महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना था कि ***'संक्षेप में ब्रिटिश शासनकाल की समाप्ति आने तक बुद्धिजीवियों ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया था कि स्वतन्त्र भारत की सरकार को एक प्रभावी जनसंख्या नीति अपनानी आवश्यक हो जायेगी।'***

2.4.2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जनसंख्या नीति

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जनसंख्या के उचित नियोजन हेतु विभिन्न प्रयत्न किये गये थे, परन्तु यह प्रयत्न संगठित नहीं थे और न ही इस दिशा में कोई स्पष्ट नीति बनायी गयी थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में जनसंख्या नीति की वास्तविक शुरूआत योजनाबद्ध विकास के साथ हुई। देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गयीं और इसके अन्तर्गत ही जनसंख्या नियोजन की ओर कदम उठाये गये, जो निम्नलिखित हैं:

2.4.2.1 पंचवर्षीय योजनाओं में जनसंख्या नीति

2.4.2.1.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56):

प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में योजना आयोग ने जनसंख्या का भारत के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसमें इस तथ्य को स्वीकार किया गया था दिया कि जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है अपितु बढ़ती हुई जनसंख्या समस्त उत्पादन एवं उपभोग व्यवस्था को प्रभावित करता है। परन्तु बाद में आयोग ने यह भी अनुभव

किया कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जीवन-स्तर को बढ़ाने में बाधक है। यह रहन-सहन के स्तर में सहायक होने की अपेक्षा इसे हतोत्साहित करती है। इस कारण से जनसंख्या नीति का मुख्य लक्ष्य जन्म-दर में करना था जिससे परिवारों का आकार सीमित किया जा सके।

प्रथम योजना में जनसंख्या नियन्त्रण नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित किये गये:

- परिवार नियोजन के लिए प्रचलित विभिन्न विधियों के सम्बन्ध में वास्तविक अनुभवों को संकलित करना तथा उनकी उपयुक्तता, लोकप्रियता और प्रभावशीलता ज्ञात करना।
- परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जनता को जागरूक करने की विभिन्न विधियों की जांच करना।
- जनता के अलग-अलग वर्गों के प्रतिनिधियों से प्रजनन प्रवृत्ति, परिवार के आकार एवं परिवार के प्रति उनके दृष्टिकोण आदि सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करना।
- मानवीय उर्वरता के मनोवैज्ञानिक तथा चिकित्सकीय पक्षों का अनुसंधान करना।
- आर्थिक, सामाजिक तथा जनसंख्या परिवर्तनों के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करना।

  वास्तव में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नीति केवल परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रारम्भिक तैयारी मात्र तक सीमित थी क्योंकि इसमें केवल तथ्यों का संकलन तथा वास्तविक समस्या को चिन्हित करने पर ही विशेष ध्यान दिया गया था। प्रथम योजना के अन्तर्गत 147 परिवार नियोजन केन्द्रों की स्थापना की गयी। इनमें 126 केन्द्र शहरी क्षेत्रों तथा 21 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये। इस योजना में 65 लाख रूपये व्यय करने का प्रावधान था किन्तु वास्तविक व्यय केवल 18 लाख रूपये ही किया गया।

2.4.2.1.2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61):

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह तथ्य स्वीकार किया गया कि जनता के दृष्टिकोण में इतनी तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है कि निश्चित अवधि के लिए इससे सम्बन्धित किसी स्थायी नीति का निर्धारण कठिन कार्य है। इसलिए प्रथम योजना में अपनाये गये जनसंख्या नीति के दीर्घकालीन दृष्टिकोण को त्याग कर उसके स्थान पर द्वितीय योजना में जनसंख्या की वर्तमान समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के महत्व को अवश्य स्वीकार किया गया था परन्तु इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का निर्धारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्यों का समावेश किया गयाः

- शिक्षा का प्रसार किया जाये। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो सकेगा जिसमें जनता निरोधक उपायों का स्वीकार करेंगे।
- जन्म-नियन्त्रण हेतु निरोधक उपायों की ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नसबन्दी की सुविधा उपलब्ध हो।
- परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाये।
- जनसंख्या समस्या से सम्बन्धित अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाये।

- एक सुसंगठित केन्द्रीय संगठन की स्थापना की जाये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में विभिन्न कार्य किये गये, जैसे- सरकारी प्रयासों से शिक्षा की दर में वृद्धि हुई, परिवार नियोजन कार्यक्रम को शिक्षित समाज का समर्थन प्राप्त हुआ, रेडियो आदि उपकरणों से इस कार्यक्रम को गांव-गांव तक प्रचारित किया गया, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 15 वर्ष कर दी गयी, प्रसव केन्द्रों की स्थापना से इस कार्यक्रम को बल मिला, विभिन्न सर्वेक्षणों से स्पष्ट हुआ कि महिलाएं परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों को जानने की इच्छा रखती हैं।

इस योजनाकाल में परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या बढ़कर 2206 हो गयी जिसमें 827 शहरी क्षेत्रों में तथा 1,379 ग्रामीण क्षेत्रों में थे। एक लाख लोगों की नसबन्दी भी की गयी। इस योजना में 5 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान था किन्तु वास्तव में 2.15 करोड़ रूपये ही व्यय किये गये। इसके साथ ही बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा त्रिवेन्द्रम में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गयी।

2.4.2.1.3 तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66):

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में तमाम प्रयासों के बाद भी जब 1961 की जनगणना हुई तो उसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। देश में मृत्यु दर तो अनुमान से कहीं अधिक कमी दर्ज हुई परन्तु जन्म दर में कमी परिलक्षित नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में जनसंख्या अनुमान की अपेक्षा अधिक तीव्र गति बढ़ी। इस कारण सरकार का ध्यान जनसंख्या नीति से हटकर जनसंख्या नियन्त्रण पर केन्द्रित हो गया। इस प्रकार, जनसंख्या नीति का स्थान परिवार नियोजन कार्यक्रम ने ले लिया। इस कार्यक्रम के महत्व की विवेचना इन शब्दों में की गई- ***'परिवार नियोजन को केवल विकास कार्यक्रम के रूप में ही अपनाना नहीं है, अपितु एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के रूप में इसे अपनाना है, जिससे व्यक्ति, परिवार एवं समाज के जीवन में सुधार लाया जा सके।'*** 1962-63 में सरकार ने जनसंख्या नीति को उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बताया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म दर को 41 प्रति हजार से घटाकर 1973 तक 25 प्रति हजार के स्तर पर लाना है।

इस योजना में जनसंख्या नीति का आधार जन्म नियन्त्रण तक ही सीमित होने के परिणामस्वरूप जनांकिकीय अनुसंधान भी केवल परिवार नियोजन तक ही सीमित हो गया। प्रथम योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु **'जनांकिकीय विनियोग'** को भी इस योजना में छोड़ दिया गया। तृतीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 27 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान था किन्तु 25 करोड़ रूपये ही व्यय किये गये। परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या बढ़कर 11,474 होना, अनेक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना होना, दिल्ली में तकनीकी परामर्श हेतु परिवार कल्याण संस्था की स्थापना होना, कानपुर में लूप बनाने के कारखाने का प्रारम्भ होना, लूप के प्ररचार-प्रसार में वृद्धि होना इस योजनाकाल में अपनायी गयी 'प्रचार नीति' की प्रमुख उपलब्धियां रहीं।

2.4.2.1.4 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74):

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में तृतीय योजना का ही अनुसरण किया गया। चतुर्थ योजना में माना गया कि यदि जनसंख्या इसी तीव्र गति से बढ़ती गयी तो राष्ट्रीय निवेश, शक्ति तथा प्रयत्नों का बहुत बड़ा भाग केवल वर्तमान रहन-सहन के स्तर को बनाये रखने में ही उपयोग होगा। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि एक गम्भीर चुनौती प्रस्तुत करती है। यह समस्या की ओर गम्भीरता और राष्ट्रीय तत्परता की मांग करती है।

जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि के परिणामस्वरूप चतुर्थ योजना में परिवार नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई, साथ ही मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया गया। इस योजना में लक्ष्यों को निर्धारित कर इनकी प्राप्ति हेतु कार्यक्रम चलाये गये, जनता को परिवार नियोजन की विधियों से प्रशिक्षित किया गया, नसबन्दी कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय कर दिया गया जिसे बाद में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। इस योजना में जन्म दर 40 प्रति हजार से घटकर 38 प्रति हजार हो गयी। इसी योजना में सन् 1972 में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की गयी। योजना में 284.43 करोड़ रूपये व्यय किये गये। योजना के दौरान देश में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, ग्रामीण उपकेन्द्र तथा शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या वृद्धि दर्ज की गयी।

2.4.2.1.5 पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-78):

पंचम अर्थात् पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी जनसंख्या नीति के परिमाणात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया गया। इसमें जनसंख्या नीति को परिवार नियोजन कार्यक्रम तक ही सीमित कर दिया गया। इसमें जनसंख्या नीति तथा परिवार नियोजन को गरीबी निवारण हेतु आवश्यक माना गया। इस योजना में परिवार नियोजन हेतु निर्धारित 497.4 करोड़ रूपये में से केवल 409 करोड़ रूपये ही व्यय किये जा सके। परिवार नियोजन कार्यक्रम को **'परिवार कल्याण कार्यक्रम'** के रूप में अपनाते हुए इस योजनावधि में 22 प्रतिशत सन्तानोत्पत्ति योग्य दम्पत्तियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया।

- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति: 1976 (आपातकाल के दौरान)**

भारत में जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की गयी। इसी दौरान 16 अप्रैल, 1976 को कांग्रेस सरकार ने नयी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य जन्म दर में कमी लाकर जनसंख्या विस्फोट की समस्या का त्वरित समाधान करना था। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि यदि वे चाहें तो कानून बनाकर बन्ध्याकरण को अनिवार्य कर सकते हैं।
- विभिन्न परिस्थितियों में अप्रैल 1972 से गर्भपात को वैध घोषित कर दिया गया।

- विवाह की न्यूनतम आयु को लड़कों हेतु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष तथा लड़कियों हेतु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
- केन्द्र द्वारा राज्यों की योजनाओं हेतु दी जाने वाली सहायता में आठ प्रतिशत परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर व्यय हेतु निर्धारित किया गया।
- जनसंख्या नियन्त्रण हेतु 1976 से दो जीवित बच्चों के बाद बन्ध्याकरण कराने पर प्रोत्साहनस्वरूप 150 रूपये, तीन बच्चों के बाद 100 रूपये तथा चार या अधिक बच्चों के बाद 70 रूपये क्षतिपूर्ति तथा एक सप्ताह का अवकाश दिये जाने की व्यवस्था की गयी।
- प्रजनन-दर में कमी लाने हेतु महिला शिक्षा के साथ ही बच्चों की उचित आहार व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया।

  परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने हेतु नयी बहुमुखी प्रेरणात्मक प्रचार नीति अपनायी गयी।

  आपातकाल के दौरान घोषित जनसंख्या नीति में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु उपरोक्त उपायों के साथ ही अन्य प्रयास भी किये गये। इस नीति में बन्ध्याकरण (sterilization) आदि के लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें कठोरता से प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनता के साथ जोर-जबरदस्ती भी की गयी। इस नीति में जन-सामान्य की खराब प्रतिक्रिया हुई।

- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति: 1977 (आपातकाल के पश्चात्)**

1976 की जनसंख्या नीति में अनिवार्यता एवं जोर-जबरदस्ती के कारण सरकार का पतन हो गया तथा केन्द्र में अगली सरकार जनता पार्टी की बनी जिसने 1977 में नई जनसंख्या नीति की घोषणा की। 1977 की इस नीति का आधार 1976 की जनसंख्या नीति ही था परन्तु इस नीति में परिवार नियोजन कार्यक्रम को सकारात्मक रूप प्रदान करते हुए इसमें **'अनिवार्यता'** के स्थान पर **'स्वेच्छा'** के सिद्धान्त को महत्व प्रदान किया गया। परिवार नियोजन के प्रति विरोध को शान्त करने के लिए **'परिवार नियोजन कार्यक्रम'** का नाम बदलकर **'परिवार कल्याण कार्यक्रम'** कर दिया गया। इस नीति में परिवार नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही जन्म नियन्त्रण हेतु आवश्यक सुविधाएं देना, इस हेतु सामाजिक संस्थाओं की सेवा लेना, जनसंख्या शिक्षा को प्रोत्साहन देना, प्रचार-प्रसार के नवीन साधनों का उपयोग करना आदि उपाय किये गये। परन्तु, परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लचीला रूख अपनाने के कारण इस कार्यक्रम को अपनाने वालों की संख्या में 68 प्रतिशत तथा बन्ध्याकरण के ऑपरेशन में 98 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गयी।

2.4.2.1.6 छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980-85):

छठवीं पंचवर्षीय योजना में भी परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी। इस योजना में कार्यक्रम पर 3,412 करोड़ रूपये व्यय किये गये। योजना में जन्म दर को 30 से घटाकर 25 प्रति हजार पर लाने तथा 24 मिलियन लोगों को बन्ध्याकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य था

परन्तु वास्तव में 17 मिलियन को ही इस दायरे में लाया जा सका। इसमें 7 मिलियन लूप लगाये गये जबकि लक्ष्य 7.9 मिलियन का था।

- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति: 1981**

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद तथा केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद का सातवां संयुक्त सम्मेलन 15-17 जून, 1981 की अवधि में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्पन्न हुआ जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तथा राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा नीतियों को स्वीकृति प्रदान की गयी। 1981 में घोषित जनसंख्या नीति की विशेषताओं में सन् 2000 तक जन्म दर को 21 प्रति हजार पर लाना, इसी अवधि में मृत्यु दर को घटाकर 9 प्रति हजार पर लाना, वर्ष 2000 तक 90 प्रतिशत दम्पत्तियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना, बन्ध्याकरण की भ्रान्तियों को दूर करना, छोटे परिवार हेतु जागरूकता लाना, जनसंख्या नियन्त्रण हेतु दीर्घकालीन नीतियों पर बल देना, परिवार नियोजन साधनों की सुलभता सुनिश्चित करना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, विभिन्न संगठनों को आर्थिक एवं तकनीकि सहायता प्रदान करना आदि प्रमुख हैं।

2.4.2.1.7 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90):

सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने स्वास्थ्य नीति में संशोधन किया तथा वर्ष 1990 तक परिवार कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किये, जैसे- प्रभावी दम्पत्ति संरक्षण दर को 42 प्रतिशत तक लाना, अशोधित जन्मदर तथा अशोधित मृत्युदर को घटाकर क्रमशः 29.1 तथा 10.4 प्रति हजार पर लाना, शिशु मृत्युदर को भी कम करके 90 प्रति हजार तक लाना, शत-प्रतिशत प्रतिरक्षीकरण करना आदि। इस योजना में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 3,121 करोड़ रूपये व्यय किये गये। योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। उदाहरणार्थ, 1990 में जन्मदर तथा मृत्युदर घटकर क्रमशः 30.2 तथा 9.7 प्रति हजार हो गयी, जबकि शिशु मृत्युदर कम होकर 80 प्रति हजार हो गयी।

2.4.2.1.8 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97):

दिसम्बर 1991 में योजना आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद को एक दस्तावेज 'जनसंख्या नियन्त्रण: चुनौतियां एवं व्यूह रचना' प्रस्तुत किया जिसमें उसने माना कि जनसंख्या विस्फोट देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है। यदि तीव्र गति से बढ़ती इस जनसंख्या को नहीं रोका गया तो इस जनसंख्या का भरण-पोषण कठिन होगा तथा सभी को सामाजिक-आर्थिक न्याय दिलाने के लक्ष्य की भी पूर्ति नहीं हो पायेगी। इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या परिमाण को नियन्त्रित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी। इस योजना में विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किये गये, जैसे- योजना के अन्त तक जन्मदर तथा मृत्युदर को कम कर क्रमशः 27 तथा 9.2 प्रति हजार तक लाना, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर को 1.78 प्रतिशत पर लाना, प्रजनन दर में कमी करना, जीवन-प्रत्याशा में वृद्धि करना आदि। योजना

में परिवार कल्याण कार्यक्रम पर 6,500 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान था परन्तु वास्तव में 7,294 करोड़ रूपये व्यय किये गये।

2.4.2.1.9 नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002):

नौवीं पंचवर्षीय योजना में माना गया कि देश की जनसंख्या वृद्धि में 15-44 प्रजनन आयुवर्ग का योगदान सबसे अधिक है, जन्म नियन्त्रण उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता न होना जनसंख्या में 20 प्रतिशत वृद्धि करता है तथा 20 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि देश में उच्च शिशु मृत्युदर के कारण हो जाती है। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए नौवीं योजना में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य शिशु मृत्युदर को 56-50 प्रति हजार तक लाना, अशोधित जन्मदर को 23 प्रति हजार तक लाना, कुल प्रजनन दर 2.6 तक लाना तथा युगल सुरक्षित दर 51-60 तक लाना था।

- **भारत की नवीन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति: 2000**

परिवार कल्याण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिये जाने के बाद भी जब देश 1 अरब जनसंख्या की ओर बढ़ रहा था तो इस कार्यक्रम के अपने लक्ष्यों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाने की चर्चाएं होने लगीं। विभिन्न संगठनों ने सरकार पर अपनी जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार करने का दबाव डालना प्रारम्भ कर दिया। उसी समय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर सलाह देने के लिए **डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन** की अध्यक्षता में गठित दल ने विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये। इस प्रकार, सन् 1996 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का एक प्रारूप तैयार कर इसे संसद से स्वीकृति प्रदान की गयी और केन्द्र सरकार ने 15 फरवरी, 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। इसमें परिवार नियोजन को स्वैच्छिक बनाये रखने, परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बाध्य न करने और प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन उपायों को न अपनाने का निर्णय लिया गया। इस नीति में जनसंख्या के परिमाण को राष्ट्रीय साधनों के अनुरूप नियन्त्रित करने एवं जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए निम्नलिखित तीन उद्देश्य निश्चित किये गये:

  - तात्कालिक उद्देश्य: पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधक उपायों का विस्तार करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढ़ांचे का विकास करना, जिससे परिवार नियोजन की सुविधाओं से वंचित लोगों को यह सुविधाएं प्राप्त हो सकें।
  - मध्यमकालीन उद्देश्य: कुल प्रजनन दर को सन् 2010 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना।
  - दीर्घकालीन उद्देश्य: सन् 2045 तक जनसंख्या ऐसे स्तर पर स्थिर करना जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विस्तार तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुकूल हो।

नवीन जनसंख्या नीति में वंचित लोगों तक प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने, 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु शिक्षा को अनिवार्य एवं निशुल्क करने, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर को घटाकर 20 प्रतिशत तक लाने, मातृत्व मृत्युदर को 100 प्रति एक लाख जीवित जन्म तथा शिशु मृत्युदर को 30 प्रति हजार जीवित जन्म तक लाने, सभी बच्चों का टीकाकरण करने,

लड़कियों के विवाह को 20 वर्ष के बाद करने को प्रोत्साहन देने, 80 प्रतिशत प्रसव संस्थाओं में तथा 100 प्रतिशत प्रसव प्रशिक्षित दाइयों द्वारा करवाने, जन्म, मृत्यु, विवाह तथा गर्भाधान का पंजीकरण करवाने, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करने, परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने आदि लक्ष्य रखे गये।

इस नीति में छोटे परिवार के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रेरक उपायों की घोषणा की गई, जिनमें प्रमुख हैं: छोटे परिवार को बढ़ावा देने वाली पंचायतों एवं जिला परिषदों को केन्द्र सरकार द्वारा पुरस्कृत करना, गरीबी रेखा से नीचे के उन परिवारों को 5000 रूपये की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देना जिनके केवल दो बच्चे हैं और उन्होनें बन्ध्याकरण करवा लिया है, बाल-विवाह निरोधक अधिनियम तथा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाना, गर्भपात सुविधा योजना को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बन्ध्याकरण की सुविधा हेतु सहायता देना आदि। इसके साथ ही देश में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राज्य जनसंख्या आयोग एवं योजना आयोग में समन्वय प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया।

2.4.2.1.10 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007):

दसवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल दिया गया। इसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु 27,125 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। इस योजना में शिशु एवं मातृ मृत्युदर को तेजी से कम करने की पहल की गयी। इसमें शिशु मृत्युदर को योजना के अन्त तक घटाकर 45 प्रति हजार पर लाने तथा 2012 तक 28 प्रति हजार पर पहुंचाने, मातृत्व मृत्युदर को 2007 तक 2 प्रति हजार जीवित जन्म तथा 2012 तक 01 प्रति हजार पर लाने के साथ ही 2001-2011 के दशक तक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को 16.2 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।

2.4.2.1.11 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012):

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी जनसंख्या नीति के अन्तर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के स्थिरीकरण में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को स्वीकार किया गया। ग्यारहवीं योजना में जनसंख्या के स्थिरीकरण हेतु योजना आयोग द्वारा एक कार्यदल का गठन किया। इस दल के कार्यों में देश में जनसंख्या स्थिरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए ग्यारहवीं योजना हेतु वर्तमान जनांकिकीय प्रक्षेपणों का पुनरीक्षण करना, वर्ष 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्यों का पुनरीक्षण करना, जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर नीतिगत सुझाव देना आदि शामिल हैं। इस योजना में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु आवश्यक सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने तथा शिशु एवं मातृ मृत्युदर को निरन्तर कम करने के

प्रयास किये गये। इस योजना के अन्त तक अशोधित जन्म दर को घटाकर 19 प्रति हजार तथा युगल संरक्षण दर 64 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया।

2.5 जनसंख्या नीति: एक मूल्यांकन

भारत में जनसंख्या नीति की वास्तविक शुरूआत योजनाबद्ध विकास के साथ ही हुई। पूर्व में जनसंख्या को कोई समस्या नहीं मानने के कारण इस नीति पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया परन्तु जब तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई तो देश में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु एक प्रभावी नीति का अनुसरण किया गया। चौथी योजना में जनसंख्या नीति के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई जबकि पांचवी योजना में आपातकाल के दौरान 16 अप्रैल, 1976 को प्रभावी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इसमें राज्य सरकारों को जनसंख्या नियन्त्रण हेतु **'अनिवार्य बन्ध्याकरण'** का कानून बनाने का अधिकार देने के साथ ही लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न कठोर उपाय किये गये। इस अनिवार्यता एवं जोर-जबरदस्ती के कारण सरकार का पतन हुआ तथा अगली सरकार ने 1977 में नई जनसंख्या नीति की घोषणा की जिसमें **'अनिवार्यता'** के स्थान पर **'स्वेच्छा'** के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की गयी साथ ही **'परिवार नियोजन कार्यक्रम'** को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इसका नाम बदलकर **'परिवार कल्याण कार्यक्रम'** कर दिया गया। इसके पश्चात् जून 1981 में भी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में संशोधन किया तथा फरवरी 2000 में देश की नवीन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा गयी।

देश में अभी तक जो जनसंख्या नीति लागू की गई हैं, उनके परिणामस्वरूप जनसंख्या के बढ़ने की दर में प्रभावी कमी आयी है, जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर में भी कमी परिलक्षित हुई है जबकि जीवन प्रत्याशा, युगल संरक्षण दर आदि में वृद्धि हुई है। परन्तु, जनसंख्या नीति में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हो पायी है। देश के कुछ राज्यों में आज भी कुल प्रजनन दर लक्ष्य से दुगुनी है जो हमारे उपलब्ध राष्ट्रीय संसाधनों पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। आज, देश की कुल जनसंख्या लगभग 122 करोड़ है जो विश्व में चीन के पश्चात् द्वितीय स्थान पर है और यह 1.41 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है। सम्भावना है कि सन् 2030 में भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जायेगा। इन परिस्थितियों में जनसंख्या नीति की सफलता हेतु आवश्यक है कि इसमें लक्ष्यों का निर्धारण देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों की विविधता को ध्यान में रखते हुए किया जाये, नीति के परिमाणात्मक पहलू के साथ-साथ गुणात्मक पहलू को भी समान महत्व दिया जाये साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम के उचित क्रियान्वयन हेतु इसमें संगठनात्मक सुधार किये जाये और इसे विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाये।

2.6 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

भारत की नवीन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जनसंख्या पर परिमाणात्मक नियन्त्रण एवं गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। इसी क्रम में, एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित किया गया जिसके अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा इसके सदस्यों में समस्त मुख्यमन्त्री, प्रमुख जनसंख्याशास्त्री, सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्री तथा जनस्वास्थ्य से सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। आयोग की प्रथम बैठक 22 जुलाई 2000 को

आयोजित की गयी। इस बैठक में सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये की प्रारम्भिक धनराशि से एक '**राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष**' गठित किये जाने की घोषणा की गयी साथ ही जनसंख्या स्थायित्व के इस राष्ट्रीय प्रयास में उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग हेतु प्रधानमन्त्री द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, व्यापार संगठनों एवं कॉरपोरेट क्षेत्र से अपील की गयी। इस कोष का प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या नीति के तात्कालिक, मध्यमकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति को सुगम बनाना है। यह सरकारी तथा स्वैच्छिक दोनों ही प्रकार की संस्थाओं को जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु तैयार परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निम्न राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकी सूचकांक वाले राज्यों में जनांकिकीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के अन्तर्गत एक कार्यदल का गठन किया जायेगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की तरह ही राज्य स्तर पर भी जनसंख्या आयोगों का गठन किया गया जिनका उद्देश्य सम्बन्धित नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

2.7 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. जनसंख्या नीति से आप क्या समझते हैं ?
2. जनसंख्या नीति 2000 में छोटे परिवार के प्रोत्साहन हेतु क्या प्रेरक उपाय किये गये ?

बहुविकल्पीय प्रश्न।

1. देश में लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु को किस जनसंख्या नीति में बढ़ाया गया:

(अ) 1976, (ब) 1977,

(स) 1981, (द) 2000।

2. जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर अवस्था में लाना है:

(अ) 2010, (ब) 2020,

(स) 2045, (द) 2050।

निम्नलिखित कथनों में सत्य/असत्य बताईये।

1. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में की गयी।

2.8 सारांश (Summary)

जनसंख्या नीति द्वारा एक देश की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या के परिमाण को नियन्त्रित करने एवं विद्यमान जनसंख्या के उत्पादक गुणों में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। भारत में भी जनसंख्या नीति को विशेष महत्व दिया जाता रहा है। देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जनसंख्या के उचित नियोजन हेतु विभिन्न प्रयत्न किये गये थे, परन्तु यह प्रयत्न संगठित नहीं थे और न ही इस दिशा में कोई स्पष्ट नीति बनायी गयी थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में जनसंख्या नीति की वास्तविक शुरूआत योजनाबद्ध विकास के साथ हुई। देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गयीं और इसके अन्तर्गत ही जनसंख्या नियोजन की ओर कदम उठाये गये। इसके साथ ही

विभिन्न समयों में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गयी जिनका उद्देश्य समय के अनुरूप जनांकिकीय लक्ष्यों की प्राप्ति कर देश को प्रगति की ओर अग्रसर करना था। देश में जनसंख्या नीति के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम को विशेष प्राथमिकता प्रदान की गयी। जनसंख्या पर प्रभावी नियन्त्रण के उद्देश्य से प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गयी। साथ ही राज्य स्तर पर भी जनसंख्या आयोगों का गठन किया गया।

2.9 शब्दावली (Glossary)

- **संतति निग्रह:** किसी भी यान्त्रिक, शारीरिक, रासायनिक तथा शल्य-क्रियात्मक ढ़ंग से स्त्री-पुरूष समागम के आनन्द को प्रभावित किये बिना गर्भ-धारण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना ही संतति-निग्रह है।
- **जनसंख्या-विस्फोट:** जनसंख्या-विस्फोट एक ऐसी स्थिति है जिसमें जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती है जिसे थोड़े समय में नियन्त्रित नहीं जा सकता है।

2.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Questions)

उत्तर 1: जनसंख्या नीति से आशय उन समस्त गतिविधियों से है जो देश की आवश्यकता के अनुरूप जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी करने एवं विद्यमान जनसंख्या के उत्पादक गुणों में वृद्धि करने के लिए की जाती हैं।

उत्तर 2: इस नीति में छोटे परिवार के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रेरक उपायों की घोषणा की गई, जैसे- छोटे परिवार को बढ़ावा देने वाली पंचायतों एवं जिला परिषदों को पुरस्कृत करना, गरीबी रेखा से नीचे के उन परिवारों को 5000 रूपये की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देना जिनके केवल दो बच्चे हैं और उन्होंने बन्ध्याकरण करवा लिया है, बाल-विवाह निरोधक अधिनियम तथा प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाना, गर्भपात सुविधा योजना को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बन्ध्याकरण की सुविधा हेतु सहायता देना आदि।

उत्तर 3: **बहुविकल्पीय प्रश्न।**

1. (अ), 2. (स)।

उत्तर 4: **निम्नलिखित कथनों में सत्य/असत्य बताईये।**

1. सत्य, 2. असत्य, 3. सत्य।

2.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Refrences/Bibliography)

- कुमार, वी. (2007): *जनांकिकी*, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि., आगरा
- पन्त, जे.सी. (2006): *जनांकिकी*, विशाल पब्लिशिंग कं., जालन्धर
- चौबे, पी .के .(2000) *भारत में जनसंख्या नीति*, कनिस्ट प्रकाशन ,नई दिल्ली

2.12 उपयोगी/सहायक पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- Carr- Saunders, A.M., World Population : Past Growth and Present Trends, Oxford : Clarendon Press, 1936.
- Coale, Ansley J. and Edgar M. Hoover, Populationi Growth and Economic development in low income countries, Princeton University Press, 1958.
- A.M. Carr Saunders : World Population, 1936, P.42
- Walter F. Willcox : Studies in American Demography, 1940 P. 40
- M.K. Bonnett: the world, 1954 3
- Ross, John, A (1982): International Encyclopedia of Population The Free Press. Macmillon Publishing co.New York.
- U.N. Determinantes and Consequences of Population Trends, 1953, P. 61
- UNFPA, The State of World Population, 1996
- United Nations Population Division , Word Population 2006.
- World Bank Atlas 1996
- Estimated from United Nations, 1986
- U.N. Demographic Year Book, 1950
- Selected World Demographic Inedicators by Region and Country or Area. 1970-75, Prepared by United Nations Population Division .

2.13 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. जनसंख्या नीति से आप क्या समझते हैं ? भारत में जनसंख्या नीति अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल रही है?
2. पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अपनायी गयी भारतीय जनसंख्या नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
3. भारत में जनसंख्या नीति के क्रमिक विकास पर एक निबन्ध लिखिए।
4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
   (क) भारत की जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख विशेषताएं।
   (ख) स्वतन्त्रता पूर्व भारत की जनसंख्या नीति।
   (ग) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग।
   (घ) जनसंख्या नीति को प्रभावशाली बनाने के उपाय।

इकाई 3- परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं महिला सशक्तिकरण
(Family Planning Programme and Women Education)

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 भारत में परिवार नियोजन
3.4 परिवार नियोजन की विधियाँ
3.5 परिवार नियोजन की विधियों के देश में उपयोग का परिदृश्य
3.6 परिवार नियोजन के लाभ
3.7 परिवार नियोजन के मार्ग में कठिनाइयाँ
3.8 परिवार नियोजन की कठिनाइयों को दूर करने के सुझाव
3.9 परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति
3.10 महिला शिक्षा
3.11 अभ्यास प्रश्न
3.12 सांराश
3.13 शब्दावली
3.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
3.16 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
3.17 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

परिवार नियोजन कई दशकों से एक केंद्रीय राष्ट्रीय मुद्दा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर जनसंख्या नियंत्रण का होता है। परिवार नियोजन लोग अपनी इच्छानुसार करते हैं पर जनसंख्या नियंत्रण योजनाकार की इच्छा पर निर्भर होता है। वर्ष 1978 से इस कार्यक्रम को मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम से जोड दिया गया जिससे विवाह की सही उम्र से लेकर गर्भावस्था में देखभाल, सुरक्षित प्रसव, माँ तथा बच्चे की देखभाल, बच्चो की जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा हेतु टीके लगाने के कार्यक्रम के साथ - साथ जनसंख्या नियंत्रण की सेवायें उपलब्ध कराकर परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया था। प्रस्तुत इकाई में परिवार नियोजन आवश्यक परिवार नियोजन की विधियाँ, परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम की अब तक की प्रगति एवं महिला शिक्षा की परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम में उपयोगिता और इससे सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत है।

3.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- ✓ बता सकेंगे कि परिवार नियोजन की विधियों से क्या आशय है।
- ✓ समझा सकेंगे कि देश के विकास हेतु परिवार नियोजन क्यों इतना आवश्यक है।
- ✓ परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को जान सकेगें। परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम की अब तक की प्रगति को जॉच सकेगें।
- ✓ महिला शिक्षा की परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम में उपयोगिता का मूल्यांकन कर सकेगें।

3.3 भारत में परिवार नियोजन

जनसंख्या नियंत्रण और जन्म नियंत्रण में जरुर अन्तर है। जनसंख्या नियंत्रण तो आज का मुद्दा है पर जन्म नियंत्रण की प्रथा तो काफी प्राचीन समय से चलती आ रही है। आधुनिक विज्ञान ने हमें प्रजनन नियंत्रण के लिए बहुत से तरीके दिए हैं। अब लगभग सम्पूर्ण गर्भ निरोधन सम्भव है। बाँझपन के इलाज के लिए भी नए-नए वैज्ञानिक तरीके आ रहे हैं। परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण कई दशकों से एक केंद्रीय राष्ट्रीय मुद्दा रहा है। परिवार नियोजन का अर्थ है कि परिवार छोटा रहे और बच्चों के बीच पर्याप्त अन्तर हो। राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर जनसंख्या नियंत्रण का होता है। परिवार नियोजन लोग अपनी इच्छानुसार करते हैं पर जनसंख्या नियंत्रण योजनाकार की इच्छा पर निर्भर होता है। परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है,जो वर्ष 1951 से चलाया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य देश की बढती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाना तथा जन्म दर मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर पर नियत्रंण के साथ संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, सुरक्षित प्रसव, प्रतिरक्षीकरण सेवाओं, पोषण, दस्त नियत्रंण जैसे कार्यक्रम प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों को पूरे देश में चलाया जाना है। पहले इस कार्यक्रम का नाम परिवार नियोजन था क्योंकि तब विभाग केवल जनसंख्या नियंत्रण की सेवा ही उपलब्ध करता था। किन्तु वर्ष 1978 से इस कार्यक्रम को मातृ शिशु

कल्याण कार्यक्रम से जोड दिया गया जिससे विवाह की सही उम्र से लेकर गर्भावस्था में देखभाल, सुरक्षित प्रसव, माँ तथा बच्चे की देखभाल, बच्चो की जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा हेतु टीके लगाने के कार्यक्रम के साथ-साथ जनसंख्या नियंत्रण की सेवायें उपलब्ध कराकर परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया था।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के नीतिगत लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की एक ऐसी सीमा तक पहुँचना है, जो पर्यावरण के साथ-साथ भावी पीढियों के संसाधन आधार को बिना संकटकग्रस्त किए ही जीवन की अत्युत्तम गुणवत्ता को स्वीकृति प्रदान करता हो। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन का अर्थ है कि परिवार को एक सीमा तक ही बढाया जाए ताकि परिवार की आमदनी का ध्यान रखते हुए जीवन स्तर को ऊँचा किया जाए या कम से कम नीचा होने से तो अवश्य रोका जाए। सार रूप में कहा जाए तो, ***"परिवार को जान बूझकर अपनी इच्छानुसार सीमित करना, उचित समय के बाद सन्तान पैदा करना ही परिवार नियोजन है।"*** इसके लिए कई उपाय काम में लाए जा सकते है:

जैसे—(1) गर्भ निरोधक साधन (2) दवाइयां (3) आपरेशन (4) लूप (5) इंजेक्शन आदि।

अन्य शब्दों में कहे तो परिवार नियोजन वह है जिसमें एक परिवार में एक या दो बच्चे होने चाहिए तथा इन बच्चों के जन्म में तीन साल का अन्तर होना चाहिए। दो बच्चों के बाद माता या पिता को अपना आपरेशन करा लेना चाहिए। अब सरकार ने इस कार्यक्रम का और विस्तार कर इसका नाम परिवार कल्याण कर दिया है।

3.4 परिवार नियोजन की विधियाँ

जनसंख्या नियंत्रण पर राज्य का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण 1950 के दशक से शुरू हुआ। 1960 में कई सारे गर्भनिरोधक तरीके शुरू किए गए थे। पर जल्दी ही हारमोन की गोलियों, कॉपर-टी और सामूहिक नसबंदी ऑपरेशनों से नए रुझान की शुरुआत हुई। नए तरीके महिलाओं की जिन्दगियों में ज्यादा दखल देने वाले, देर तक असर करने वाले और डॉक्टर द्वारा नियंत्रित थे। अब हमारे पास और भी असरकारी तरीके जैसे हारमोन के इंजेक्शन (नैट- एन, डीपो प्रोवेरा) और रोप (नॉर प्लांट), दुर्बीन से नलिकाबन्दी और गर्भ निरोधक टीके उपलब्ध हैं। पहले के जन्म नियंत्रण के तरीके महिला, जोड़े और परिवार की भलाई पर केन्द्रित थे। पर नए तरीके सिर्फ संख्या नियंत्रित करने वाले तरीके हैं।

इन रुझानों के निशाने पर पुरुषों के मुकाबले महिलाएँ ज्यादा हैं। किसी समय में पुरुष नसबन्दी को, महिला नलिकाबन्दी से ज्यादा महत्व दिया जाता था। पर अब नसबन्दी तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होने के बावजूद बिलकुल गायब ही हो गई है। प्रजनन नियंत्रण का पूरा भार इस तरह से महिलाओं पर ही डाल दिया गया है।

परिवार नियोजन की विधियाँ निम्नवत है-

(1) आत्म संयम (2)सुरक्षा काल का पालन (3) गर्भ निरोधक गोली (4) आर. यू. एस. डी. विधि अपनाना (5) हारमोन इन्जेक्शन (6) गर्भ निरोधक क्रीम तथा वर्तिका (7) आवरण विधि (8) सहवास अवरोध (9) शल्य क्रिया द्वारा गर्भ निरोध।

3.5 परिवार नियोजन की विधियों के देश में उपयोग का परिदृश्य

परिवार नियोजन की विधियों की जानकारी भारत में सार्वभौम है, 99 प्रतिशत से अधिक महिलाएं किसी न किसी एक विधि की जानकारी रखती हैं। तथापि सभी आधुनिक विधियों की जानकारी केवल 49 प्रतिशत को ही प्राप्त है। सभी आधुनिक विधियों (नसबंदी और नलबंदी, आई यू डी, खाने वाली गोली और कण्डोम) की जानकारी रखने वाली महिलाओं का अनुपात राज्य वार अलग-अलग है - यह अनुपात मेघालय में 2 प्रतिशत से लेकर हिमाचल प्रदेश में 8. प्रतिशत तक है।

डी. एल. एच. एस. (2003-04) के अनुसार इस समय भारत में 15-44 वर्ष की आयु वाली विवाहित महिलाओं में से लगभग 53 प्रतिशत महिलाएं परिवार नियोजन की किसी न किसी एक विधि का प्रयोग करती है परन्तु उनमें से अधिकांश महिलाएं (35 प्रतिशत) परिवार नियोजन की स्थायी विधि अपना चुकी है। सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों से यह पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में परिवार नियोजन संबंधी ऐसी आवश्यकताएं अभी भी काफी शेष हैं जिन्हें अभी पूरा करना है। गर्भनिरोधक की प्रचलित दर के जरिए जिलों के श्रेणीकरण और मानचित्रण से उन जिलों में अत्यधिक प्रभावी ढंग से कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता मिलती है जिन जिलों में गर्भनिरोधक का प्रचलन बहुत कम है। जिलों के श्रेणीकरण और मानचित्रण (सामाजिक-आर्थिक विकास सूचकों पर आधारित) के अनुसार दंपत्ती संरक्षण दर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि श्रेणी में नीचे से 100जिले अरूणाचल प्रदेश, बिहार (राज्य के 37 जिलों में से 29जिलों), उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंध रखते हैं। 1880 लाख जोड़ों को गर्भनिरोधक की आवश्यकता है। उनमें से केवल 53 प्रतिशत व्यक्ति ही गर्भनिरोधक का प्रयोग कर रहें हैं |जानकारी और पहुंच संबंधी समस्याओं के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग गर्भनिरोध सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते यद्यपि वे सेवाएं यहां उपलब्ध हैं।

3.6 परिवार नियोजन के लाभ

परिवार नियोजन का लाभ उस अपनाने वाले परिवार के साथ ही देश और समाज को है इसको हम निम्न रूप में देख सकते है।

(1) बच्चो को लाभ- परिवार नियोजन का बच्चों पर अनुकूल प्रभाव पड.ता है। कम बच्चे होने को कारण उनकी पढाई तथा पालन-पोषण अच्छे ढंग से किया जा सकेगा। उनके शिक्षा स्वास्थ्य पर हम अच्छा विकास कर सकेगें। जो आगे चलकर देश के अच्छे नागरिक बन सकेंगे।

(2) माता-पिता को लाभ– परिवार नियोजन का माता-पिता के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पडता है। वे अपने परिवार का जीवन स्तर ऊँचा रख सकते है। माताओं को अच्छा स्वास्थ्य अधिक लम्बी आय और अधिक सखीजीवन तथा बच्चों की अधिक देखभाल और पालन-पोषण एवं शिक्षण के लिए परिवार नियोजन आवश्यक है।

(3) समाज को लाभ- परिवार नियोजन व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि कम बच्चो पर व्यक्ति उनका अच्छे से पालन-पोषण कर सकेगा जो आगे अच्छे नागरिक बनेगा जिसके कारण समाज उन्नत बन सकेगा तथा समाज का स्तर ऊपर उठेगा।

(4) राष्ट्र को लाभ- परिवार नियोजन को प्रभावी रूप में लागू करने पर ही देश का आर्थिक रूप से तीव्र विकास संभव है। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है।

3.7 परिवार नियोजन के मार्ग में कठिनाइयाँ (Obstacles in the Family Planning)

परिवार नियोजन के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं :

(1) गरीबी - देश की जनसंख्या का बहुत अधिक हिस्सा अभी गरीबी में जीवनयापन करता है। वे परिवार नियोजन के प्रतिबंधक उपायों पर होने वाले खर्च सहन नहीं कर सकते। साथ ही अधिक बच्चों को वह परिवार में आय वृद्धि की आशा जोड़ते हैं।

(2) अशिक्षा- परिवार नियोजन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण नियोजन के महत्त्व को समझ नहीं पाते। फलस्वरूप परिवार नियोजन कार्यक्रम में उनकी भागीदारी तथा स्वीकृति उत्साहजनक नहीं है। **(3) भाग्यवाद-** भारतीय जनमानस में भाग्यवादिता का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति उनकी रूचि लगभग न के बराबर होती है।

(3) धर्म विरूद्ध- देश में कुछ लोग अज्ञानतावस परिवार नियोजन को धर्म विरूद्ध तथा अनैतिक क्रिया मानते है। अतः इस कार्यक्रम का समर्थन करने की बजाए वे इसका विरोध करते हैं।

(4) अपर्याप्त कोष– धन के अभाव में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार देश में प्रत्येक कोने तक नहीं हो सका है।

(5) सस्ती एवं लोकलुभावन प्रभावपूर्ण विधियों का आभाव- परिवार नियोजन संम्बन्धी अनुसंधान अपर्याप्त है। परिणामस्वरूप सस्ती एवं लोकलुभावन प्रभावपूर्ण विधियों का अभाव पाया जा रहा है।

(6) प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी- देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के जानकार प्रशिक्षित स्ट्राफ का अभाव है, जिस कारण परिवार नियोजन कार्यक्रमों को जन-जन तक नहीं पहुंचा सके हैं।

(7) सर्वभौमिक प्रचार-प्रसार का अभाव- भारत एक विषम भौगोलिक, संस्कृति भाषा और क्षेत्र का देश है जिस कारण परिवार नियोजन संबधी सूचना इन दूरस्थ स्थानों तक पहुँचाना बहुत कठिन कार्य है। फलस्वरूप परिवार नियोजन कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी अपर्याप्त रहती है।

3.8 परिवार नियोजन की कठिनाइयों को दूर करने के सुझाव

परिवार नियोजन की कठिनाइयों को दूर करने हेतु निम्नलिखित कदम आवश्यक है :

1. **शिक्षा का प्रसार :-** शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बिना इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। शिक्षित लोग परिवार नियोजन के महत्व को भली-भाँति समझ सकता है, और इसके लिए प्रयत्न करता है।
2. **वित्तीय सहायता की मात्रा में वृद्धि :-** इस कार्यक्रम हेतु व्यापक पैमाने पर परिवार नियोजन केन्द्रों, गर्भ निरोधक साधनों, प्रचार की आवश्यकता है, जिस कार्य हेतु अधिक वि-य सहायता की जरूरत है।

3. **सस्ते और प्रभावशाली उपाय किए जाना :-** सन्तान निरोधक उपाय सस्ते और प्रभावी हो इस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि सभी लोग आसानी से इनका उपयोग कर सकें।
4. **व्यापक प्रचार :-** परिवार नियोजन कार्यक्रमों एवं साधनों का व्यापक रूप में पिछडे. ग्रामीण आदि क्षेत्रों में अखबार ,रेडियों टी.वी.,गीत ड्रामा आदि से प्रचार किया जाना चाहिए।
5. **नियत्रण-बद्ध उपाय :-** अभी यह कार्यक्रम स्वैच्छिक है, परन्तु इसे नियत्रंण बद्ध किया जाए जैसे- सिविल अधिकारों को रद्ध करना, सरकारी नौकरी में मनाही, चुनाव लडने से रोक आदि।
6. **सामाजिक विचारधारा में परिवर्तन :-** हमारे यहां परिवार नियोजन के साधन को लोग अनैतिक कार्य मानते है जो एक गलत दृष्टिकोण है। इस सम्बन्ध में व्यापक रूप में नैतिक प्रचार-प्रसार करना चाहिए।
7. परिवार नियोजन सुविधाओं की सरलता से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
8. शिशु एवं बाल मृत्यु दर नियंत्रण में करना चाहिए।
9. देर से विवाह को बढावा देना चाहिए।
10. समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठाना की नितांत आवश्यकता है।
11. राजनैतिक दलों द्वारा अपने कार्यक्रम में परिवार नियोजन को महत्व प्रदान करना।

3.9 परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति

जन्म दर तथा मृत्यु दर के आधार पर परिवार नियोजन सम्बन्धी उपायों की कुछ सीमा तक सफलता मिली है, परन्तु बढती जनसंख्या अभी तक एक जटिल समस्या बनी हुई है। इसका कारण यह है कि जन्म–दर में होने वाली कमी जनसंख्या की वृद्धि दर को ज्यादा घटाने में पर्याप्त नहीं है। प्रजनन दर अर्थात 15 से 45 वर्ष तक प्रजनन दर अर्थात 15 से 45 वर्ष तक प्रजनन आयु समूह के प्रति हजार महिलाओं की प्रतिस्थापना दर जो 1971 में 5.2 थी वह 2007 में घटकर 2.7 एवं 2012 में 2.3 हो गई। शिशु मृत्यु दर जो 1985 में 95 प्रति हजार थी वह 2012 में 65 हो गई। बाल मृत्यु दर जो 1985 में 80प्रति हजार थी वह 2012 45 हो गई। दम्पति सुरक्षा दर 1972 में 12.2 प्रतिशत थी, वह 2012में 64प्रतिशत हो गई।

देश में विशेष रूप से उन जिलों को चिन्हित कर कार्य किया जा रहा है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये जिले विशेष रूप से उत्तर भारत के प्रमुख हिन्दी भाषी राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखण्ड से है। यहां जनसंख्या नियत्रंण के लिए गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। निजी क्षेत्र को शामिल करने तथा उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए भी उपाय किए रहे है। चीन में जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 0.6 प्रतिशत हो गया है, जबकि भारत में यह अभी भी 1.28 प्रतिशत है। इसलिए भारत में, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को गहनता से अपनाना होगा।

परिवार की खुशियाँ आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, तथा मानसिक स्तरों पर निर्भर करती है। पति-पत्नी की खुशी तभी है जबकि उनका तथा बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो तथा परिवार के पालन-पोषण तथा रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा हो। परिवार नियोजन का तात्पर्य केवल कम बच्चे पैदा करने से ही नहीं है बल्कि दो बच्चों के जन्म के बीच के समय पर नियत्रंण करना भी इसी का एक पहलू है।

3.10 महिला शिक्षा

शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए इस तरह महत्वपूर्ण है जिस तरह ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी हैं। शिक्षा के बिना मनुष्य बिल्कुल जानवर की तरह है यही शिक्षा है जो इंसान को बुद्धि और चेतना के धन से मालामाल करती है और जीवन की हकीक़तों से अवगत कराती है बिना ज्ञान मनुष्य कभी भी सीधी राह पर नहीं चल सकता हैं। ज्ञान ही मनुष्य को अधिकार की राह की ओर ले जाता हैं। शिक्षा के महत्व के बारे में लगभग सभी लोग परिचित हैं और इसी कारण कई लोग अपने जीवन को ज्ञान की प्राप्ति के लिए निछावर कर देते हैं और यही वजह है की सभी धर्मों में ज्ञान प्राप्त करने पर काफी जोर दिया गया है।

आज के विकसित दौर में जो भी देश का निर्माण व विकास चाहता है वह अपनी विकास यात्रा में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भागीदारी भी चाहता है क्योंकि किसी भी देश का विकास व उन्नति में पुरुषों के साथ महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो महिलायें इस भूमिका में हिस्सा ले रही हैं उनका महत्व बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता हैं। महिलाएं भी पुरुषों की तरह विभिन्न विभाग और सेवाओं में हिस्सा ले कर देश की सेवा कर रही हैं और यह केवल इसलिए संभव हुआ है कि शिक्षा के गहने से सुसज्जित हैं।

वैसे तो शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करना हर मर्द और औरत का अधिकार है लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्ति ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी की अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण जो करनी होती हैं। आगे आने वाली पीढ़ी की अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण में एक पढ़ी-लिखी माँ ही बेहतर हिस्सा ले सकती हैं। इसलिए उनका शिक्षित होना जरूरी है ताकि वह देश की खुशहाली और स्थिरता में अपनी भूमिका निभा सकें! देखने में आया है कि पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा और प्रशिक्षण का बेहतर रूप-रेखा तैयार कर सकती हैं और उनका बेहतर खयाल कर सकती हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जल्दी विकास कर सकते हैं. इसके विपरीत अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी महिलाएं अपने बच्चों की उस तरह परवरिश नहीं कर पाती हैं जिस तरह से परवरिश करनी चाहिए साथ ही उसके बच्चे भी बीमारियों का शिकार रहते हैं, क्योंकि वह स्वास्थ्य नियमों के अनुसार अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाती हैं। जबकि पढ़ी लिखी माँ बच्चे की शुरू दिन से ही बेहतरीन ख़याल रखती हैं भोजन उचित देने के कारण वह स्वस्थ रहते हैं।

जब माँ अच्छी परवरिश देकर बच्चों को अच्छी दिशा देंगीं तो हमारा राष्ट्र भी अच्छा राष्ट्र बनेगा जिससे यह बात साबित होती है कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र तब बनता है जब माँ पढ़ी-लिखी, जागरूक और समझदार होती हैं आज जब हर तरफ मीडिया अपने प्रभाव लोगों पर डाल रहा है इंटरनेट, केबल और वीडियो गेम भी बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. ऐसे में एक पढ़ी लिखी और जागरूक माँ ही अपने बच्चों को उनके प्रभाव से सुरक्षित रख सकती है और समय की आवश्यकताओं के अनुसार अपने बच्चों का प्रशिक्षण सही रूप से कर सकती हैं। क्योंकि शिक्षित होने की वजह से वह अच्छे बुरे की तमीज़ बेहतर कर सकती है जो कि बच्चों को एक अच्छा इंसान और उपयोगी नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होता है हिन्दुस्तान के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर अफ़सोस नाक हद तक कम है, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है कि वहां पर शिक्षण संस्थानों का अभाव हैं। वहां पर शैक्षणिक संस्थान तो हैं मगर वहां के घर के मुखियाओं में महिलाओं को शिक्षा

दिलाने का रुझान नहीं हैं। घर के मुखियाओं के अनुसार शिक्षा पाने के बाद वह अपने अधिकारों की मांग करने लगती हैं और पढ़ लिख कर परिवार की बदनामी का कारण बनेंगी इन क्षेत्रों की महिलाएं पूर्ण रूप से शिक्षा और समाज की जानकारी चाहती हैं, लेकिन सामाजिक प्रथा व रिवाज़ और पर्दे के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं और इसके साथ ही घर वाले भी लड़कियों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं देते जो एक चिंतनीय विषय है अब यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह हर हाल में इस पर विचार करे ताकि यह महिलाएं भी शिक्षित हो कर आने वाले भविष्य और समय में आने वाली पीढ़ी को विकसित कर पाए तथा अपनी योग्यताओं को भी प्रयोग में ला सकें।

पिछले कुछ सालों से महिलाओं में शिक्षा पाने की चेतना उजागर हुई हैं। जिसकी वजह से अब पहले की तुलना में काफी संख्या में महिलाएं विभिन्न क्षेत्र में पढ़ाई कर रही हैं और अलग-अलग विभाग में नौकरी कर के देश की सेवा के साथ साथ घरवालों का प्रायोजन कर रही हैं. और देखने में यह भी आया है की घर के प्रमुख के ना रहने की स्थिति में या घर का प्रमुख कामकाज के योग्य ना-रहने की वजह से घर प्रणाली चलाने की जिम्मेदारी भी महिलाएं बा-खूबी संभाल लेती हैं इसके अलावा आज के इस दौर में जब महंगाई की मार हर जगह पड़ रही है कमाने वाला एक और खाने वाले दस हो तो यह जरूरी हो जाता है कि आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए महिलाएं भी पुरुषों के साथ काम करें और यह तभी संभव होता है जब वह शिक्षा के गहने से सुसज्जित हैं क्योंकि बिना शिक्षा के वह किसी भी प्रकार की उत्कृष्ट नौकरी नहीं कर सकती हैं इसलिए हर महिला को जितनी भी हो सके शिक्षा के मैदान में आगे आना चाहिए ताकि कल को किसी भी अप्रिय स्थिति में अपने पांव पर खुद खड़ी हो सकें और किसी पर बोझ न बनें। जनन क्षमता का माता के शिक्षा स्तर के साथ गहरा सम्बन्ध है।

3.11 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. परिवार नियोजन के क्या अभिप्राय है?
2. भारत में परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है?
3. इसके रास्ते की मुख्य कठिनाइयों का वर्णन करें तथा इन्हें दूर करने के सुझाव दे।
4. परिवार नियोजन के प्रमुख विधियों को बताइए।
5. परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता हेतु सुझाव दीजिए।
6. परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
7. महिला शिक्षा पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

सही विकल्प चुनें

1. परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया।

(अ) 1951 (ब) 1955

(स) 1958 (द) 1959

2. परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम 1978 में बदल कर क्या किया गया।

(अ) परिवार सुरक्षा कार्यक्रम (ब) परिवार नियंत्रण कार्यक्रम

(स) परिवार कल्याण कार्यक्रम (द) परिवार कार्यक्रम

3. परिवार नियोजन की विधियाँ है

(अ) आत्म संयम (ब) सुरक्षा काल का पालन

(स) गर्भ निरोधक गोली (द) ये सभी

4. परिवार नियोजन का लाभ होगा

(अ) व्यक्ति को (ब) प्रदेश को

(स) राष्ट्र को (द) सभी को

5. दम्पति सुरक्षा दर 1972 में 12.2 प्रतिशत थी, वह 2012 में कितने प्रतिशत हो गई थी?

(अ) 64 (ब) 84

(स) 94 (द) 54

3.12 सारांश (Summary)

परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण कई दशकों से एक केंद्रीय राष्ट्रीय मुद्दा रहा है। परिवार नियोजन का अर्थ है कि परिवार छोटा रहे और बच्चों के बीच पर्याप्त अन्तर हो। राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर जनसंख्या नियंत्रण का होता है। परिवार नियोजन लोग अपनी इच्छानुसार करते हैं पर जनसंख्या नियंत्रण योजनाकार की इच्छा पर निर्भर होता है। हां जनसंख्या नियत्रंण के लिए गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। निजी क्षेत्र को शामिल करने तथा उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए भी उपाय किए रहे है। चीन में जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 0.6 प्रतिशत हो गया है, जबकि भारत में यह अभी भी प्रतिशत है। इसलिए भारत में, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को गहनता से अपनाना होगा। परिवार की खुशियाँ आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, तथा मानसिक स्तरों पर निर्भर करती है। पति-पत्नी की खुशी तभी है जबकि उनका तथा बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो तथा परिवार के पालन-पोषण तथा रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा हो। परिवार नियोजन का तात्पर्य केवल कम बच्चे पैदा करने से ही नहीं है बल्कि दो बच्चों के जन्म के बीच के समय पर नियत्रंण करना भी इसी का एक पहलू है।।

महिलाओं में शिक्षा पाने की चेतना उजागर हुई हैं। जिसकी वजह से अब पहले की तुलना में काफी संख्या में महिलाएं विभिन्न क्षेत्र में पढ़ाई कर रही हैं और अलग-अलग विभाग में नौकरी कर के देश की सेवा के साथ साथ घरवालों का सहयोग कर रही हैं और देखने में यह भी आया है की घर के प्रमुख के ना रहने की स्थिति में या घर का प्रमुख कामकाज के योग्य ना-रहने की वजह से घर प्रणाली चलाने की जिम्मेद महिलाएं बाखूबी संभाल लेती हैं इसके अलावा आज के इस दौर में जब महंगाई की मार हर जगह पड़ रही है, कमाने वाला एक और खाने वाले दस हो तो यह जरूरी हो जाता है कि आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए महिलाएं भी पुरुषों के साथ काम करें और यह तभी संभव होता है। जब वह शिक्षा के गहने से सुसज्जित हैं क्योंकि बिना शिक्षा के वह किसी भी प्रकार की उत्कृष्ट नौकरी नहीं कर सकती हैं इसलिए हर महिला को जितनी भी हो सके शिक्षा के मैदान में आगे आना चाहिए ताकि कल को किसी भी कठिन स्थिति में अपने पांव पर खुद खड़ी हो सकें और किसी पर बोझ न बनें।

3.13 शब्दावली (Glossary)

- **परिवार नियोजन :-** परिवार नियोजन से अभिप्राय परिवार का छोटा आकार तथा बच्चों की आयु के बीच सही अंतर से है।
- **परिवार कल्याण :-** परिवार कल्याण से अभिप्राय परिवारों के जीवन की गुणवत्ता है। इसमें परिवार नियोजन को न केवल जीवन को बेहतर गुणवत्ता के एक साधन के रूप में सम्मिलित किया है बल्कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अच्छी शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।
- **समन्वयवादी परिवार :-** एक ऐसा परिवार , जिसमें पति-पत्नी मिलकर अधिकांश निर्णय लेते है, समन्वयवादी परिवार कहलाता है।
- **जनसंख्या की वृद्धि दर**-जनसंख्या की वृद्धि दर का अर्थ वह दर है जिस पर प्रति वर्ष प्रति हजार व्यक्तियों की वृद्धि होती है।
- **पारिवारिक पूँजीवाद :-** ऐसा पूँजीवादी उद्योग,जिसका प्रशासन व मालिक परिवार के सदस्यों के पास होता है।
- **जन्म दर** :- एक वर्ष में एक हजार व्यक्तियों के पीछे जितने बच्चे जन्म लेते है।
- **मृत्यु दर :-** एक वर्ष में एक हजार व्यक्तियों के पीछे जितने लोग मरते है।

3.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Questions)

सही विकल्प चुनें

1. (अ) 1951 2. (स) परिवार कल्याण कार्यकम
3. (द) ये सभी 4. (द) सभी को। 5. (अ) 64

3.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची(References/Bibliography)

- डॉ. मिश्रा, जे.पी., *जनांकिकी*, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा
- डॉ. बघेल, डी.एस., *जनांकिकी*, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
- डॉ. पन्त, जीवन चन्द्र, *जनांकिकी*, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ
- अशोक कुमार, *जनसंख्या, एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन*, हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रयाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

3.16 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- Dr. Premi, M.K., Ramanamma, A., Bambawale, Usha,. *An Introduction to social demography*, Vikas Publishing House, New Delhi.

- Appleman, Philip (ed.) Thomos Robert Malthus : *An Essay on the Principle of Population*, New York : W.W. Norton and Co., Inc., 1976.
- Carr- Saunders, A.M., *World Population : Past Growth and Present Trends*, Oxford : Clarendon Press, 1936.
- Coale, Ansley J. and Edgar M. Hoover, *Population Growth and Economic development in low income countries*, Princeton University Press, 1958.

3.17 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. भारत में परिवार नियोजन के पक्ष में तर्क दीजिए। इस देश में परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली बाधाएँ बताइए।
2. भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपने ऐच्छिक उद्देश्यों की पूर्ति से क्यों सफल नहीं हुए?
3. परिवार नियोजन कार्यक्रम और महिला शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए है,व्याख्या कीजिए?

इकाई 4- स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण से सम्बन्धित नीतियाँ
(Policies Related to Health, nutrition, Education and Training)

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 स्वास्थ्य

4.3.1 स्वास्थ्य संबन्धी नीतियां

4.4 पोषण संबन्धी नीतियां

4.5 शिक्षा संबन्धी नीतियां

4.6 प्रशिक्षण संबन्धी नीतियां

4.7 अभ्यास प्रश्न

4.8 सांराश

4.9 शब्दावली

4.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

4.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

4.12 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री

4.13 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

इस इकाई से पूर्व आपने जनसंख्या एवं उससे जुडी प्रवृत्तियों तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम का अध्ययन किया। आप जान गये होगे कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश हैं। इस विशाल जनसंख्या को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि उपलब्ध करवाना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार ने 1983 में सभी के लिए स्वास्थ्य की घोषणा की। 2005 में प्रारम्भ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं आदि कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढता प्रदान की हैं। शरीर के कार्य हेतु ऊर्जा, गर्भवती महिला एवं उसके बच्चे का पोषण, बच्चों का विकास, मानसिक विकास आदि संतुलित भोजन से ही प्राप्त होते है।

अतः संतुलित भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन आदि पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए। पोषण तत्वों की कमी होने के कारण ही कुपोषण जैसी बीमारियां एवं मौते होती है। विश्व में 12 प्रतिशत कुपोषण के कारण मौत होती है तथा 16 प्रतिशत लोग पोषण तत्वों की कमी के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते है। प्रतिवर्ष 6 मिलियन बच्चों की मौत औसत से कम वजन एवं कुपोषण से होती है। अतः सरकार ने इसे गम्भीरता से लेते हुए कुपोषण को मिटाने हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए है। इन कार्यक्रमों का विश्लेषण इसी अध्याय में किया गया है।

शिक्षा के संदर्भ में 1986 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गयी। 2002 में इस नीति में संशोधन कर शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया। इसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस संशोधित कार्यक्रम में शिक्षा में एकरूपता, प्रौढ़ शिक्षा, सभी को शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, बालिका शिक्षा आदि पर विशेष बल दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नवनियुक्ति कर्मचारियों को विभागों में भेजने से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है तथा जो कर्मचारी काफी वर्षों से कार्यरत है उनकी जानकारी को नवीनतम करने हेतु तथा नवीन तकनीकों से समन्वय स्थापित कराने हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते है। नयी अवधारणाओं एवं नयी व्यवस्था को समझने हेतु भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस इकाई में हम सरकार की स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण सम्बन्धी नीतियों का विश्लेषण करेंगे।

4.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको

- ✓ सरकार की स्वास्थ्य एवं पोषण संक्षिप्त कार्यक्रमों की जानकारी हो जायेंगी।
- ✓ सरकार के शिक्षा और प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का विश्लेषण कर सकेंगे।
- ✓ शिक्षा में मूल अधिकार से आशय क्या है, समझा सकेंगे।

4.3. स्वास्थ्य संबन्धी नीतियां

4.3.1 स्वास्थ्य की व्यवस्था

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है; तथापि, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को मदद करने हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जैसे विशाल देश के लिए जहाँ 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना अपने आप में एक चुनौती है।

इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार ने 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत सभी के लिए स्वास्थ्य की घोषणा की। वर्ष, 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तथा 2005 में स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी वृहत आर्थिक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का मत था कि स्वास्थ्य सुविधाओं की लागता बढ़ती जा रही हैं, सामाजिक सुरक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजबूत बनाने की आवश्यकता हैं तथा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता को कम किए बगैर उन्हें व्यापक सेवा पैकेज प्रदान करने की आवश्यकता हैं इसके लिए जन-स्वास्थ्य का व्यय जीडीपी के 2 से 3 प्रतिशत तक होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं आदि कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढता प्रदान की गयी।

सरकार द्वारा बीमारियों के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य के प्रमुख कारकों सफाई, स्वच्छता, पोषण और सुरक्षित पेयजल पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सेवा में स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करने हेतु मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, और उन्नत सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर मानव संसाधन विकास के असंतुलन को भी दूर करेगा। इस योजना के तहत एम्स की तरह के 6 संस्थानों की स्थापना के अलावा 13 मेडिकल कॉलेजों का उच्चीकरण भी किया जायेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देशभर में अंधापन एडस, कैंसर, मानसिक रोग आदि के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर रहा है। स्वास्थ्य देखभाल, मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान में लगे केन्द्रीय संस्थानों और संगठनों को लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि उभरने वाली बीमारियों से निपटा जा सके।

देश की जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में 1990 से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। पुरूषों की औसत आयु 59.7 वर्ष से बढ़कर 66.1 वर्ष तथा महिलाओं की औसत आयु 60.9 से बढ़कर 64.6 वर्ष हो गयी है। बाल-मृत्यु, अपरिपक्व जन्मदर और मृत्युदर में भी गिरावट आयी है। कुष्ट और टी0बी0 जैसे संचारी रोगों के लिए बनाई गई रणनीति पूरी तरह सफल रही है।

भारत में स्वास्थ्य संबंधी अलग-अलग तरह की चुनौतियां हैं। क्षयरोग, मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन, तथा कैंसर आदि आज भी अपनी गहरी जड़ें जमाएं हुए हैं। मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर की उँची दरें आज भी देश के लिए एक चुनौती बनी हुई है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम बनाये गये हैं जिनमें से प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं

1. राष्ट्रीय संकामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय संकामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानी एंसेफलाइटिस और कालाजार की रोकथाम और नियंत्रण कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती है। जनजातीय इलाकों में मलेरिया आज भी एक बडी बीमारी है। मलेरिया नियंत्रण एवं कालाजार उन्मूलन हेतु विश्व बैंक ने एक 5 वर्ष की एक योजना तैयार की हैं जो 2008-09 से प्रारम्भ हुई। बहु औषध (मल्टी ड्रग) थेरेपी का व्यापक प्रयोग वर्ष 1982 से किया जाने लगा और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का आरंभ 1983 में किया गया। उसके बाद से कुष्ठ रोगियों की संख्या कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है। दृष्टिहीनता के राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप दृष्टिहीनता मात्र 1 प्रतिशत रह गयी हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, 1976 से निरंतर जारी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 2020 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को कम करके 0.3 प्रतिशत तक लाना है। **"विजन 2020: Right to Sight"** के अन्तर्गत मोतियाबिंद, दृष्टि दोष, ग्लूकोमा, मधुमेह रेटिनोपैथी और दृष्टिहीनता आदि पर फोकस किया गया है। मनुष्यों में रेबीज की बीमारी की रोकथाम हेतु विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों को नोडल एजेन्सी के रूप में विकसित किया गया हैं।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2003 में तम्बाकू उत्पाद अधिनियम तथा 2008 में इसमें संशोधन किया गया। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध कर दिया गया हैं। एड्स के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया हैं जो एचआईवी/एड्स की गतिविधियों की रोकथाम हेतु निजी क्षेत्र, सरकारी विभाग, गैर सरकारी संस्थाएं आदि मिलकर देखभाल, सहायता, इलाज और सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगें। नाको, जागरूकता अभियान के साथ-साथ लांछन और भेदभाव, सेवाएं उपलब्ध करवाना, परामर्श और जांच, कन्डोम का इस्तेमाल, रक्त सुरक्षा आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं। गलकंड/घंघा रोग के निवारण हेतु 2006 से बिना आयोडीन के नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हैं। 2001 में भारत को गिनी वर्म रोग से मुक्त देश घोषित कर दिया गया हैं।

कैंसर भारत की एक गंभीर समस्या हैं। इसकी रोकथाम हेतु 1975-76 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत तथा 2004 में इस कार्यक्रम में तीसरा संशोधन किया गया। जिसके अन्तर्गत नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की मान्यता के साथ-साथ इसके शोध एवं जागरूकता कार्यक्रम पर भी ध्यान दिया गया हैं। राष्ट्रीय आरोग्य नीधि का गठन 1997 में किया गया इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। जो जानलेवा बीमारियों से पीड़ित है, ताकि वे सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। समन्वित रोग निगरानी परियोजना की शुरूआत 2004 में की गयी। जिसका उद्देश्य बीमारियों की सम्भावित प्रकोप के लक्षणों का समय रहते ही पता लगाना, जिससे शीघ्रताशीघ्र उपचार हो सके। इस सम्बंध में देश में किसी भी स्थान से बीमारियों के विषय में चेतावनी देने के लिए कॉल सेन्टर बनाया गया है जिसमें टेलीफोन नं0

1075 पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। लड़कियों की उपेक्षा तथा लड़कों को अधिक महत्तव देना, महिलाओं की निम्न स्थिति, लड़कों से जुड़ी सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा, दहेज एवं महिलाओं के खिलाफ हिंसा आदि अनेक ऐसी सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जिसके कारण प्रसव पूर्व ही लडकियों को मार दिया जाता है इसलिए सरकार द्वारा गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रसव पूर्व लिंग की जाँच को अंसवैधानिक करार दिया हैं। बालिका भ्रूण हत्या को कम करने के लिए लिंग अनुपात में कमी लाने हेतु 2008 में राष्ट्रीय स्तर पर बालिका बचाओं अभियान की शुरूआत की गयी। प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, अप्रजनन, गर्भनिरोधक और परिवार कल्याण संबंधी समस्यायों की जानकारी हेतु राष्ट्रीय हेल्प लाइन सेवा प्रारम्भ की गयी है, जिसका उद्देश्य किशोरों, विवाह करने जा रहे किशोरों, नए दंपत्तियों तथा उपर्युक्त मुद्दों पर विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराना हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय हेल्पलाइन टॉल फ्री नम्बर 1800-11-6555 हैं।

2. गैर-संचारी रोग (एनसीडी)

गैर-संचारी रोगों में तंबाकू-सेवन, अल्कोहल का अनुचित उपयोग, अनुपयुक्त आहार तथा व्यायाम का अभाव शामिल हैं। पूरे विश्व और भारत में तंबाकू नियंत्रण सबसे बड़ी सार्वजनिक चुनौती बना हुआ है। प्रति वर्ष भारत में लगभग 8-9 लाख मौतें प्रत्यक्षतः तंबाकू सेवन के कारण होती हैं। पुरूषों में लगभग 50 प्रतिशत तथा महिलाओं में 20 प्रतिशत कैंसर का कारण तंबाकू सेवन है। मौजूदा और भावी पीढ़ियों को तंबाकू से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, संदाय एवं संवितरण का विनियमन) अधिनियम, को वर्ष 2003 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार निकोटिन और तंबाकू युक्त पदार्थों गुटका, पैकेटबंद, चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध हैं। भारत सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर ध्यान देने के लिए ***"राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम"*** शुरू किया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे देश में उत्कृष्ट केन्द्रों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे मनोचिकित्सा और क्लीनिकल मनोविज्ञान में अध्यापन एवं शोध कार्यक्रम शुरू कर पाएं। पोषाहार आयोडीन की कमी से गर्भपात, मृत बच्चे का जन्म, मानसिक मंदता, बौनापन, बधिरता, मूक होना, भैंगापन, घंघा, सामान्य बुद्धिमता में कमी आदि हो सकती है। 100 प्रतिशत केन्द्र से सहायता प्राप्त कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम जिसे पहले राष्ट्रीय घंघा नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, को पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। बिना आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध है।

3 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)

ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर कमजोर वर्गों को अच्छी एवं आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की गयी। इस मिशन में

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ इस कार्यक्रम में जल, सफाई, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य के अनेक निर्धारकों पर विशेष बल दिया गया हैं। एनआरएचएम का उद्देश्य "लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और प्रतिक्रियाशील एकसमान, वहनीय और उत्तम स्वास्थ्य परिचर्या की व्यापक सुविधा प्राप्त करना" है। इस मिशन की प्रमुख विशेषता यह है कि यह कार्यक्रम एक विकेन्द्रित कार्यक्रम हैं। मिशन के प्रमुख लक्ष्य निम्न हैं

- शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति 1000 जीवित जन्म से नीचे लाना
- मातृ मृत्यु दर को 100 प्रति 100000 जीवित जन्म से नीचे लाना
- कुल प्रजनन दर को 2 प्रति महिला पर लाना
- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों को हासिल करना
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को हासिल करना

  राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख घटक निम्न है।

- **आशा:**

  आशा कार्यक्रम एनआरएचएम का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ग्रामीण समुदाय, निर्धन और उपेक्षित वर्गों विशेष तौर पर महिलाओं एवं बच्चों के लिए आशा एक प्रकाश की किरण है। आशा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कहा जाता है। आशा की नियुक्ति कॉलोनी के आधार पर होती है इसलिए आशा की पहुँच प्रत्येक महिला तक होती है जिसके कारण यह कार्यक्रम लोगों को जन स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने में सफल रहा है। इसलिए यह एक सफल कार्यक्रम हैं। किशोरियों में रक्त अल्पता को कम करने हेतु आशा घर-घर जाकर आयरन की गोलियाँ स्वयं अपने हाथ से खिला रही हैं। बच्चों के टीकाकरण एवं पोलियो की देखरेख के कार्य में भी आशा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 8.84 लाख से अधिक आशा को प्रशिक्षण के बाद तैनात किया गया है और ड्रग किट भी उपलब्ध कराई गई। आशा कार्यक्रम का राज्यों में विस्तार हो रहा है और यह नए सुविधा केन्द्रों तथा अवसंरचना के सृजन में काफी सुधार हुआ है हालांकि इन सुविधा केन्द्रों में योग्य स्वास्थ्य कार्मिक की पर्याप्त तैनाती एक समस्या बनी हुई है। औषधियों की उपलब्धता में प्रत्येक स्तर पर वृद्धि हुई है।

- **जननी सुरक्षा योजना:**

  इस योजना के अंतर्गत आशा निर्धन परिवारों की गर्भवती महिलाओं को न्यूनतम आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती है तथा बच्चा जनने हेतु उस महिला को निकटवर्ती अस्पताल में भी ले जाती हैं। इस योजना ने 1961 से ही चल रही राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में 2007 में संशोधन कर लक्षित महिलाओं को देय मातृत्व बोनस की राशि को 250 रूपये से बढाकर 1000 रूपये कर दिया गया है। अब तक जेएसवाई के अंतर्गत 570.19 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना**

  भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 से लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा के जरिए बीमारियों के उपचार की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रत्येक परिवार हेतु स्मार्ट कार्ड जारी किये गये है। जिसके अन्तर्गत प्रति बीपीएल परिवार (पांच सदस्य) को अधिकतम 30000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष देता है। दिसम्बर 2011 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2.55 करोड बीपीएल परिवारों को बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किये जा चुके है।

4 परिवार नियोजन कार्यक्रम

भारत ने वर्ष 1952 में विश्व का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें जनसंख्या को ***"राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षा के अनुरूप स्तर पर स्थिर करने हेतु"*** जन्म दरों में आवश्यकता कमी लाने हेतु परिवार नियोजन पर बल दिया गया था। तभी से परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रमिक विकास हुआ है

परिवार नियोजन कार्यक्रम अवांछित और असमय होने वाले गर्भधारणों से बचने में सहायता प्रदान करता हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है। भारत सरकार ने जन्म अंतराल पद्धतियां, विशेषकर आईयूसीडी (प्रसवोत्तर और अंतराल दोनों) पर ज्यादा फोकस करने के लिए अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम को नया रूप दिया है। इसके अन्तर्गत पहले बच्चे के जन्म में विलंब तथा पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म में स्वस्थ अंतराल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया हैं।

5 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के एक उप-मिशन के रूप में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शहरी गरीबों पर फोकस करके शहरी जनसंख्या के लिए अनिवार्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना हैं। मंहगी होती स्वास्थ्य सेवाओं को कम व्यय पर उपलब्ध करवाना इस कार्यक्रम का लक्ष्य हैं। यह प्रणाली स्वास्थ्य कार्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ उसके कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य भी समुदाय की भागीदारी के साथ करता है। शहर की बढ़ती आबादी के साथ स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का सामना करने का कार्य भी यह मिशन करेगा। गैर-सरकारी संगठनों, धमार्थ अस्पतालों और अन्य भागीदारों के साथ भागीदारी के लिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य भी यह मिशन करेगा।

एनयूएचएम में 50000 से अधिक की आबादी वाले सभी शहर/ कस्बे शामिल होंगे। 50000 से कम आबादी वाले कस्बों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें झुग्गी निवासियों सहित अन्य सीमांत शहरी निवासियों जैसे रिक्शा चालकों, रेहड़ी वालों, रेलवे और बस

अड्डे के कुलियों, बेघर लोगों, बेघर बच्चों, भवन निर्माण स्थल के मजदूरों जो झुग्गी या निर्माण स्थल पर हो सकते हैं, इन सभी को शामिल किया गया

6 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) के दीर्घावधिक लक्ष्यों के अन्तर्गत 2010 तक सकल प्रजनन की दर 2:1, नवजात मृत्यु दर में 30/1000 जीवित जन्मों में कमी करना और मातृ मृत्यु दर में 100/100,000 जीवित जन्मों तक कमी करने की बात कही गयी हैं। अतः इस नीति में मूल प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिकाधिक फोकस किया गया है।

7 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग एवं जनसंख्या स्थिरता कोष

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 2002 में की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का गठन राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के तहत जुलाई, 2000 में किया गया था। इसके बाद इसे अप्रैल, 2002 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे जून, 2003 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860) के तहत जनसंख्या स्थिरता कोष के रूप में पुनः नामित एवं पुनर्गठित किया गया।

लड़की के विवाह 19 वर्ष की आयु के बाद, कन्या शिशु के जन्म पर, माता-पिता में से कोई भी दूसरे बच्चे के जन्म के एक वर्ष के भीतर परिवार नियोजन की स्थायी विधि स्वेच्छापूर्वक अपनाने पर अथवा बंध्यीकरण ऑपरेशन पर दिया जाने वाला पुरस्कार राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष से ही दिया जाता हैं।

8 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):

पीएमएसएसवाई का लक्ष्य किफायती/भरोसेमंद तृतीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधओं में सुधार करना है।

- पहले चरण में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश और द्वितीय चरण में, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 6 एम्स जैसे संस्थानों का निर्माण,
- पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 6 मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना है। छह एम्स जैसे संस्थानों में 50 एमबीबीएस सीटों के लिए अकादमिक पाठ्यक्रम सितम्बर 2012 में शुरू हो चुका है और अस्पतालों के सितम्बर 2013 तक प्रचालनीय होने की संभावना है।

9 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्वि एवं समचिकित्सा (आयुष)

भारतीय औषध प्रणाली को अधिक विकसित करने हेतु 2012-13 में 990 करोड़ रुपएकी योजनागत परिव्यय का आवंटन किया गया। आयुष स्वास्थ्य सेवा को मुख्य ऐलोपैथिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करने के लिए राज्यों के सभी अस्पतालों में आयुष सुविधाओं का विस्तार करना है।

4.4 पोषण संबन्धी नीतियां

स्वास्थ्य और निरोग रहने के लिए हमें अपने रोजाना के भोजन में सही प्रकार के और सही मात्रा में खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। शरीर के कार्य हेतु ऊर्जा, गर्भवती महिला एवं उसके बच्चे का पोषण, बच्चों का विकास, मानसिक विकास आदि संतुलित भोजन से ही प्राप्त होते है। संतुलित भोजन में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन आदि पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए। आप तीन किलोग्राम के नवजात शिशु और बड़े होने पर 60 किग्रा वजन होने तक उसकी मांशपेशियों और हड्डियों के विकास पर विचार कीजिए। आप समझ पायेगे कि शरीर के विकास के लिए पौष्टिक तत्व कितने आवश्यक है। मांसपेशियों, वजन और शरीर के अंगो की वृद्धि हेतु प्रोटीन आवश्यक है तो हड्डियों और दांतो के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज जरूरी होते है।

अतः आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रोगो से बचाव एवं शरीर के अंगो में वृद्धि हेतु पौष्टिक तत्वों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन ही नही रेशेदार भोजन भी आवश्यक है। पोषण तत्वों की कमी होने के कारण ही बीमारियां एवं मौते होती है। विश्व में 12 प्रतिशत लागों की कुपोषण के कारण मौत होती है तथा 16 प्रतिशत लोग पोषण तत्वों की कमी के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते है। प्रतिवर्ष 6 मिलियन बच्चों की मौत औसत से कम वजन एवं कुपोषण के कारण होती है। कुपोषण को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न कार्यक्रम चलाए गये है

1 समोकित बाल विकास सेवा स्कीम

भारत सरकार का यह प्रमुख कार्यक्रम 1975 में प्रारम्भ हुआ था। भारत सरकार ने 2008 में इस स्कीम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए विकास मानक लागू किये है। इस स्कीम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास, किशोरी बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के किए उचित पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

2 राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम

इस स्कीम को सबला के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम को 2010 से प्रारम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य 11-18 वर्ष के आयुवर्ग वाली किशोर लड़कियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास सहित समग्र विकास के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इसमें स्कूल न जाने वाली किशोरियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं

A. पोषण घटक के अंतर्गत 11-14 के आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली लड़कियों और 14-18 आयु वर्ग की सभी किशोरियों के लिए **'घर ले जाओ राशन'** या **'गर्म पका खाना'** के रूप में पोषण दिया जा रहा है।

B. गैर-पोषण घटक के अंतर्गत 11-18 वर्ष की किशोर लड़कियों की विकासात्मक आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। इसमें इस आयु वर्ग की लड़कियों को आयरन–पोलिक एसिड पूरक खुराकें, स्वास्थ्य जांच और निर्दिष्ट सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा,

परिवार कल्याण पर परामर्श / मार्ग दर्शन, कौशल शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं की अभिगम्यता पर मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किशोरियों के समग्र विकास के अन्तर्गत निम्न सेवाएं प्रदान की जाती है

- आयरन फौलिक एसिड (प्रतिवर्ष 52 गोलियां)
- स्वास्थ्य जांच
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
- परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल देखरेख पद्धत्तियों और गृह प्रबंधन पर परामर्श मार्गदर्शन।

इस स्कीम का लक्ष्य एक वर्ष में 1 करोड़ किशोरियों को पोषण प्रदान करना है। वर्ष 2012-13 के लिए 750 करोड़ रुपए के आबंटन किए गए हैं जिससे 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 87.23 लाख किशोरियां लाभान्वित हुई हैं।

3 इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

गर्भवती एवं धाती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। केन्द्र सरकार की इस योजना की शुरूआत 2010 में की गयी है। यह योजना अक्तूबर, 2010 से देश के 53 चुनिंदा जिलों में प्रारंभ में प्रायोजिक आधार पर कियान्वित की गई थी। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 3 लाख से अधिक लाभान्वितों को शामिल किया गया है और राज्यों को 27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

4.4.4 कुपोषण के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान

पोषण नीति और भारत की पोषण चुनौतियों सम्बन्धी प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद द्वारा कुपोषण एक राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा और संप्रेषण अभियान की शुरूआत 2012 में की गयी है। इस अभियान के उद्देश्य इस प्रकार है

- पोषण सम्बन्धी चुनौतियों एवं पोषण के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।
- शिशुओं एवं छोटे बच्चों की उपयुक्त आहार पद्धत्तियों, बाल देखरेख एवं विकास आदि सेवाओं के बेहतर उपयोग को बढावा देना।
- पोषण शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है।

5 भारत की पोषण चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न कार्यों पर विशेष बल दिया गया है

- समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का सुदृढीकरण तथा पुर्नरचना

- अत्यधिक कुपोषण वाले चुनिंदा 200 जिलों में मात्र तथा बाल कुपोषण को मिटाने के लिए बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम 2012-13 में प्रारम्भ किया गया कुपोषण के विरूद्ध एक राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा एवं संप्रेक्षण अभियान की शुरूआत नवम्बर 2012 में की गयी।
- क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता, स्कूली शिक्षा, कृषि एवं खाद्य तथा सार्वजननिक वितरण आदि का मानिटरिंग योजना आयोग द्वारा की जायेगी।

6 केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

1996 में प्रारम्भ किये गये इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है। 1993 में स्वच्छता की अवधारणा में विस्तार किया गया। 1999 में इसे सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम दिया गया। 2012 में इसे निर्मल भारत अभियान कहा जाने लगा है।

7 विश्व स्तरीय सम्मेलन

2012 में लंदन में आयोजित विश्व पोषण समारोह का उद्देश्य अगले चार वर्षों (2016) तक 170 मिलियन बच्चो हेतु भुखमरी एवं कुपोषण को मिटाने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किये गये है। 2012 में ही दिल्ली में शिशुओं एवं छोटे बच्चों के आहारों को बढावा देने के लिए विश्व स्तनपान सम्मेलन का आयोजन किया गया। पोषण के विश्व में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है।

4.5 शिक्षा संबन्धी नीतियां

1976 के संविधान संशोधन से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गयी। 1972 एवं 2002 में इसमें संशोधन किया गया। 2002 में शिक्षा को एक मूल अधिकार मानते हुए अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस संशोधित कार्यक्रम में शिक्षा में एकरूपता, प्रौढ़ शिक्षा, सभी को शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, बालिका शिक्षा आदि पर विशेष बल दिया गया। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय, खेल-कूद, शारीरिक शिक्ष, योग को बढावा, मूल्यांकन प्रक्रिया, विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन ढ़ांचा आदि विषयों को भी नयी शिक्षा नीति में शामिल किया गया। जिसके अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र में लागू की गयी सरकार की प्रमुख नीतियां निम्नलिखित है

1 सर्वशिक्षा अभियान/शिक्षा का अधिकार

इस अभियान के अन्तर्गत भारत के संविधन के अनुच्छेद 21 (क) को कानून बनाते हुए बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा लागू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन आबादी वाले क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नही है, वहां नए स्कूल खोलना तथा अतिरिक्त कक्षाओं हेतु नए

कमरें, शौचालय, पेयजल, रख-रखाव एवं स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से नये स्कूल खोलना और उनमें सुधार लाना है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर शिक्षा दिलाने का भी प्रावधान है।

2 मध्यान्तर भोजन योजना

स्कूलों में नामांकन को बढ़ाने और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों के बीच पोषण के स्तर को सुधारने के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 1995 से शुरू किया गया। 2004 तथा 2006 में इस कार्यक्रम में संशोधन किया गया। विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्यान्तर भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त और राष्ट्रीय श्रम परियोजना विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को पका हुआ दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। दोपहर के भोजन में प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी उर्जा घटक और 12 ग्राम प्रोटीन अंश तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी उर्जा घटक और 20 ग्राम प्रोटीन अंश प्रदान करता है। एनआरएचएम के अनुरूप लौह, फॉलिक एसिड और विटामिन ए जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा की भी सिफारिश की गयी है।

3 शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा

ऐसे दुर्गम आबादी वाले क्षेत्रों जहां बच्चे स्कूल नही जा पा रहे हैं, को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान का ही एक हिस्सा है। वैकल्पिक शिक्षा में समाज के वंचित वर्ग के बच्चों, सड़को पर जीवन-यापन करने वाले बच्चों आदि के लिए जो 9 वर्ष से अधिक आयु के है के लिए प्रारम्भ की गयी है। 4.5.4 महिला स्वास्थ्य योजना ग्रामीण क्षेत्र में पिछडे समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए प्रारम्भ की गयी है।

5 अध्यापक शिक्षा योजना

अध्यापक शिक्षा योजना एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ऐसी योजनाएं है जो शिक्षा की गुणवत्ता हेतु अध्यापकों को नवीन तकनीकी एक अध्यापन प्रविधियों पर बल देती है।

6 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

इस मिशन का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर करना है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी इसी मिशन का एक भाग है। स्कूलों में गुणवत्ता सुधार हेतु निम्न घटकों को शामिल किया गया है

- राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना
- स्कूली शिक्षा को पर्यावरणोन्मुखी बनाना।
- स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार करना।
- स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देना।
- अन्तराष्ट्रीय विज्ञान ओलोपियाड़

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसे अब साक्षर भारत का नाम दिया गया है, महिला साक्षरता को सर्वाधिक महत्व देता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत साक्षरता लाना था। 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 प्रतिशत साक्षरता हो पाई है। तथापि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत अधिक सुधर आया है तथा यह पुरुषों के संबंध में 75.26 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत बढ़कर 82.14 प्रतिशत हो गया तथा महिलाओं के संबंध में 53.67 प्रतिशत से 11.8 प्रतिशत बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गया हैं। साक्षरता का स्तर राज्यों जिलों सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में एक समान नहीं रहा। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों और लक्षित समूहों में विषमताओं कम करने के लिए केन्द्रीकृत उपाय किए हैं।

7 मॉडल स्कूल स्कीम:

ब्लाक स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के तौर पर प्रति ब्लाक एक स्कूल के साथ 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करने की स्कीम नवंबर 2008 में शुरू की गई थी ताकि प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मुहैया कराई जा सके। इस स्कीम के कार्यान्वयन के दो रूप हैं।

- शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अधिकाधिक ब्लाकों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के जरिए 3500 स्कूल स्थापित किए जाने हैं
- शेष 2500 स्कूल पीपीपी मोड के जरिए ऐसे ब्लाकों में स्थापित किए जाने हैं जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं।

8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ विद्यालय खोले जा रहे है। प्रत्येक जिले में एक आवासीय नवोदय एवं केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा की तरफ बढ़ते कदम है। राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालय संस्थान एवं सी0बी0एस0ई. (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) शिक्षा की गुणवत्ता हेतु प्रयत्नशील है।

9 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

माध्यमिक शिक्षा में पहुंच बढ़ाने और गुणता में सुधार के उदेश्य से मार्च, 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरूआत की गई थी। वर्ष 2011-12 के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए 3124 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है नए विद्यालय भवनों के निर्माण और विद्यमान माध्यमिक विद्यालयों की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत अध्यापकों व कर्मचारियों का वेतन, उन्नत शिक्षण कार्यक्रम, इक्विटी हस्तक्षेप आदि के लिए जारी किए जा चुके हैं।

10 उच्च शिक्षा

उच्चतर शिक्षा की प्रासंगिकता को बढ़ाने, व्यावसायीकरण, नेटवर्किंग तथा उच्चतर शिक्षा में शासन के सुधारों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और दुरस्त शिक्षा के प्रयोग पर फोकस करते हुए ग्याहरवीं योजना अवधि के दौरान कई पहलें की गई है। उच्च शिक्षा हेतु प्रारम्भ किये गए कार्यक्रम निम्नलिखित है

- 11वीं योजना के दौरान 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय गठित किए गए थे जिनमें तीन राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलना भी शामिल था। सात नए भारतीय प्रबन्ध संस्थान, आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा 2 योजना और वास्तुकला स्कूल गठित किए गए थे।
- आई.सी.टी के माध्यम से शिक्षा राष्ट्रीय मिशन, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को हाई-स्पीड ब्रॉड बैन्ड की कनेक्टीविटी प्रदान करना तथा विभिन्न विषयों में ई-सामग्री (e-content) का विकास करना है, का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बढ़ती हुई दक्षता चुनौतियों के समाधन के लिए सरकार ने पीपीपी आधर पर बीस नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। परियोजना को 2011-12 से 2019-20 तक नौ वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार, राज्यों के चिन्हित जिलों में नए सरकारी पॉलीटेक्निकों की स्थापना की लागत को पूरा करने के लिए प्रति पॉलीटेक्निक 12.30 करोड़ रूपए की सीमा तक वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

जहां तक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या का सवाल है भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली संसार की बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। स्वतन्त्राता के समय केवल 20 विश्वविद्यालय और 200 महाविद्यालय और 0.1 मिलियन विद्यार्थी थे तथा अब 2011-12 की स्थिति के अनुसार 690 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं है और 35539 महाविद्यालय हैं। 690 विश्वविद्यालयों में से 44 केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, 309 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 145 राज्यों के गैर सरकारी विश्वविद्यालय है, 130 मानद् विश्वविद्यालय, 60 राष्टीय महत्व के संस्थान है तथा पांच संस्थाएं राज्य विधान अधिनियम के अंतर्गत गठित हैं।

4.6 प्रशिक्षण संबन्धी योजनाएं

नवनियुक्ति कर्मचारियों को विभागों में भेजने से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसे प्रथम स्तर ट्रेनिंग कहते है। जो कर्मचारी काफी वर्षों से कार्यरत है उनकी जानकारी को अद्यतन (Update) करने हेतु तथा नवीन तकनीकों से समन्वय स्थापित करने हेतु जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते है उसे मिड कैरियर प्रशिक्षण कहते है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु तथा तनाव रहित माहौल आदि उपलब्ध करवाने हेतु एक अथवा दो सप्ताह के भी प्रशिक्षण दिये जाते है। यह प्रशिक्षण देश में अथवा देश से बाहर भी हो सकते है। नयी अवधारणाओं

एवं नयी व्यवस्था के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विभागवार चलाये जाते हैं। इन विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने हेतु सरकार निम्न विभाग स्थापित किये गये हैं

1 राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति

मानव संसाधन के कौशल विकास हेतु अप्रैल 1996 में राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति का प्रारम्भ किया गया था। भारत की जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में विकसित करने हेतु मानव संसाधन मंत्रालय ने 2012 में इसे पुनः संशोधित कर नयी राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति लागू की गयी। कार्य प्रणाली आदि को समझाने हेतु प्रशिक्षण आदि आवश्यक है। पुराने कर्मचारियों को नवीन समयानुरूप तकनीकी से परिचय कराने हेतु भी प्रशिक्षण अति आवश्यक है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों को उसके कैडर/पद के अनुसार वार्षिक /समयानुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। विभाग के उद्देश्यों, लक्ष्यो के संदर्भ में भी कर्मचारियों को 3-4 सप्ताह का भी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे ओरियोन्टेशन कार्यक्रम कहते है।

2 राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद

राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का लक्ष्य 2022 तक 500 मिलियन लोगों को कौशल उपलब्ध कराना है। इससे पूर्व केवल मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं श्रामिक एवं रोजगार मंत्रालय ही प्रशिक्षण का कार्य करते थे। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद सार्वजनिक एवं नीजि सहभागिता की अवधारणा पर आधारित है। इस परिषद द्वारा पूरे देश में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां प्रशिक्षण की अति आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्रों में कौशल परिषद के गठन की बात कही है जिसमें से 6 क्षेत्र कौशल परिषद का गठन किया जा चुका है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा प्रशिक्षण के कार्यो मे प्रत्यक्ष रूप से वित्त, सुविधाएं एवं सलाह उपलब्ध कराता है।

3 स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ढांचागत सुधार हेतु मुख्य घटकों को प्रशिक्षित करना है। आशाओं को उनकी भूमिका में सक्षम बनाने हेतु अधिकतर राज्यों ने प्रशिक्षण एवं सहयोग के लिए आवश्यक संस्थानात्मक संरचना स्थापित की है। आशओं की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन भी किया जाता है। विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न योजनाओ/ क्रियाकलापों की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता एवं कार्यक्षमता कर्मचारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। बहु परियोजना स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) की *'बुनियादी प्रशिक्षण योजना'* भारत सरकार द्वारा 1984 में लागू की गयी है। प्रशिक्षण अवधि 1 साल है तथा देश में 49 प्रशिक्षण स्कूल है। देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों को परिवार नियोजन कार्यक्रमों के जरिए उनके रूख में बदलाव लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान देश के विभिन्न भागों में 18 सहयोगी प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से विविध प्रशिक्षणों का समन्वय तथा निगरानी कर रहा है।

4 शिक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण

शिक्षा स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु अध्यापक शिक्षा योजना प्रारम्भ की गयी थी जिसके अन्तर्गत जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। राज्य शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया गया है। इस योजना में 2003 एवं 2004 में संशोधन किया गया है। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान सेवाकालीन और सेवा पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमोंका आयोजन करता है। जिससे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सकें।

सेवारत प्राथमिक और द्वितीयक अध्यापकों का व्यवसायिक विकास करना जिससे अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण प्राप्त होगा तथा अध्यापनरत अध्यापकों को प्रशिक्षण द्वारा विषय की जानकारी भी अद्यतन हो जायेगी।

- अध्यापक शिक्षकों व्यावसायिक विकास हेतु रिफ्रेशर पाठ्यक्रम चलाये गये है।
- अध्यापक शिक्षा में प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन 1995 में इस लक्ष्य के साथ किया गया था कि अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकों एवं स्तरों का उचित ध्यान दिया जा सके।

4.7 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सर्वशिक्षा अभियान को संक्षेप में समझाइये।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विशेषताओं को बताइये।
3. सबला योजना क्या है?

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत कब हुई ?

   (a) 2003 (b) 2004 (c) 2005 (d) 2006

2. 2002 में निम्न में से किसको मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है।

   (a) शिक्षा (b) स्वास्थ्य (c) प्रशिक्षण (d) पोषण

3. सबला योजना निम्न में से किससे सम्बन्धित हैं?

   (a) बच्चों से (b) बुजुर्ग महिलाओं से

   (c) युवकों से (d) किशोरियों से

4. मध्यान्तर भोजन की व्यवस्था किस विभाग में प्रारम्भ की गयी हैं?

   (a) प्रशिक्षण (b) स्वास्थ्य

   (c) शिक्षा (d) पोषण

5. निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र से सम्बन्धित हैं?

   (a) स्वच्छता (b) शिक्षा

   (c) प्रशिक्षण (d) पोषण

4.8 सारांश (Summary)

स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण से सम्बन्धित नीतियों के अध्ययन के बाद आप समझ गये होगे कि सरकार लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के प्रति कितनी संवेदनशील है परन्तु बढती जनसंख्या के कारण अभी बहुत लक्ष्यों को प्राप्त करना अभी बाकी हैं। इन प्रयासो का ही परिणाम है कि प्रजनन दर में गिरावट हुई है, यद्यपि यह गिरावट बहुत कम है। बीमारियों से मरने वालो की संख्या में गिरावट आयी है। शिशु मृत्यु दर घट कर 63 प्रति हजार रह गयी है। 2011 में जन्म दर 21.8 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार हो गयी है। जीवन प्रत्याशा बढकर पुरूषों में 66.1 वर्ष तथा महिलाओं में 64.6 वर्ष हो गयी हैं। इसका प्रमुख कारण सरकार द्वारा पोषण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुपोषण को जड़ से मिटाने हेतु सरकार प्रयत्नशील है। आशा के द्वारा घर-घर जाकर किशोरियों को आयरन की गोलियां खिलाना कुपोषण के खिलाफ एक नयी जंग की शुरूआत की गयी है। सभी को शिक्षा एवं शिक्षा को मूल अधिकार बनाये जाने के परिणाम स्वरूप साक्षरता दर में पिछले दस वर्षों में लगभग 10 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि 2001 की तुलना में 2011 में महिला साक्षरता दर में लगभग 12 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई हैं जबकि पुरूषों में यह बढोत्तरी मात्र 7 प्रतिशत हुई हैं। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते है। कर्मचारियों को तनाव रहित माहौल को प्रदान करने की व्यवस्था आदि हेतु भी एक अथवा दो सप्ताह के भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते है। नयी अवधारणाओं एवं नयी व्यवस्था को जानने और समझने हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को नयी स्फूर्ति प्रदान करते है।

4.9 शब्दावली (Glossary)

- **जी.डी.पी**.- सकल घरेलू उत्पाद
- **मृत्यु दर** – प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या
- **जन्म दर-** प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या
- **साक्षर**- सात साल का हर वह बच्चा जो अपना नाम लिख सकता है, साक्षर कहलाता है।
- **गैर संचारी रोग**-जब संचार रोग से पीडित व्यक्ति दूसरे के सम्पर्क में आता है तो वह उस रोग से प्रभावित नही होता है।
- **नाको-** राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल संगठन, जो एड्स के विभिन्न मुद्दों एवं भ्रांतियों के सम्बन्ध में लोगो को जागरूक एवं शिक्षित कर रहा है।

4.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 2005 2. शिक्षा 3. किशोरियों से
4. शिक्षा 5. स्वच्छता

4.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय*, भारत सरकार
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग*, भारत सरकार
- *भारतः 2013*, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

4.12 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- Agarwal, S.N. (1972), *India's population problem*. Tata Mcgraw Hill Co., Bombay.
- Choubey, P.K. (2000), *Population Policy in India*, Kanishk Publication, New Delhi
- Gulati, S.C. (1988), *Fertility in India and Econometric Study of Metropolis*, Sage, NewDelhi.
- Gulati, S.C. (1998), *Basic Demographic Techniques and Applications*, Saga Publication, New Delhi.
- Srinivasan, K. (1998), *Basic Demographic Techniques and Applications*, SagaPublication, New Delhi

4.13 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. सरकार की स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बंधी नीतियों को संक्षेप में समझाइये।
2. शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा हैं, समझाइये।

इकाई 5- विश्व जनसंख्या की विभिन्न वर्षों में प्रवृत्तियाँ
(Trends of World Population in Different Years)

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 विश्व जनसंख्या प्रवृत्ति
5.4 विश्व जनसंख्या: एक नजर में
5.5 विश्व जनसंख्या के प्रतिमान
5.6 विश्व की जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्तियाँ
5.7 विश्व जनसंख्या के अनुमान
5.8 वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट
5.9 पॉपुलेशन रिफ्रेन्स ब्यूरो रिपोर्ट
5.10 अभ्यास प्रश्न
5.11 सारांश
5.12 शब्दावली
5.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
5.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
5.15 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री
5.16 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

आप पिछले अध्यायों में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न घटकों, उनमें परस्पर निर्भरता, जनसंख्या के विभिन्न सिद्धान्तों, जनसंख्या की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले सांख्यिकीय तथ्यों एवं भारत में जनसंख्या सम्बन्धी विभिन्न प्रवृत्तियों का अध्ययन कर चुके हैं। इसमें विश्व जनसंख्या की विभिन्न वर्षों में प्रवृत्तियों, विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट एवं वृद्धि तथा उनमें लिंग संरचना एवं उनका जनसंख्या पिरामिड तथा उनमें जीवन गुणवत्ता सूचकांक एवं गरीबी तथा विकास सूचकांक का अध्ययन करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या प्रभाव द्वारा 14 मार्च, 2007 को **'2006 विश्व जनसंख्या परिदृश्य'** नामक रिपोर्ट जारी की गयी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 9.2 अरब तक पहुँच जायेगी। इस तरह विश्व की वर्तमान जनसंख्या 6.7 अरब की दृष्टि से आगामी 43 वर्षो में लगभग 2.5 अरब लोग और जुड़ जायेंगे। लगभग इसी तरह के आँकड़े अमेरिकी जनसंख्या ब्यूरो की वर्ष 2006 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 तक विश्व की जनसंख्या 7 अरब को पार कर जायेगी। इसमें बढ़ता विकासशील देशों का प्रतिशत अन्ततः उनकी स्थिति को गम्भीरता से प्रभावित करेगा। जिसके अनेक वैश्विक परिणाम भी होगें। इस इकाई के अन्तर्गत विश्व जनसंख्या की विभिन्न वर्षो की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे।

5.2 उद्देश्य (Objectives)

विश्व जनसंख्या की विभिन्न वर्षों की प्रवृत्तियों के अध्ययन के निम्न मुख्य उद्देश्य हैं:

- ✓ विश्व में जनसंख्या के विकास की जानकारी प्राप्त करना।
- ✓ विभिन्न अनुमानों द्वारा जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करना।
- ✓ विकसित एवं विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के अध्ययन को व्यापक स्वरूप देना।
- ✓ वैश्विक जनसंख्या सम्बन्धी समस्यायों के समाधान हेतु व्यापक रणनीति का आधार प्रस्तुत करने हेतु जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़ों का क्षेत्रवार अध्ययन करना।
- ✓ भावी जनसंख्या की जानकारी करना जिससे सम्बन्धित समस्याओं का सम्यक अध्ययन हो सके।

5.3 विश्व जनसंख्या प्रवृत्ति (World Demographic Trends)

मानव विज्ञान शास्त्रियों का विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव का उद्भव टर्शियरीकल्प के प्लायोसीन युग में हुआ। मानव सभ्यता के इतिहास के अधिकांश काल में मानव शिकारी एवं संग्रहणकर्त्ता की भूमिका में ही रहा। इस भूमिका ने मानव की संख्या को सीमित रखा। कृषि युग के प्रारम्भ से मानव संख्या में बढ़ोतरी होने लगी क्योंकि कृषि कार्य द्वारा मानव की खाद्यान आपूर्त्ति सुनिश्चित हुई। जनसंख्या विशेषज्ञों ने विश्व की जनसंख्या के विकास को अनेक कालों में विभाजित किया है। जिसमें मुख्य रूप से निम्न विभाजन सर्वाधिक मान्य है

1. 1650 के पूर्व विश्व की जनसंख्या (प्राचीन काल)
2. 1650 से 1800 के मध्य विश्व की जनसंख्या (मध्य काल)
3. 1800 से वर्तमान समय तक विश्व की जनसंख्या (आधुनिक काल)

आधुनिक काल को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्न कालों में विभाजित किया जा सकता है:

(अ) 1800 से 1900 के मध्य विश्व की जनसंख्या

(ब) 1900 से 1950 के मध्य विश्व की जनसंख्या

(स) 1950 से 2000 के मध्य विश्व की जनसंख्या

(द) 2000 से आगे की विश्व जनसंख्या

जिनका सम्मिलित अध्ययन निम्न रूप से किया जा सकता है:

वर्ष 1A.D. में विश्व की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी जो सामान्य गति से बढ़ती हुई 1650 में 50 करोड़ तथा 1750 में 76 करोड़ हो गई। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् जीवन स्तर ऊँचा हो जाने से जनसंख्या में सामान्य से अधिक वृद्धि होने लगी यद्यपि कुछ भागों में बीमारियों एवं अकालों से जनसंख्या में कमी भी आई। वर्ष 1800 में विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब हो गयी। 1850 में 1.26 अरब जबकि 1900 में 1.65 करोड़ हो गयी। 1850 से 1900 के बीच विश्व जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 0.5 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1965 में 2 प्रतिशत हो गई। किन्तु जनसंख्या की यह वार्षिक वृद्धि दर कम होकर 1985 में 1.7 प्रतिशत तथा 2004 में 1.14 प्रतिशत हो गई थी।

सारणी-5.1

विश्व जनसंख्या में वृद्धि - 1650-2010	
वर्ष	**जनसंख्या (अरब में)**
1650	0.50
1750	0.76
1800	0.97
1850	1.26
1900	1.65
1950	2.55
2000	6.07
2010	6.90
2050 (अनुमान)	9.10

सैकड़ों वर्षो तक जनसंख्या में हुई धीमी वृद्धि पिछली शताब्दी में विस्फोटक हो गई। 1960 से 1975 के बीच अर्थात् 15 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में 1 अरब की वृद्धि हुई। अगले 1 अरब की वृद्धि 1975-87 अर्थात् 12 वर्षो में ही हो गई। 12 अक्टूबर 1999 को विश्व की जनसंख्या 6 अरब को पार कर गई। आशय यह है कि प्रत्येक 1 अरब जनसंख्या की वृद्धि का समय निरन्तर कम होता जा रहा है। बीसवीं शताब्दी में विश्व 1.6 अरब जनसंख्या के साथ प्रवेश किया था। जबकि 6.07 अरब जनसंख्या के साथ विश्व ने इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश किया है। अमेरिकी जनसंख्या ब्यूरो की वर्ष 2006 की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2012 तक विश्व की जनसंख्या 7 अरब को पार कर जायेगी। भारतीय जनगणना - 2011 के अनन्तिम (provisional) आँकड़ों के अनुसार-1 जुलाई, 2010 को विश्व की जनसंख्या 6.9081 अरब हो चुकी थी। देखें सारणी-5.2

सारणी-5.2

विश्व जनसंख्या वितरण (प्रतिशत में)				
महाद्वीप	**1950**	**2000**	**2004**	**क्षेत्रफल (प्रतिशत में)**
एशिया	56.2	60.7	60.6	29.5
अफ्रीका	8.9	13.1	18.8	20.2
उत्तर अमेरिका	8.6	7.9	5.1	16.2
यूरोप	21.4	12.0	11.4	6.5
दक्षिण अमेरिका एवं कैरीबियन देश	6.5	8.6	8.4	11.8
ओसीनिया	0.5	0.5	0.5	5.3

विश्व की कुल जनसंख्या का 75.5 प्रतिशत भाग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया तथा माइक्रोनेशिया के अल्पविकसित/विकसित क्षेत्रों में निवास करता है। ये सभी क्षेत्र जनांकिकी संक्रमण की प्रथम या द्वितीय अवस्था से गुजर रहे हैं। जनसंख्या का शेष भाग 24.5 प्रतिशत यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं न्यूजीलैण्ड जैसे विकसित देशों में निवास करता है। जनसंख्या में यह वैश्विक असमानता उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्धों के बीच भी विद्यमान है।

विश्व की 90 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या उत्तरी गोलार्द्ध में रहती है। इसी प्रकार विश्व में जनसंख्या के सघन संकेन्द्रण के तीन प्राथमिक क्षेत्र - दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तर-पूर्वी अमेरिका हैं, जहाँ जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है। इन तीनों ही क्षेत्रों में विश्व की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। चीन में विश्व की जनसंख्या का 19.4 प्रतिशत एवं भारत में 17.5 प्रतिशत भाग पाया जाता है। इन दोनों देशों के बाद क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका (4.5 प्रतिशत), इण्डोनेशिया (3.4%), ब्राजील (2.8%), पाकिस्तान (2.7%), बांग्लोदश (2.4%), नाइजीरिया (2.3%), रूस (2.0%), जापान (1.9%), तथा अन्य देशों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 41.2% है। भारतीय जनगणना- 2010 के अनुसार-विश्व जनसंख्या वर्ष 2010 में यह परिवर्तन हुआ है कि रूस, जो वैश्विक जनसंख्या सहभागिता में 7वें स्थान पर था, अब 9वें स्थान पर है, जापान जो पहले 8 वें स्थान पर था, अब 10वें स्थान पर है। इसके अलावा बांग्लादेश 8वें स्थान से 7वें स्थान पर तथा नाइजीरिया 10वें स्थान से 8वें स्थान पर आ गया है।

नया वैश्विक जनसंख्या सहभागिता क्रम सारणी-5.3 में देखें-

सारणी-5.3

जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 10 सबसे बड़े देश (2010)						
क्र0सं0	**देश का नाम**	**महाद्वीप**	**सन्दर्भ तिथि**	**जनसंख्या (करोड़ में)**	**दशकीय वृद्धि (प्रतिशत में)**	**लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरूष पर)**
1.	चीन	एशिया	01.11.2010	134.10	5.43	926
2.	भारत	एशिया	01.03.2011	121.02	17.54	940
3.	संयुक्त राज्य	उत्तरी	01.04.2010	30.87	7.25	1025

	अमेरिका	अमेरिका				
4.	इण्डोनेशिया	एशिया	31.05.2010	23.76	15.07	988
5.	ब्राजील	दक्षिण अमेरिका	01.08.2010	19.07	9.39	1042
6.	पाकिस्तान	एशिया	01.07.2010	18.48	24.78	943
7.	बांग्लादेश	एशिया	01.07.2010	16.44	16.76	1167
8.	नाइजीरिया	अफ्रीका	01.07.2010	15.83	26.84	978
9.	रूस	यूरोप	01.07.2010	14.04	(-)4.29	1055
10.	जापान	एशिया	01.10.2010	12.81	1.1	987
	अन्य	-	01.07.2010	284.47	15.43	-
	विश्व	-	01.07.2010	690.81	12.97	984

स्त्रोतः भारतीय जनगणना - 2011

उपर्युक्त भारतीय अनुमान विलकॉक्स, कार साउण्डर्स, थाम्पसन तथा लेविस, U.N.O. के अनुमानों से थोड़ा अलग देख सकते हैं परन्तु सम्भावित निष्कर्षों में समानता देखी जा सकती है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक अनुमान के अनुसार 1930 से 1960 के बीच विश्व जनसंख्या मे तेजी से वृद्धि हुई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में विकास तथा महामारियों के रोकथाम अन्य कारणों से मृत्यु दर में भारी कमी, उन्नत साधनों के विकास एवं अन्य कारणों से जन्म दर में वृद्धि तथा अन्य अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक कारणों से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जिससे माल्थस का अनुमान सही दिखने लगा और विश्व जनसंख्या 1930 की अपेक्षा 1960 में बढ़कर लगभग 1) गुनी हो गयी जबकि कई विकासशील देशों में लगभग दो गुनी भी हो गयी। देखें सारिणी-5.4 एवं सारिणी-5.5।

सारणी-5.4 विश्व की जनसंख्या (1500 से 2050 (अनुमानित)

(जनसंख्या लाखो में)

वर्ष	जनसंख्या	वर्ष	जनसंख्या
1500	4,200	1970	35,810
1700	6,150	1975	40,800
1800	9,000	1980	44,500
1900	1,625	1985	48,450
1920	18,110	1990	52,460
1930	20,150	1995	58,041
1940	22,480	2000	60,550
1950	25,100	2025 (अनुमानित)	82,943
1960	29,950	2050 (अनुमानित)	94,000

सारणी-5.5

विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश

(जनसंख्या लाखों में)

क्र.सं.	देश	वर्ष	जनसंख्या	लिंगानुपात
	विश्व		60,550	986
1.	चीन	2000	12,776	944
2.	भारत	2001	10,270	933
3.	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	2000	2,814	1029
4.	इंडोनेशिया	2000	2,121	1004
5.	ब्राजील	2000	1,700	1025
6.	पाकिस्तान	2000	1,565	938
7.	रूस	2000	1,469	1140
8.	बांग्लादेश	2000	1,292	954
9.	जापान	2000	1,269	1041
10.	नाइजीरिया	2000	1,115	1016

महाद्वीपों के आधार पर विश्व की जनसंख्या के वितरण को सारणी-5.6 से देख सकते हैं।

सारणी-5.6

विश्व जनसंख्या का वितरण, 2001

क्र.सं.	महाद्वीप	विश्व जनसंख्या का%भाग
1.	एशिया	57
2.	यूरोप	13
3.	उत्तरी अमेरिका	8
4.	दक्षिणी अमेरिका	7
5.	अफ्रीका	10
6.	आस्ट्रेलिया	4

5.4 विश्व जनसंख्या: एक नजर में (World Population at a Glance)

- 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 2000 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी।
- विश्व जनसंख्या 1 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।
- चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है।
- जार्डन सर्वाधिक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि (+4.4 प्रतिशत) वाला देश है।

- इस्तोनिया न्यूनतम वार्षिक जनसंख्या वृद्धि (-0.9:) वाला देश है।
- विश्व का औसत जनघनत्व 46 व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर है।
- सर्वाधिक घनत्व वाला देश सिंगापुर (5285) है।
- मंगोलिया न्यूनतम जनघनत्व (1) वाला देश है।
- विश्व का औसत लिंगानुपात 986 है।
- सर्वाधिक लिंगानुपात - रूस (1140)
- न्यूनतम साक्षरता दर नाइजीरिया 22% (पुरूष 15% महिला 7%)
- शत-प्रतिशत साक्षरता दर-अमेरिका, स्वीडन आदि।
- औसत जीवन प्रत्याशा पुरूष (65 वर्ष) महिला (75 वर्ष)
- सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा-पुरूष-स्वीडन 77 वर्ष
- सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा-महिला-जापान 84 वर्ष
- सर्वाधिक शिशु मृत्युदर-सियरालियोन (323/हजार)
- न्यूनतम शिशु मृत्युदर डेनमार्क (3 प्रति हजार)

5.5 विश्व जनसंख्या के प्रतिमान (Pattern of World Population)

विश्व जनसंख्या अध्ययन निम्न तीन प्रतिमानों के आधार पर किया जाता है -

1. **जनहीन क्षेत्र**: यह विश्व का वह भाग है, जहाँ या तो जनसंख्या नगण्य होती है या निर्जन होता है। इसके अन्तर्गत धुरवीय अथवा उपध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थलीय, उच्च पर्वतीय प्रदेश और भूमध्य सागरीय वन प्रदेश आते हैं।
2. **लघु जनसंख्या क्षेत्र**: यह विश्व का वह भाग है, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम होता है। इसके अन्तर्गत पठारी भाग और मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं।
3. **बृहत जनसंख्या क्षेत्र**: इसके अन्तर्गत वे देश आते हैं, जहाँ की जनसंख्या अधिक है। पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिमी यूरोप, रूस का पश्चिमी भाग, कनाडा, सेट लारेंस इसके अन्तर्गत आते हैं।

5.6 विश्व की जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्तियाँ(Present Trends of World Population)

विश्व की जनसंख्या को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि सभी क्षेत्रों में जनसंख्या समान दर से नहीं बढ़ी है। लेकिन अमेरिका में जहाँ जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी है वहीं उत्तरी, पूर्वी यूरोप में वृद्धि सबसे कम रही है।

कुछ देशों में जहाँ जन्म और मृत्यु-दर दोनों ऊँची रही है वहाँ जनसंख्या कम बढ़ी है। इन देशों में तिब्बत, दक्षिण अमेरिका, अरब, अफगानिस्तान तथा अफ्रीका के कुछ देश हैं। वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ जन्म-दर में तो

कम गिरावट आयी तथा मृत्यु-दर काफी घट गयी है। अतः जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इन देशों में भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि को रखा जा सकता है।

विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बडा भाग अन्तर्राष्ट्रीय देशान्तर से प्रभावित हुआ है। यूरोप तथा एशिया से जनसंख्या का काफी मात्रा में प्रवास अमेरिका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया की ओर हुआ। अमेरिका की जनंसख्या में भारी वृद्धि का कारण यह देशान्तर ही रहा है।

प्रो. हेनरी एस. बिलार्ड का कथन है कि यदि विश्व की जनसंख्या केवल 1.5% की दर से बढ़ती रहेगी तो सन् 4250 में जनसंख्या का भार स्वयं पृथ्वी के बराबर हो जायेगा।

U.N.O. ने नवम्बर 1969 में जो जनसंख्या रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या वृद्धि के प्रति निम्न सम्भावनाएँ व्यक्त की गईं थी- ***'1950 से 1990 तक उच्च कटिबंध अफ्रीका में 9 गुनी, दक्षिण अमेरिका में 7 गुनी, पूर्वी एशिया में 4 गुनी तथा शेष अफ्रीका व एशिया में 5 गुनी जनसंख्या बढ़ जायेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि दक्षिणी अमेरिका में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सर्वाधिक ऊँचा रहेगा।'***

उपर्युक्त विश्व की जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्ति तथा जनसंख्या प्रक्षेपणों को देखते हुये निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विश्व की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है जिसका मूल कारण पिछड़े व अर्द्ध विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं-प्रथम जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण मृत्युदर का कम हो जाना, पर प्रजननदर का ऊँचा रहना है। द्वितीय यहाँ जन्मदर और मृत्युदर दोनों ही अधिक हैं मृत्युदर को ही जनवृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक माना जा सकता है। इन देशों में स्वास्थ्य व चिकित्सा की सेवाओं के प्रचार-प्रसार से बीमारियों और महामारियों पर काफी हद तक नियन्त्रण लग गया है। इसी तरह सभ्यता और आर्थिक विकास के कारण उत्पादन, रहन-सहन के स्तर, यातायात संचार के साधन, व्यवसायों का विकास, उदरपूर्ति के साधन, औद्योगीकरण व नगरीकरण में वृद्धि हुई है, फलतः मृत्युदर तेजी से घटी है पर जन्मदर में इन अनुपात मे गिरावट नहीं आ पाई है। इसके विपरीत विकसित राष्ट्रों में जन्म और मृत्युदर दोनों ही गिर रही है अतः वहाँ तुलनात्मक जनवृद्धि की दर निम्न है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विज्ञान, सभ्यता और परिवार नियोजन के उन्नत साधनों के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि की दर भविष्य में गिरेगी।

5.7 विश्व जनसंख्या के अनुमान (Estimates of World Population)

किसी स्थान अथवा क्षेत्र की वर्तमान जन्म दर, मृत्यु दर तथा जनसंख्या देशान्तरण दर के आधार पर उस स्थान अथवा क्षेत्र की भावी जनसंख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के जनसंख्या विभाग द्वारा 1947 में यह अनुमान लगाया गया कि जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर यदि इसी तरह, (1.8 प्रतिशत वार्षिक) जारी रही तो 40 वर्षों में विश्व की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी और 1990 तक 4.8 अरब से भी अधिक हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्रसंघ के जनसंख्या विभाग ने 1975 में पुनः अनुमान लगाया कि वर्तमान समय में जिस दर (1.89 प्रतिशत वार्षिक) से जनसंख्या वृद्धि जारी है उस आधार पर मात्र 37 वर्षो में विश्व की जनसंख्या दुगनी हो जायेगी और सन् 2000 ई. तक यह बढ़कर 6.25 अरब हो जाएगी। यदि वृद्धि की दर में और भी वृद्धि

हुई तो जनसंख्या के दुगनी होने में और भी कम समय लगेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लगाए गए अनुमानों के आधार पर विश्व की जो जनसंख्या 1998 में लगभग 5.89 अरब थी (1.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर) वह सन् 2015 मे बढ़कर 7.29 अरब तथा 2050 में बढ़कर 9.37 अरब हो जाएगी।

प्रो. स्टाम्प के अनुसार सन् 2600 ई. तक विश्व की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि समस्त पृथ्वी पर एक व्यक्ति के निवास एवं कारोबार के लिए मात्र एक वर्गमीटर भूमि ही उपलब्ध हो पाएगी।

विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग ने प्रजनन तथा मृत्यु दर के आधार पर विश्व को तीन क्षेत्रों मे विभाजित किया है- प्रथम क्षेत्र के अन्तर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहाँ जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही अपेक्षाकृत कम हैं। द्वितीय क्षेत्र के अन्तर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहाँ जन्म दर अभी ऊँची है परन्तु मृत्यु दर घटना प्रारम्भ हो गयी है। तृतीय क्षेत्र के अन्तर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहाँ जन्म-दर बहुत ऊँची है, जिसके घटने का कोई संकेत नही मिल रहा है। विश्व के इन तीन प्रकार के क्षेत्रों के आधार पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के जनसंख्या विभाग द्वारा विश्व की भावी जनसंख्या के अनुमान निम्नवत् लगाए गए हैं%

सारणी-5.7

विश्व जनसंख्या के अनुमान (मिलियन में)

क्षेत्र	**1950**	**1960**	**1970**	**1980**	**1990**	**2000**	**2015**	**2050**
सम्पूर्ण विश्व	2518	2995	3626	4487	5705	6254	7219	9367
अफ्रीका	209	254	348	458	620	814	1181	2046
यूरोप	576	641	713	791	878	540	717	638
उत्तरी अमेरिका	168	199	230	272	325	388	345	384
लैटिन अमेरिका	163	206	284	387	537	756	625	810
एशिया	1380	1679	2033	2557	3317	4401	4381	5443
ओसोनिया	13	17	18	22	26	33	36	45

स्त्रोत: यूनाईटेड नेशन्स पापुलेशन रिपोर्ट 2006

संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों के आधार पर जो विश्व की भावी जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है जिसे सारणी-5.7 में दिया गया है जिसे स्पष्ट है कि -

1. विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।
2. जनसंख्या में होने वाली वृद्धि व वृद्धि -दर कम विकसित देशों में अधिक है जबकि विकसित देशों में कम है।
3. 1990 के लिए जनसंख्या के जो अनुमान लगाये गये थे वे लगभग पूरे होते दिखाई दिये हैं।
4. सबसे अधिक जनसंख्या मे वृद्धि एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के देशों में है, यहाँ 30 वर्षो में ही जनसंख्या ढाई गुनी हो गई है या हो जाने की सम्भावना है।

उपर्युक्त बातों को वैश्विक रिपोर्ट तथा पापुलेशन रिफेन्स ब्यूरो रिपोर्ट भी स्पष्ट करती है।

5.8 वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट (World Population Report)

विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति को देखते हुए अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 40 वर्षो में विश्व के विकसित देशों में कुल जनसंख्या लगभग स्थिर रहेगी तथा विकासशील देशों के ही जनसंख्या में वृद्धि होगी।

- 2009 में विश्व की कुल जनसंख्या- 6.83 अरब
- 2009 में विकसित देशों की जनसंख्या-1.23 अरब
- 2050 में विश्व की जनसंख्या होगी-9.18 अरब
- 2050 में विकासशील एवं विकसित देशों की जनसंख्या क्रमशः 7.9 एवं 1.28 अरब होगी।

उक्त अनुमान संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनसंख्या अनुमान की **'2008 रिवीजन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन'** शीर्षक से मार्च 2009 में जारी रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund) के ताजा आंकलन के अनुसार भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। जिससे सन् 2050 तक देश की कुल जनसंख्या 165.8 करोड़ हो जाएगी, जबकि चीन, जो वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, की जनसंख्या उस समय 140.8 करोड़ ही होगी। कोष की **'स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन-2008'** शीर्षक से गत नवम्बर माह में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर वर्तमान में 0.6 प्रतिशत ही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में, जहाँ चीन में कुल प्रजननता दर (Total Fertility Rate) 1.73 है, वही भारत में यह 2.78 बताई गई है।

5.9 पॉपुलेशन रिफ्रेन्स ब्यूरो रिपोर्ट (Population Reference Bureau Report)

अमरीका के पॉपुलेशन रिफेन्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या जो वर्तमान मे लगभग 6.86 अरब है, इस वर्ष 2011 में 7 अरब का बिन्दु पार कर जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्वभर में प्रति मिनट 267 शिशु जन्म लेते हैं, जबकि मरने वालो की कुल संख्या 108 प्रति मिनट है। इस प्रकार विश्व की कुल जनंसख्या में हर एक मिनट में 159 व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि मुख्यतः विकासशील देशों में ही होती है।

ज्ञातव्य है कि विश्व की कुल जनसंख्या ने 5 अरब का बिन्दु 11 जुलाई, 1987 को तथा 6 अरब का बिन्दु 12 अक्टूबर, 1999 को पार किया था। इस प्रकार 5 अरब के बाद एक अरब की वृद्धि होने में 12 वर्ष लगे थे तथा 6 अरब के बाद जनसंख्या मे एक अरब की एक और वृद्धि में भी 12 वर्ष ही लगेंगे।

5.10 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

लघु उत्तरीय प्रश्न

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

(अ) विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश

(ब) विश्व जनसंख्या अनुमान

(स) विश्व जनसंख्या में वृद्धि

(द) विश्व जनसंख्या वितरण

बहुविकल्पीय प्रश्न

क) वर्ष 2010 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी?

1. 6.90 अरब 2. 7.90 अरब

3. 8.90 अरब 4. 9.90 अरब

ख) वर्ष 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी?

1. 9.10 अरब 2. 10.10 अरब

3. 10.6 अरब 4. 8.5 अरब

ग) जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?

1. 14 फरवरी 2. 11 जुलाई

3. 21 अगस्त 4. 31 सितंबर

5.11 सारांश (Summary)

जैसा कि हम देख सकते है कि इकाई 5 के अन्तर्गत विश्व जनसंख्या की विभिन्न वर्षो में प्रवृत्तियों के अध्ययन को कुल 9 शीर्षकां-प्रस्तावना, उद्देश्य, विश्व जनसंख्या प्रवृत्ति, विश्व जनसंख्या: एक नजर में, विश्व जनसंख्या के प्रतिमान, विश्व जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्तियाँ, विश्व जनसंख्या के अनुमान, वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट, पापुलेशन रिफ्रेन्स ब्यूरो रिपोर्ट के रूप में, अध्ययन किया गया है।

इन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुमानित 2050 तक विश्व की जनंसख्या के 9.2 अरब तक पहुँचने के अनुमान के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न समयान्तरालों में बढ़ती प्रवृत्ति को सारणी-5.1 विश्व जनसंख्या वितरण को सारणी-5.2, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 10 बड़ें देशों की जनसंख्या को सारणी - 5.3 विभिन्न जनसंख्या अनुमानों को सारणी-5.4, लिंगानुपात को सारणी-5.5 द्वारा दिखाया गया है। साथ ही विश्व जनसंख्या एक नजर में विश्व जनसंख्या प्रतिमान विश्व जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्तियों भावी जनसंख्या अनुमानों विभिन्न वैश्विक रिपोर्टों द्वारा समझने का प्रयास किया गया है।

यद्यपि विश्व जनसंख्या में जन्म दर घटने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तथापि विश्व के लगभग सभी देशों में शैक्षिक जागरूकता तथा बढ़ते स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आयी है। फिर भी कुछ विशेष जड़वादी समुदायों, विकासशील देशों तथा क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या वैश्विक समस्यादिख रही है। आवश्यकता इस बात की है कि सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन कर समस्या को सही प्ररिप्रेक्ष्य में समझकर समस्याओं का निवारण किया जाए तथा बढ़ती जनसंख्या प्रवृत्ति को कम करते हुए खुशहाल विश्व की कल्पना की जाए।

5.11 शब्दावली (Glossary)

- प्रवृत्ति :Trends
- अनुमान :Estimates
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष :United Nation Population Fund
- कुल प्रजननता दर :Total Fertility Rate
- प्रतिमान :Pattern

5.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न

क) 1 ख) 1 ग) 2

5.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- डॉ. मिश्रा, जे. पी., जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा।
- डॉ. बघेल, डी. एस., जनांकिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
- डॉ. पन्त, जीवन चन्द्र, जनांकिकी, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
- अशोक कुमार, जनसंख्या, एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रयाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय*, भारत सरकार
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग*, भारत सरकार
- *भारतः 2013*, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

5.14 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- A.M. Carr Saunders : World Population, 1936, P.42
- Walter F. Willcox : Studies in American Demography, 1940 P. 40
- M.K. Bonnett: the world, 1954 3
- Ross, John, A (1982): International Encyclopedia of Population The Free Press. Macmillon Publishing co.New York.
- U.N. Determinantes and Consequences of Population Trends, 1953, P. 61
- UNFPA, The State of World Population, 1996
- United Nations Population Division , Word Population 2006.

- World Bank Atlas 1996
- Estimated from United Nations, 1986
- U.N. Demographic Year Book, 1950
- Selected World Demographic Inedicators by Region and Country or Area. 1970-75, Prepared by United Nations Population Division .

5.15 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. विश्व की जनसंख्या समस्या पर एक निबन्ध लिखिए।
2. विश्व की जनसंख्या की वर्तमान प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए।
3. विश्व की जनसंख्या के महत्वपूर्ण प्रक्षेपणों का वर्णन कीजिए।

इकाई 6 - जनसंख्या विस्फोट: विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या विस्फोट

(Population Explosion: Population Growth and Explosion in Developed and Developing Countries)

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 जनसंख्या विस्फोट

6.4 विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या, जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि

6.5 विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश (2004)

6.6 विश्व जनसंख्या घनत्व की कुछ मुख्य

6.7 अभ्यास प्रश्न

6.8 सारांश

6.9 शब्दावली

6.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

6.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

6.12 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री

6.13 निबंधात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

इकाई 14 में आप जान गये हैं कि विश्व जनसंख्या में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। 1930 से 1960 के मध्य विश्व जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि तथा महामारियों की रोकथाम, उन्नत साधनों की खोज और उनके प्रयोग से मृत्युदर में भारी गिरावट देखी गयी है। जबकि विशेष रुप से विकासशील देशों में जन्मदर में कमी न होने से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि देखी गयी है। इसी कारण 1930-60 को **'जनसंख्या विस्फोट काल'** कहा जाता है।

यद्यपि वर्तमान विश्व में लगभग सभी देशों में जन्मदर में कमी आयी है परन्तु अब भी कई देशों में जन्म एवं मृत्यु दर का अन्तर अधिक होने से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति दिखायी पड़ती है। विशेष रूप से अरब, अफगानिस्तान, इथोपिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, तिब्बत, दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीकी राष्ट्रों के अनेक देशों में ऊँची जन्म एवं ऊँची मृत्यु दर (लगभग 40-50 प्रति हजार) के कारण जनाधिक्य की समस्या बनी हुई है। इसका मुख्य कारण इनका पिछड़ा होना है। ऐसे देश ऊँची स्थिरता वाले देशों के अन्तर्गत आते हैं। दूसरे क्रम में शीघ्र जनसंख्या बढ़ने वाले देशों में भारत, म्याँनमार, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया, टर्की व लैटिन अमेरिका के कुछ देश आते हैं। जिनमें जन्मदर में सम्भावित गिरावट नहीं हुई जबकि मृत्यु दर न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इनमें भारत जैसे देश भी हैं जहाँ पहले ही जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी, में क्रमशः जनसंख्या की समस्या गम्भीर बनी हुई है।

तीसरे क्रम में जनसंख्या में धीमी वृद्धि वाले देश आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से रूस, जापान, अर्जेण्टाईना, पोलैण्ड, बुल्गारिया, रूमानिया, यूगोस्लोविया, इटली, स्पेन व चिली आदि देश आते हैं। जहाँ जन्म एवं मृत्युदर दोनों कम हैं परन्तु जन्मदर थोड़ा अधिक है। जिससे ऐसे देशों में जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हो रही है। ऐसे देश अपने आर्थिक विकास द्वारा जनसंख्या विस्फोट की समस्या से बचे हुए हैं।

चौथे क्रम में निम्न जनसंख्या स्थिरता वाले देश आते हैं जिसमें मुख्य रूप से वेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, नार्वे, स्विटजरलैण्ड, चेकोस्लाविया, चीन आदि देश आते हैं। यहाँ जन्म एवं मृत्यु दर दोनों कम होने से जनसंख्या वृद्धि नगण्य है। ऐसे देश जनसंख्या विस्फोट की समस्या से लगभग मुक्त हैं।

पाँचवें क्रम में ऐसे देश आते हैं जहाँ जनसंख्या में घटने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। ऐसे देशों में मुख्य रूप से तसमानिया व उष्ण ओसीनिया आदि कुछ ही राष्ट्र आते हैं। यद्यपि ऐसे राष्ट्रों की संख्या बहुत कम है जहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय मृत्युदर ऊँची होने के कारण घटने लगती है। ऐसे राष्ट्र जनाधिक्य की समस्या से पहले से ही मुक्त हैं।

प्रो. हेनरी एस. विलार्ड का यह कथन कि यदि विश्व की जनसंख्या केवल 1.5 प्रतिशत की दर से बढ़ती रहे तो सन् 4250 तक जनसंख्या का भार पृथ्वी के लगभग बराबर हो जायेगा तथा लोगों के पास मुश्किल से खड़ा होने का जगह बचेगा, स्वयं में भयावह तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है।

यद्यपि जनसंख्या विस्फोट का यह पक्ष मुख्यतः जन्म एवं मृत्यु दर से सम्बन्धित है। जिसके अन्तर्गत निराशावादी विचारधारा के समर्थक अर्थशास्त्री मुख्य रूप से क्लार्क (Clarck), हक्सले (Huxley), लीग्रास (Legross), ओसबोर्न (Osborn),अन्य विश्व की बड़ी भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। जिसका समर्थन खाद्य

और कृषि संगठन (food and agriculture organization- F.A.O.) और अन्य संगठन भी करते हैं। परन्तु इसके विपरीत आशावादी विचारक **एल. बागरामोव (L. Bagramov), साइनीजिन (Sinyagin) के.एम. मालिन (K.M. Malin) बी. रास्टीनिकोव (V.Rastynikov)** हैं, जिनका मानना है कि जनंसख्या विस्फोट का तर्क सही नहीं है। पिछड़ी तकनीक के स्थान पर नयी तकनीक का प्रयोग कर, शाकाहारी भोजन के स्थान पर मांसाहारी भोजन प्रयोग कर, बीज, खाद, सिचाई अन्य की व्यवस्था में सुधार कर जनसंख्या विस्फोट की समस्या से बच सकते हैं।

6.2 उद्देश्य (Objectives)

- ✓ जनसंख्या विस्फोट के वास्तविक अर्थ अर्थात् जनसंख्या वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग में समन्वय का अर्थ समझना।
- ✓ जनसंख्या विस्फोट के प्रति आशावादी तथा निराशावादी विचारों से अवगत होना।
- ✓ विश्व के प्रमुख विकसित एवं विकासशील देशों के जन्म एवं मृत्यु दर की जानकारी प्राप्त करना।
- ✓ विश्व जनसंख्या सम्बन्धी वितरण की जानकारी प्राप्त करना।

6.3 जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion)

जनसंख्या विस्फोट की स्थिति सामान्यतया ऊँची जन्म दर तथा नीची मृत्युदर के समय होती है। यह स्थिति विकास के द्वितीय चरण की स्थिति मानी जाती है। जिसके अन्तर्गत कोई देश विकास की तरफ प्रथम चरण से द्वितीय चरण की तरफ अग्रसर होता है। कृषि की दशा में सुधार होने लगता है। कृषि में यंत्रीकरण की शुरूआत हो जाने से उत्पादन बढ़ने लगता है। उद्योगों का विकास भी प्रारम्भ हो जाता है। परिवहन साधनों का विकास होने लगता है। श्रम की गतिशीलता बढ़ने लगती है। शिक्षा का विस्तार होने लगता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें सुलभ होने लगती हैं। रहन-सहन का स्तर बढ़ने लगता है।

फलतः मृत्यु दर तेजी से घटने लगती है। परन्तु सामाजिक सोच में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने से सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण जन्म दर में कोई कमी नहीं आती। परिवार नियोजन के विषय में धार्मिक अन्धविश्वास तथा सामाजिक निषेध मौजूद रहने के कारण, लोग परिवार के आकार पर विशेष नियंत्रण के लिये प्रयत्न नहीं करते। मृत्युदर में कमी होने और जन्मदर में परिवर्तन न होने से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिससे अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या की ऊँची वृद्धि -दर से देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती है। फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा रहता है। इस प्रकार जन-सामान्य के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होता, लोग पिछड़े ही रहते हैं। विश्व जनसंख्या तथा भारत के इतिहास में लगभग 1930 से 1970 का समय **'जनसंख्या विस्फोट काल'** कहा जाता है।

प्रो. सी. पी. ब्लेकर के अनुसार जनसंख्या विस्फोट को निम्न चित्र 6.1 तथा **कार्ल सैक्स** के अनुसार जनसंख्या विस्फोट को चित्र 6.2 में दिखाया गया है। जिसमें तेजी से घटती मृत्यु दर धीमी गति से गिरती जन्म दर

को दिखाया गया है। लगभग इसी तरह के विचार अन्य जनसंख्या विशेषज्ञों ने भी दिये हैं। हार्वे लीबिन्सटीन, बेकर और ईस्टलीन, कार्ल सैक्स तथा अन्य ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किये हैं।

चित्र - 6.1

प्रो. सी. पी. ब्लेकर का जनसंख्या विस्फोट रेखाचित्र

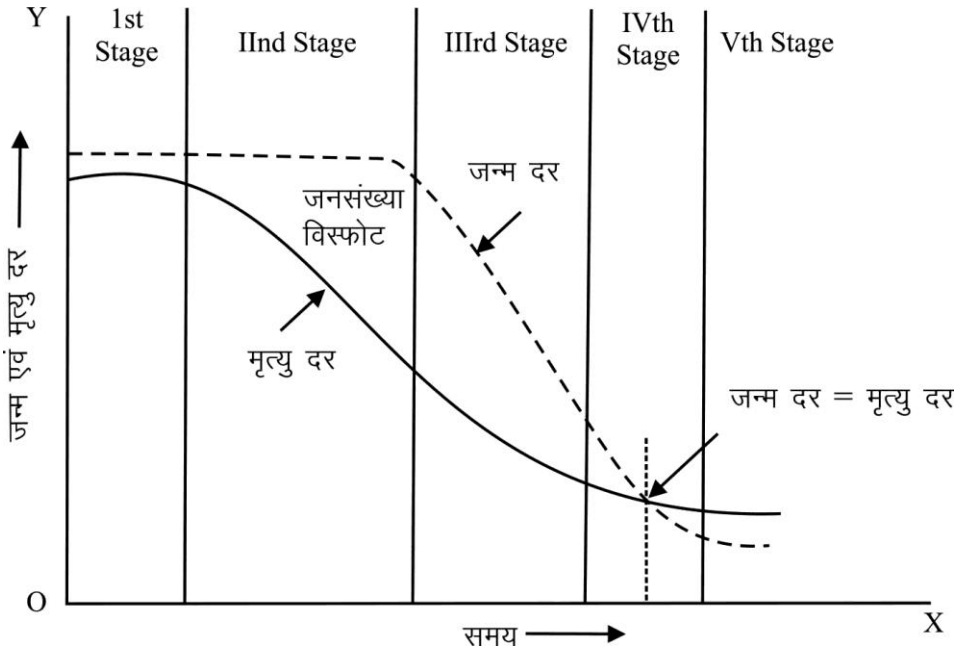

चित्र - 6.2

प्रो. कार्ल सैक्स का जनसंख्या विस्फोट रेखाचित्र

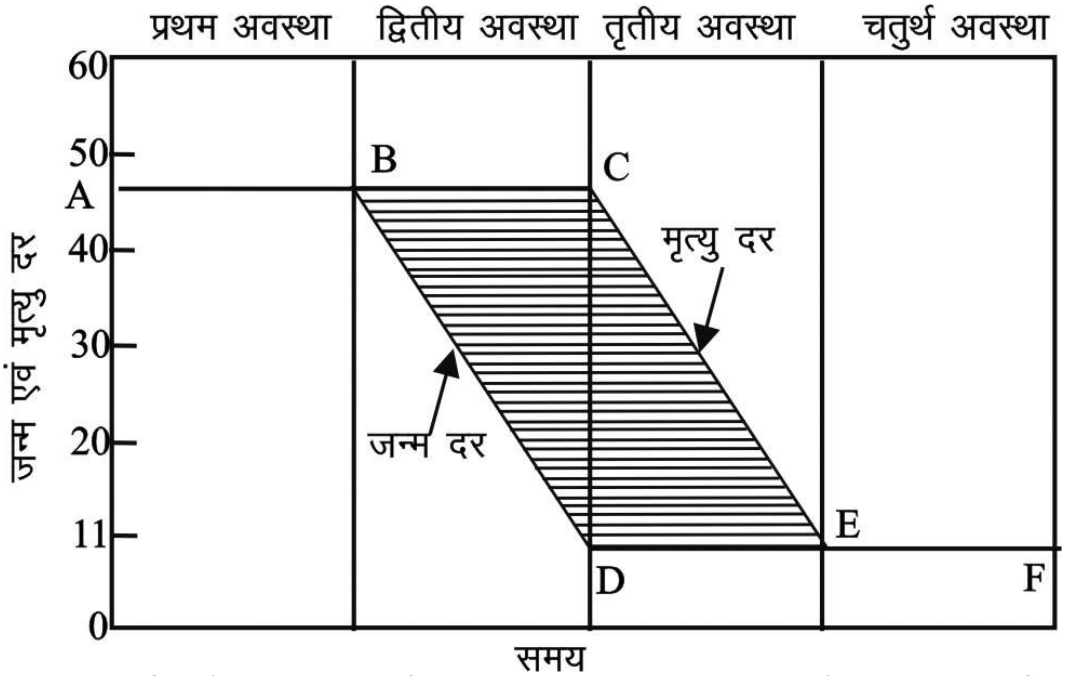

यद्यपि **'जनसंख्या विस्फोट'** किस स्तर को माना जाय, इस पर एक मत नहीं है, फिर भी विश्व में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने - अपने विचार व्यक्त किए हैं। पीयरसन एवं हार्पर का विचार है कि यदि विश्व के सभी क्षेत्रों में लोग उत्तरी अमेरिका के जीवन-स्तर से रहें, तब विश्व की

जनसंख्या 90 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि विश्व की जनसंख्या यूरोप के स्तर पर रहे तो अधिकतम जनसंख्या को 210 करोड़ तथा एशिया के जीवन स्तर पर 280 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।

खाद्य और कृषि संगठन (food and agriculture organization- F.A.O) के प्रतिवेदनों के अनुसार सन् 2000 ई. में जनसंख्या को 2400-2500 कैलोरी तथा 20 ग्राम जीव प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिए अफ्रीका को अपने उत्पादन में 160 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इसी तरह, मध्य पूर्व में 200 प्रतिशत दक्षिणी तथा अमेरिका को 200 प्रतिशत उत्पादन को बढ़ाना होगा।

उपरोक्त विचारों के अतिरिक्त आशावादी विचारकों का मानना है कि विश्व में प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा विश्व के समक्ष जनसंख्या आधिक्य की कोई समस्या नहीं है। विश्व के वर्तमान संसाधनों से वर्तमान जनसंख्या से कई गुना अधिक जनसंख्या का भरणपोषण किया जा सकता हैं। अतः विश्व की बढ़ती जा रही जनसंख्या से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन विचारकों में सोवियत विशेषज्ञों का प्रमुख स्थान है।

सोवियत विशेषज्ञ एल. बागरामोव (L. Bagramov) का मत है कि विश्व में लगभग 25 करोड़ परिवार कृषि की पिछड़ी तकनीक को अपनाए हुए हैं। यदि इनके स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जाए तो कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी। साथ ही, अविकसित देशों में भूमि का उचित विवरण नहीं है। बचत की कमी से पूँजी में कमी है। अतः यदि अर्थव्यवस्था में सुधार हो तथा कृषि उत्पादन को नियोजित किया जाय, तो विश्व की खाद्य समस्या हल हो जाएगी।

बागरामोव पुनः मत व्यक्त करते हैं कि खाद्य समस्या को हल करने के लिए मछली आदि के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। अभी तक हम ताजे पानी की मछली का केवल 10 प्रतिशत ही उपयोग कर पाए हैं, जबकि शेष 90 प्रतिशत का कोई उपयोग नहीं होता है।

इसी तरह आशावादी विचारक साइनीजिन (Sinyagin) का कथन है कि विश्व के इतिहास में एक ऐसा भी उदाहरण दिखाई नहीं पड़ता, जहां विश्व में एक लम्बे समय तक खाद्यान्न संकट रहा हो। युद्ध अथवा प्राकृतिक कारणों से ऐसा किसी काल विशेष में तो हो सकता है, परन्तु ऐसा होना कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने स्पष्ट किया कि सन् 1936 से 1966 की अवधि में विश्व की जनसंख्या 50 प्रतिशत बढ़ी, जबकि इसी अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में 70 से 75 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसी तरह, विश्व की कुल भूमि का मात्र 11 प्रतिशत ही कृषि के अन्तर्गत है जिसे विज्ञान की सहायता से तीन गुना अर्थात 33 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार, रबर, जूट तथा कपास के स्थान पर भी खाद्यान्नों का उत्पादन किया जा सकता है क्योंकि इन उत्पादों को कृत्रिम वस्तुओं के उत्पादों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

तकनीकी प्रगति तथा परमाणु शक्ति के प्रयोग से रेगिस्तानों, पहाड़ों तथा टुण्ड्रा प्रदेशों में भी खेती की जा सकती है। साइनीजिन पुनः मत व्यक्त करते हैं कि उर्वरकों के प्रयोग से प्रति हेक्टेअर कृषि उपज में वृद्धि की जा सकती है तथा कीटनाशक दवाओं के पर्याप्त प्रयोग से 20 से 30 करोड़ जनसंख्या के लिए अतिरिक्त अनाज को बचाया जा सकता है। अतः भविष्य के प्रति निराशा का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता।

इसी तरह, खाद्य और कृषि संगठन (food and agriculture organization- F.A.O) के अनुसार विश्व के सिंचित क्षेत्र में सहजता से तीन गुना वृद्धि की जा सकती है जिससे पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादनों को बढ़ाया जा सकता है।

इस तरह से हम देख सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट पर विवाद है। इस हेतु हमें न तो विश्व की भावी जनसंख्या के बारे में अत्यधिक निराश होने की आवश्यकता है और न ही अधिक आशावान। जिस गति से विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस पर नियन्त्रण करना आवश्यक है। साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि करना भी आवश्यक है। कृषि में वैज्ञानिक विधियों, नवीनतम उपकरणों, उन्नत बीजों, सिंचाई के साधनों, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है तथा विश्व को निराश होने से बचाया जा सकता है।

6.4 विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या, जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि (Population of Different Areas of the World, Birth Rate and Population Growth)

जनसंख्या प्रक्षेपणों तथा विश्व की यदि वास्तविक जनसंख्या की प्रवृत्तियों पर नजर डाली जाये तो यह स्पष्ट होता है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म व मृत्यु दर भिन्न-भिन्न हैं। जहाँ कुछ भागों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है वहीं कुछ भागों में कम है। इसका मूल कारण स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, महामारियों-बीमारियों की रोकथाम तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम में वृद्धि व सफलता तथा असफलता है। किसी देश की जसंख्या की वृद्धि दर का निर्धारण साधारणतः उस देश विशेष की जन्मदर, मृत्युदर व देशान्तरण दर पर निर्भर है। विकसित राष्ट्रों में जन्मदर और मृत्युदर दोनों नीची हैं तथा वहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ जन्म वृद्धि दर नीची है जबकि कम विकसित राष्ट्रों में परिस्थितियां इसके विपरीत होती हैं। अतः वहाँ जनवृद्धि दर ऊँची रहती है। देखें सारणी 6.1।

सारणी-6.1

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ

क्षेत्र	कुल जनसंख्या (मिलियन)	प्रक्षेपित जनसंख्या (मिलियन)	औसतन वृद्धि दर%	नगरीय प्रतिशत	प्रजनन दर
	1996	2025	1995-2000	1995	2000
विश्व	5804.1	8294.3	1.5	45	2.98
अधिक विकसित क्षेत्र	1170.7	1238.4	0.3	75	1.71
कम विकसित क्षेत्र	4633.4	7055.9	1.8	38	3.29
अविकसित देश	591.8	1162.3	2.7	22	5.27

Source: UNFPA, The State of World Population, 1996

सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि उच्च जन्म-दर एवं निम्न मृत्यु-दर का परिणाम है, लेकिन अमेरिका जैसे कुछ विशेष देश की जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन का जन्म-दर एवं मृत्यु-दर के साथ-साथ प्रवास भी प्रभावित किया है।

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की जन्मदर, मृत्युदर, प्राकृतिक वृद्धि दर , लिंगानुपात तथा प्रति वर्ग किमी, जनधनत्व को सारणी-6.2 में दिखाया गया है। जिसमें स्पष्ट है कि पृथ्वी की औसत जनघनत्व 52

व्यक्ति/वर्ग किमी (2008) है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया में पाया जाता है। इसके पश्चात् यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका का स्थान आता है। ओशीनिया में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। जबकि अफ्रीका में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों सर्वाधिक है। यही कारण है कि अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर अन्य सभी महाद्वीपों से अधिक है। यूरोप में जन्म दर मृत्यु दर से कम होने के कारण यहाँ जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर ऋणात्मक है।

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि की दर उत्तरी-पूर्वी यूरोप मे सबसे कम है जबकि लैटिन अमेरीका में सबसे अधिक है। विश्व जनसंख्या 2004 में जन्मदर, मृत्युदर के आधार पर जनघनत्व को विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों को सारणी 6.2 से दिखाया गया है।

सारणी - 6.2

विश्व जनसंख्या: 2004

क्षेत्र	**जन्म-दर (प्रति हजार)**	**मृत्यु-दर (प्रति हजार)**	**प्राकृतिक वृद्धि दर (% में)**	**वृद्धि दर (% में)**	**लिंगानुपात**	**जनघनत्व /वर्ग किमी**
विश्व (2008)	20.00	8.00	1.13	1.14	984:1000	52 (2008)
अफ्रीका	35.90	14.20	2.17	2.14	1017:1000	29
उत्तरी अमेरिका	17.20	7.60	0.97	1.11	1050: 1000	16
द. अमेरिका	19.70	7.70	1.20	1.19	-	25
एशिया	20.70	7.60	1.31	1.28	960:1000	122
यूरोप	10.2	11.4	(-) 0.12	0.00	1051:1000	31
ओशेनिया	17.10	7.20	0.99	1.29	983:1000	04

1950 के उपरान्त विश्व की जनसंख्या एवं वार्षिक वृद्धि दर को निम्न सारिणी - 6.3 में प्रदर्शित किया गया है। जिसमें 1960-70 का समय जनसंख्या विस्फोट माना जाता है।

सारणी - 6.3

विश्व जनसंख्या - आकार एवं वृद्धि दर (1950-2004)

वर्ष	**जनसंख्या(मिलियन में)**	**निरपेक्ष वृद्धि (मिलियन में)**	**वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)**
1950	2513	-	-
1955	2745	+232	1.8
1960	3027	+282	2.1
1965	3344	+317	2.1
1970	3678	+334	2.0
1975	4033	+355	1.9
1980	4415	+382	1.9
1985	4837	+422	1.9

1990	5225	+388	2.1
1996	5768	+543	1.5
1998	5896	+128	1.6
2002	6201	+305	1.4
2004	6389	+188	1.6

Source (1) United Nations Population Division,1996,(ll) Human Development Report, 2006

6.5 विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश (World's Highly Populated Countries)

विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है जिसकी जनसंख्या 1,308 मिलियन है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का स्थान है जिसकी जनसंख्या 1,087 मिलियन है। तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है जिसकी संख्या 295.5 मिलियन है। निम्न सारणी - 6.4 में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 10 बड़े देशों को प्रदर्शित किया गया है:

सारणी-6.4

जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व के सबसे बड़े देश (2004)

क्रमांक	देश	कुल जनसंख्या	विश्व जनसंख्या का प्रतिशत (2000)
1.	चीन	1,308	21.4
2.	भारत	1,087	16.4
3.	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	295.5	4.7
4.	इण्डोनेशिया	220	3.5
5.	ब्राजील	184	2.8
6.	पाकिस्तान	154.8	2.4
7.	रूसी फेडरेशन	144	2.6
8.	बांग्लादेश	139	2.1
9.	नाइजीरिया	128.7	2.0
10.	जापान	145.6	2.2

Source: Human Development Report, 2006

उपरोक्त सारणी - 6.4 से स्पष्ट है कि चीन में सम्पूर्ण विश्व की 21.4 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह भारत में 16.4 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4.7 प्रतिशत इण्डोनेशिया में 3.5 प्रतिशत, ब्राजील में 2.8 प्रतिशत, रूसी फेडरेशन में 2.6 प्रतिशत, पाकिस्तान में 2.4 प्रतिशत, जापान में 2.2 प्रतिशत, बांग्लादेश में 2.1 प्रतिशत तथा नाइजीरिया में विश्व की जनसंख्या का 2.0 प्रतिशत भाग निवास करती है स्पष्टता चीन तथा भारत में कुल विश्व की तिहाई से अधिक जनसंख्या निवास करती है।

सारणी 15.5 में 10 सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों का क्रम दिखाया गया है। जिसमें हांगकांग प्रथम तथा इजराइल 10 वें स्थान पर है।

सारणी 6.5

सर्वाधिक जनघनत्व वाले देश, 1999

क्रमांक	देश	जनघनत्व (सर्वाधिक)	क्रमांक	देश	जनघनत्व(सर्वाधिक)
1	हांगकांग	6,950	6	भारत	335
2	सिंगापुर	5,285	7	जापान	336
3	बांग्लादेश	985	8	बेल्जियम	312
4	द0 कोरिया	475	9	अल साल्वाडोर	299
5	लेबनान	418	10	इजराइल	296

चीन की अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तथा द. पूर्वी भाग में पाई जाती है। भारत की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या सतलज और गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की 85 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 100^0 पश्चिमी देशान्तर के पूर्वी भाग में पायी जाती है। इंडोनेशिया में जावा तथा मदुरा द्वीपों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। जावा द्वीप का क्षेत्रफल यद्यपि देश के क्षेत्रफल का मात्र 7 प्रतिशत है परन्तु यहाँ इंडोनेशिया की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। ब्राजील या यों कहें कि सम्पूर्ण दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख नगरों में हाइपर सेफालिज्म (Hyper Cephalism) अर्थात् अत्यधिक उच्च जन-जमाव की प्रकृति पायी जाती हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग राजधानी नगरों में बसता हैं। पाकिस्तान की अधिकांश जनसंख्या सिन्धु नदी के निचले मैदानों व डेल्टा प्रदेश तथा सतलज सिन्धु नदी के दोआब क्षेत्र में पाई जाती है।

बांग्लादेश की 90 प्रतिशत जनसंख्या गंगा-ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में संकेन्द्रित है। जापान की अधिकांश जनसंख्या 330 से 370 उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है।

पृथ्वी पर ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जो विरल जनसंख्या वाले हैं और जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से भी कम है। ऐसे क्षेत्रों में उच्च अक्षांशीय क्षेत्र (विशेषकर 600 उत्तरी अक्षांश के ऊपर में स्थित क्षेत्र), अण्टार्कटिका क्षेत्र, उष्ण कटिबन्धीय मरुस्थली क्षेत्र, उच्च पर्वतीय और पठारी क्षेत्र तथा भूमध्य रेखीय वर्षा प्रचुर वन वाले क्षेत्र उल्लेखनीय है। इसी तरह सर्वाधिक 5000 वर्ग किमी तक की आबादी वाले देशों में 4 शीर्ष जनघनत्व वाले देश सारणी 6.6 (अ), शीर्ष पाँच जनघनत्व वाले छोटे द्वीपीय देशों सारणी 15.6 (ब) तथा शीर्ष न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 देशों को सारणी-6.6 (स) में दिखाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि बांग्लादेश मालदीव, चैनल आइसलैण्ड तथा बारबोडास सर्वाधिक जनघनत्व/प्रति वर्ग किमी वाले देश हैं। जबकि मंगोलिया में 2 प्रति वर्ग किमी जनघनत्व है।

सारणी 6.6 (अ)

सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 शीर्ष देश (मई 2009 - अनुमानित)

देश	बांग्लादेश	मालदीव	चैनल आइसलैण्ड	बारबोडास
जनघनत्व व्यक्ति/वर्ग किमी.	**1127**	**1057**	**804**	**653**

वे देश जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्ग किमी से अधिक है को सारणी 6.6 (ब) में दिखाया गया है।

सारणी 6.6 (ब)

विश्व: शीर्ष पाँच जनघनत्व वाले छोटे द्वीपीय देश – 2009

देश	मोनाको	मकाऊ	सिंगापुर	हांगकांग	बहरीन
जनघनत्व	35,382	21,346	7,486	6,403	1,754

Source: UNDF

सारणी - 6.6 (स)

विश्व: शीर्ष न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 देश – 2008

देश	प्रति वर्ग किमी.
मंगोलिया	2
नामीबिया/आस्ट्रेलिया/लीबिया/वोत्सवाना/आइसलैण्ड	3
कनाडा/गुयाना	4

मंगोलिया विश्व का सबसे कम आबादी वाला देश है।

6.6 विश्व जनसंख्या घनत्व की कुछ मुख्य बिंदु (Some Important Facts about the Densityof World Population)

विश्व की वर्ष 2004 में जनसंख्या 6,389 मिलियन थी, परन्तु यह जनसंख्या विभिन्न महाद्वीपों के मध्य समान रूप से वितरित नहीं थी। कहीं जनसंख्या सघन बसी हुई थी तो कहीं विरल। सम्पूर्ण विश्व का जनघनत्व 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। विकसित देशों में जनघनत्व 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है, जबकि विकासशील देशों में जन घनत्व 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है।

अफ्रीका महाद्वीप में जनघनत्व 29 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी., यूरोप में 31 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी., एशिया में 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी., लैटिन अमेरिका में 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी., उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी तथा ओशेनियाँ में 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है।

विश्व में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जन घनत्व अत्यधिक कम है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से भी कम है। इन क्षेत्रों को जनरिक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है:

1. एशिया में मध्य एशिया, अरब, उत्तरी साइबेरिया, मंगोलिया।
2. यूरोप मे उत्तरी यूरोप।

3. उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर ग्रीनलैण्ड तक तथा अलास्का से दक्षिण की तरफ राकी पर्वतीय क्षेत्र तथा मैक्सिको।
4. दक्षिणी अमेरिका में अमेजन की घाटी तथा मध्य एण्डीज से पैटागोनिया तक का क्षेत्र।
5. अफ्रीका मे सहारा मरुभूमि, कालाहारी मरुभूमि तथा दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका।
6. अंटार्कटिका का जनरिक्त क्षेत्र।
7. आस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा।

ये सभी जनरिक्त क्षेत्र विश्व के लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं।

इसके विपरीत विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या बहुत घनी बसी है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से अधिक है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं:

1. पूर्वी एशिया (चीन, जापान, कोरिया को सम्मिलित करते हुए)।
2. दक्षिणी एशिया (भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका को सम्मिलित करते हुए)।
3. उत्तर-पश्चिमी तथा मध्य यूरोप।
4. उत्तर-पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।
5. मिस्त्र में नील नदी की घाटी।
6. दक्षिण-पूर्वी ब्राजील।
7. आस्ट्रेलिया में सिडनी का समीपवर्ती क्षेत्र।

इसके अतिरिक्त विश्व के शेष क्षेत्र सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं।

6.7 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

लघु उत्तरीय प्रश्न

(अ) जनसंख्या विस्फोट

(ब) विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश

(स) विश्व जनसंख्या घनत्व की मुख्य बातें

(द) विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या को प्रवृत्तियाँ

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या था?

A. मृत्यु दर में कमी B. जन्म दर में कमी

C. औद्योगिक क्रांति D. जन्म दर में वृद्धि

2. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनसंख्या विस्फोट के कारण को व्यक्त करता हैं?

A. कृषि में मशीनीकरण B. धार्मिक अंधविश्वास

C. सामाजिक रीति-रिवाज D. उपरोक्त सभी

3. मानव जनसंख्या वृद्धि और भविष्य के विकास की भविष्यवाणी में प्रवृत्तियों का अध्ययन को किस विषय के रूप में जाना जाता है?

A. जनसांख्यिकी B. भूगोल

C. दर्शनशास्त्र D. मनोविज्ञान

4. निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनसंख्या वृद्धि से नहीं जुड़ी हैं?

A. संसाधनों की खपत में वृद्धि B. पर्यावरण प्रदूषण

C. खाद्य और ऊर्जा भंडारण D. उपरोक्त में से कोई नहीं

5. जनसंख्या पिरामिड किसके लिए उपयोगी होता हैं?

A. जनसंख्या वृद्धि दर को व्यक्त करना B. आयु-लिंग वितरण को व्यक्त करना

C. जन्म दरों को इंगित D. मृत्यु दर इंगित

6. समान जन्म और मृत्यु दर के कारण शून्य जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता हैं?

A. प्राकृतिक वृद्धि B. जनसांख्यिकीय संतुलन

C. प्रजनन दर D. प्रतिस्थापन स्तर

6.8 सारांश (Summary)

इस इकाई में प्रस्तावना के अन्तर्गत जनाधिक्य की समस्या को समझते हुए जनसंख्या विस्फोट को स्पष्ट किया गया है। पुनः इकाई के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए जनसंख्या विस्फोट को चित्र के आधार पर स्पष्ट करते हुए आशावादी एवं निराशावादी विचारों को समझने का प्रयास किया गया है। इस तरह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर एवं जनसंख्या वृद्धि को विभिन्न सारणियों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। इन सारणियों के अन्तर्गत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की प्रवृत्तियों, विश्व जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि -दर, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों, सर्वाधिक जनघनत्व वाले देशों अन्य को आँकड़ों के आधार पर स्पष्ट किया गया है। इस इकाई के अन्त में विश्व जनसंख्या घनत्व की कुछ मुख्य बातों को समझने का प्रयास किया गया है।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकतें हैं कि विश्व के अविकसित तथा कम विकसित क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या अधिक भयावह है। विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि की समस्या अब भी गम्भीर बनी हुई है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीप, चैनल आइसलैण्ड, बारबोडास अन्य देशों में जनघनत्व अधिक होने के साथ - साथ विकास की गति धीमी है जिससे जनसंख्या विस्फोट की दशा दिखती है। ऐसे समय इन राष्ट्रों को जन्मदर पर नियंत्रण रखते हुए विकास की गति बढ़ानी होगी।

6.9 शब्दावली (Glossary)

- **जनसंख्या विस्फोट :** Population Explosion
- **F.A.O.:** United Nations Food Agricultural Organization.

- **जन घनत्व:**PopulationDensity
- **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष:** United Nations Population Fund UNPF

6.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Questions)

1. C. 2. D. 3. A.
4. D. 5. B. 6. B.

6.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- डॉ. मिश्रा, जे. पी., जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा।
- डॉ. बघेल, डी. एस., जनांकिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
- डॉ. पन्त, जीवन चन्द्र, जनांकिकी, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
- अशोक कुमार, जनसंख्या, एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रयाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय*, भारत सरकार
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग*, भारत सरकार
- *भारतः 2013*, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

6.12 सहायक/उपयोग पाठ्य सामग्री(Useful/Helpful Text)

- A.M. Carr Saunders : World Population, 1936, P.42
- Walter F. Willcox : Studies in American Demography, 1940 P. 40
- M.K. Bonnett: the world, 1954 3
- Ross, John, A (1982): International Encyclopedia of Population The Free Press. Macmillon Publishing co.New York.
- U.N. Determinantes and Consequences of Population Trends, 1953, P. 61
- UNFPA, The State of World Population, 1996
- United Nations Population Division , Word Population 2006.
- World Bank Atlas 1996
- Estimated from United Nations, 1986
- U.N. Demographic Year Book, 1950

- Selected World Demographic Inedicators by Region and Country or Area. 1970-75, Prepared by United Nations Population Division .

6.13 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1.जनसंख्या विस्फोट से क्या समझते हैं? इसके सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षों को स्पष्ट कीजिये।

2. विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या प्रवृत्तियों एवं जनसंख्या विस्फोट को स्पष्ट कीजिये।

इकाई 7 - विकसित एवं विकासशील देशों में आयु एवं लिंग संरचना के प्रतिमान तथा विभिन्न वर्गों में जनसंख्या पिरामिड

(Pattern of Age and Sex Composition in Developed and Developing Countries and Population Pyramids in Different Groups)

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 आयु संरचना

7.4 लिंग संरचना

7.5 जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्युदर

7.6 जनसंख्या पिरामिड

7.7 आयु-संरचना एवं लिंग अनुपात का महत्व

7.8 अभ्यास प्रश्न

7.9 सारांश

7.10 शब्दावली

7.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

7.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

7.14 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

पिछली इकाईयों में हम विश्व जनसंख्या की विभिन्न वर्षो में प्रवृत्तियों एवं विकसित तथा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या विस्फोट का अध्ययन कर चुके हैं। इस इकाई में विकसित और विकासशील देशों में आयु एवं लिंग संरचना के प्रतिमानों के साथ-साथ विभिन्न वर्गों में जनसंख्या पिरामिड का अध्ययन करेंगे।

किसी भी क्षेत्र अथवा देश के जनसंख्या अध्ययन में वहाँ की आयु एवं लिंग संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। उस क्षेत्र अथवा देश की कितनी जनसंख्या किस आयु वर्गों में पायी जाती है, इसके अध्ययन से वहाँ की श्रमशक्ति, प्रजनन योग्य आयु की स्त्रियों का अनुपात, मृत्युदर एवं वैवाहिक दरें आदि ज्ञात की जा सकती है। इन सभी तत्वों का समेकित प्रभाव उस देश की सामाजिक-आर्थिक विकास पर पड़ता है। विशेष रूप से उस क्षेत्र अथवा देश विशेष की क्रियाशील जनसंख्या का आकार, आयु वर्ग एवं स्त्री-पुरूष अनुपात के बिना मानव - संसाधन का सही नियेाजन सम्भव नहीं है।

जब जनसंख्या की आयु एवं लिंग संरचना को रेखांकित किया जाता है तो जो रेखीय चित्र बनता है वह पिरामिड कहलाता है जिसमें सामान्य रूप से बच्चों की संख्या अधिक होने से आधार चौड़ा तथा वृद्धों की संख्या कम होने से शीर्ष सकरा होता है। यद्यपि विकसित तथा विकासशील देशों का जनसंख्या पिरामिड अलग-अलग दिखाई देता है। क्योंकि उनकी परिस्थितियों में अन्तर होने से उनके आंकड़ों में अन्तर होता है। विकसित देशों में सामान्यतः जन्म एवं मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होती है जबकि विकासशील देशों में जन्मदर मृत्युदर की तुलना में अधिक होने से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। यही नहीं विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या का अनुपात तथा जीवन प्रत्याशा विकासशील देशों से अधिक होने से लिंग अनुपात अपेक्षाकृत संतुलित होता है जबकि विकासशील देशों में स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। क्षेत्र विशेष, देश विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष, शिक्षा, सामाजिक, भौगोलिक तथा आर्थिक अन्तरों के आधार पर भी जनसंख्या पिरामिड का स्वरूप बदलता रहता है।

भारत जैसे विकासशील देशों में सामान्यतया शिशु जन्म दर अधिक, मृत्यु दर सामान्यतया स्थिर एवं कम, जनसंख्या की तेज वृद्धि दर, स्त्री-पुरूष अनुपात में कमी, बढ़ती युवाओं की संख्या अन्य कारणों से जनसंख्या पिरामिड का आकार विकसित देशों के जनसंख्या पिरामिड से अलग दिखाई देता है। भारत का पिरामिड सामान्यतः लट्टू के आकार का, जबकि विकसित देशों में जनसंख्या पिरामिड का आकार आधार स्तर पर भी लगभग मध्य स्तर के पिरामिड का आकार बनाता है।

7.2 उद्देश्य (Objectives)

- ✓ विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों की आयु संरचना की जानकारी प्राप्त करना।
- ✓ विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों की लिंग संरचना की जानकारी प्राप्त करना।
- ✓ विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों की जनसंख्या की विभिन्न आयु वर्गों में वितरण की जानकारी प्राप्त करना।

- ✓ विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य जीवन प्रत्याशा की जानकारी प्राप्त करना।
- ✓ विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों की क्रियाशील जनसंख्या की जानकारी प्राप्त करना।
- ✓ जनसंख्या पिरामिड के माध्यम से आयु एवं लिंग संरचना की जानकारी प्राप्त करना।
- ✓ भावी जनसंख्या नीति को तय करते समय वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना।

7.3 आयु संरचना (Age Composition)

किसी भी क्षेत्र अथवा देश की जनसंख्या की आयु संरचना उस क्षेत्र अथवा देश की प्रजननशीलता, मरणशीलता तथा प्रवास का प्रतिफल होती है। जनसंख्या की आयु - संरचना उसके आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक प्रारूप को प्रभावित करती है। उस क्षेत्र अथवा देश की कितनी-कितनी जनसंख्या किस-किस आयु वर्ग में पायी जाती है, इसके अध्ययन से वहाँ की श्रमशक्ति, प्रजनन योग्य आयु की स्त्रियों का अनुपात, मृत्युदरें एवं वैवाहिक दरें आदि ज्ञात की जा सकती है।

किसी भी देश की क्रियाशील जनसंख्या के भावी विकास को जानने के लिए वहाँ के समस्त लोगों का आयु वर्ग के आधार पर अध्ययन करना आवश्यक है। निम्न सारणी 7.1 में विश्व जनसंख्या की आयु संरचना को प्रदर्शित किया गया है:

सारणी - 7.1 विश्व के प्रमुख देशों की आयु संरचना (2004)

क्षेत्र/देश	0-14 वर्ष	15-64 वर्ष	65 या अधिक वर्ष
सम्पूर्ण विश्व	28.5	64.2	7.3
अधिक विकसित देश	18.4	67.0	14.6
विकासशील देश	31.2	63.4	5.4
अल्प विकसित देश	42.0	54.8	3.2
अफ्रीका	43.9	53.0	3.1
पूर्वी एशिया एण्ड पैसेफिक	24.3	68.9	6.8
मध्य एवं पूर्वी यूरोप	18.6	68.7	12.7
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	20.9	66.8	12.3
ग्रेट ब्रिटेन	18.2	65.9	15.9
जापान	14.1	66.7	19.2
चीन	22.0	70.5	7.5
भारत	32.5	62.3	5.2
श्रीलंका	24.5	68.4	7.1
पाकिस्तान	38.9	57.3	3.8
नेपाल	38.9	56.9	3.6
नाइजर	49.0	49.0	2.0

Source:Human Development Report, 2006

उपरोक्त सारणी 7.1 के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण विश्व में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात लगभग 64 प्रतिशत है। जबकि आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत 36 है।

सारणी 7.1 के द्वारा विश्व आयु संरचना का अध्ययन आयु को निम्न तीन वर्गों में बाँटकर किया जा सकता है:

(1) शिशुओं एवं बच्चों का आयु वर्ग (0-14 वर्ष)- इस आयु वर्ग में 15 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं एवं बच्चों को रखा जाता है। यह आयु वर्ग आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादक समझा जाता है तथा यह समाज तथा देश पर बोझ रहता है क्योंकि इनके भोजन, वस्त्र शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय करना पड़ता है। परन्तु यही आयु वर्ग भविष्य की आधारशिला भी है। विश्व की लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या इसी आयु वर्ष में है।

आर्थिक रूप से विकसित देशों में सम्पूर्ण जनसंख्या का 18 प्रतिशत भाग, कम विकसित देशों में 31 प्रतिशत भाग तथा अल्प तथा पिछड़े देशों में लगभग 42 प्रतिशत भाग इसी वर्ग में आता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान तथा अन्य यूरोपीय देशों में इस आयु वर्ग में सम्पूर्ण जनसंख्या का 22 प्रतिशत से कम ही भाग आता है। इसके विपरीत, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान तथा अन्य एशियाई देशों में इस आयु वर्ग में 32 से 46 प्रतिशत तक जनसंख्या आती है। अल्प विकसित एवं पिछड़े देशों में इस जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होने के कारण इन देशों में ऊँची जन्म दर व्याप्त रहती है।

(2) प्रौढ़ आयु वर्ग (15-64 वर्ष)- इस आयु वर्ग में सामान्यतया 15 से 64 वर्ष के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इसी कार्यशील जनसंख्या पर देश के विकास की पूरी जिम्मेदारी रहती है। यह आयु वर्ग आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक तथा जनांकिकीय दृष्टि से सर्वाधिक गतिशील होता है। विश्व की लगभग 64 प्रतिशत जनसंख्या इसी आयु वर्ग में है। विकसित देशों में इस आयु वर्ग में सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 67 प्रतिशत भाग रहता है, जबकि विकासशील एवं पिछड़े देशों में सम्पूर्ण जनसंख्या का 55 से 60 प्रतिशत भाग इस आयु वर्ग से आता है।

(3) वृद्ध आयु वर्ग (65 वर्ष से अधिक)- इस आयु वर्ग में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग सम्मिलित किए जाते हैं। विश्व की लगभग 7.0 प्रतिशत जनसंख्या इस आयु वर्ग में आती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न देशों में इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। इसका प्रमुख कारण इन देशों में जन्म दर में आयी कमी तथा जीवन प्रत्याशा में होने वाली वृद्धि है। विकसित देशों में इस आयु वर्ग में लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या आती है। पिछड़े एवं विकासशील देशों में जीवन प्रत्याशा कम होने के कारण इस आयु वर्ग में लोगों की संख्या कम रहती है। पिछड़े एवं विकासशील देशों में इस आयु वर्ग में लगभग 5 प्रतिशत जनसंख्या आती है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट होती है कि विकसित देशों में प्रौढ़ों की जनसंख्या अधिक है जबकि विकासशील देशों में कम आयु वर्ग के शिशुओं एवं बच्चों की भरमार है। अन्य शब्दों में, विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा आश्रितों की संख्या बहुत कम है।

भारतीय जनसंख्या के आयु पिरामिड का विश्लेषण करने से पूर्व प्रसिद्ध संख्या शास्त्री सुन्दर वर्ग द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या वर्गीकरण का अध्ययन अपेक्षित है। जिसके अन्तर्गत जनसंख्या को तीन वर्गों ख्बच्चे (0-14), जवान (15-49) तथा बूढ़े (50 से अधिक), में बाँटकर किया गया है। इस आधार पर सुन्दरवर्ग ने विभिन्न जनसंख्या की प्रवृत्तियों की ओर संकेत किया है:

(अ) प्रगतिशील- प्रगतिशील जनसंख्या के अन्तर्गत 40 प्रतिशत बच्चे, 50 प्रतिशत जवान तथा 10 प्रतिशत बूढ़े पाये जाते हैं।

(ब) स्थिर-यदि जनसंख्या में बच्चे, जवान व बूढ़ों का प्रतिशत क्रमशः 27, 50, 23 हो तो वह स्थिर जनसंख्या कहलायेगी।

(स) अधोगामी- यदि जनसंख्या की आयु संरचना में 20 प्रतिशत बच्चे, 50 प्रतिशत जवान तथा 30 प्रतिशत बूढ़े पाये जाए तो यह अधोगामी जनसंख्या कहलाती है।

(द) अनुक्रमिक - इस जनसंख्या में उक्त अनुपात क्रमशः 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 20 पतिशत पाया जाता है।

(य) अनानुक्रमिक- इस जनसंख्या में उक्त अनुपात 25 प्रतिशत 60 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत पाया जाता है।

सुन्दरवर्ग के वर्गीकरण के अनुसार भारत की जनसंख्या अति प्रगतिशील मानी जानी चाहिये परन्तु अन्य अध्ययनों में भारत की जनसंख्या विकासशील ही मानी जाती है। **जे. वी. गार्नियर** ने अपने अध्ययन में जनसंख्या आयु वर्ग का अध्ययन निम्न तीन वर्गों में किया है:-

(अ) पश्चिमी यूरोपीय तुल्य - जहाँ 20 वर्ष से कम आयु वाली जनसंख्या 30 प्रतिशत से कम तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वालों का प्रतिशत 15 के आस पास हो।

(ब) संयुक्त राज्य अमेरिका तुल्य - इसमें यूरोप के बाहर बसे अधिकांश गोरों की जनसंख्या वाला समूह आता है। इसमें 20 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 30-40 प्रतिशत तथा 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 8 से 12 प्रतिशत के मध्य होना चाहिये।

(स) ब्राजील तुल्य - इसके अन्तर्गत वे देश सम्मिलित हैं, जहाँ बच्चों की संख्या सर्वाधिक तथा बृद्ध व्यक्ति बहुत कम पाये जाते हैं। ब्राजील में 20 वर्ष से कम आयु वालों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत है। लैटिन अमेरिका (अर्जेण्टाईना, युरूग्वे को छोड़कर), अफ्रीका एवं एशिया आदि इसी वर्ग में आते हैं। यहाँ की दशा उच्च जन्मदर तथा निम्न स्वास्थ्य सेवाओं के कारण है।

सारणी 7.2 में विश्व के कुछ देशों की जनसंख्या में आयु संरचना तथा सारणी 7.3 में 65 वर्ष से ऊपर आबादी वाले 5 शीर्ष देशों को दिखाया गया है। जिसमें भारत में बच्चों की संख्या अधिक तथा बूढ़ों की कम संख्या का पता चलता है। इसी तरह 7.3 में 65 वर्ष ओर उससे अधिक उम्र के 5 शीर्ष आबादी वाले देख सकते हैं।

सारणी 7.2

विश्व के कुछ विकसित देशों के साथ भारत की जनसंख्या की आयु संरचना, 1991

देश	15 वर्ष से कम	59 वर्ष से अधिक
भारत	36.0	7.4
पश्चिमी जर्मनी	21.0	19.1
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	29.0	21.1
फ्रांस	24.7	21.4
स्वीडन	35.4	11.0

सारणी 7.3

65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 5 शीर्ष आबादी वाला देश

देश	जनसंख्या प्रतिशत में (2007)
मोनैको	22.60
जापान	20.00
इटली	19.70
जर्मनी	19.40
ग्रीस	19.00
भारत (124 वॉ स्थान)	4.9
विश्व	7.4

7.4 लिंग संरचना (Sex Composition)

किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्री-पुरूष अनुपात को लिंग अनुपात (Sex Ratio) कहते हैं। लिंग-अनुपात को सांख्यिकीय आधार पर $\text{Sex Ratio} = (\frac{M}{F}) \times K$ के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जहाँ

M= पुरूषों की कुल संख्या

F= कुल स्त्रियों की संख्या तथा

K=1000 ।

प्रो. थाम्पसन के अनुसार, लिंग अनुपात प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे पुरूषों की संख्या है। यह पुरूषों की कुल जनसंख्या में स्त्रियों की कुल संख्या के भाग देने तथा इसमें 1000 का गुणा करने से ज्ञात होता है। लिंग अनुपात की तीन दशायें हो सकती हैं:

(अ) स्त्री और पुरूषों की समान संख्या,

(ब) स्त्रियों की अपेक्षा पुरूषों की अधिक संख्या,

(स) पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की अधिक संख्या,

यद्यपि कुछ देशों में लिंग अनुपात $= (\frac{M}{F}) \times K$ के आधार पर प्रति 1000 पुरूषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। लिंगानुपात सम्बन्धी भ्रम को दूर करने के लिये पुरूषों की संख्या प्रति हजार स्त्रियों पर या महिलाओं की संख्या प्रति हजार पुरूषों पर (Males per 1000 females or females per 1000 males) का प्रयोग किया जाता है। लिंग अनुपात से न केवल राष्ट्र की जनसंख्या की बनावट का बोध होता है बल्कि उस राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था का भी बोध होता है। वर्तमान में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या (females per 1000 males) का अधिक प्रचलन है।

7.4.1 विश्व में लिंग अनुपात प्रतिरूप (Pattern of Sex Ratio in the World)

विश्व स्तर पर पुरूषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। परन्तु महाद्वीपीय स्तर पर विभिन्नता पाई जाती है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका व अफ्रीका में स्त्रियों की संख्या पुरूषों से कम है। सर्वाधिक यौन अनुपात पूर्व सोवियत संघ (1137), यूरोप (1051), उत्तरी अमेरिका (1050) तथा अफ्रीका (1017) में है। एशिया महाद्वीप में स्त्रियों की संख्या (960) है। जबकि पूर्व सोवियत रूस में प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या 1137 है। देखें सारणी 7.4।

सारणी 7.4

विश्व में लिंग अनुपात (Females Per Thousand Males)

प्रदेश	लिंग अनुपात	प्रदेश	लिंग अनुपात
विश्व	993		
अफ्रीका	1017	द0प0 एशिया	960
पश्चिमी अफ्रीका	1014	यूरोप	1051
पूर्वी अफ्रीका	1030	पश्चिमी यूरोप	1068
दक्षिण अफ्रीका	1062	दक्षिणी यूरोप	1044
मध्य अफ्रीका	1038	पूर्वी यूरोप	1037
उत्तरी अमेरिका	1050	उत्तरी यूरोप	1050
लैटिन अमेरिका	995	आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड	989
उष्ण कटिबन्धीय दक्षिण अमेरिका	990	मेलानेशिया	895
मध्य अमेरिका	979	माइक्रोनेशिया व पालीनेशिया	1000
एशिया	960	पूर्व सोवियत संघ	1137
पूर्वी एशिया	1011	ओसेनिया	983
दक्षिण एशिया	955	भारत	933

Source:World Development Report, 2004.

विकसित देशों में स्त्रियों की संख्या पुरूषों की तुलना में अधिक है। विश्व के प्रमुख विकसित एवं विकासशील देशों में यौन अनुपात को निम्नांकित सारणी 7.5 में दिखाया गया है:

सारणी 7.5

विश्व के प्रमुख विकसित एवं विकासशील देशों में लिंग अनुपात (Females Per Thousand Males)

देश	लिंग अनुपात	देश	लिंग अनुपात
पूर्व सोवियत संघ	1137	कनाडा	1049
जर्मनी	1071	म्यांमार	1017
इंग्लैण्ड	1057	भारत	933
फ्रांस	1051	पाकिस्तान	904
जापान	1036	हिन्देशिया	932
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	1051	बांग्लादेश	942
आस्ट्रेलिया	1006	श्रीलंका	945

Source:World Development Report 2004.

सारणी 7.6 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 देशों तथा सारणी 7.7 में भारत के पड़ोसी देशों का लिंगानुपात दिखाया गया है। उपर्युक्त सभी सारणियों से स्पष्ट है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों का लिंगानुपात असंतुलित है तथा नेपाल, म्यामार जैसे कुछ देशों को छोडकर शेष देशों में स्त्रियों की संख्या कम है।

सारणी 7.6

सर्वाधिक पुरूष लिंगानुपात वाले 4 देश

देश	लिंगानुपात (प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरूषों की संख्या 2009)
कतर	3070
संयुक्त अरब अमीरात	2050
कुवैत	1470
ओमान	1290

सारणी 7.7

भारत के पड़ोसी: वर्ष 2011 (लिंगानुपात प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियाँ की संख्या)

देश	2001	2011
भारत	933	940
चीन	944	926
पाकिस्तान	938	943
बांग्लादेश	958	978
श्रीलंका	1010	1034
नेपाल	1005	1014
अफगानिस्तान	930	931
भूटान	919	897
म्यांमार	1011	1048

स्त्रोत: भारत की जनगणना 2011

7.5 जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्युदर (Life Expectancy and Infant Mortality)

विकासशील देशों में जीवन प्रत्याशा एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार होने से लोगों की आयु बढ़ने के साथ-साथ जनसंख्या की संरचना बदल रही है। यद्यपि अब भी विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जीवन प्रत्याशा कम तथा शिशु मृत्यु दर अधिक है। देखे सारणी 7.8, सारणी 7.9, सारणी 7.10, सारणी 7.11, सारणी 7.12 तथा सारणी 7.13।

सारणी 7.8 विश्व में जीवन प्रत्याशा एवं शिशु मृत्युदर, 1960-2025

वर्ष	जीवन प्रत्याशा	शिशु मृत्यु-दर
1960	49.6	136
1974	56.3	95
1987	60.9	73
1998 (अनुमानित)	64.2	55
2010 (अनुमानित)	67.3	43
2022 (अनुमानित)	70.3	36
2025 (अनुमानित)	71.3	27

Source: Estimated from United Nations) 1986.

सारणी 7.9 कम तथा अधिक विकसित क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा, 1958-2025

वर्ष	जीवन प्रत्याशा	शिशु मृत्युदर
1958	44.2	172
1975	54.2	94
1990	61.2	68
2002 (अनुमानित)	63.8	57
2014 (अनुमानित)	67.1	43
2025 (अनुमानित)	70.2	30
अधिक विकसित राष्ट्र क्षेत्र		
1965	71.5	28
2025 (अनुमानित)	78.4	7

सारणी 7.10 शीर्ष 5 पुरूष जीवन प्रत्याशा वाले देश

देश	औसत आयु वर्ष में
आइसलैण्ड	80.5
स्वीटजरलैण्ड	79.8
हांगकांग	79.7
जापान/आस्ट्रेलिया	79.6
स्वीडन	79.1
विश्व	67

स्त्रोत: ICPD: 2010

सारणी 7.11

शीर्ष 5 महिला जीवन प्रत्याशा वाले देश

देश	औसत आयु वर्ष में
जापान	86.6
हांगकांग	85.4
फ्रांस	85.0
स्वीटजरलैण्ड/सिंगापुर	84.4
आस्ट्रेलिया	84.1
विश्व	71.0

स्त्रोत: ICPD: 2010

सारणी 7.12

न्यूनतम पुरूष जीवन प्रत्याशा वाले शीर्ष देश

देश	औसत आयु वर्ष में
अफगानिस्तान/जिम्बाम्बे	44.7
अंगोला	46.1
कांगो प्रजा. गण.	46.4
जाम्बिया	46.7
स्वाजीलैण्ड	46.8
सियरा लिओन	46.9

स्त्रोत: ICPD: 2010

सारणी 7.13 न्यूनतम महिला जीवन प्रत्याशा वाले शीर्ष देश

देश	औसत आयु वर्ष में
अफगानिस्तान	44.6
लेसोथो	45.9
स्वाजीलैण्ड	46.0
जिम्बाम्बे	46.7
जाम्बिया	47.8

स्त्रोत: ICPD: 2010

लिंग अनुपात का ज्ञान - लिंगानुपात का ज्ञान राष्ट्र विशेष के भावी एवं स्वस्थ जनसंख्या कों इंगित करता है।

जीवन प्रत्याशा का ज्ञान - जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर का ज्ञान जनसंख्या वृद्धि तथा स्वस्थ्य जीवन का बोध कराता है।

7.6 जनसंख्या पिरामिड (Population Pyramid)

जनसंख्या पिरामिड के अन्तर्गत आयु, लिंग एवं जीवन प्रत्याशा का रेखीय माडल बनाया जाता है। जनसंख्या पिरामिड वस्तुतः आयु एवं लिंग का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए भारतीय जनसंख्या पिरामिड को चित्र संख्या 7.1 तथा अमेरिका की जनसंख्या की आयु पिरामिड को चित्र संख्या 7.2 से दिखाया जा सकता है।

चित्र - 7.1

भारतीय जनसंख्या का पिरामिड

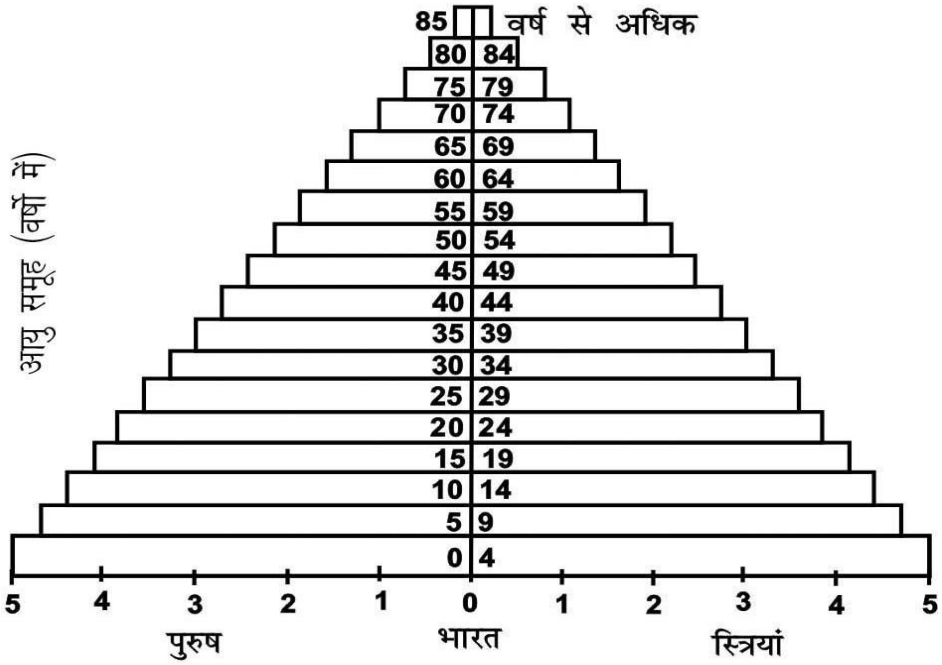

चित्र - 7.2

अमेरिका में कुल जनसंख्या का वितरण पिरामिड

7.7 आयु-संरचना एवं लिंग अनुपात का महत्व (Importance of Age composition and Sex Ratio)

1. **आश्रित अनुपात का ज्ञान**- सामान्यतया 15 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या आश्रित मानी जाती है। देश की श्रम शक्ति में केवल उसी जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष से कम होती है। उस जनसंख्या को आदर्श माना जाता है, जिसमें आश्रितों का अनुपात न्यूनतम होता है।
2. **उपभोग के स्वरूप का निर्धारण** - जनसंख्या की आयु-संरचना से सम्बन्धित क्षेत्र के उपभोग के स्वरूप की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिस समाज में शिशुओं की संख्या अधिक होगी, उस समाज में बेबी फूड, दूध, दवाईयों तथा भोजन पर अधिक व्यय होगा। जबकि युवा समाज में वस्त्र, शिक्षा, विवाह, फैशन, यातायात अन्य पर अधिक व्यय होगा।
3. **श्रम शक्ति की औसत आयु का ज्ञान**- किसी देश की जनसंख्या की बनावट से उस देश की श्रम शक्ति की औसत आयु (Average age of labour force) का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। **प्रो. डेविड** के अनुसार ***"नौजवान जनसंख्या अधिक लचीली होती है तथा नयी प्रविधि-सीखने को अधिक उत्सुक रहती है जबकि वरिष्ठ जनसंख्या अधिक जिम्मेदार तथा अनुभवी होती है। (A younger lobour may have the advantage that its worker will be more flexible and able to learn new skills more readily. On the other hand an older labour force may be more responsible and experienced - David M. Society and Population)"***
4. **वैचारिक महत्व** - जिस समाज में युवकों की संख्या अधिक होगी, वहाँ की विचारधारा अधिक प्रगतिशील होने के साथ-साथ समाज में होने वाले समाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करने की अधिक क्षमता होगी। सामाजिक परिवर्तनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। जबकि अधिक वृद्धों वाले समाज में रूढ़िवादी तथा परम्परावादी विचारों का अधिक महत्व होगा।
5. **विवाह पद्धति पर प्रभाव**-अपेक्षाकृत युवाओं वाले समाज में प्रेमविवाह, तलाक, पृथक्करण, अलगाव, पुनर्विवाह, आदि की प्रवृत्ति अधिक दिखायी पड़ती है।
6. **मृत्यु दर की स्थिति का ज्ञान** - अपेक्षाकृत युवाओं वाले समाज में मृत्युदर कम होती है। जबकि अधिक बच्चों तथा वृद्धों वाले समाज में मृत्युदर अधिक होती है।

7.8 अभ्यास प्रश्न(Practice Questions)

निम्न पर टिप्पणी लिखें।

(अ) विश्व आयु संरचना

(ब) लिंग संरचना

(स) विश्व जनसंख्या का लिंग अनुपात प्रतिरूप

(द) जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. किसी भी देश की जनसंख्या की आयु संरचना किस पर निर्भर करती हैं?

A. प्रजनन B. मृत्यु दर C. प्रवास D. उपरोक्त सभी

2. मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, विश्व की कामकाजी आबादी लगभग कितनी प्रतिशत थी?

A. 60 B. 64 C. 68 D. 70

3. मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत लोग 0-14 वर्ष आयु वर्ग के अंतर्गत आते थे?

A. 28.50 B. 30.50 C. 32 D. 34

4. मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, विश्व की जनसंख्या में वृद्ध लोगों (65 वर्ष और उससे अधिक) की जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत थी?

A. 4 B. 5 C. 7 D. 12

7.9 (Summary)

इस इकाई खण्ड 7 के प्रस्तावना में विकसित और विकासशील देशों में आयु एवं लिंग संरचना के साथ जनसंख्या पिरामिड के सामान्य अर्थ को समझाया गया है। तत्पश्चात् इकाई के विभिन्न उद्देश्यों को बताया गया है। आयु संरचना को स्पष्ट करते हुए विश्व के प्रमुख देशों की आयु संरचना सारणी 7.1 का अध्ययन किया गया है। जिसके अन्तर्गत पाया गया है कि विश्व के विकसित देशों में आश्रितों की संख्या कम तथा कार्यकारी जनसंख्या अधिक है। जबकि विकासशील देशों में आश्रितों की संख्या अधिक तथा कार्यशील जनसंख्या कम है। दूसरे शब्दों में 14 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक वृद्धों की संख्या का प्रतिशत योग विकासशील देशों में अधिक होता है तथा 15 से 64 वर्ष के बीच कार्यकारी जनसंख्या का प्रतिशत कम होता है। जबकि विकसित देशों में कार्यकारी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होने से उनके विकास की संभावना बनी रहती है। अल्प विकासशील देशों में कार्यकारी जनसंख्या का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक कम होने से उनका विकास दर प्रभावित होता है तथा उनकी आर्थिक वृद्धि दर कम होती है। इसी क्रम में सुन्दरवर्ग तथा जे.पी. गार्नियर के अध्ययनों को स्पष्ट किया गया है। सारणी 7.2 में विश्व के कुछ विकसित देशों के साथ भारत की जनसंख्या की आयु संरचना की तुलना की गयी है तथा पाया गया है कि भारत में 15 वर्ष से कम तथा 59 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का भार विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है। इसी तरह सारणी 7.3 में दिखाया गया है कि बढ़ते वृद्धों की आबादी वाले देशों में भारत का स्थान विश्व में 124वाँ है।

लिंग संरचना के अन्तर्गत लिंग अनुपात को परिभाषित करते हुए उनकी दशाओं का वर्णन किया गया है तथा पाया गया है कि वे दशायें सर्वोत्तम हैं जिन देशों में लिंग अनुपात समान हैं। इस हेतु लिंग अनुपात का विश्व प्रतिरूप सारणी 7.4 में दिखाया गया है तथा पाया गया है कि विकसित क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरूषों की अपेक्षाकृत अधिक है जबकि इसके विपरीत कम विकसित क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। जिसे सारणी 7.5 द्वारा विश्व के प्रमुख विकसित तथा विकासशील देशों के आधार पर तथा सारणी 7.6 में सर्वाधिक

लिंगानुपात तथा सारणी 7.7 में भारत के पड़ोसी देशों के लिंगानुपात को दिखाया गया है। सारणी 7.8 तथा सारणी 7.9 में जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर को दिखाते हुए सारणी 7.10 में शीर्ष जीवन प्रत्याशा तथा सारणी 7.11 में शीर्ष महिला तथा सारणी 7.12 में शीर्ष पुरूष तथा सारणी 7.13 में न्यूनतम महिला जीवन प्रत्याशा वाले देशों को दिखाया गया है। तत्पश्चात् जनसंख्या पिरामिड का वर्णन करते हुए भारतीय जनसंख्या का पिरामिड बनाया गया है।

इकाई के अन्त में आयु-संरचना एवं लिंग अनुपात के महत्व को समझाया गया है। जिसमें यह स्पष्ट है कि इकाई का अध्ययन आश्रितों के अनुपात के ज्ञान के साथ-साथ उपभोग के स्वरूप का निर्धारण, श्रम शक्ति की औसत आयु, विवाह के स्वरूप, मृत्यु दर की स्थिति, लिंग अनुपात, जीवन प्रत्याशा, जनसंख्या पिरामिड आदि का विवरण प्राप्त कर जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन के लक्ष्य का विश्लेषण द्वारा समस्या के समाधान का आधार पाया जा सकता है।

7.10 शब्दावली (Glossary)

- प्रतिमान - Pattern
- श्रम शक्ति - 15 से 65 वर्ष के बीच की आयु वाली जनसंख्या
- आयु संरचना – Age Composition
- लिंग अनुपात - Sex Ratio=(M/F)*K (Female per 1000 Male)
- जीवन प्रत्याशा –Life Expectancy

7.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. D 2. B 3. A 4. C

7.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- डॉ. मिश्रा, जे. पी., जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा।
- डॉ. बघेल, डी. एस., जनांकिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
- डॉ. पन्त, जीवन चन्द्र, जनांकिकी, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
- अशोक कुमार, जनसंख्या, एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रयाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय*, भारत सरकार
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग*, भारत सरकार
- *भारतः 2013*, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

7.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री(Useful/Helpful Text)

- A.M. Carr Saunders : World Population, 1936, P.42
- Walter F. Willcox : Studies in American Demography, 1940 P. 40
- M.K. Bonnett: the world, 1954 3
- Ross, John, A (1982): International Encyclopedia of Population The Free Press. Macmillon Publishing co.New York.
- U.N. Determinantes and Consequences of Population Trends, 1953, P. 61
- UNFPA, The State of World Population, 1996
- United Nations Population Division , Word Population 2006.
- World Bank Atlas 1996
- Estimated from United Nations, 1986
- U.N. Demographic Year Book, 1950
- Selected World Demographic Inedicators by Region and Country or Area. 1970-75, Prepared by United Nations Population Division .

7.14 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. विश्व की आुय संरचना की विशेषतायें बताइयें।
2. विश्व में लिंग संरचना के प्रतिरूपों को बताइये।
3. विश्व में आयु एवं लिंग संरचना के महत्व तथा उदद्श्यों को स्पष्ट कीजिये।

इकाई 8 - जीवन गुणवत्ता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, गरीबी सूचकांक एवं लिंग समानता

(Physical Quality of Life Index (PQLI), Human Development Index and Gender Equality)

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषायें

8.3.1 संवृद्धि , विकास एवं प्रगति

8.3.2 सतत् (धारणीय या प्रतिपालनीय) विकास की अवधारणा

8.3.3 धारणीय अथवा टिकाऊ विकास की शर्तें

8.4 आर्थिक विकास की माप एवं अभिसूचक

8.4.1 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार

8.4.2 अधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार

8.5 जीवन गुणवत्ता सूचकांक या जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक

8.6 मानव विकास सूचकांक

8.7 मानव निर्धनता सूचकांक

8.8 लिंग-सम्बन्धित विकास

8.9 आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ मापदण्ड या सूचक

8.10 अभ्यास प्रश्न

8.11 सारांश

8.12 शब्दावली

8.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

8.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

8.15 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

8.16 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

इस इकाई में जनसंख्या से सम्बन्धित विकास की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे।

विकास का सामान्य अर्थ **'आर्थिक विकास'** से लिया जाता है। सरल शब्दों में - ***'आर्थिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन-साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है।'*** सूचकांक एक सांख्यिकीय मापक के रूप में दो विभिन्न परिस्थितियों/स्थानों/समयों के बीच एक निश्चित आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रविधि होती है।

इस अर्थ में विकास से सम्बन्धित शब्दावलियों संवृद्धि , प्रगति, विकास तथा सतत् विकास के अर्थों को समझते हुए जनसंख्या से सम्बन्धित जीवन गुणवत्ता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, गरीबी सूचकांक एवं लिंग समानता को स्पष्ट करेंगे। इन सूचकांकों को निर्धारित करने वाले कारकों का अध्ययन कर जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ाने में इनकी भूमिका देखेंगे। विशेष रूप से आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विभिन्न मापकों में सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता-अभिसूचकों के सामाजिक सूचकों का अध्ययन; भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक के विभिन्न अवयवों-जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर तथा शिक्षा; मानव विकास सूचकांक के विभिन्न अवयवों - दीर्घायु, शैक्षणिक स्तर तथा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को समझेंगे। साथ ही लिंग सम्बन्धित विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक को समझते हुए आर्थिक विकास के सर्वश्रेष्ठ मापक को भी जानने का प्रयास करेंगे। अन्त में विकास के सर्वश्रेष्ठ मापक पर विचार करेंगे।

8.2 उद्देश्य (Objectives)

- ✓ आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न शब्दों - संवृद्धि , विकास, प्रगति तथा सतत् विकास के अर्थों को समझना।
- ✓ आर्थिक विकास की माप के प्रतिष्ठित तथा आधुनिक विचारों को समझना।
- ✓ आर्थिक विकास के विभिन्न आधुनिक मापों से परिचित होना।
- ✓ सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता अभिसूचक के विभिन्न सामाजिक सूचकों तथा आर्थिक कल्याण के सम्बन्धों को समझना।
- ✓ जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक तथा आर्थिक विकास के बीच सम्बन्धों को समझना।
- ✓ मानव विकास सूचकांक तथा आर्थिक विकास के बीच सम्बन्धों को समझना तथा इनके बीच गणितीय सम्बन्ध स्थापित करना।
- ✓ लिंग-सम्बन्धित विकास सूचकांक एवं आर्थिक विकास में सम्बन्ध स्थापित करना।
- ✓ मानव निर्धनता सूचकांक एवं आर्थिक विकास के सम्बन्धों को समझना।
- ✓ आर्थिक विकास के सर्वश्रेष्ठ मापक को जानना।

8.3 आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषायें (Meaning and Definition of Economic Development)

आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है, जिसकी सार्वभौमिक स्वीकृति वाली परिभाषा देना सहज नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा विकास के भिन्न-भिन्न आधारों को दृष्टि में रखकर देने का प्रयास किया है। पहली श्रेणी में उन विद्वानों को रखा जाता है जो राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन एवं लगातार वृद्धि को आर्थिक विकास का प्रतीक मानते हैं। इनमें मुख्य रूप से मायर एवं वाल्डविन, पाल एलबर्ट, यंगसन एवं साइमन कुजनेट्स प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणी में वे विचारक हैं जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में की जाने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास की संज्ञा देते हैं। इनमें से प्रमुख रूप से **डॉ. बेन्जामिन हिगिन्स, एच.एफ.एफ. विलियमसन, जैकब वाइनर, क्राउज, रोस्टोव** आदि लोग सम्मिलित हैं। तीसरी श्रेणी में उन विद्वानों को रखा जाता है, जो आर्थिक विकास की संकल्पना को अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं और वे जन सामान्य के कल्याण में वृद्धि को ही आर्थिक विकास का प्रतीक मानते हैं। इन विद्वानों में प्रमुख रूप से **डॉ. ब्राइट सिंह**, **ओकेन** एव **रिचर्डसन** तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी गयी परिभाषायें सम्मिलित की जाती हैं।

उपर्युक्त विभिन्न संकल्पनाओं पर आधारित आर्थिक विकास की परिभाषाओं में से कुछ परिभाषायें निम्नवत् हैं:

मेयर एवं वाल्डविन (Meier and Baldwin) के अनुसार, ***"आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। (Economic development is a process where by an economy's real national income increases over a log period of time.)"***

प्रो. रोस्टोव (W.W.Rostow) के अनुसार, ***"आर्थिक विकास एक तरफ पँूजी व कार्यशील शक्ति में वृद्धि की दरों के मध्य और दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि की दर के मध्य एक ऐसा सम्बन्ध है जिससे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। (Economic Growth is a relation between the rates of increase in the capial and the working force on the one hand and increase in population on the other, so that per capita output is rising.)"***

डॉ. ब्राइट सिंह (Dr. Bright Singh) के अनुसार, ***"यह (आर्थिक विकास) एक बहुआयामी घटना है, जिसके अन्तर्गत केवल मौद्रिक आय में होने वाली वृद्धि ही शामिल नहीं होती बल्कि वास्तविक आदतें, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अधिक आराम के साथ-साथ एक पूर्ण एवं सुखी जीवन का निर्माण करने वाले समस्त सामाजिक एवं आर्थिक सुधार भी सम्मिलित रहते हैं।(It is the multidimensional phenomenon, it involves not only increase in money incomes, but also money improvement in real habits, education, public health, greater leisure, and infact all trhe social and economic circumstances that make foe a fuller and happier life.)"***

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ***''विकास, मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं, बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी सम्बन्धित होना चाहिये। इस तरह विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत् तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होना चाहिये।''***

इन सभी तीनों श्रेणियों के विचारों की मूल धारणाओं को मिलाकर आर्थिक विकास की एक उपयुक्त परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है:

''आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत देश में उपलब्ध समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है, आर्थिक विषमता में कमी आती है, सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में बढ़ोत्तरी होती है।''

8.3.1 संवृद्धि , विकास एवं प्रगति (Growth,Development and Progress)

संवृद्धि, विकास एवं प्रगति तीनों मापकों को कभी-कभी सामानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है यद्यपि अर्थशास्त्र में इनके अर्थों में अन्तर पाया जाता है।

अर्थव्यवस्था के भौतिक साधनों में स्थिर वृद्धि (Steady Increase) को संवृद्धि (Growth), भौतिक एवं अभौतिक साधनों में ढाँचागत वृद्धि (Structural increase) को विकास (Development) तथा वांछित लक्ष्य की ओर वर्द्धमान परिवर्तन (Increasing change to achieve target) को प्रगति अथवा उन्नति (progress) कहेंगे। यहाँ संवृद्धि में स्थिर वृद्धि का अर्थ है **'सम-रस वृद्धि'** (Proportional increase) अर्थात् वह वृद्धि जो बेढँगा न हो। यह वृद्धि एक आयामी अथवा एक दिशागत् होता है। विकास के अन्तर्गत होने वाली वृद्धि एक दिशागत् न होकर अनेक दिशागत् अथवा बहुआयामी होता है। किन्तु प्रगति के अन्तर्गत होने वाली वृद्धि **'मनोवांछित' (Warrented)** तथा **'सप्रयास' (Effortful)** होती है। यह वृद्धि एक दिशागत् (एक आयामी) अथवा अनेक दिशागत (बहु आयामी) अथवा दोनों हो सकती है। भौतिक प्रगति, नैतिक प्रगति, अध्यात्मिक उन्नति आदि एक आयामी प्रगति के उदाहरण हैं। आर्थिक प्रगति बहुआयामी प्रगति का उदाहरण है।

सारांश यह है कि आर्थिक संवृद्धि एक आयामी (One dimensional) अवधारणा है तो आर्थिक विकास एवं आर्थिक प्रगति बहुआयामी (Multidimensional) अवधारणाएं है। अतः आर्थिक संवृद्धि का माप संभव है किन्तु आर्थिक विकास एवं आर्थिक प्रगति को मापा नहीं जा सकता।

सक्षेप में,

संवृद्धि	**विकास**	**प्रगति अथवा उन्नति**
1. अर्थ व्यवस्था में केवल भौतिक (मात्रात्मक) वृद्धि	'भौतिक (मात्रात्मक) एवं अभौतिक (गुणात्मक) वृद्धि	भौतिक (मात्रात्मक) एवं अभौतिक (गुणात्मक) वृद्धि
2. 'स्थिर' एवं 'क्रमिक' वृद्धि	ढांचागत वृद्धि	'सप्रयास' एवं 'वांछित' वृद्धि
3. प्रमुख आधार - 'आय'	प्रमुख आधार 'पूँजी'	प्रमुख आधार आय एवं पूँजी दोनों
4. एक आयामी अवधारणा	बहुआयामी अवधारणा	बहुआयामी अवधारणा
5. मापनीय	माप संभव नहीं	माप संभव नहीं
6. प्रायः विकसित देशों से सम्बन्धित	प्रायः अल्पविकसित देशों से सम्बन्धित	अल्पविकसित एवं विकसित दोनों प्रकार के देशों से सम्बन्धित

निष्कर्ष:- 'संवृद्धि ' विकास की केन्द्रीय समस्या है, जिसका 'सप्रयास' हल 'प्रगति' कहलाएगा।

यद्यपि आर्थिक संवृद्धि , आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति (अथवा आर्थिक उन्नति) में भेद करना सम्भव है किन्तु इस प्रकार का भेद व्यावहारिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। व्यावहारिक जीवन में इन शब्दों अथवा अवधारणाओं का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। **पाल बरान (Paul Baran)** के अनुसार ***"विकास और संवृद्धि के विचार किसी पुरानी और बेकार चीज से किसी नयी स्थिति की ओर परिवर्तन को बतलाते हैं। (The mere notions of development and growth suggest a transition to something that is new from something that is old that has outlived itself-paul baran-the political econo,my of growth)"***

8.3.2 सतत् (धारणीय या प्रतिपालनीय) विकास की अवधारणा (Concept of Sustainable Development)

निरन्तर विकास मानव की स्वाभाविक प्रकृति है तथा पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण विकास को रोका नहीं जा सकता है, तो पर्यावरण ह्रास के कारण समस्त जीव जगत पर बढ़ते संकट की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। अतः पर्यावरण को बचाते हुए सतत् विकास की अवधारणा विकसित हुई। इसे प्रतिपालनीय विकास की अवधारणा भी कहते हैं।

पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आयोग के ब्रंटलैण्ड प्रतिवेदन में दी गई स्थिर अथवा टिकाऊ अथवा धारणीय विकास की परिभाषा इस प्रकार है – ***"धारणीय अथवा टिकाऊ विकास वह है, जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को क्षति पहुँचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे।"*** इस तरह टिकाऊ विकास एक सर्वग्राह्य (universal) अवधारणा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों का समावेश है।

विकास में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को सम्मिलित करके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी किया जा सकता है तथा पारिस्थितिकी संकट से बचा भी जा सकता है। सन्तुलित विकास, समन्वित विकास तथा सतत् विकास इसके विभिन्न पक्ष हैं। सतत् विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से हैं, जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना जीवन की गुणवत्ता जारी रख सके। विकास को मात्र आर्थिक उपादन से न जोड़कर उसके सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए। पारिस्थितिक तन्त्र के अनुरूप विकास हेतु पर्यावरण को कम से कम हानि पहुँचाने वाली प्रौद्योगिकी का विकास, जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का नियोजित व नियमित उपभोग, संसाधन संरक्षण आदि उपायों पर अमल करना होगा। चूँकि हमारा अस्तित्व पर्यावरण के साथ जुड़ा है अतः पर्यावरण को बचाते हुए सतत् विकास की अवधारणा को विकसित करना समयानुकूल होगा।

8.3.3 धारणीय अथवा टिकाऊ विकास की शर्तें –

टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं:

1. ऐसी राजनीतिक प्रणाली जिसमें निर्णय की प्रक्रिया में नागरिक कारगर रूप से भाग लेते हों।
2. ऐसी आर्थिक प्रणाली, जो अपने परिश्रम से और टिकाऊ तौर पर अधिशेष और प्रौद्योगिकी ज्ञान पैदा करती हो।
3. ऐसी सामाजिक प्रणाली, जिसमें गैर-सामंजस्यपूर्ण विकास से उठने वाले तनावों को सुलझाने की व्यवस्था हो।
4. ऐसी उत्पादन प्रणाली, जो विकास की पारिस्थितिकीय आधार को सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य मानती हो।
5. ऐसी प्रौद्योगिकी प्रणाली, जो निरन्तर नये सुझाव खोज सके।
6. ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली, जो व्यापार व वित्त के टिकाऊ तौर-तरीकों को बढ़ावा दे।
7. ऐसी प्रशासनिक प्रणाली जो लचीली हो और जिसमें उसके भूलों को सुधारने की क्षमता हो।

8.4 आर्थिक विकास की माप एवं अभिसूचक(Measurement and Indicator of Economic Development)

आर्थिक विकास एक **'सापेक्षिक'** शब्द है। इसका सम्बन्ध एक समय विशेष से न होकर दीर्घकालीन परिवर्तनों से हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास का एक निश्चित मापदण्ड देना अत्यन्त कठिन है। यही कारण है कि आर्थिक विकास के मापदण्ड के विषय में अर्थशास्त्रियों के विचारों में विभिन्नता रही है। आर्थिक विकास के मापदण्ड के विषय में प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इसके सम्बन्ध में वाणिज्यवादियों से लेकर आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार इस प्रकार हैं:

सारणी 8.1 आर्थिक विकास के मापदण्ड

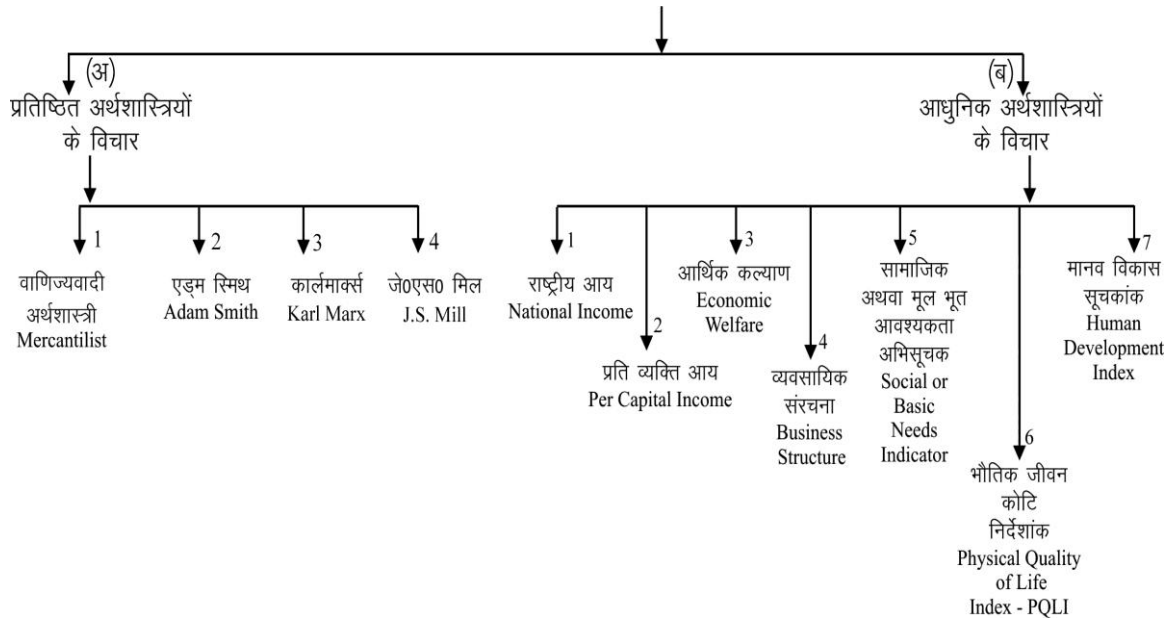

8.4.1 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार

वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री विकास के मापदण्ड को विदेशी व्यापार तथा सोना-चाँदी की उपलब्धता से; एडम स्मिथ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से; मार्क्स अधिकतम सामाजिक कल्याण से जबकि मिल सहकारिता के विकास से मापते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाये गये मापदण्ड एकाकी थे, यद्यपि उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था।

8.4.2 अधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार (Views of Modern Economists)

प्राचीन अर्थशास्त्रियों की ही भांति आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी आर्थिक विकास का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं बताया है। फिर भी आधुनिक विकासवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक विकास के निम्नलिखित मापदण्ड प्रस्तुत किए जाते हैं , जिसे चित्र 8.1 में दिखाया गया है:

चित्र - 8.1

राष्ट्रीय आय एवं समय में संतुलन का रेखाचित्र

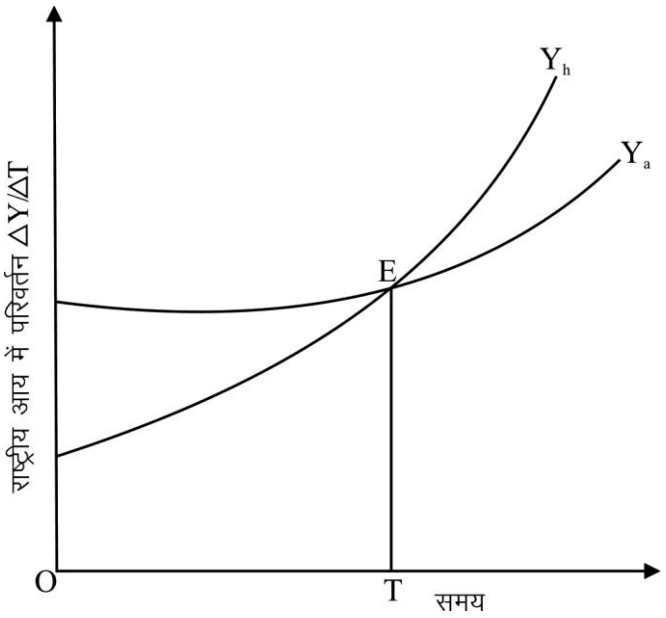

1. **वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि मापदण्ड -** इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं – प्रो. मायर एवं बाल्डविन, कुजनेट्स, यंगसन तथा मीड आदि। इन विकासवादी अर्थशास्त्रियों ने किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को उस देश के आर्थिक विकास का सूचक बताया है। अन्य शब्दों में, यदि किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरन्तर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तो कहा जाएगा कि वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। यह विचारधारा एक महत्वपूर्ण मापदण्ड के रूप में स्वीकार की जाती है।

   इस कथन को संलग्नक चित्र 8.1 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र में क्षैतिज अक्ष पर समय को तथा अनुलम्ब अक्ष पर समय के साथ राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है।

रेखा Y_a देश A में राष्ट्रीय आय के स्तर को तथा Y_b देश B में राष्ट्रीय आय के स्तर को प्रदर्शित करती है समय T तक देश A की राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश B की अपेक्षा अधिक है। परन्तु दीर्घकालीन विकास परियोजनाओं के प्रारम्भ होने से देश B की राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि होती है। जैसा कि उपर्युक्त चित्र में प्रदर्शित है, बिन्दु E के पश्चात $Y_b > Y_a$ हो जाता है। इस सन्दर्भ में मॉयर एवं बाल्डविन का कथन है कि ***"आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है।"***

2. **प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मापदण्ड -** इस विचार के समर्थकों का मत है कि राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास का सही मापदण्ड नहीं है बल्कि देश में प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को उस देश के आर्थिक विकास के अभिसूचक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी भी देश के सम्मुख सबसे प्रमुख समस्या होती है अपने देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और जीवन स्तर का प्रति व्यक्ति आय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। **प्रो. पॉल बरन** के अनुसार, ***"आर्थिक वृद्धि की परिभाषा भौतिक वस्तुओं की एक निश्चित काल में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि के रूप में की जानी चाहिए।"*** इस तरह प्रति व्यक्ति आय विचारधारा आर्थिक विकास मापने का एक अच्छा अभिसूचक है।
3. **आर्थिक कल्याण वृद्धि मापदण्ड -** यह मापदण्ड राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के स्थान पर लोगों के आर्थिक कल्याण या जीवन स्तर में वृद्धि को आर्थिक विकास की कसौटी के रूप में स्वीकार करता है। इसके अन्तर्गत मुख्यतः देश में बढ़ता हुआ उपभोग व जीवन स्तर ही आर्थिक विकास का सूचक है।
4. **अर्थव्यवस्था में व्यवसायिक संरचना का स्वरूप** - किसी देश की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न व्यवसायों में लगा होना है। आर्थिक विकास एवं जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण के बीच धनात्मक सम्बन्ध होता है।
5. **सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता अभिसूचक** (Social or Basic Needs Indicator)- विकास से संबद्ध आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि आर्थिक विकास **'मानव विकास'** अथवा समुदाय के कल्याण से सम्बन्धित होता है। मानव विकास अथवा समुदाय का कल्याण शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खुराक, आवास आदि के रूप में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं (Basic Human Needs) पर निर्भर करती है। अतः मुख्य उद्देश्य गरीबों को मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं प्रदान करने उनकी उत्पादकता बढ़ाना और गरीबी दूर करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष प्रबंध करने से मानव संसाधन (Human Resource) का विकास होता है, उसकी उत्पादकता उच्च स्तर की हो जाती है, जिससे गरीबी पर थोड़े संसाधनों द्वारा और थोड़े समय में प्रभाव पड़ता है। ऐसा विशेष तौर पर वहाँ होता है, जहाँ ग्रामीण भूमिहीन अथवा शहरी गरीब पाये जाते हैं तथा जिनके पास काम करने की इच्छा और तत्परता के सिवाय भौतिक संपत्ति नगण्य होती है।विकास के सूचक के रूप में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय से असंतुष्ट होकर 1970 के दशक से आर्थिक विचारकों ने विकास प्रक्रिया की गुणवत्ता की ओर ध्यान देते हुए **'जीवन प्रत्याशा'**, शिशु मृत्यु दर, **'साक्षरता दर'** जैसे सामाजिक अभिसूचकों (Social Indicators) पर ध्यान देना आरम्भ किया है। इन अभिसूचकों की

विशेषता यह है कि वे लक्ष्यों से जुड़े हैं। और इनके अनुसार मानव विकास (Human Development) आर्थिक विकास इन लक्ष्यों का प्राप्त करने का एक साधन है।

इस कूटनीति के अन्तर्गत मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रबंध के अतिरिक्त रोजगार के सुअवसरों, पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल देना और उचित कीमतों एवं दक्ष वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं को गरीब वर्गों तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

हिक्स और स्ट्रीटन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए छह सामाजिक सूचकों पर विचार करते हैं:

मूल आवश्यकता	**सूचक**
स्वास्थ्य	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा
शिक्षा	प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार दाखिले द्वारा साक्षरता की दर
खाद्य	प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति
जल आपूर्ति	शिशु मृत्युदर तथा पीने योग्य पानी तक कितने प्रतिशत जनसंख्या की पहुँच
स्वच्छता	शिशु मृत्युदर तथा स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत
आवास	कोई नहीं

इस प्रकार इस कूटनीति में आय वृद्धि के साथ-साथ गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व शिक्षा तथा वितरण विषमताओं को दूर करने के उद्देश्यों को यथोचित स्थान दिया गया है। अनेक अर्द्धविकसित देशों के हाल के अनुभवों व अध्ययनों की पृष्ठभूमि में इस कसौटी को न्याय संगत ठहराया गया है।

फाई रैनिस तथा **स्टुअर्ट** ने नौ देशों का अध्ययन किया जिसके अनुसार उन्होंने पाया कि,

1. ताईवान, दक्षिण कोरिया तथा इंडोनेशिया में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ औसत से अधिक आर्थिक विकास हुआ है।
2. ब्राजील ने मात्र न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया तथा औसत से अधिक आर्थिक विकास किया।
3. सोमाली, क्यूबा, मिस्र तथा श्रीलंका ने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत अच्छी तरह से की लेकिन आर्थिक विकास औसत से कम था।
4. केवल एक देश मालदीव ने मात्र न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के प्रावधान के साथ औसत से कम आर्थिक विकास प्राप्त किया।

उपुर्यक्त अध्ययन के अनुसार **फाई, रैनिस तथा स्टुअर्ट** इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आर्थिक विकास और मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति के बीच कोई विवाद नहीं है। अर्थात् विकासशील देशों की आर्थिक विकास की दर मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति द्वारा बढ़ी है। जिसे हम रेखाचित्र 8.2 की सहायता से भी यह स्पष्ट कर सकते हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति, कुल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, व आर्थिक कल्याण के मापदण्ड से श्रेष्ठ है।

चित्र - 8.2

आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति उपभोग

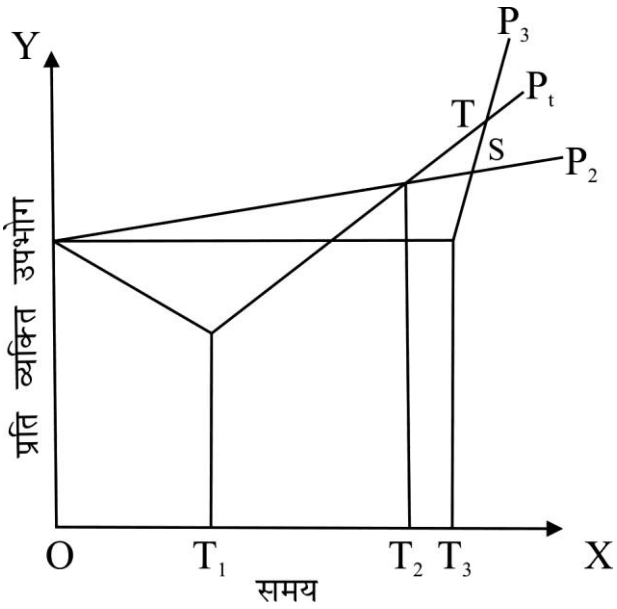

OX अक्ष पर समयावधि और OY पर प्रति व्यक्ति उपभोग (विकास दर) दर्शाया गया है।

P_1, P_2, P_3 तीन विकास पक्ष हैं। P_1 पक्ष का संबंध कुल राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की कूटनीति से है। इस पथ में शुरू में गरीबों में प्रति व्यक्ति उपभोग समय T_1 तक घटता है क्योंकि तेजी से औद्योगीकरण से गरीबी बेरोजगारी, असमानता बढ़ती है। परन्तु जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का लाभ गरीबों तक **'रिस कर'** पहुँचता है तो उनके रोजगार तथा आय में वृद्धि होती है और समय T_1 के बाद प्रति व्यक्ति उपभोग में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है।

पथ P_2का संबंध आर्थिक कल्याण की धारणा से है जो गरीबों के प्रति व्यक्ति उपभोग की धीमी वृद्धि को दर्शाता है। वह पथ समय T_2 से पथ P_1 से पीछे रहता है।

पथ P_3 मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति से संबंधित हैं, जिसमें शुरू में गरीबों में उपभोग के मूलभूत न्यूनतम वेतनमान स्तर को प्राप्त करने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है जो समय T_3 तक आर्थिक कल्याण तथा प्रति व्यक्ति आय के उपभोग स्तरों से कम रहता है। परन्तु दीर्घकाल में जब गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं के पूरा होने के कारण उनकी उत्पादकता तथा आय के स्तरों में वृद्धि हो जाती है तो समय T_3 से आगे आर्थिक विकास तीव्र गति से होने लगता है।

इस प्रकार P_3 से पहले P_2 को Rबिन्दु पर पीछे छोड़ देता है तथा बाद में S बिन्दु पर पथ P_1 से ऊपर चला जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति या मापदण्ड कुल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय व आर्थिक कल्याण की आर्थिक विकास की कूटनीति से श्रेष्ठ है।

6. **भौतिक जीवन कोटि निर्देशांक (Physical Quality of Life Index- PQLI) - मौरिस डी. मौरिस** (Mooris D. Mooris) ने **'जीवन प्रत्याशा'**, **'साक्षरता दर'** तथा **'शिशु दर'** नामक तीनों मदों को लेकर **'भौतिक जीवन कोटि निर्देशांक' PQLI** का 1977 में निर्माण किया और इस आधार

पर 23 विकसित और विकासशील देशों के आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस सूचकांक से मानव विकास को मापने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। इसका बृहद वर्णन इसी इकाई में आगे 1.5 में किया गया है।

7. **मानव विकास सूचकांक** (Human Development Index-HDI)- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme – UNDP) के साथ जुड़े हुए अर्थशास्त्री **महबूब-उल-हक** ने **'विकास के एक सर्वमान्य सूचकांक'** को विकसित करने की दिशा में सबसे पहले प्रयास शुरू किया। उनके कहने पर नोबल पुरस्कार से सम्मानित **प्रो. ए. के. सेन** तथा **प्रो. सिंगर** के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने मानव विकास सूचकांक (HDI) विकसित किया।

HDI की पूरी धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि ***"किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग ही उस राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति है।"*** आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना, जिससे लोग लम्बे, स्वस्थ तथा सृजनात्मक जीवन का आनन्द उठा सकें। इस सूचकांक का बृहद वर्णन इसी इकाई में आगे 1.6 में किया गया है।

8.5 जीवन गुणवत्ता सूचकांक या जीवन का भौतिक गुणवत्ता (Quality of Life Index Or Physical Quality of Life Index)

इस इकाई के 1.4.2 के अन्तर्गत सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचकांक को अध्ययन कर चुके हैं। जिसमें हिक्स तथा स्ट्रीटन ने अपने अध्ययन के अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा आवास जैसे छः सामाजिक सूचकों को सम्मिलित कर जीवन की प्राथमिक आवश्यकता से सम्बन्धित जीवन गुणवत्ता को मापने का प्रयास किया है। परन्तु सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता सूचकों से सम्बन्धित विकास का एक सामान्य सूचक बनाने के मार्ग में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं;

(i) ऐसे सूचक में शामिल किए जाने वाली मदों की संख्या और किस्मों के बारे में अर्थशास्त्रियों के बीच एक मत नहीं है। उदाहरणार्थ – हेगन (Hagen) और संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक विकास के लिए अन्वेषण संस्था 11 से 18 मदों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से बहुत कम समान हैं। जबकि डी. मौरिस तुलनात्मक अध्ययन के लिए विश्व के 23 विकसित और विकासशील देशों से सम्बन्धित **'जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचक' (PQLI)** बनाने के लिए केवल तीन मदों अर्थात् **जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर** तथा **साक्षरता दर** को सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त,

(ii) विभिन्न मदों को भार देने की भी समस्या उत्पन्न होती है।

(iii) सामाजिक, सूचक वर्तमान कल्याण से सम्बन्धित होते हैं न कि भविष्य के कल्याण से।

(iv) अधिकतर सूचक आगतें हैं न कि निर्गत, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। (GNP) उनमें मूल्य निर्णय पाये जाते हैं। अतः मूल्य निर्णयों से बचने और सुगमता के लिए अर्थशास्त्री तथा यू.एन.ओ. के संगठन सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति की आर्थिक विकास के माप के रूप में प्रयोग करते है।

प्रो. मैरिस तीनों सूचकों (मदों) 15.1 जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्युदर तथा साक्षरता दर को विकास का परिमाप मापते हैं।

PQLI संकेतक से बहुत से सूचकों, जैसे - स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पोषण तथा स्वच्छता आदि का पता चलता है। प्रत्येक सूचक के तीनों घटकों को शून्य से 100 तक के पैमाने पर रखा गया है। जिसमें शून्य को निम्नतम तथा 100 को सर्वोत्तम प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया गया है। च्फस्प् सूचक की गणना तीनों घटकों को समान भार (Weight) देते हुए औसत निकाल कर की जाती है तथा सूचक को भी शून्य से 100 के पैमाने पर रखा गया है।

इस निर्देशांक के आधार पर देश में विकास होने या न होने का पता चलता है। यदि जीवन-निर्देशांक में स्थायी तौर से वृद्धि होती है जो कि तभी संभव है, जबकि देश में कुल राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण और उपयोग इस ढंग से हो कि अधिकाधिक लोग लाभ उठा सकें और फलस्वरूप शिशु मृत्यु-दर घटे तथा प्रत्याशित आयु और साक्षरता बढ़े तो यह इस बात का सूचक होगा कि देश में आर्थिक विकास हो रहा है।

मौरिस के अनुसार तीनों सूचकों (मदों) में प्रत्येक सूचक परिणाम मापता है। उसके अध्ययन के अनुसार

(i) जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर में उच्च डिग्री का ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक प्राप्त है।

(ii) शिक्षा और शिशु मृत्यु दर में भी उच्च डिग्री का ऋणात्मक सहसंबंध प्राप्त है।

(iii) शिक्षा और जीवन प्रत्याशा में उच्च डिग्री का धनात्मक सहसंबंध प्राप्त है अर्थात् शिक्षा के साथ-साथ जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि होती है।

सन् 1950 में गेबन (जापान) की शिशु मृत्यु दर 229 प्रति हजार को मंदत्तम (निम्नत्तम) मानते हुए मौरिस ने इसे शून्य पर स्थिर कर दिया तथा इसकी उच्चतम सीमा को 2000 तक 7 प्रति हजार का लक्ष्य बनाया गया। इसी प्रकार वियतनाम मे एक वर्ष की आयु पर जीवन संभाव्यता सन् 1950 में 38 वर्ष थी। इसे मौरिस ने जीवन संभाव्यता सूचक पर शून्य का स्थान दिया। इसकी उच्चतम सीमा पुरूषों में तथा महिलाओं को मिलाकर सन् 2000 तक 77 वर्ष रखी गयी। अंत में 15 वर्ष की आयु में शिक्षा की दर को शिक्षा सूचक बनाया गया। इस अध्ययन के निष्कर्ष नीचे सारणी 8.2 में दर्शाये गये है।

सारणी - 8.2 आयु जीवन प्रत्याशा व शिक्षा में सहसंबंध

कुल देशों की संख्या (N=150)	शिशु मृत्यु दर(IMR)	जीवन-प्रत्याशा(Expectation of Life)
एक वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा	(-) 0.919	
शिक्षा	(-) 0.919	(+) 0.897

मौरिस के अनुसार एक वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर अर्थात् जीवन की भौतिक गुणवत्ता के बहुत अच्छे संकेतक हैं। यही बात शिक्षा तथा जीवन प्रत्याशा के बारे में कही गयी है। मौरिस के अनुसार शिक्षा सूचक विकास की संभावनाओं को व्यक्त करता है अर्थात् शिक्षा विकास का श्रेष्ठ मापक है।

PQLI व प्रति व्यक्ति आय में सहसंबंध: अपने अध्ययन में मौरिस ने यह पाया कि प्रति व्यक्ति आय व PQLI के बीच कोई स्वतः तालमेल नहीं होता, उन्होंने पाया कि यद्यपि श्रीलंका का च्फस्प् भारत से कहीं अधिक था, जबकि इसकी औसत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर लगभग भारत के बराबर थी। इसी प्रकार अमेरिका तथा इटली

दोनों ही विकसित देशों का PQLI काफी ऊँचा था। परन्तु इटली की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर अमेरिका से लगभग दुगुनी थी। अतः उनका मत था कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय नहीं बल्कि च्फस्प् ही आर्थिक विकास एक उचित मापदण्ड है। उपर्युक्त तथ्यों से संबंधित आँकड़ों को नीचे सारणी 8.3 में दर्शाया गया है:

सारणी 8.3

जीवन का भौतिक गुणवत्ता निष्पादन तथा GNP प्रति व्यक्ति वृद्धि दर

देश	(PQLI)			औसत वार्षिक GNP प्रति व्यक्ति वृद्धि दर%
	1950	1960	1970	
भारत	14	30	40	1.8
श्रीलंका	65	75	80	1.9
इटली	80	87	92	5.0
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	89	91	93	2.4

सीमाएं (Limitations) अनेक अर्थशास्त्री इस मापदंड की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना करते हैंः

(i) PQLI मूल आवश्यकताओं को केवल एक सीमा तक ही माप सकता है।

(ii) यह मापदण्ड सामाजिक और आर्थिक संगठन के बदले हुए ढाँचे को भी नहीं प्रदर्शित करता है। अतः यह आर्थिक विकास को नहीं मापता।

(iii) इसके अन्तर्गत केवल तीन सूचकों को ही लिया गया है और अनेक सूचकों को छोड़ दिया गया है जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

(iv) PQLI कुल कल्याण को भी नहीं मापता है।

उपर्युक्त सीमाओं के होते हुए भी च्फस्प् जीवन की गुणवत्ताओं को मापता है जो गरीबों के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही यह अल्पविकास के उन विशेष क्षेत्रों का पता लगाने तथा सामाजिक नीतियों की असफलता तथा उपेक्षा की शिकार समाज के विभिन्न वर्गों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। यह उस सूचक की ओर संकेत करता है कि जहाँ तत्काल सरकारी हस्तक्षेप व कार्यवाहियों की आवश्यकता होती है। सरकार ऐसी नीतियाँ अपना सकती है जिससे PQLI में भी शीघ्र वृद्धि हो तथा आर्थिक विकास भी त्वरित हो।

भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक के अन्तर्गत क्रयशक्ति समता सूचकांक का भी उपयोग किया जाता है। जिसका सर्वप्रथम प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था। आजकल विभिन्न देशों के रहन-सहन की तुलना के लिये विश्वबैंक द्वारा इस सूचकांक का उपयोग किया जा रहा है।

क्रयशक्ति समता सूचकांक (Purchasing Power Parity Index): आर्थिक विकास के मापदंड के रूप में क्रयशक्ति समता सूचकांक का भी उपयोग किया जाता है। इस सूचकांक का सर्वप्रथम उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1993 में किया था। आजकल विभिन्न देशों के रहन-सहन की तुलना के लिए विश्व बैंक द्वारा इस सूचकांक का उपयोग किया जा रहा है।

क्रयशक्ति समता विधि के अन्तर्गत किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय को किसी पूर्ण निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर न व्यक्त करके, उस देश के भीतर मुद्रा की क्रयशक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है और विभिन्न देशों के रहन-सहन के स्तर के माप व तुलना के लिए क्रयशक्ति समता स्थापित की जाती है।

क्रयशक्ति समता स्थापित करने की विधि को हम एक उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। मान लीजिए X तथा Y दो देश हैं, जिनका अपनी मुद्रा में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 30 हजार व 35 हजार है। चूँकि दोनों देशों में अलग-अलग मुद्राओं का प्रचलन है। अतः इनकी तुलना तब तक संभव नहीं है जब तक कि इन्हें किसी एक मुद्रा या एक इकाई में बदल नहीं दिया जाता है। ऐसा करने के लिए एक सरल तरीका यह होगा कि देशों के प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद को किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसे डालर में बदल दिया जाय। मान लीजिए दोनों देशों की मुद्राओं के संबंध में निर्धारित विनिमय दर 1$=50 रूपए है। ऐसी स्थिति में X देश की प्रति व्यक्ति आय 600 डालर तथा Y देश की प्रति व्यक्ति आय 700 डालर होगी। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूंकि Y देश में प्रति व्यक्ति की आय अधिक है। इसलिए वहाँ के निवासियों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा है।

परन्तु उपर्युक्त निष्कर्ष जिसमें डालर के रूप में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर व्यक्तियों का रहन-सहन या उपभोग का स्तर मापा गया है। यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ के निवासियों के जीवन का स्तर का सही चित्र प्रस्तुत करे, क्योंकि हो सकता है दोनों देशों में मुद्रा (डालर) की क्रय शक्ति अलग-अलग हो जिससे उनकी वास्तविक आय पृथक-पृथक् होगी।

वस्तुतः रहन-सहन का स्तर वास्तविक आय पर निर्भर करता है और यदि दोनों देशों में डालर की क्रयशक्ति समान नहीं है तो डालर के रूप में व्यक्त की गयी प्रति व्यक्ति आय भ्रामक निष्कर्ष दे सकती है। उदाहरण के लिए यदि X देश में एक डालर की क्रयशक्ति 20 वस्तुओं व सेवाओं की इकाई है और Y देश में 10 वस्तुओं व सेवाओं की इकाई है तो वास्तविक रूप में परिवर्तित करने पर X देश की प्रति व्यक्ति आय 12000 वस्तुएँ व सेवाएँ तथा Y देश की प्रति व्यक्ति आय 7000 वस्तुएँ व सेवाएँ होंगी। इस आधार पर सही निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि X देश में उपभोग का स्तर Y देश के उपभोग के स्तर से ऊँचा है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने क्रयशक्ति समता सूचकांक (Purchasing Power Parity Index) तैयार किया जिसके आधार पर क्रयशक्ति समता के रूप में विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय को विश्व बैंक व्यक्त करता है। क्रयशक्ति समता के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1998 में 1700 डालर थी और इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। परन्तु अधिकांश अर्थशास्त्री क्रयशक्ति समता सूचकांक को आर्थिक विकास के मापन की एक अच्छी विधि नहीं मानते हैं।

8.6 मानव विकास सूचकांक (Human Development Index)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United nation development programme) के साथ जुड़े अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक ने वर्ष 1990 में **'विकास के एक सर्वमान्य सूचकांक'** को विकसित करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास शुरू किया। उनके कहने पर नोबल पुरस्कार से सम्मानित प्रो. ए. के. सेन तथा प्रो. सिंगर के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने **'मानव विकास सूचकांक'** HDI विकसित किया। इसके उपरान्त इसे

और अधिक परिष्कृत करने के उद्देश्य से **'लिंग-सम्बन्धित विकास सूचक**' GDI तथा '**मानव विकास निर्धनता सूचक**' HPI का विकास किया गया।

मानव विकास सूचक की अवधारणा इस आधारभूत परिकल्पना पर आधारित है कि ***"किसी राष्ट्र के निवासी ही उस राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति होते हैं।"*** आर्थिक विकास का मूलभूत उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे लोग लम्बे समय तक स्वस्थ एव सुखी जीवन का आनन्द उठा सकें।

मानव विकास की अवधारणा की विवेचना करते हुए यू.एन.डी.पी. की मानव विकास रिपोर्ट (1997) में इंगित किया गया है कि, ***"यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसामान्य के विकल्पों का विस्तार किया जाता है और इनके द्वारा उनके कल्याण के उच्च स्तर को प्राप्त किया जाता है। यही मानव विकास की धारणा का मूल है। ऐसे सिद्धान्त न तो सीमाबद्ध होते हैं और न ही स्थैतिक, परन्तु विकास के स्तर को दृष्टि में रखते हुए जनसामान्य के पास तीन विकल्प हैं - एक लम्बा और स्वस्थ्य जीवन व्यतीत करना, ज्ञान प्राप्त करना और अच्छा जीवन-स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों तक अपनी पहुँच बढ़ाना। कई और भी विकल्प हैं जिन्हें बहुत से लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। इनमें उल्लेखनीय है - राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता से सृजनात्मक और उत्पादक बनने के अवसर और स्वाभिमान एवं गारण्टीयुक्त मानव अधिकारों का लाभ उठाना।"*** इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए **मानव विकास रिपोर्ट** में उल्लेख किया गया है, ***"आय केवल एक विकल्प है और जो लोग प्राप्त करना चाहेंगे, चाहे यह महत्वपूण है, परन्तु यह उनके समस्त जीवन का सार नहीं है। आय एक साधन है, जबकि मानव विकास एक लक्ष्य है।"***

संक्षेप में, हम देख सकते हैं कि मानव विकास की अवधारणा मुख्य रूप से मनुष्य की तीन आवश्यक पसंदगियों पर आधारित माना गया है और ये हैं - लम्बी और स्वस्थ जिंदगी जीने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा और एक खूबसूरत जिंदगी व्यतीत करने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँचने की इच्छा। यदि ये तीनों पसंदगियाँ उपलब्ध नहीं हैं तो व्यक्ति को अनेक अवसरों से वंचित होना पड़ेगा।

उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति धनी है किन्तु अस्वस्थ (बीमार) एवं अशिक्षित है तो वह अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हुए भी जिंदगी का वास्तविक आनंद नहीं उठा सकता है और उसकी जिंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। इसी तरह एक व्यक्ति ऐसा है जो स्वस्थ है, पढ़ा लिखा है किन्तु निर्धन है तो वह जिन्दगी की अपनी जरूरतों को पूरा करने में न तो सक्षम होगा और न ही आनन्दपूर्ण जिन्दगी को ही जी सकेगा। अतः एक व्यक्ति धनी होते हुए भी आनन्द से वंचित है क्योंकि वह स्वस्थ और शिक्षित नहीं है। दूसरा स्वस्थ एवं शिक्षित होते हुए भी आनन्द से वंचित हैं क्योंकि वह निर्धन है। अतः मानव कल्याण के साध्य 'मानव विकास' के लिए संसाधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य तीनों ही खूबसूरत जिन्दगी व्यतीत करने के लिए जरूरी है।

मानव विकास सूचक(HDI)

तीन सामाजिक अभिसूचकों अथवा मापदण्डों (Social indicators) का एक मिश्रित सूचक है, जिसमें वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलु आय का भी ध्यान रखा जाता है। किसी देश के HDIका मूल्य निकालने के लिए निम्नलिखित तीन सूचकों को लिया जाता है:

1. **दीर्घायु (Longevity)** इसे जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा (Expectation of life at birth) द्वारा मापा जाता है जिसे वर्तमान समय में अर्थशास्त्रियों द्वारा न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 85 वर्ष तक दर्शाया जा रहा है।
2. **शैक्षणिक उपलब्धियाँ** (Educational Attainment) शैक्षणिक उपलब्धियों की माप निम्नलिखित 2 चरों (Variables) द्वारा की जाती है।

   1. वयस्क साक्षरता अनुपात (Adult literacy Ratio-ALR) 15 वर्ष या उससे ऊपर आयु के 100 व्यक्तियों में से जितने व्यक्ति साधारण कथन (Statement) को पढ़ व लिख सकते हैं, उसे प्रौढ़ साक्षरता दर कहते हैं।

   2. सकल नामांकन दर (Gross Enrolement Ratio - GER) जनसंख्या का वह भाग जिसका नामांकन प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल या विश्वविद्यालय स्तर पर हुआ है उसे सकल नामांकन दर कहते हैं। यह दर जितनी ही अधिक होगी जीवन किस्म (Quality of Life) उतनी ही श्रेष्ठ होगी। अतः प्रत्येक दर GER को बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयास करता है।

   इस प्रकार मानव विकास सूचक के शैक्षिक योग्यताओं की प्राप्ति के लिए साक्षरता या ज्ञान की प्राप्ति के स्तर की माप प्रौढ़ शिक्षा की दर ;।स्त्द्ध तथा सकल नामांकन दर ;ळम्त्द्ध से प्राप्त की जाती है।

   शैक्षिक योग्यताओं की प्राप्ति प्रौढ़ शिक्षा 2/3 भार तथा प्राथमिक माध्यमिक व क्षेत्रीय विद्यालयों में उपस्थित (नामांकन) अनुपातों के 1/3 भार के मिश्रण के रूप में मापा जाता है।

   3. वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP per capita) जीवन स्तर को डालर की क्रयशक्ति समता **(Purchasing power parity-PPP**) द्वारा मापा जाता है।

   इस प्रकार मानव विकास सूचकांक के निर्माण में जीवन प्रत्याशा साक्षरता (शैक्षिक) स्तर व प्रतिव्यक्ति वास्तविक घरेलू आय स्तर को सम्मिलित किया जाता है।

मानव विकास सूचकांक के निर्माण के चरण (Steps in Construction of Human Development Index)

मानव विकास सूचकांक के निर्माण के निम्नलिखित दो कदम हैं

I. प्रासंगिक सूचकांक का निर्माण (Construction of relevant indices)
II. तीनों सूचकांकों का सरल औसत लेना (Taking the simple averages of three indices)

(1) प्रासंगिक सूचकांक का निर्माण (Construction of relevant indices)

इसके लिए निम्नलिखित कार्य करने होते हैं:

(a) मानव विकास के प्रत्येक संकेतक के लिए निम्नत्तम व उच्चत्तम मूल्य को निश्चित (Fixing minimum and maximum values of each indicator of HDI)के निर्माण हेतु पहला कार्य उसके संकेतकों के

निम्नत्तम व उच्चत्तम मूल्य का निर्धारण करना है। UNO ने HDI के निर्माण हेतु जो मूल्य निर्धारित किये थे वह निम्न सारणी 8.4 में दिया गया है

सारणी 8.4

HDI के संकेतकों के निम्नतम व उच्चतम मूल्य

संकेतक	न्यूनतम मूल्य	अधिकत्तम मूल्य
जीवन प्रत्याशा	25	85
प्रौढ़ साक्षरता दर	0%	100%
सकल नामांकन दर	0%	100%
क्रय शक्ति समता पर आधारित वास्तविक प्रति व्यक्ति GDP	$100	$40000

(b) व्यक्तिगत सूचकांकों का निर्माण ;ब्वउचनजपदह प्दकपअपकनंस प्दकपबमेद्ध: HDI के निर्माण के लिए आवश्यक है कि तीनों संकेतकों के पृथक् पृथक् सूचकांक का निर्माण किया जाय। व्यक्तिगत सूचकांकों के निर्माण के लिए सामान्य सूत्र निम्न प्रकार है:

$$\text{सूचकांक} = \frac{\text{वास्तविक मूल्य} - \text{न्यूनतम मूल्य}}{\text{अधिकत्तम मूल्य} - \text{न्यूनतम मूल्य}}$$

उपर्युक्त सूत्र के उपयोग की व्याख्या हम जीवन प्रत्याशा सूचकांक के संबंध में करेंगे। मान लीजिए ष्।ष् देश में सन् 2002 में जन्म के समय प्रत्याशित आयु 59.4 है, अधिकत्तम जीवन प्रत्याशा 78.4 है और न्यूनतम आयु प्रत्याशा 41.8 है तो । देश का जीवन प्रत्याशा निर्देशांक निम्न प्रकार होगा:

A देश का जीवन प्रत्याशा निर्देशांक $=\frac{59.4-41.8}{74.8-41.8} = 0.492$

इसी प्रकार हम शैक्षिक स्तर का निर्देशांक ज्ञात करेंगे।

मान लीजिए Aदेश का अधिकत्तम प्रौढ़ शैक्षिक दर 100 है और न्यूनतम प्रौढ़ शैक्षिक दर 12.3 है तथा वास्तविक प्रौढ़ शैक्षिक स्तर 60 है तो । देश का शैक्षिक स्तर निर्देशांक निम्न प्रकार होगा:

A देश का शैक्षिक स्तर निर्देशांक

अब हम A देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक निकालेंगे।

मान लीजिए A देश में अधिकतम प्रति व्यक्ति वास्तविक घरेलू उत्पाद 3.68 है, न्यूनतम वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2.34 है एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2.90 है तो A देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद निर्देशांक होगा

A देश का प्रति सकल व्यक्ति घरेलू उत्पाद निर्देशांक

2. तीनों सूचकांकों का सरल औसत लेना (Taking the simple average of thyree indices) जीवन प्रत्याशा सूचकांक शैक्षिक उपलब्धि सूचकांक तथा वास्तविक प्रति व्यक्ति GDP सूचकांक पृथक-पृथक तैयार करने के बाद हम तीनों सूचकांकों का सरल औसत निकाल कर मानव विकास सूचकांक (HDI) का निर्माण करते हैं। अतः HDI के निर्माण के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है:

$$\text{HDI} = \frac{\text{जीवन प्रत्याशा सूचकांक } + \text{ शैक्षणिक उपलब्धि सूचकांक} + \text{ वास्तविक प्रति व्यक्ति ळक्च् सूचकांक}}{3}$$

उदाहरण: उपर्युक्त उदाहरण में (अ) देश का जीवन प्रत्याशा सूचकांक 0.492 है, (ब) शैक्षणिक उपलब्धि सूचकांक 0.544 है और (स) क्रय शक्ति समता पर आधारित वास्तविक प्रति व्यक्ति सूचकांक 0.418 है तो HDI ज्ञात कीजिए।

हल उपर्युक्त ऑकड़ों के आधार पर हम देश के HDI का निर्माण निम्न प्रकार से कर सकते हैं:

$$\text{HDI} = \frac{0.492 + .544 + .481}{3} = 0.485$$

जीवन की संभाव्यता सूचक, शैक्षिक प्राप्तियाँ सूचक तथा समायोजित वास्तविक प्रति व्यक्ति सूचक का सरल औसत सूचक है (HDI is a simple average of life expectancy index, educational attainment index and the adjusted real GDP per capital index) इसकी गणना इन तीनों संकेतकों के योग को 3 से विभाजित कर निकाली जाती है। इसमें प्रत्येक चर का न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य स्थिर है, जिसे घटाकर शून्य (0) तथा एक (1) के बीच पैमाने पर रखा गया है तथा प्रत्येक देश उस पैमाने के किसी न किसी बिंदु पर आता है। ऐसे देश जिनका HDI मूल्य 0.5 से कम है, उन्हें निम्न स्तर के मानव विकास क्रम में रखा जाता है तथा 0.5 से 0.8 मूल्य वाले देशों को माध्यम तथा 0.8 से ऊपर HDI मूल्य वाले देश उच्च स्तर में गिने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि HDI का अधिकतम मूल्य एक के बराबर होगा।

विश्व के विभिन्न देशों के HDI मूल्य के अनुसार मानव विकास के किस क्रम में रखा जाता है, इसका विवरण सारणी 8.5 में दिखाया गया निम्न है:

सारणी 8.5

मूल्य(HDI Value)	**मानव विकास का क्रम(Rank of Human Development)**
0.8 से ऊपर	उच्च मानव विकास (विकसित देश)
0.5 से 0.79	मध्यम मानव विकास (विकासशील देश)
0.5 से कम	निम्न मानव विकास (अल्पविकसित देश)

प्रत्येक देश का HDI मूल्य यह दर्शाता है कि उसे अपने कुछ परिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कितना प्रयास करना है। ये परिभाषित लक्ष्य हैं: 85 वर्ष के औसत जीवन की अवधि, सभी के लिए शिक्षा की उपलब्धि तथा उत्कृष्ट जीवन स्तर। HDI एक दूसरे संबंध में विभिन्न देशों का क्रम (Rank) तय करता है। किसी भी देश का HDI क्रम विश्व आवंटन के बीच ही तय होता है। उदाहरण के लिए यह क्रम प्रत्येक विकसित तथा विकासशील

देशों से संबंधित अपने HDI मूल्य पर आधारित है जिसके लिए उस देश द्वारा HDI न्यूनतम मूल्य शून्य (0) से HDI अधिकतम मूल्य एक (1) तक प्रयास किये गये।

HDI की सीमाएं (Limitations of HDI)

आर्थिक विकास के मापदण्ड या संकेतक के रूप में मानव विकास सूचकांक की निम्नलिखित सीमाएं व कमियाँ हैं:-

1. इस संकेतक के तीनों आधार जीवन प्रत्याशा, साक्षरता एवं आय (जो कि क्रय शक्ति के आधार पर मापी गयी है) वस्तुतः आय से ही संबंधित है क्योंकि जिस देश की आय अधिक होगी सामान्यतया वहाँ के लोगों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा होने के कारण जीवन प्रत्याशा व साक्षरता दर भी ऊँची होगी। अतः संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रयोग किये गये तीनों आधार सिमट कर अमरीकी डालरों में आमदनी से ही संबंधित हो जाते हैं, इसलिए जो देश मानव विकास सूचकांक की उच्च श्रेणी में है जैसे कनाडा, फ्रांस, नार्वे तथा अमेरिकी ये सभी देश अमीर देश हैं।
2. किसी देश के मानव विकास सूचकांक से उस देश में पायी जाने वाली ऊँची असमानता को दूर करने में कोई सहायता नहीं मिलती है।
3. मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित केवल तीन सूचकों को मानव विकास का सूचक नहीं कहा जा सकता उसके अन्तर्गत शिशु मृत्यु दर, पोषण आदि सामाजिक सूचकों को भी सम्मिलित करना चाहिए।

U.N.D.P. ने मानव विकास के परिदृश्य के और स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित दो और महत्वपूर्ण सूचकांक तैयार किये हैं: (1) लैंगिक विकास सूचकांक GDI जिसके आधार पर भेदभाव लैंगिक भेदभाव की स्थिति ज्ञात होती है तथा (2) मानव गरीबी सूचकांक HPI जो HDI के ही चरों पर आधारित होता है, मानव गरीबी सूचकांक विकसित तथा विकासशील दोनों देशों के लिए अलग-अलग ढंग से तैयार किया जाता है।

इस प्रकार HDI,GDI तथा HPI तीनों मिलकर किसी देश के मानव विकास परिदृश्य का स्पष्ट चित्र सामने रखते हैं। UNDP ने मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करने के लिए अपनी पहली रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित की। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2002 के अनुसार विश्व के 173 देशों में भारत को 124वीं रैंकिंग प्रदान की गयी, जबकि नार्वे पूर्व वर्षों की भांति प्रथम स्थान पर था। सबसे नीचे अर्थात् 173वें स्थान पर सिएरा लियॉन का नाम था। इस रिपोर्ट में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे स्थान पर क्रमशः स्वीडन, कनाडा, बैल्जियम, आस्ट्रेलिया व अमेरिका का स्थान था।

8.7 मानव निर्धनता सूचकांक (Human Poverty Index-HPI)

मानव विकास रिपोर्ट 1997 द्वारा मानव निर्धनता सूचक की अवधारणा का विकास किया गया जो मानव जीवन के तीन अनिवार्य अंगों में पृथक्करण अथवा वंचन (Deprivation) पर ध्यान संकेन्द्रित करता है जो मानव विकास सूचक में परिलक्षित होती है - दीर्घ जीवन, ज्ञान एवं एक अच्छा जीवन स्तर।

सबसे प्रथम पृथक्करण अथवा वंचन अपेक्षाकृत कम आयु में मृत्यु सम्बन्धी दुर्बलता है और इस सूचक में इसका संकेत 40 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत से प्राप्त होता है। दूसरा वंचन

ज्ञान से सम्बन्धित है और इसका माप वयस्कों में गैर-साक्षरों के प्रतिशत से प्राप्त किया जाता है। तीसरा वंचन अच्छे जीवन-स्तर से सम्बन्धित है। यह तीन चरों से सम्बद्ध है - जन सामान्य का प्रतिशत जिसमें (क) स्वास्थ्य सेवाएं, (ख) शुद्ध पेय जल की उपलब्धता, (ग) पाँच वर्ष से कम आयु वाले कुपोषित बच्चों का प्रतिशत।

इस तरह, मानव निर्धनता सूचक में बच्चों के कुपोषण की विद्यमानता का प्रयोग किया गया है, जिसकी माप अपेक्षाकृत आसान है और जिसके आँकड़े भी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और सुरक्षित पेय जल की पहुँच को भी सम्मिलित किया गया है। इन तीनों चरों को जोड़कर मानव निर्धनता की पर्याप्त एवं सही तस्वीर बनाना युक्ति संगत माना गया।

स्पष्टतया आय-निर्धनता रेखा की अपेक्षा मानव निर्धनता सूचक एक अधिक व्यापक माप है, क्योंकि आय निर्धनता रेखा एक ही चर पर आधारित है।

8.8 लिंग-सम्बन्धित विकास (Gender Related Development Index-GDI)

मानव विकास सूचक, निश्चित रूप से आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। परन्तु वास्तव में केवल तीन सूचक-लम्बा तथा स्वस्थ जीवन, ज्ञान प्राप्त करना तथा अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिये साधनों की क्रय शक्ति क्षमता ही मानव विकास का पर्याप्त सूचक नहीं माना जा सकता, क्योंकि शिशु मृत्युदर, पोषण आदि अन्य सूचकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। साथ ही सापेक्ष मानव विकास के साथ-साथ निरपेक्ष मानव विकास एवं उच्च विषमता की भी जानकारी होनी चाहिये। जिससे विकास का विस्तृत एवं गहन अध्ययन हो सके।

लिंग सम्बन्धित विकास सूचक को लैंगिक विकास सूचकांक भी कहते हैं। जिसके अन्तर्गत लिंग सम्बन्धी भेदभाव ;ळमदकमत क्पेबतपउपदंजपवदद्ध की स्थिति ज्ञात होती है। यह सूचक पुरुषों एवं स्त्रियों में असमानता को दर्शाता है जबकि मानव विकास सूचक औसत उपलब्धि की माप है। लिंग-सम्बन्धित विकास सूचक में जिन तीनों बातों को सम्मिलित किया जाता है वे - स्त्रियों मे जन्म पर जीवन प्रत्याशा, स्त्री वयस्क साक्षरता एवं कुल नामांकन अनुपात तथा ; स्त्री प्रति व्यक्ति आय।

लिंग असमानता विद्यमान न होने की दशा में मानव विकास सूचक तथा लिंग-सम्बन्धित विकास सूचक समान होंगे। यदि लिंग-असमानता विद्यमान है तो लिंग सम्बन्धित विकास सूचक मानव विकास सूचक से कम होगा। इन दोनों में जितना अधिक अन्तर होगा, उतनी ही अधिक लिंग-असमानता होगी। मानव विकास रिपोर्ट की सूचनाओं के अनुसार अधिक लिंग-असमानता वाले देश हैं: सऊदी अरब, ईरान, भारत, मिस्र तथा नाइजीरिया। जिन देशों में लगभग लिंग-समानता विद्यमान हैं वे हैं - नार्वे, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, रूसी फेडरेशन, मलेशिया, फिलीपीन्स, श्रीलंका, चीन, वियतनाम आदि।

कुछ देशों की जीवन प्रत्याशा तथा लिंगानुपात सारणी-8.6 में दिखाया गया है। जिन देशों में लिंगानुपात ठीक है वहाँ अपेक्षाकृत विकास की स्थिति अच्छी है। सारणी 8.7 में 5 शीर्ष जन्म के समय लिंगानुपात, सारणी-8.8 में पांच शीर्ष (0-14) वर्ष पुरुष जनसंख्या वाले देश तथा सारणी-8.9 में पांच शीर्ष (0-14) वर्ष महिला जनसंख्या देश दिखाये गये हैं। जबकि सारणी-8.10 में भारत में मानव विकास के चुनिन्दा संकेतकों को दिखाया गया है।

सारणी - 8.6 न्यूनतम पुरूष जीवन प्रत्याशा वाले शीर्ष देश	
देश	**औसत आयु वर्ष मं**
अफगानिस्तान/जिम्बाब्बे	44.7
अंगोला	46.1
कांगो प्रजा.गण.	46.4
जाम्बिया	46.7
स्वाजीलैण्ड	46.8
सियरालिओन	46.9

स्रोत: ICPD:2010

सारणी - 8.7

शीर्ष जन्म के समय लिंगानुपात वाले देश	
देश	जनसंख्या (2007)
आर्मेनिया	1.17
जार्जिया	1.15
चीन	1.12
अलबानिया	1.10
सन मैरिनो	1.09
भारत	1.05
विश्व	1.06

सारणी - 8.8

शीर्ष (0-14 वर्ष) पुरूष जनसंख्या वाले देश	
देश	जनसंख्या (2007)
भारत	173478760
चीन	145461833
इण्डोनेशिया	35995919
पाकिस्तान	33293428
यूएसए	31095847
विश्व	919219446

सारणी - 8.9

शीर्ष (0-14 वर्ष) महिला जनसंख्या वाले देश	
देश	जनसंख्या (2007)

भारत	163852827
चीन	128445739
इण्डोनेशिया	34749582
पाकिस्तान	31434314
यूएसए	29715872
विश्व	870242271

सारणी - 8.10

भारत में मानव विकास के चुनिन्दा संकेतक		
जीवन प्रत्याशा (2002-2006)	पुरूष महिला कुल	62.6 वर्ष 64.2 वर्ष 63.5 वर्ष
अशोधित जन्म दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	(2009)	22.5
अशोधित मृत्यु दर (प्रति 1000 जनसंख्या)	(2009)	7.3
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	(2009)	50
i. बालक मृत्यु दर (4 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित नवजात)	(2009)	49
ii. बालिका मृत्यु दर (4वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित नवजात)	(2009)	52
मातृत्व मृत्यु दर (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म)	(2004-06)	254
कुल प्रजनन दर (प्रति महिला औसतन)	(2008)	2.6
सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य	(2007)	मध्यप्रदेश (72प्रति हजार जीवित जन्म)
न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य	(2007)	मणिपुर (12 प्रति हजार जीवित जन्म)
प्रति 10,000 पर पंजीकृत चिकित्सक	(2004-2005)	6.0

स्त्रोत: आर्थिक समीक्षा 2010-11

8.9 आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ मापदण्ड या सूचक (The Best Indicator of Economic Development)

पूर्ण शुद्धता के साथ आर्थिक विकास का माप अत्यन्त कठिन है। दीर्घकालीन विकास के माप में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं -

i. विभिन्न कालों में राष्ट्रीय आय के आँकड़े अपर्याप्त व अधूरे हो सकते हैं।
ii. कुछ वैचारिक कठिनाइयाँ हो सकती है, क्योंकि उत्पादन की रूपरेखा समय के साथ बदलती रहती है। कारण यह है कि समय के साथ-साथ माँग बदलती है, आदतें बदलती हैं, तकनीकी में सुधार होता है व नयी-नयी वस्तुएँ बाजार में बिकती हैं।
iii. आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कुछ सामाजिक व राजनीतिक तत्व भी होते हैं, जिन्हें अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण भी विकास का माप करना कठिन हो जाता है।
iv. आर्थिक संस्थाएँ बदलती रहती हैं या बदलती हुई नीतियाँ अपनाती रहती हैं, जिनके कारण भी विकास का क्रमबद्ध माप करना कठिन हो जाता है।

उपयुक्त मानदंड क्या हो? आर्थिक विकास के विभिन्न मानदंडों के अध्ययन के बाद अब प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक विकास की माप हेतु उपयुक्त मानदंड किसे माना जाय ? वस्तुतः आर्थिक विकास के अभिसूचक के रूप में मुख्य विवाद राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय के बीच में है। चूँकि इन दोनों मानदंडों के अपने-अपने गुण व दोष हैं इसलिए सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था के लिए किसी एक ही प्रकार के मानदंड का चयन करना उचित नहीं होगा।

हमारे विचार में विकसित देशों के आर्थिक विकास का अभिसूचक राष्ट्रीय आय में वृद्धि माना जाना चाहिए। परन्तु अर्द्धविकसित देशों के लिए आर्थिक विकास की कसौटी हेतु प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की अपेक्षा श्रेष्ठतर है क्योंकि विकास की समस्या मुख्य रूप से अर्द्धविकसित देशों के विकास की समस्या से संबंधित है। इन देशों में **'मानव विकास'** का लाभ **'सामाजिक सूचक'** के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु इसका लाभ (i) गरीब वर्ग के लिए, एवं (ii) दीर्घकाल में प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यह अवधि 100 वर्ष भी हो सकती है, ऐसा सुझाव **'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम'** का है। इससे कम अवधि में, उदाहरण के लिए 40-50 वर्षों में, यही लाभ **'प्रति व्यक्ति आय'** से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक विकास का एक सरल मापक है। अतः अधिकांश अर्थशास्त्री आज भी **'प्रति व्यक्ति आय'** मापक (अथवा मापदंड) का अधिक समर्थन करते हैं। अर्थशास्त्रियों की राय में **'प्रति व्यक्ति वास्तविक आय'** आर्थिक विकास का एक उपयुक्त तथा श्रेष्ठ अभिसूचक अथवा मापदंड है।

8.10 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये

(1) सतत् विकास

(2) संवृद्धि, विकास एवं प्रगति में अन्तर

(3) सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता अभिसूचक

(4) क्रय शक्ति समता सूचकांक

(5) लिंग सम्बन्धित विकास सूचकांक

(6) मानव निर्धनता सूचकांक

(7) आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ मापदण्ड या सूचक

(8) मानव विकास सूचकांक के निर्माण के चरण

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मानव विकास सूचकांक में दीर्घायु के लिए प्रॉक्सी चर कौन सा है?

A. स्वास्थ्य और पोषण। B. जीवन स्तर

C. शिशु मृत्यु दर D. क्रय शक्ति समता

2. आर्थिक विकास है

A. एक आयामी अवधारणा B. द्वि आयामी अवधारणा

C. तीन आयामी अवधारणा D. बहु आयामी अवधारणा

8.11 सारांश (Summary)

इस इकाई की प्रस्तावना में विकास शब्द के समानार्थी शब्दों - संवृद्धि, प्रगति, विकास तथा सतत् विकास को बताते हुए विकास से सम्बन्धित जीवन गुणवत्ता, मानव विकास, गरीबी तथा लिंग सूचकांकों के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। तत्पश्चात् विकास के समानार्थी शब्दों-सवृद्धि, प्रगति तथा विकास के अन्तरों को स्पष्ट करते हुए, सतत् विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। पुनः आर्थिक विकास के विभिन्न मापकों एवं अभिसूचकों का वर्णन है। जिसमें प्रतिष्ठित तथा आधुनिक विचारों को स्पष्ट किया गया है। आधुनिक विचार धाराओं से सम्बन्धित वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि , प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि , आर्थिक कल्याण में वृद्धि , अर्थव्यवस्था में व्यवसायिक संरचना का स्वरूप सामाजिक अथवा मूलभूत आवश्यकता, भौतिक जीवन गुणवत्ता तथा मानव विकास निर्देशांकों का संक्षिप्त वर्णन है। तत्पश्चात् भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक (PQLI), मानव विकास सूचकांक (HDI), मानव निर्धनता सूचकांक (HPI) तथा लिंग-सम्बन्धित विकास सूचकांक (GDI) का विस्तृत वर्णन है।

अन्त में निष्कर्ष के रूप में सर्वश्रेष्ठ मापक या सूचक को बताया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कोई एक मापक सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिये उचित नहीं हो सकता। विकसित तथा विकासशील देशों में अलग-अलग मापक ठीक रहेंगे। विशेषकर अति निर्धन देशों में विकास तथा वितरण को देखते हुए **'प्रति व्यक्ति वास्तविक आय'** को मापते हैं।

8.12 शब्दावली (Glossary)

- **भौतिक जीवन कोटि या गुणवत्ता सूचकांक-**Physical Quality Of Life Index

- **मानव विकास सूचकांक-** Human development Index
- **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-**United nation development programme
- **लिंग-सम्बन्धित विकास सूचकांक-** Gender Related Development Index
- **मानव-निर्धनता सूचकांक-**Human Poverty Index

8.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. A 2. D

8.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- डॉ. मिश्रा, जे. पी., जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा।
- डॉ. बघेल, डी. एस., जनांकिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
- डॉ. पन्त, जीवन चन्द्र, जनांकिकी, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
- अशोक कुमार, जनसंख्या, एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रयाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय*, भारत सरकार
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग*, भारत सरकार
- *भारतः 2013*, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

8.15 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- Agarwal, S.N. (1972), *India's population problem*. Tata Mcgraw Hill Co., Bombay.
- Choubey, P.K. (2000), *Population Policy in India*, Kanishk Publication, New Delhi
- Gulati, S.C. (1988), *Fertility in India and Econometric Study of Metropolis*, Sage, NewDelhi.
- Gulati, S.C. (1998), *Basic Demographic Techniques and Applications*, Saga Publication, New Delhi.
- Srinivasan, K. (1998), *Basic Demographic Techniques and Applications*, SagaPublication, New Delhi
- Dr. Premi, M.K., Ramanamma, A., Bambawale, Usha,. An Introduction to social demography, Vikas Publishing House, New Delhi.

8.16 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. आर्थिक विकास से क्या समझते हैं? संवृद्धि, विकास एवं प्रगति में अन्तर बताइये।
2. आर्थिक विकास के विभिन्न मापदण्डों एवं अभिसूचकों को बताइये।
3. भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक को स्पष्ट कीजिये।
4. मानव विकास सूचकांक से क्या समझते हो? मानव विकास सूचकांक के विभिन्न चरणों को समझाये।

इकाई 9 - प्रवासन और नगरीकरण: अवधारणा और प्रारूप
(Migration and Urbanization: Concept and Models)

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 प्रवास

9.3.1 देशान्तरण को प्रभावित करने वाले कारक

9.3.2 देशान्तरण के मार्ग में बाधाएं अथवा गतिरोध

9.3.3 प्रवास या देशान्तरण की माप

9.3.4 देशान्तरण दरें

9.3.5 प्रवास के परिणाम

9.4 नगरीकरण

9.4.1 नगरीकरण के प्रभाव

9. 4.2 विश्व में नगरीकरण की कालिक प्रवृत्ति

9. 4.3 विश्व में नगरीकरण का प्रारूप

9. 4.4 विश्व में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर

9. 4.5 विश्व के कुछ प्रमुख देशों में नगरीकरण का स्तर

9. 4.6 भारत में नगरीकरण सम्बन्धी कुछ तथ्य

9.5 अभ्यास प्रश्न

9.6 सारांश

9.7 शब्दावली

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

9.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

9.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

9.11 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना(Introduction)

मानव का स्वभाव, आदिकाल से ही घुमन्तू प्रवृत्ति का रहा है। वह भूमि एवं साधनों की खोज, महामारियों, युद्धों, अनेक तरह के भेदभावों तथा अत्याचारों से बचने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता रहा है, जिसे प्रवास या देशान्तरण या स्थानान्तरण (Migration) कहते हैं। अपने प्रवास के द्वारा मानव अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति करता रहा है। मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति उसके प्रवास की सबसे बड़ी उत्प्रेरक है। अपने वास स्थान से नये क्षेत्रों की ओर गमनागमन (transit) तथा अपेक्षाकृत और सुगम एवं अनुकूल क्षेत्रों की खोज प्रागैतिहासिक काल से ही चली आ रही है। वैश्विक प्रवास के इतिहास में मानव नये-नये क्षेत्रों की खोज करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप तथा परिस्थितियों को स्वयं के अनुकूल बनाता रहा है। इस तरह नये क्षेत्रों की तलाश, यात्रा का रोमांच, कुछ नया करने की प्रवृत्ति, कुछ नया पाने की लालसा, पारिस्थितिक प्रखरतायें, सामाजिक-राजनैतिक तथा आर्थिक तत्व मानव प्रवास के मूल कारण रहे हैं।

'राष्ट्र' के उदय के साथ प्रवास का स्वरूप आन्तरिक तथा वाह्य या अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास को अनेक नियमों द्वारा कठोर एवं असहज बना दिया गया। यद्यपि 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति के साथ प्रवास के अनेक कठोर नियमों एवं बाधाओं के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास की नीति अपेक्षाकृत सरल हुई है। लोगों में प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ी है। परन्तु पहले के स्थायी प्रवास की अन्तर्राष्ट्रीय नीति की अपेक्षा अल्पकालिक या अस्थायी प्रवास की नीति को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

दूसरे शब्दों में मनुष्य जहाँ से स्थान परिवर्तन करता है, वहाँ उसके स्थानान्तरण को प्रबसन (Emigration) तथा प्रवासी को (Emigrants) प्रब्रजक कहते हैं। जबकि प्रवासित जनसंख्या जहाँ जाकर बसती है, वहाँ उसका आवासन Immigration होता है तथा आवासी को आब्रजक (Immigrants) कहते हैं। उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति इग्लैण्ड से आकर भारत में बसता है तो वह इग्लैण्ड के लिये प्रब्रजक (Emigrant) तथा भारत में जहाँ वह बसना चाहता है आब्रजक (Immigrants)कहलायेगा।

आन्तरिक प्रवास या देशान्तरण का आधार भी कमोवेश अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास के तर्कों की पुष्टि करता है। परन्तु आन्तरिक प्रवास के अन्तर्गत प्रवासी को एक राष्ट्र की सीमाओं के अन्तर्गत अपने मूल स्थान को छोड़कर उसी राष्ट्र के दूसरे स्थान पर जाकर बसना होता है। इसे अन्तर्गमन (In-Migration) या आन्तरिक प्रवास कहते हैं। ऐसे प्रवासी अन्तरप्रवासी (In-Migrants) कहलाते हैं। परन्तु जब प्रवासी जनसंख्या किसी दूसरे राष्ट्र में आकर बसती है तो यह प्रक्रिया अप्रवासन (Immigration) कहलाती है तथा ऐसी जनसंख्या आब्रजक (Immigrant) कहलाती है। अन्तर तथा बाह्य प्रवास की इस प्रक्रिया में नगरीकरण का स्वरूप तथा क्षेत्र बदलता गया। अनेक आर्थिक, भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक कारणों से ग्रामीण जनसंख्या की बड़ी मात्रा न केवल पुराने नगरों की आबादी बढ़ाती जा रही है, बल्कि अनेक नये नगरों का निर्माण भी कर रही है। नगरीकरण के सकारात्मक प्रभावों के फलस्वरूप नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों के फलस्वरूप नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्यायें भी बढ़ रही हैं। परन्तु वैश्विक स्तर पर नगरों की संख्या तेजी

से बढ़ रही है। 2001 के ऑकड़ों के अनुसार विश्व में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 36 से अधिक है, जिसमें मेक्सिको सिटी (मेक्सिको - 20.2 मिलियन) प्रथम; टोकियो (जापान - 18.1 मिलियन) द्वितीय; साओ पोलो (ब्राजील - 17.4 मिलियन) तृतीय तथा मुम्बई (भारत - 16.4 मिलियन) चौथे; स्थान पर है जबकि कोलकाता (भारत - 13.2 मिलियन) सातवें; दिल्ली (भारत - 12.8 मिलियन) आठवें; चेन्नई (भारत - 6.4 मिलियन) 29वें; बंगलौर (भारत - 5.7 मिलियन) 31वें तथा हैदराबाद (भारत - 5.5 मिलियन) 32वें स्थान पर (कुल 6, भारतीय महानगर) हैं। इसी तरह विश्व के अनेक कस्बे, नगरों एवं महानगरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जबकि कई गाँव बड़े कस्बों में परिवर्तित होते जा रहे हैं तथा यह क्रम लगातार बना हुआ है।

9.2 उद्देश्य (Objectives)

- ✓ जनसंख्या स्थानान्तरण के अप्रवासन तथा प्रब्रजन की अवधारणा को स्पष्ट करना।
- ✓ वैश्विक प्रवासन तथा आवासन से सम्बन्धित विभिन्न घटकों की जानकारी प्राप्त करना।
- ✓ प्रवास से सम्बन्धित बाधाओं, प्रवास की माप, प्रवास के परिणाम तथा प्रवास के लाभ की जानकारी प्राप्त करना।
- ✓ नगरीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करना।
- ✓ नगरीकरण के आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कारणों को समझना।
- ✓ विश्व के कुछ प्रमुख देशों में नगरीकरण के प्रभावों, नगरीकरण का स्तर अन्य की जानकारी प्राप्त करना।

9.3 प्रवास (Migration)

जब मानव या मानव समूह एक निवासित स्थान से अन्य स्थान पर या एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र को या एक देश से अन्य देश में स्थान परिवर्तन करता है, तो जनसंख्या स्थानान्तरण कहलाता है। मनुष्य जहाँ से स्थान परिवर्तन करता है, वहाँ जाने को उत्प्रवासन (Emigration) तथा जाने वाली जनसंख्या को उत्प्रवासी (Emigrants) कहते हैं। जबकि प्रवासित जनसंख्या जहाँ जाकर बसती है उसे अप्रवासन (Immigration) तथा आकर बसने वाली जनसंख्या को आब्रजक कहते हैं। वह देश जहाँ से व्यक्ति आता है - मूल देश तथा जहाँ जाता है - प्रवासी देश कहलाता है। उदाहरण के लिये यदि एक भारतीय अमेरिका में बसता है तो उस भारतीय प्रब्रजक को प्रवासी भारतीय कहते हैं। भारत उसका मूल देश तथा अमेरिका प्रवासी देश है। अल्पकाल या थोड़े समय के लिये कहीं घूमने जाने अथवा व्यापारिक उद्देश्य से जाने को देशान्तरण या प्रवासन नहीं माना जाता। लम्बे समय अथवा स्थायी रूप से जाने को ही देशान्तरण या प्रवासन कहा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O) के अनुसार, ***"देशान्तरण निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में विचरण का एक स्वरूप है। (Migration is form of geographical mobility between one geographical unit to another, generally involving a change of residence)"***

उक्त से यह स्पष्ट है कि देशान्तरण के अन्तर्गत निवास में परिवर्तन हो जाता है तथा यह परिवर्तन अल्पकालीन न होकर दीर्घकालीन एवं स्थायी होता है; साथ ही देशान्तरण के लिए किसी भौगोलिक इकाई को पार करना भी आवश्यक होता है।

देशान्तरण के अन्तर्गत दो प्रकार की गतिशीलता हो सकती है। जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसता है तो उसे परदेशवासी या बहिर्गन्तुक या उत्प्रवासी तथा स्वदेश छोड़कर बाहर जाकर बसने की क्रिया को उत्प्रवास या वहिर्गमन (Emigration) कहा जाता है। इसी तरह, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से आकर किसी देश में बसता है तो उसे आगन्तुक या अप्रवासी तथा आकर बसने को अन्तर्गमन या अप्रवास कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनांकिकी शब्दकोश के अनुसार एक देश के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ष्प्नज.उपहतंजपवदष् तथा किसी स्थान पर अन्य जगहों से आने को ष्प्द.उपहतंजपवदष् कहा जाता है। जबकि राष्ट्रीय सीमा को जब पार कर लिया जाता है तो इसके लिए Emigration एवं प्उउपहतंजपवद शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना ब्यूरो में उन व्यक्तियों को जो एक देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, उन्हें देशान्तरण अथवा प्रवास (Migration) में सम्मिलित किया जाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन्हें विचरणकर्ताओं में सम्मिलित किया जाता है। इस तरह वहाँ विचरणकर्ता व प्रवासित शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

9.3.1 देशान्तरण को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting or Causes of Migration)

देशान्तरण को प्रभावित करने वाले कई घटक एक साथ प्रभावी हो जाते हैं। देशान्तरण को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों को जनांकिकीविदों द्वारा मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम-आकर्षक कारक (PULL factors) तथा द्वितीय-प्रत्याकर्षक कारक (PUSH factors)

(अ) आकर्षक कारक (PULL factors) देशान्तर के आकर्षक कारक वे हैं जो मनुष्य को अपना निवास स्थान छोड़कर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ प्रमुख आकर्षक कारक निम्न हैं:

1. रोजगार एवं व्यवसाय के श्रेष्ठ अवसर।
2. अधिक आय अर्जित करने के अवसर।
3. शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा आवास की सुविधायें।
4. मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता।
5. स्वास्थ्यप्रद जलवायु।
6. सगे-सम्बन्धियों एवं इष्ट-मित्रों का आकर्षण।
7. उन्नत नगरीय जीवन।

उपरोक्त कारणों से आकर्षित होकर व्यक्ति अपने स्वाभाविक निवास को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसे positive migration भी कहा जाता है। गाँव से शहरों की ओर प्रवास के लिए यही कारक मुख्य रूप से आकर्षित करते हैं। **पोन्सिओन (Ponsioen)** के अनुसार, ***"आर्थिक विकास प्रायः सभी भौगोलिक क्षेत्रों में***

समान रूप से नहीं वितरित रहता है और विकास प्रक्रिया ही गाँवों से शहर की ओर प्रवास का प्रमुख कारण है। ग्रामीण लोग शहरों को 'समृद्ध भूमि' मानते हैं। लोग शहरी जीवन को उसके औपचारिक प्रशासन, अवैयक्तिक नियमों का शासन, विपणन तथा बैंकिंग से सम्बद्ध मौद्रिक अर्थव्यवस्था, बाजारोन्मुख उत्पादन व्यवस्था, साक्षरता, स्कूली शिक्षा, आराम के क्षणों को बिताने के लिए ललित कलाएं, हितकारी संस्थागत सेवाएं तथा सुलभ पुलिस बल के कारण प्राथमिकता प्रदान करते हैं। (Economic development is usually unequally distributed over geographical areas and the development process is the main factor for rural-urban migration. Rural people regraded towns as 'promised land'. People prefer urban life for its formal administration, the rule of impersonal law for order, money economy connected with wide marketing and banking, market oriented production, literacy, school education, a leisure class enjoying fine arts, institutionalised services for welfare and a standing police force)"

(ब) प्रत्याकर्षक कारक (PUSH factors)-देशान्तरण के प्रत्याकर्षक कारकों से आशय उन परिस्थितियों से होता है जिनसे बाध्य होकर कोई व्यक्ति अपने स्वाभाविक निवास का परित्याग करता है। प्रत्याकर्षक के कुछ प्रमुख कारक निम्नवत् हैं:

1. रोजगार के अवसरों का अभाव।
2. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा प्रशिक्षण का अभाव।
3. मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव।
4. आय प्राप्ति तथा उन्नति के अवसरों का अभाव।
5. सामाजिक तिरस्कार तथा बहिष्कार।
6. वैमनस्य एवं शत्रुता।
7. असामाजिक तत्वों का आतंक।
8. राजनीतिक, जातीय तथा धार्मिक आधार पर भेदभाव।

उपरोक्त कारणों से व्यक्ति गाँव छोड़कर शहर की ओर भागता है कि वहाँ जीवन-यापन का कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा और वह कष्टों से छुटकारा पा जाएगा।

9.3.2 देशान्तरण के मार्ग में बाधाएं अथवा गतिरोध (Hurdles in Migration)

मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होने के कारण किसी कार्य को करने से पहले सोचता-विचारता है और उसके लाभों एवं हॉनियों की पूरी विवेचना करता है। यही बात प्रवास के सम्बन्ध में भी लागू होती है। प्रवासी किसी स्थान को अपनी इच्छा से तब तक नहीं छोड़ना पसन्द करता है जब तक कि गन्तव्य स्थान उसके वर्तमान स्थान से अधिक लाभप्रद अथवा हितकारी नहीं लगता। कभी-कभी उसे अपनी इच्छा के विरूद्ध सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक बाध्यता के कारण एक देश (या स्थान) से दूसरे देश (या स्थान) को प्रवासित होना पड़ता

है। परन्तु कभी-कभी वह प्रवास की इच्छा रखते हुए भी स्थानान्तरण नहीं कर पाता है। क्योंकि उसे स्वराष्ट्र त्याग की अनुमति या प्रवेश पत्तन नहीं दिया जाता है। सामान्यतया देशान्तरण के मार्ग में निम्न तत्व बाधा उत्पन्न करते हैं

1. **दूरी** (Distance) निवास स्थान से गन्तव्य स्थान की दूरी जितनी अधिक होती है प्रवास की सम्भावना उतनी ही कम रहती हैं क्योंकि अधिक दूरी वाले स्थानों पर जाने में जोखिम तथा व्यय दोनों में वृद्धि हो जाती है।
2. **भाषा, संस्कृति एवं रीति-रिवाज** (Language, Culture and Social Customs) - मानव स्वभावतः अपनी बोली, भाषा, खान-पान, संस्कृति तथा सह-धर्मियों में ही उठना बैठना पसन्द करता है। दूसरे स्थान पर इन सबसे वंचित हो जाने तथा अपने आपको अलग तथा अकेला पाने का भय उसे देशान्तरित होने से रोकता है।
3. **वर्तमान व्यवसाय व स्थान से लगाव** (Attachment to present place and work) व्यक्तियों का अपने वर्तमान व्यवसाय, स्थान, परिवार, समाज तथा पास-पड़ोस के लोगों से इतना भावनात्मक लगाव होता है कि वे दूसरे स्थान या देश में प्रोन्नति एवं अधिक आय प्राप्त करने की सम्भावना के बावजूद प्रवास को पसन्द नहीं करते हैं।
4. **मार्ग व्यय** (Travelling expense) एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जैसे-जैसे दूरी बढ़ती जाती है मार्ग व्यय बढ़ता जाता है। मार्ग व्यय जितना अधिक होगा प्रवास उतना ही कम होगा।
5. **प्रवास क्षमता** (Migration Capacity) एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने के लिए एक विशेष प्रकार की क्षमता, निडरता तथा प्रगतिशीलता की आवश्यकता होती है। ग्रामीणों में इन गुणों की प्रायः कमी देखने की मिलती है। वे स्वभावतः संकोची एवं अशिक्षित होते हैं तथा शहरों में जाने से हिचकिचाते हैं। भारत में पंजाब के व्यक्तियों की प्रवास क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है।
6. **प्रवास के नियम** (Migration Laws)- अन्तर्राष्ट्रीय देशान्तरण में सबसे प्रभावपूर्ण बाधा देशों द्वारा बनाए गये प्रवास नियमों से होती है। कुछ देश अपने देश के निवासी को दूसरे देश में बसने की आज्ञा नहीं देते जबकि कुछ अपने यहाँ बहुत मुश्किल से बसने की आज्ञा देतें हैं। सामान्यतया आन्तरिक देशान्तरण पर किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं होता। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय देशान्तरण की अपेक्षा आन्तरिक देशान्तरण अधिक होता है।

9.3.3 प्रवास या देशान्तरण की माप (Measurement of Migration)

सामान्यतया प्रवास का विश्वसनीय आँकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे प्रवास या देशान्तरण का संख्यात्मक माप कठिन है परन्तु अध्ययन की सुविधा के लिये देशान्तरण या प्रवास को दो प्रकार से मापा जा सकता है: प्रत्यक्ष माप एवं अप्रत्यक्ष माप।

1 प्रत्यक्ष माप (Direct Measurement)

इस विधि में उन सभी व्यक्तियों की गणना की जाती है, जो प्रवास करते हैं। इसके अन्तर्गत जब कोई व्यक्ति एक स्थान से निवास बदल कर दूसरे स्थान पर जाता है तब उससे सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं यथा- नाम,

आयु, लिंग, व्यवसाय, कहाँ से निवास छोड़कर आया तथा कहाँ आकर बसा आदि का पंजीकरण किया जाता है। इन सूचनाओं का पंजीकरण न किए जाने पर देशान्तरण की प्रत्यक्ष माप करना सम्भव नहीं है। देशान्तरण के सम्बन्ध में एकत्र किए जाने वाले समंकों को दो भागों में बांटा जा सकता है - प्रथम प्रकार के समंकों को पारगमन समंक (Transit Statistics) कहते हैं जो किसी प्रशासनिक सीमा को पार करते समय एकत्रित किए जाते हैं। दूसरे प्रकार की गणना से सम्बन्धित समंकों को जनगणना-समंक (Census Statistics) कहते हैं जो किसी स्थान विशेष पर बाहर से आए व्यक्तियों की संख्या, स्थान व समय के सम्बन्ध में सूचना देते हैं।

यद्यपि क्षेत्रीय सीमा, कुल तथा वास्तविक प्रवासियों की संख्या, निवास की अवधि, एकल तथा बहुल स्तरीय प्रवास, मौसमी, उच्चावचन, समय अन्य की समस्याओं के कारण समंकों को एकत्र करने में कठिनाईयाँ होती हैं।

2 परोक्ष माप (Indirect Measurement)

प्रवास को मापने की परोक्ष बिधियाँ निम्नलिखित हैं:

(1) जीवन समंक विधि (Vital Statistics Methods) - इस विधि द्वारा दो जनगणनाओं के बीच की अवधि के लिए देशान्तरण का अनुमान लगाया जाता है तथा देशान्तरण की माप के लिए जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी समंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह की गणना के लिये निम्न सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है:

$$\mathbf{P_2 = P_1 + B - D + (I - E)}$$

उपरोक्त समीकरण में,

$\mathbf{P_2}$ = द्वितीय वर्ष की t_2 जनसंख्या $\mathbf{P_1}$ = प्रथम वर्ष की t_1 जनसंख्या

$\mathbf{B}$ = सजीव जन्मों की संख्या $\boldsymbol{D}$ = मृतकों की संख्या

$\mathbf{I}$ = अन्तर्गमन (Immigration) E = बहिगर्मन (Emigration)

उपरोक्त समीकरण के आधार पर तथा समयावधि के बीच प्रवास अथवा देशान्तरण को भी मापा जा सकता है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

$$\mathbf{(I - E) = (P_2 - P_1) - (B - D)}$$

इस तरह, उपरोक्त समीकरण की सहायता से दो समयावधियों के मध्य होने वाले देशान्तरण की गणना उस स्थान की कुल जनसंख्या वृद्धि में से जन्म तथा मृत्यु के अन्तर को घटाकर की जा सकती है।

उपर्युक्त समीकरण तभी प्रभावी हो सकता है जब किसी स्थान विशेष से सम्बन्धित सभी जन्म एवं मृत्यु उस स्थान में हों। शुद्ध परिणाम को प्राप्त करने के लिए समीकरण को निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है

$$\mathbf{P_2 = P_1 + B_i - D_i + B_e - D_e + (I - E)}$$

उपरोक्त समीकरण में,

$\mathbf{B_i}$ = स्थान विशेष में जन्म $\mathbf{D_i}$ = स्थान विशेष में मृत्यु

$\mathbf{B_e}$ = स्थान विशेष से बाहर जन्म $\mathbf{D_e}$ = स्थान विशेष से बाहर मृत्यु

उपरोक्त सूत्र को निम्नानुसार भी व्यक्त किया जा सकता है:

$$(\mathbf{P_2 - P_1}) - (\mathbf{B_i - D_i}) = (\mathbf{I - E}) + (\mathbf{B_e - D_e})$$

या

$$(\mathbf{I - E}) = (\mathbf{P_2 - P_1}) - (\mathbf{B_i - D_i}) - (\mathbf{B_e - D_e})$$

या

$$\mathbf{M} = (\mathbf{P_2 - P_1}) - (\mathbf{B_i - D_i}) - (\mathbf{B_e - D_e})$$

जहाँ, $\mathbf{M}$ =देशान्तरण

(2) सम्पूर्ण जीवन काल में सहगण के प्रवास की माप (Measurement of Cumulative Life Time Migration of Cohort) - इस विधि द्वारा किसी सहगण के सम्पूर्ण जीवन काल में प्रवास के प्रभाव की माप की जाती है। इस विधि में यह मान लिया जाता है कि जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का शत प्रतिशत पंजीकरण होता है। इस विधि द्वारा एक सहगण के सम्पूर्ण जीवन काल या जन्म से लेकर किसी वर्ष विशेष तक के प्रवास की माप की जाती है।

इस हेतु निम्न सूत्र दिया जाता है:

$$M = B - (D + P_2)$$

उपरोक्त सूत्र में,

M =प्रवास या देशान्तरण

B =स्थान विशेष एवं समय विशेष में सजीव जन्में शिशुओं की पंजीकृत संख्या

D =स क्षेत्र विशेष में पंजीकृत मृत्युओं की संख्या

P_2 = विशिष्ट सहगण से सम्बन्धित जीवित व्यक्तियों की संख्या जो जनगणना से प्राप्त हुई।

अर्थात्

प्रवास = किसी समय विशेष एवं क्षेत्र विशेष में पंजीकृत जन्मों की संख्या

− (उस क्षेत्र में पंजीकृत मृत्युओं की संख्या

+ उस सहगण से सम्बन्धित जीवित व्यक्तियों की संख्या जो जनगणना से प्राप्त हुई।)

3. उत्तर-जीविता अनुपात विधि (Survival Ratio Method) - इस विधि द्वारा देशान्तरण की गणना के लिए आयु वर्गानुसार आयु विशिष्ट जन्म एवं मृत्यु दर के आधार पर उसके वास्तविक जनसंख्या और भविष्य की प्रक्षेपित जनसंख्या का अन्तर मालूम कर लिया जाता है। यह अन्तर ही देशान्तरण की मात्रा है।

4. जन्म स्थान विधि (Birth Place Method)- इस विधि में देशान्तरण का अनुमान जनगणना के आँकड़ों के आधार पर लगाया जाता है। जनगणना में जन्म स्थान का उल्लेख किया जाता है। वर्तमान निवास स्थान से जन्म स्थान की तुलना करके अन्तर ज्ञात कर लिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें देशान्तरण काल का पता नहीं चल पाता।

5. सर्वेक्षण विधि (Survey Method)- इस विधि द्वारा प्रवास की जानकारी हेतु क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण के अन्तर्गत प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्ति विशेष के निवास स्थान, जन्म स्थान, कहाँ-कहाँ पिछला निवास रहा आदि की जानकारी एकत्र की जाती है। इन आँकड़ों के आधार पर प्रवास की गणना सहजता से की जा सकती है। यह विधि उन स्थानों पर अधिक उपयोगी होती है, जहाँ जनगणना नहीं हुई होती है।

9.3.4 देशान्तरण दरें (Migration Rates)

देशान्तरण के विविध प्रकारों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की देशान्तरण की दरों की गणना की जाती है। देशान्तरण की कुछ महत्वपूण दरें निम्नलिखित हैं:

1. सकल देशान्तरण दर (Gross Migration Rate) $M_g = \frac{I+O}{P} \times K$

2. शुद्ध देशान्तरण दर (Net Migration Rate) $M_n = \frac{I-O}{P} \times K$

3. अन्तर्देशान्तरण दर (In-.Migration Rate) $M_i = \frac{I}{P} \times K$

4. बहिर्देशान्तरण दर (Out-Migration Rate) $M_o = \frac{O}{P} \times K$

उपरोक्त सूत्र में,

I=अन्तर्देशान्तरणकारियों की सम्पूर्ण संख्या

O= बहिर्देशान्तरणकारियों की सम्पूर्ण संख्या

P= देशान्तरण अन्तराल के मध्य की सम्पूर्ण जनसंख्या

K= अनुपात दर, जो सामान्यतया प्रति हजार से होती है

9.3.5 प्रवास के परिणाम (Consequences of Migration)

प्रवास के नकारात्मक परिणाम के साथ-साथ कुछ विशेष लाभ भी हैं। जिन्हें निम्न तरह से समझा जा सकता है:

1 प्रवास के नकारात्मक परिणाम (Negative Consequences of Migration)

(1) सांस्कृतिक संघर्ष।

(2) आर्थिक विघटन

(3) धार्मिक विघटन

(4) पारिवारिक विघटन

(5) आत्महत्या

(6) नैतिक पतन

(7) निम्न स्वास्थ्य स्तर

(8) कार्यक्षमता में ह्रास

(9) उत्पादन में बाधा

(10) सुविधाओं से वंचित

(11) बेरोजगारी का भय

(12)श्रम संघों के विकास में बाधा

(13) अस्थिर जीवन

प्रवास के लाभ (Merits of Migration)

प्रवासिता अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं, जिससे व्यक्ति और समाज को अनेक प्रकार की हानियाँ उठानी पड़ती हैं, किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं हैं कि प्रवासिता से सिर्फ हानियाँ ही हैं, लाभ नहीं है। प्रवासिता से श्रमिकों तथा व्यापार को कुछ विशेष लाभ भी होते हैं। संक्षेप में, प्रवास के जो प्रमुख लाभ हैं, उन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है -

(1) आर्थिक लाभ - प्रवासिता से श्रमिक और उसके परिवार की आर्थिक दशा सुधरती है। श्रमिक शहरों में काम करते हैं। वे अपनी आर्थिक आय का कुछ भाग नियमित रूप में अपने परिवार के सदस्यों को भेजते हैं। इससे गाँव वालों की आर्थिक दशा अच्छी होती है। वे आसानी से अपने ऋण की अदायगी कर सकते हैं और साथ ही कृषि की उन्नति तथा अन्य प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं।

(2) सुरक्षा की भावना - उन श्रमिकों के लिए जो प्रवासी प्रवृत्ति के होते हैं, गाँव सुरक्षा का स्थान होता है। गाँव हर प्रकार के व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति जब भी बीमार, असहाय या अपंग हो जाता है तो ऐसे समय असहाय के लिए गाँव सुरक्षा का काम करता है।

(3) स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर - प्रवासी प्रवृत्ति श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। गाँव का वातावरण अत्यन्त ही स्वस्थ रहता है तथा यहाँ आकर व्यक्ति यान्त्रिक जीवन की नीरसता को भूल जाता है तथा अपनी थकान को कम करता है। इससे व्यक्ति को दोहरा लाभ होता है:

(i) व्यक्ति कुछ समय के लिए नगरों तथा औद्योगिक केन्द्रों के गन्दे वातावरण से अपने को दूर कर लेता है

(ii) गाँव के स्वस्थ वातावरण में रहकर वह अपने में नई स्फूर्ति और नई शक्ति का अनुभव करता है।

(4) भूमि पर जनसंख्या का कम दबाव - प्रवासिता से यह भी लाभ होता है कि इससे जनसंख्या का भूमि पर भार कुछ हल्का हो जाता है। इसका कारण यह है कि प्रवासन से खेती पर दबाव कम हो जाता है।

9.4 नगरीकरण (Urbanisation)

विश्व में नगरों का विकास कई शताब्दियों पूर्व हो चुका है। कहा जाता है कि नगरों की उत्पत्ति मानव सभ्यता के साथ ही आरम्भ हुई है। नगरों का सबसे पहले विकास मध्यपूर्व की उन नदियों की मैदानी घॉटियों में हुआ, जहाँ सिंचाई की उत्तम सुविधा सुलभ थी। मिस्र, इराक, पश्चिमी भारत में क्रमशः नील, दजला-फरात और सिन्धु की घाटियों में ईसा के 2,000 से 500 वर्ष पूर्व सिंचाई की व्यवस्थायें उपलब्ध थीं। मैम्फिस (मिस्र में) लगभग 3,000 वर्ष पुराना नगर है। मोहनजोदड़ों और हड़प्पा भी उतने ही पुराने नगर थे। इसके बाद यूनानी काल में अनेक नगरों का विकास हुआ। टर्की में इफीसस और मिलिटस, इटली में नेपल्स, मिस्र में सिकन्दरिया नगर पनपे। रोमन युग में ट्यूरिन, कोलोन, लन्दन, बेल्जियम नगर पनपे। अन्ध एवं मध्य युग में नगर, दुर्ग, छावनी या सैनिक केन्द्र, व्यापारिक नगरों के रूप में विकसित हुए। कार्लाइस (इंग्लैण्ड), बेल्स में कानबें, रूस में बारसा एवं मास्को, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट, इटली में वेनिस, मिलन एवं फ्लोरेंस, पश्चिमी एशिया में बगदाद एवं बसरा तथा अफ्रीका में ट्यूनिस, ट्रिपोली, आदि। पुनर्जागरण युग में भी अनेक नगरों का विकास एवं पुराने नगरों की बसावटों में परिवर्तन

किया गया। यूरोप में सेंटपीटर्सबर्ग, कोपेनहेगन, मैड्रिड, म्यूनिख आदि नगर विकसित हुए। आधुनिक काल में तो अब अनेक देशों में आवश्यक घटकों के कारण सैकड़ों नगर स्थापित हो चुके हैं।

1 नगरीकरण का अर्थ (Meaning of Urbanization)

सामान्यतया नगर से तात्पर्य उस स्थान विशेष से होता है, जहाँ एक बड़ा जनसमूह एक साथ रहता है। **ब्लाशे Blache** के अनुसार, ***"नगर एक व्यापक क्षेत्रीय संगठन होता है, यह सभ्यता के उस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जिन तक कुछ क्षेत्र नहीं पहुँच पाएं हैं और शायद जो कभी पहुँच भी न सकें। (A city is a social ogranisation of much greater scope, it is the expression of a stage of civilization which certain localities have not achieved and which they may perhaps never of themselves attain.)"***

इस तरह, नगर किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक विकास और संस्कृति प्रगति के सूचक होते हैं। इसी तरह की परिभाषा बर्गेल, थाम्पसन एवं लेविस, ग्रिफिथ टेलर, एल. रेसमैन अन्य भी दिये हैं। इस हेतु **प्रो. रेसमैन** का कथन उल्लेखनीय है, ***"नगरीकरण के अन्तर्गत परिवर्तन की सम्पूर्ण प्रक्रिया और उन परिणामों को जो कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलने पर तथा लघु अनुकूल समाज से प्रतिकूल बृहद् महानगरीय समाज में स्थानान्तरित होने से उत्पन्न होते हैं"*** को समाहित किया है।

2 नगरीकरण की विशेषतायें (Characteristics of Urbanization)

नगरीकरण की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं:

1. नगरीकरण एक प्रक्रिया हैं;
2. नगरीकरण की यह प्रक्रिया निरंतर गतिशील होती है;
3. इस प्रक्रिया का संबंध गामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन से है और
4. इस प्रक्रिया में जो परिवर्तन होता है, उससे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में समन्वय बनता है।

3 नगरीकरण के कारण (Causes of Urbanization)

नगरीकरण को बढ़ावा देने वाले कारणों को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है:

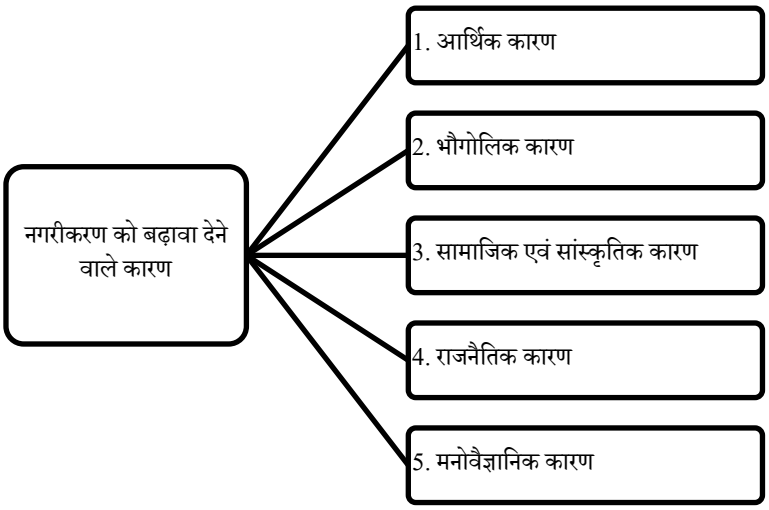

1. आर्थिक कारण:

i. **कृषि जोतों का अनार्थिक होना -** कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के फलस्वरूप अपखण्डन एवं विखण्डन के कारण कृषि जोतें अनार्थिक होती जा रही हैं। अतः वैकल्पिक रोजगार की तलाश में लोग गाँवों से शहरों की ओर आने लगते हैं।

ii. **कृषि-क्रान्ति -** कृषि क्रान्ति के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या की आवश्यकता रह गयी है। विकसित देशों में कृषि क्षेत्र में मात्र 5 से 10 प्रतिशत जनसंख्या कार्य करती है। कृषि क्षेत्र से अलग हुई यह जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए नगरों की तरफ प्रवास करती है।

iii. **यातायात के साधनों का विकास -** नगरों के विकास का एक अन्य कारण यातायात के साधनों का तीव्र गति से होने वाला विकास भी है।

iv. **औद्योगीकरण -** जिस स्थान पर उद्योगों की स्थापना होती है वहाँ पर यातायात के साधन, व्यापार तथा अन्य सम्बन्धित क्रिया-कलापों का विकास होने लगता है, श्रमिकों की आवश्यकता की चीजें भी वहाँ उपलब्ध होने लगती हैं जो अन्ततः श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और श्रमिक वहीं जाकर रहने लगता है। आवश्यक संरचना के विकास के फलस्वरूप अन्य व्यक्ति भी रोजगार की तलाश में आने लगते हैं। इस तरह नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। किंग्सले डेविस (Kingsley Davis) ने अपनी पुस्तक 'The Population of India and Pakistan'' में यह लिखा है कि ***"औद्योगिक विकास तथा नगरों में नवागन्तुकों की संख्या में वृद्धि के मध्य अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है।"***

v. **अद्ध व्यापार -** व्यापार नगर के अस्तित्व के लिए उतना ही आवश्यक है, जितना कि एक प्राणी के शरीर में रक्त का संचार आवश्यक है। व्यापार एवं व्यवसाय का केन्द्र होने के कारण ही प्राचीन काल में नगरों का विकास हुआ।

2. भौगोलिक कारण:

अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण के कारण प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता से हो जाती है। यही कारण है कि संसार में नगरों का विकास पहले नदियों की घाटियों में तथा समुद्र तटों के पास हुआ।

3. सामाजिक व सांस्कृतिक कारण:

अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक कारण भी नगरीकरण को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं यथा:

i. **शिक्षा केन्द -** जब कोई नगर शिक्षा का केन्द्र हो जाता है तो उसका विकास तेजी से होता है, क्योंकि वहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवसायी भी आकर बसने लगते हैं। इससे नगर का विकास होने लगता है। इलाहाबाद तथा वाराणसी नगर इसके उदाहरण हैं।

ii. **स्वास्थ्य व मनोरंजन के केन्द्र** - नगरों में उपलब्ध अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं तथा मनोरंजन के आधुनिक साधन भी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं।

iii. **धार्मिक व सांस्कृतिक केन्द्र -** भारत में काशी, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार इसके उदाहरण हैं।

iv. **ऐतिहासिक केन्द्र** - दिल्ली, आगरा, जयपुर, पटना तथा हैदराबाद जैसे नगरों का विकास इनके विभिन्न राजाओं की राजधानी होने के ऐतिहासिक महत्व से हुई है।

4. राजनैतिक कारण:

नगरों के विकास और नगरीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ राजनीतिक कारण निम्न हैं:

i. सुरक्षा - गाँवों की अपेक्षा नगरों में जीवन तथा सम्पत्ति सुरक्षित होने से लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं।

ii. प्रशासनिक केन्द्र - लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, नयी दिल्ली आदि नगरों का तेजी से विकास होने का कारण उनका राजधानी होना है।

iii. सरकारी नीति व सहायता - सरकारी उद्योगों की स्थापना, परिवहन, विद्युत आपूर्ति तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था में वृद्धि नगरीकरण को बढ़ावा देता है। भारत में चण्डीगढ़ तथा भुवनेश्वर जैसे नगरों की स्थापना, उन्हें राजधानी बनाने के साथ-साथ वहाँ सरकारी सुबिधाओं की वृद्धि से नगरीकरण का विकास हुआ।

5. मनौवैज्ञानिक कारण:

सामान्यतया यह देखा जाता है कि गाँवों में अनेक सुविधाओं के उपलब्ध होने के बावजूद लोग नगरों में ही बसना अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं, अन्य मनौवैज्ञानिक कारण भी नगरों के विकास में सहयोग करते हैं।

9.4.1 नगरीकरण के प्रभाव (Effects of Urbanization)

नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन निम्नलिखित दो शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है:

1. नगरीकरण के सकारात्मक एवं अच्छे प्रभाव
2. नगरीकरण के नकारात्मक प्रभाव

1 नगरीकरण के सकारात्मक प्रभाव:

1. ग्रामीण जनसंख्या में कमी तथा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि विकास का सूचक है।
2. कृषि का यंत्रीकरण प्रारम्भ होने से कृषि के साथ ही अन्य व्यवसायों का जन्म हो जाता है, जिससे कृषि का स्वरूप नगरोन्मुख व्यावसायिक हो जाता है।
3. शासकीय संस्थाओं का विकास होता है, जैसे - पुलिस, जेल, न्यायालय, शिक्षा संस्थाएँ, चिकित्सालय आदि।
4. व्यवसाय की विविधता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो जाती है।
5. राजनीतिक जागरूकता का विकास होता है। प्रजातन्त्र की महत्ता में वृद्धि होती है।
6. प्राथमिक समूहों की संख्या में कमी होती है और द्वैतीयक समूहों की संख्या में वृद्धि होने से उद्योग क्षेत्र में विकास होता है।
7. जाति-प्रथा का महत्व कम होने लगता है और नए-नए वर्गों का जन्म होता है। ये वर्ग अर्थ, शिक्षा, पद आदि पर आधारित होते हैं।

8. आवागमन और संचार के साधनों का विकास होने लगता है।
9. जनसंख्या अत्यधिक गतिशील रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि पड़ोस का विशेष महत्व नहीं होता है।
10. भौतिकवादी विचारधारा का विकास होता जाता है।
11. कूपमण्डूकता समाप्त होती है और बौद्धिक विकास होता है।
12. प्राथमिक नियन्त्रण के साधन शिथिल होते जाते हैं और द्वैतीयक नियन्त्रण के साधनों में वृद्धि होने से विकास की संभावना बढ़ती है।
13. धर्म के प्रभाव में कमी होने लगती है।
14. व्यापारिक मनोरंजनों की संख्या में वृद्धि होने लगती है और इन्हें जीवन की आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाता है।
15. अवकाश के महत्व में वृद्धि हो जाती है और जीवन अत्यन्त ही व्यस्त हो जाता है।
16. श्रम विभाजन को अधिक महत्व दिया जाने लगता है और विशेषीकरण में वृद्धि होती है।
17. ग्राहकों को लुभाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन होता है तथा उत्पादन और उपभोग में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
18. नगरीकरण के कारण आर्थिक प्रतिस्पर्धा प्रधान व्यवस्था का जन्म होता है। इसका परिणाम यह होता है कि शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को अपने कौशल प्रदर्शित करने के अच्छे अवसर मिलते हैं और वह तेजी से तरक्की पा सकते हैं।

2 नगरीकरण के नकारात्मक प्रभाव:

1. विशाल जनसंख्या के एक स्थान पर निवास करने के कारण मकानों की कमी हो जाती है और गन्दी बस्तियों का विकास होता है।
2. प्राथमिक समूहों की तुलना में द्वैतीयक समूहों के महत्व में वृद्धि से ग्रामीण उद्योग नष्ट होते हैं।
3. परिवार का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। संयुक्त परिवारों का विघटन प्रारम्भ हो जाता है और व्यक्तिगत परिवारों की संख्या में वृद्धि होने लगती है।
4. समूह की भावना समाप्त होने लगती है और व्यक्तिवाद की भावना का विकास होता है।
5. परार्थवाद की भावना का विनाश प्रारम्भ हो जाता है और स्वार्थवाद की भावना का विकास प्रारम्भ हो जाता है।
6. यौन अपराध बढ़ते हैं।
7. नैतिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगता है और नैतिकता की नवीन व्याख्या की जाती है।
8. विवाह का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। धर्म के स्थान पर विवाह में समझौता को अधिक महत्व दिया जाता है। वैवाहिक बन्धनों में शिथिलता का विकास हो जाता है।
9. जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही साथ अपराधों और बुरी आदतों का विकास होता है।
10. ग्रामीण उद्योग धन्धों का विनाश हो जाता है और नगरीय उद्योग-धन्धों में वृद्धि हो जाती है।

11. कानून व्यवस्था और सुरक्षा सम्बन्धी राज्यों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि हो जाती है। जिससे सरकारी व्यय बढ़ता है।

9.4.2 विश्व में नगरीकरण की कालिक प्रवृत्ति (Periodic Tendency of Urbanization in World)

औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व नगरों की संख्या तथा नगरीय जनसंख्या बहुत कम थी। प्राचीन नगरों का प्रमुख आधार उपजाऊ कृषि क्षेत्र थे। सन् 1850 ई. तक विश्व की लगभग 4 प्रतिशत जनसंख्या ही नगरीय थी। मध्ययुग में इनका आधार व्यापार तथा कुटीर उद्योग हो गया। धीरे-धीरे नगरों के विकास में राजनीतिक आधार के साथ आर्थिक आधार महत्वपूर्ण होता गया। आधुनिक नगरीकरण औद्योगिक क्रान्ति के साथ प्रारम्भ हुई। इसका सूत्रपात 18वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में हुआ तथा वहाँ से यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में तीव्रता से फैला। औद्योगिक केन्द्रों में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से इन केन्द्रों की ओर भारी स्थानान्तरण हुआ जिससे नगरीय जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ी। रोजगार के अवसर के अतिरिक्त नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ, कार्य सम्बन्धी उत्तम दशाएँ, समुचित आवास व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के साधनों, नागरिक सेवा तथा समाज कल्याण आदि कार्यों ने भी ग्रामीण जनसंख्या को अधिक आकर्षित किया। वस्तुतः नगरों के प्रधान कार्य वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग, विभिन्न संसाधन व अन्य सेवाएँ हैं। इन्हीं के विकास की अवस्था से नगरीकरण की मात्रा निर्धारित होती है। औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व किसी भी क्षेत्र में नगरीकरण का प्रभाव अत्यन्त अल्प था। इसका प्रमुख कारण गाँवों के पास कृषि उत्पादन की उस मात्रा में कमी थी जिसके माध्यम से नगरों से सम्बन्ध जुड़ता है। परन्तु तकनीकी व औद्योगिक विकास के साथ-साथ कृषि क्षेत्रों में खाद्यान्नों के साथ अन्य उत्पादनों को बल मिला जिससे नगरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी। सारणी 9.1 में 1800 से 1990 ई. में मध्य संसार में हुए नगरीकरण की प्रबृत्ति के विकास का विवरण प्रस्तुत है।

सारणी 9.1

विश्व में नगरीकरण की कालिक प्रवृत्ति

वर्ष	विश्व की कुल जनसंख्या (मिलियन में)	कुल नगरीय जनसंख्या (मिलियन में) (20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगर)	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	दशाब्दि वृद्धि - दर प्रतिशत में
1800	906	21.7	2.4	26.5
1850	1171	50.4	4.3	38.7
1900	1608	147.9	9.2	48.0
1950	2530	502.6	20.0	50.0
1960	3027	753.7	24.9	41.6
1980	4415	1408.0	31.9	61.7
1990	5295	2277.0	43.0	26.5

Source:U.N.Demographic Year Book,1992

9.4.3 विश्व में नगरीकरण का प्रारूप (Pattern of Urbanization in World)

विश्व में नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी व्यापक असमानता पायी जाती है। अल्पविकसित, विकासशील व विकसित देशों में नगरीकरण की मात्रा में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है।

विश्व में नगरीकरण की मात्रा के आधार पर 4 क्षेत्र प्रमुख हैं -

1. **अति उच्च नगरीकरण के क्षेत्र -** इस क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत से अधिक भाग नगरों में रहता है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, उत्तर-पश्चिम यूरोप के देश, दक्षिण अमेरिका का अर्जेण्टाइना, बेनेजुएला, ब्राजील, चिली तथा उरूग्वे, जापान, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड आदि सम्मिलित हैं।
2. **उच्च नगरीकरण के क्षेत्र -** इस क्षेत्र के अन्तर्गत वे देश सम्मिलित हैं जहाँ 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय केन्द्रों में निवास करती है। ऐसे देशों में दक्षिणी तथा पूर्वी यूरोप के देश, रूस, कोलंबिया, इक्वाडार, पीरू, बोलीबिया, मध्य अमेरिकी देश, दक्षिण-पूर्व एशिया, ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, जार्डन आदि प्रमुख हैं।

   उपर्युक्त प्रमुख देशों के अतिरिक्त अफ्रीका में अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, दक्षिण अफ्रीका तथा एशिया में कोरिया, मंगोलिया आदि नगरीकरण के क्षेत्र बिखरे हुए हैं।
3. **मध्यम नगरीकरण के क्षेत्र -** इसके अन्तर्गत ऐसे देश सम्मिलित हैं, जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है तथा सामान्य औद्योगीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। विश्व में मध्यम नगरीकरण के निम्नांकित 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है।
   - दक्षिणी व दक्षिण-पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान व यमन;
   - पूर्वी व दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन, इण्डोनेशिया, मलयेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन्स;
   - उत्तरी अफ्रीका में मिस्र व मोरक्कों;
   - पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट से होते हुए सेनेगल तक का क्षेत्र;
   - मध्य अफ्रीकी देश तथा पूर्वी अफ्रीका के जांबिया, जिम्बाम्बे, मोजाम्बिक तथा दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया व बोत्सवाना।
4. **निम्न नगरीकरण के क्षेत्र -** विश्व के 25 प्रतिशत से कम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पूर्वी अफ्रीकी, दक्षिण एशियाई व दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश सम्मिलित हैं। ये देश कृषि व पशुपालन प्रधान हैं।

9.4.4 विश्व में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर

विश्व में 36 महानगर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। ऐसे महानगरों का नाम एवं उनकी जनसंख्या को इस सारणी 9.2 में प्रदर्शित किया गया है:

सारणी 9.2

क्रमांक	महानगर का नाम	सम्बन्धित देश का नाम	जनसंख्या (मिलियन में)
1.	मेक्सिको सिटी	मेक्सिको	20.2
2.	टोकियो	जापान	18.1
3.	साओ पोलो	ब्राजील	17.4
4.	ग्रेटर मुम्बई	भारत	16.4
5.	न्यूयार्क	यू.एस.ए.	16.2
6.	शंघाई	चीन	13.4
7.	कोलकाता	भारत	13.2
8.	दिल्ली	भारत	12.8
9.	लास एंजिल्स	यू.एस.ए.	11.9
10.	ब्यूनस आयर्स	अर्जेन्टाइना	11.5
11.	सियोल	कोरिया गणराज्य	11.0
12.	बीजिंग	चीन	10.8
13.	रियोडिजेनारियो	ब्राजील	10.7
14.	तियानजिन	चीन	9.4
15.	जकार्ता	इण्डोनेशिया	9.3
16.	कैरो	मिस्र	9.0
17.	मास्को	रूस	8.8
18.	मेट्रो मनीला	फिलीपीन्स	8.5
19.	ओसाका	जापान	8.5
20.	पेरिस	फ्रांस	8.5
21.	कराची	पाकिस्तान	7.7
22.	लागोस	नाइजीरिया	7.7
23.	लन्दन	यू.के.	7.4
24.	बैंकाक	थाईलैण्ड	7.2
25.	शिकागो	यू.एस.ए.	7.0
26.	तेहरान	ईरान	6.8
27.	इस्तांबूल	तुर्की	6.7
28.	ढाका	बांग्लादेश	6.6
29.	चेन्नई	भारत	6.4
30.	लीमा	पेरू	6.2
31.	बंगलौर	भारत	5.7
32.	हैदराबाद	भारत	5.5
33.	हांगकांग	चीन	5.4
34.	मिलान	इटली	5.3
35.	मैड्रिड	स्पेन	5.2
36.	लेनिनग्राद	रूस	5.1

नोट - भारत के महानगरों की जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े 2001 की जनगणना पर आधारित हैं तथा शेष अन्य महानगरों की जनसंख्या सम्बन्धी ऑकड़े संयुक्त राष्ट्र संघ की नगरीय संख्या चार्ट, 1990 पर आधारित है।

उपरोक्त सारणी 9.2 से स्पष्ट होता है कि मेक्सिको सिटी विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है जिसकी जनसंख्या 20.2 मिलियन है। दूसरे स्थान पर टोकियो (18.1 मिलियन) तीसरे स्थान पर साओ पोलो (17.4 मिलियन), चौथे स्थान पर ग्रेटर मुम्बई (16.4 मिलियन) तथा विश्व में जनसंख्या के आधार पर सातवाँ स्थान कोलकाता (13.2 मिलियन) महानगर का है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विश्व में 50 लाख से अधिक आबादी वाले जो 36 महानगर हैं, उनमें से छः - मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर तथा हैदराबाद भारत में हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बढ़कर 35 हो गयी थी, जबकि 2011 में यह संख्या अधिक हो गयी है।

9.4.5 विश्व के कुछ प्रमुख देशों में नगरीकरण का स्तर (Level of Urbanization in Selected Countries of the World)

अग्र सारणी 9.3 में विश्व के चुने हुए देशों में उसकी कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात को प्रदर्शित किया गया है।

सारणी - 9.3

विश्व के कुछ चुने हुए देशों में नगरीकरण का स्तर (2004)

देश/क्षेत्र	देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
सम्पूर्ण विश्व	48.3
आस्ट्रेलिया	88.0
न्यूजीलैण्ड	86.1
यू.एस.ए.	80.5
जापान	65.7
चीन	39.5
भारत	28.5
पाकिस्तान	34.5
श्रीलंका	15.2
थाईलैण्ड	32.0
बांग्लादेश	24.7
नेपाल	15.3
बेलारूस	71.8

Source: Human Development Report, 2006

उपरोक्त सारणी 9.3 से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण विश्व की 48.3 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उक्त सारणी के अनुसार आस्ट्रेलिया की 88 प्रतिशत, न्यूजीलैण्ड की 86.1 प्रतिशत, यू.एस.ए. की 80.5 प्रतिशत, जापान की 65.7 प्रतिशत, बेलारूस की 71.8 प्रतिशत, जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जबकि चीन में 39.5 प्रतिशत, पाकिस्तान में 34.5 प्रतिशत, भारत में 28.5 प्रतिशत, थाईलैण्ड में 32.0 प्रतिशत, श्रीलंका में 15.2 प्रतिशत, बांग्लादेश में 24.7 प्रतिशत तथा नेपाल में 15.3 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है।

इस तरह, हम देख सकते हैं कि भारत सहित अन्य विकासशील देशों में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बहुत नीचा है। औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत बहुत ऊँचा है। इससे स्पष्ट होता है कि औद्योगीकरण के फलस्वरूप नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है।

सारणी - 9.4

(अ) सर्वाधिक नगरीकृत 5 देश - 2008	
देश	नगरीकरण % में
हांगकांग/सिंगापुर	100%
कुबैत	98
बेल्जियम	97
कतर	96
भारत	29.0
विश्व	50
(ब) न्यूनतम नगरीकृत 5 देश - 2008	
देश	नगरीकरण % में
तुरूड़ी	10
पापुआ न्यू गिनी	12
उगांडा/त्रिनिदाद	13
श्रीलंका	15
नाइजर	16

9.4.6 भारत में नगरीकरण सम्बन्धी कुछ तथ्य (Some Facts About India's Urbanization)

- 1991 में भारत मे केवल 4 मेगापालिस प्रकार (मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई) के नगर थे।
- 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मेगापोलिस (50 लाख से अधिक) नगरों की संख्या 6 हो गयी है, जो इस प्रकार हैं -मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर एवं हैदराबाद।
- भारत में चतुर्थ श्रेणी के नगरों की सर्वाधिक संख्या है।
- सर्वाधिक नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में हैं।

- 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 महानगर हैं जबकि 1991 में 23 ही थे।
- इन 35 महानगरों में से 6 उत्तर प्रदेश के हैं, जिनका नामं - कानपुर (26,90,486), लखनऊ (22,66,933), आगरा (13,21,410), वाराणसी (12,11,749), मेरठ (11,67,399) एवं इलाहाबाद (10,49,579) है।

सारणी 9.5

(अ) शीर्ष पाँच नगरी जनसंख्या	
राज्य	जनसंख्या (करोड़ में)
महाराष्ट्र	4.11
उत्तर प्रदेश	3.45
तमिलनाडु	2.74
पं0 बंगाल	2.24
आन्ध्र प्रदेश	2.08
(ब) न्यूनतम पाँच नगरीय जनसंख्या	
राज्य	जनसंख्या (लाख में)
सिक्किम	0.59
अरूणाचल प्रदेश	2.27
नागालैण्ड	3.42
मिजोरम	4.41
मेघालय	4.54

2001 के नगरीकरण के आँकड़ों के अनुसार पूर्वी भारत की अपेक्षा पश्चिमी भारत तथा उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत का नगरीकरण अधिक हुआ है। उत्तर व उत्तर पूर्व में हिमालय के पर्वतीय भाग भारत के सबसे कम नगरीकरण वाले क्षेत्र हैं।

सामान्यतः नगरीकरण से कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात का बोध होता है। यदि ग्रामीण जनसंख्या का वृद्धि दर नगरीय जनसंख्या के वृद्धि दर के समान हो तो नगरीकरण की वृद्धि दर शून्य मानी जाती है। यदि ग्रामीण जनसंख्या का वृद्धि दर नगरीय जनसंख्या के वृद्धि दर से अधिक हो तो नगरीकरण की वृद्धि दर ऋणात्मक होती है। इस अर्थ में भारत में नगरीकरण बढ़ रहा है।

सारणी 9.6

प्रमुख नगर	वास्तुकार
नई दिल्ली	ई. लूटयेन्स
चण्डीगढ़	कार्बुसियर
कोलकाता	जॉब चार्नाक

- चण्डीगढ़ एवं पाण्डिचेरी नियोजित नगर हैं।
- शीर्ष पाँच नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले प्रदेशों के अलावा पंजाब (33.9 प्रतिशत), कर्नाटक (34.0 प्रतिशत), हरियाणा (28.9 प्रतिशत) तथा पश्चिम बंगाल (28.0 प्रतिशत) में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

सारणी 9.7

सर्वाधिक नगरीय केन्द्रशासित जनसंख्या	
केन्द्रशासित क्षेत्र	जनसंख्या % में
दिल्ली	93.2
चण्डीगढ़	89.8
पाण्डिचेरी	66.6
लक्षद्वीप	44.5
दमन एवं दीव	36.2

सारणी 9.8

(अ) न्यूनतम पाँच नगरीय जनसंख्या प्रतिशत	
राज्य	जनसंख्या % में
हिमाचल प्रदेश	9.8
बिहार	10.5
सिक्किम	11.1
असम	12.9
उड़ीसा	15.0
(ब) शीर्ष पाँच नगरीय जनसंख्या प्रतिशत	
राज्य	जनसंख्या % में
गोवा	49.8
मिजोरम	49.6
तमिलनाडु	44.0
महाराष्ट्र	42.4
गुजरात	37.4
(स) न्यूनतम तीन नगरीय केन्द्रशासित जनसंख्या	
केन्द्रशासित क्षेत्र	जनसंख्या % में
दादरा एवं नगर हवेली	22.9
अण्डमान, निकोबार	32.6
दमन एवं दीव	36.2

सारणी 9.9

भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर (2001 की अनंतिम स्थिति)	
शहर	जनसंख्या
1.बृहत मुम्बई (महाराष्ट्र)	16368084
2.कोलकाता (पं0 बंगाल)	13216546
3.दिल्ली	12791458
4.चेन्नई (तमिलनाडु)	6424624
5.बंगलौर (कर्नाटक)	5686844
6.हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	5533640
7.अहमदाबाद (गुजरात)	4519278
8.पुणे (महाराष्ट्र)	3755525
9.सूरत (गुजरात)	2811466
10.कानपुर (उत्तर प्रदेश)	2690486
11.जयपुर (राजस्थान)	2324319
12.लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	2266933
13.नागपुर (महाराष्ट्र)	2122965
14.पटना (बिहार)	1707429
15.इन्दौर (मध्य प्रदेश)	1639044
16.बड़ोदरा (गुजरात)	1492398
17.भोपाल (मध्य प्रदेश)	1454830
18.कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	1446034
19.लुधियाना (पंजाब)	1395053
20.कोच्चि (केरल)	1355406
21.विशाखापत्तनम् (आन्ध्र प्रदेश)	1329472
22.आगरा (उत्तर प्रदेश)	1321410
23.वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	1211749
24.मदुरई (तमिलनाडु)	1194665
25.मेरठ (उत्तर प्रदेश)	1167399
26.नासिक (महाराष्ट्र)	1152048
27.जबलपुर (मध्य प्रदेश)	1117200
28.जमशेदपुर (झारखण्ड)	1101804
29.आसनसोल (पं. बंगाल)	1090171
30.धनबाद (झारखण्ड)	1064357
31.फरीदाबाद (हरियाणा)	1054981
32.इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	1049579
33.अमृतसर (पंजाब)	1011327
34.विजयवाड़ा (राजस्थान)	1011152
35.राजकोट (गुजरात)	1002160

9.5 अभ्यास प्रश्न(Practice Questions)

लघु उत्तरीय प्रश्न

निम्न पर टिप्पणी लिखें -

(अ) देशान्तरण के मार्ग की बाधायें।

(ब) विश्व में नगरीकरण का प्रारूप

(स) नगरीकरण की विशेषतायें

(द) नगरीकरण की कालिक प्रवृत्ति

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. प्रवासन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है?

A. पानी की कमी B. बेरोजगारी

C. चिकित्सा सुविधाएं D. महामारी

2. प्रवासन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है?

A. पानी की कमी B. रोज़गार

C. चिकित्सा सुविधाएं D. शिक्षण सुविधाएं

3. प्रवासन में निम्नलिखित में से कौन से कारक बाधा हैं?

A. दूरी

B. भाषा, संस्कृति और सामाजिक रीति-रिवाज

C. वर्तमान स्थान और कार्यों के लिए लगाव

D. उपरोक्त सभी।

9.6 सारांश (Summary)

इस इकाई की प्रस्तावना में विषय को स्पष्ट करते हुए प्रवासन तथा नगरीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। तत्पश्चात् प्रवास तथा स्थानान्तरण को बताया गया है। पुनः देशान्तरण को प्रभावित करने वाले आकर्षक तथा प्रत्याकर्षक कारकों, देशान्तरण की बाधाओं, देशान्तरण की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष मापों, देशान्तरण दरों, प्रवास के परिणामों को बताया गया हे। इस तरह इस शीर्षक के प्रथम भाग में देशान्तरण के विभिन्न तकनीकी शब्दों को स्पष्ट किया गया है।

शीर्षक के दूसरे भाग में नगरीकरण का अर्थ, नगरीकरण की विशेषतायें, नगरीकरण के कारण, नगरीकरण के सकरात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों को बताया गया है। इसी तरह नगरीकरण के प्रारूप को स्पष्ट करने के लिए विश्व में नगरीकरण की कालिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए विश्व में नगरीकरण का प्रारूप बताया गया है। जिसके अन्तर्गत विश्व के सम्पूर्ण क्षेत्र को चार भागों - अति उच्च नगरीकरण, उच्च नगरीकरण, मध्यम नगरीकरण तथा निम्न नगरीकरण में बाँटा गया है। साथ ही विश्व में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 36 महानगरों का क्रम दिया गया है। विषय की स्पष्टता हेतु विश्व के कुछ प्रमुख देशों में नगरीकरण का स्तर, सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र वाले 5 देशों

के साथ-साथ भारत में नगरीकरण सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाया गया है। इस तरह इस इकाई के अध्ययन में प्रवासन और नगरीकरण की अवधारणा के साथ साथ इसके विभिन्न प्रारूपों को स्पष्ट किया गया है।

9.7 शब्दावली (Glossary)

- उदारीकरण - Liberalisation
- निजीकरण - Privatisation
- वैश्वीकरण - Globalisation
- प्रब्रजक या प्रवासी - Emigrants
- आब्रजक या अन्तर प्रवासी - Immigrants
- विचरणकर्ता - Movers
- बाधायें - Hurdles

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. C 2. A 3. D

9.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- डॉ. मिश्रा, जे. पी., *जनांकिकी*, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा।
- डॉ. बघेल, डी. एस., *जनांकिकी*, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
- डॉ. पन्त, जीवन चन्द्र, *जनांकिकी*, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
- अशोक कुमार, *जनसंख्या, एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन*, हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रयाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय*, भारत सरकार
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग*, भारत सरकार
- *भारतः 2013*, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

9.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- Agarwal, S.N. (1972), *India's population problem*. Tata Mcgraw Hill Co., Bombay.
- Choubey, P.K. (2000), *Population Policy in India*, Kanishk Publication, New Delhi
- Gulati, S.C. (1988), *Fertility in India and Econometric Study of Metropolis*, Sage, NewDelhi.

- Gulati, S.C. (1998), *Basic Demographic Techniques and Applications*, Saga Publication, New Delhi.
- Srinivasan, K. (1998), *Basic Demographic Techniques and Applications*, SagaPublication, New Delhi
- Dr. Premi, M.K., Ramanamma, A., Bambawale, Usha,. An Introduction to social demography, Vikas Publishing House, New Delhi.
- Appleman, Philip (ed.) Thomos Robert Malthus : An Essay on the Principle of Population, New York : W.W. Norton and Co., Inc., 1976.

9.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. प्रवास से क्या समझते हैं? प्रवासन के उद्देश्यों को बताइये।
2. देशान्तरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझाइये।
3. प्रवास या देशान्तरण की माप से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष मापों को बताइये।
4. आप नगरीकरण से क्या समझते हैं? नगरीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिये।
5. नगरीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजियें।

इकाई 10 - जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रतिमान पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन के प्रभाव, प्रवासन के प्रभावकारी कारक

(Impact of National and International Migration on Population Growth and its Paradigm)

10.1 प्रस्तावना

10.2 उद्देश्य

10.3 प्रो. वेब का जनसंख्या परिवर्तन का प्रवासन

10.4 प्रवासन या देशान्तरण के प्रभावकारी कारक

10.5 देशान्तरण के मार्ग में बाधायें अथवा गतिरोध

10.6 वैश्विक जनसंख्या में स्थानान्तरण की प्रवृत्तियाँ

10.7 प्रवासन या स्थानान्तरण या देशान्तरण के प्रभाव

10.8 अभ्यास प्रश्न

10.9 सारांश

10.10 शब्दावली

10.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

10.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

10.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

10.14 निबंधात्मक प्रश्न

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

इस इकाई के अन्तर्गत हम प्रवासन के प्रभावकारी कारकों तथा जनसंख्या वृद्धि एवं उसके आधार पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन के प्रभावों का अध्ययन करेंगे।

10.2 उद्देश्य (Objectives)

- ✓ प्रवास एवं जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि के सम्बन्धों को समझना।
- ✓ प्रवासन के मूल कारकों - आकर्षण तथा विकर्षण तत्वों का अध्ययन करना।
- ✓ देशान्तरण की बाधाओं को समझना।
- ✓ वैश्विक जनसंख्या में स्थानान्तरण की प्रवृत्तियों - प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक एवं आधुनिक जनसंख्या स्थानान्तरण की स्थितियों का अध्ययन करना।
- ✓ प्रवासन के प्रभावों को समझना।

10.3 प्रो. बेब का जनसंख्या परिवर्तन का प्रवासन (Prof. WEB'sMigration Theory of Population Trends)

प्रवासन या देशान्तरण जीवन का सत्य है। वास्तव में, जनसंख्या के देशान्तरण का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है, सम्भवतः उतना ही जितना कि मनुष्य का। अन्तर्राष्ट्रीय देशान्तरण की घटनाएँ भी सदियों पुरानी हैं। यदि इतिहास का अवलोकन करें तो ईसा से अनेक वर्षों पूर्व आर्य मध्य एशिया से भारत आये थे। इसी प्रकार मध्यकाल में अंग्रेज तथा फ्रांसीसी आस्ट्रेलिया तथा उत्तरी अमेरिका में जाकर बस गये थे। विभिन्न देशों का इतिहास इसी प्रकार की प्रवास की घटनाओं से भरा हुआ है।

अनेक ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में जहाँ गतिशीलता का अभाव होता है, वहाँ भी लगभग आधी जनसंख्या - महिला जनसंख्या विवाहोपरान्त प्रवासित होती है। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय देशान्तरण साधनों, श्रम-शक्ति, रोजगार के अवसरों, आवास सुविधाओं के सन्दर्भ में लोगों का पुनर्वितरण करता है। देशान्तरण से तात्पर्य थोड़े समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने से नहीं लिया जाता है बल्कि इसके अन्तर्गत प्रवास एक अवधि के लिए होना चाहिए।

विभिन्न जनांकिकीवेत्ता एवं संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने जनसंख्या सम्बन्धी विचार को जन्म व मृत्यु-दर एवं आर्थिक विकास के आधार पर प्रस्तुत किया है। परन्तु प्रव्रजन (Migration) से स्थानीय जनसंख्या बहुत प्रभावित होती है। **प्रो. वेब** ने जनसंख्या के स्थानान्तरण को भी ध्यान में रखकर जनसंख्या-विकास का विश्लेषण किया है। किसी देश की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तीन तत्व हैं –

i. जन्म-दर
ii. मृत्यु दर तथा
iii. प्रवास।

गत्यात्मक जनांकिकी के अध्ययन के लिए देशान्तरण का अध्ययन आवश्यक है। किसी समाज में जनसंख्या वृद्धि तीन प्रकार से सम्भव है; यथा

i. जन्म-दर में वृद्धि हो,
ii. मृत्यु-दर घट जाये अथवा
iii. अप्रवासन (Immigration) के द्वारा जनसंख्या वृद्धि हो।

इसी प्रकार किसी समाज में जनसंख्या में कमी भी तीन प्रकार से सम्भव है: यथा

i. जन्म-दर में कमी,
ii. मृत्यु दर में वृद्धि , तथा
iii. उत्प्रवासन (Emigration) के द्वारा जनसंख्या में कमी।

प्रो. वेब ने अपने **'कार्टीशियन कोआर्डिनेट ग्राफ'** चित्र 10.1 की सहायता से जनसंख्या परिवर्तनों को स्पष्ट किया है। जिसके आधार पर प्रो. वेब ने जनसंख्या परिवर्तन के आठ प्रकार बताये हैं:

1. यदि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि शुद्ध प्रवास से अधिक होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी।
2. यदि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि शुद्ध अप्रवास से अधिक होगी तो भी जनसंख्या में वृद्धि होगी।
3. यदि शुद्ध अप्रवास जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से अधिक हो तो जनसंख्या बढ़ेगी।
4. यदि जनसंख्या में प्राकृतिक ह्रास के साथ शुद्ध अप्रवास अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होती है।
5. यदि जनसंख्या का प्राकृतिक ह्रास शुद्ध अप्रवास से अधिक हो, तो जनसंख्या घटेगी।
6. यदि जनसंख्या का प्राकृतिक ह्रास शुद्ध प्रवास से अधिक हो तो जनसंख्या में ह्रास होगा।
7. यदि जनसंख्या का वास्तविक ह्रास शुद्ध प्रवास से अधिक होगा तो जनसंख्या में कमी आयेगी।
8. यदि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से शुद्ध प्रवास अधिक पाया जाता है तो भी जनसंख्या घटेगी।

चित्र - 10.1 क्लार्क का कार्टिशियन कोआर्डिनेट ग्राफ

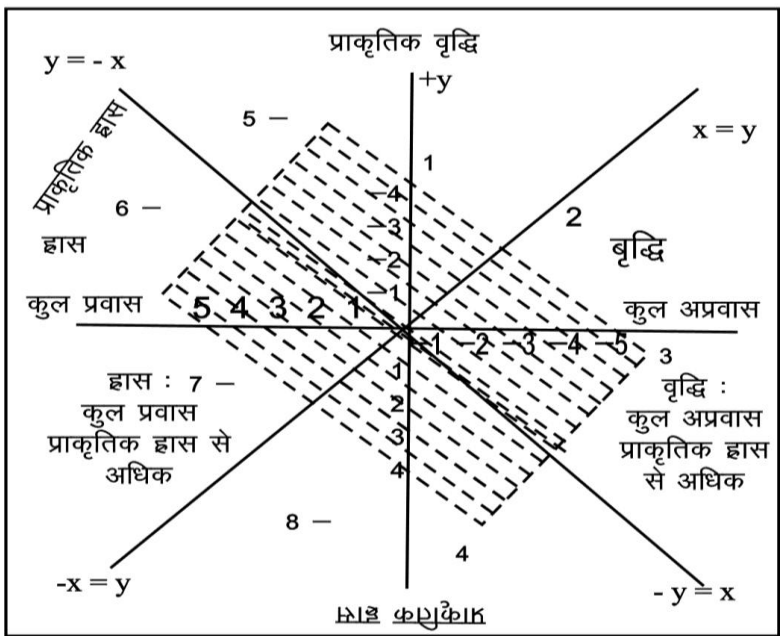

इस तरह प्रो. वेब के अनुसार जनांकिकी अध्ययन की दृष्टि से प्रवास (Migration) का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण यह है कि यह जनसंख्या के आकार, संरचना तथा वितरण को तत्काल प्रभावित करता है। जनसंख्या के परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले अन्य दो तत्व जन्म-दर तथा मृत्यु-दर दोनों का स्वरूप इस प्रकार का है कि वे जनसंख्या को धीमी गति से प्रभावित करते हैं तथा इन दोनों तत्वों का पूर्वानुमान भी लगाया जाना सम्भव है। जहाँ तक प्रवास का सम्बन्ध है यह एक आकस्मिक घटना होती है एवं इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकना सम्भव नहीं होता। देशान्तरण से विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जनांकिकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों की श्रृंखला प्रारम्भ हो जाती है। **बार्कले (Barclay)** के शब्दों में, ***"देशान्तरण सामान्यतः इन प्रक्रियाओं की 'सामान्य' गति को छिन्न-भिन्न कर देती है। इसका प्रभाव अत्यन्त तीव्र गति से होता है, इसके द्वारा कुछ ही माहों में करोड़ों लोगों का स्थानान्तरण हो जाता है तथा इससे लोगों की गतिविधियाँ तथा वितरण भी महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। (Migration usually disrupts the 'normal' course of these processes. It can be very rapid in the effects, transferring millions of persons in a matter of months and altering significantly the distribution of people and their activities.)"***

जनांकिकी अध्ययन में देशान्तरण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बार्कले (Barclay) ने लिखा है कि ***"इन शक्तियों के साथ, देशान्तरण वृहद् तथा आकस्मिक परिवर्तनों से सम्बन्धित है। इसी कारण से अक्सर इसका पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं होता है तथा अध्ययन कठिन होता है। यह आर्थिक उच्चावचनों तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं से अत्यन्त निकटता से सम्बन्धित है तथा सम्भवतः जनांकिकी में अन्य किसी भी विषय की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करता है। (With these potentialities, migration is associated with large and rather sudden change. For this reason it is often unpredictable and difficult to study. It is closely connected with economic fluctuation and important national events and probably occupies more attention than any other topic in demography.)"***

10.4 प्रवासन या देशान्तरण के प्रभावकारी कारक (Factors Affecting Migration)

देशान्तरण को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रवास अमुक विशिष्ट तत्व से ही प्रभावित होता है। देशान्तरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों में से कभी कोई तत्व प्रमुख होता है तो कभी कोई दूसरा तत्व तो कभी अनेक तत्व एक साथ क्रियाशील हो जाते हैं। देशान्तरण को प्रभावित करने वाले तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यथा- प्रथमतः आकर्षक तत्व (Pull Factors) तथा द्वितीयतः प्रत्याकर्षक तत्व (Push Factors)।

1 आकर्षक तत्व (Pull Factors)

देशान्तरण के आकर्षक तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति को अपना निवास-स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर बसने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दूसरे शब्दों में ये ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन तत्वों के अन्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों का समावेश किया जाता है:

(1) रोजगार के अच्छे अवसर।

(2) स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा प्रावैधिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ।

(3) मनोरंजन के विभिन्न साधनों की उपलब्धता।

(4) आय वृद्धि के अवसर।

(5) उन्नत नगरीय जीवन।

(6) शैक्षणिक योग्यता तथा विशिष्ट प्रशिक्षण के उपयुक्त रोजगार की उपलब्धता।

(7) सगे-सम्बन्धियों तथा इष्ट मित्रों का आकर्षण।

(8) स्वास्थ्यप्रद जलवायु के क्षेत्र।

उपरोक्त तत्व गाँव से शहरों की ओर आकर्षित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। पौन्सिओन (Ponsioen) के मतानुसार ***''आर्थिक विकास सामान्यतः विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में असमान होता है तथा विकास प्रक्रिया गाँवों से नगरों में देशान्तरण का प्रमुख कारण है। ग्रामीण जनसंख्या नगरों को सम्प्रतिज्ञ-भूमि मानती है। लोग नगरीय जीवन को उसके औपचारिक प्रशासन, अवैयक्तिक नियमों का शासन, विपणन तथा बैंकिंग से सम्बन्ध मौद्रिक अर्थव्यवस्था, बाजारोन्मुखी उत्पादन, साक्षरता, स्कूली शिक्षा, विश्राम के क्षणों को व्यतीत करने के लिए ललित कलाएँ, कल्याण के लिए संस्थागत सेवाएँ तथा उपलब्ध पुलिस दल के कारण प्राथमिकता प्रदान करते हैं। (Economic development is usually unequally distributed over geographical areas and the development process is the main factor of rural – urban migration. Rural population regarded towns as 'promised land'. People prefer urban life for its formal administration, the rule of impersonal law for order, money economy connected with wide marketing and banking, market oriented productions, literacy, school education, a leisure and enjoying fine arts, institutionalised services for welfare and a standing police force.)''***

2 प्रत्याकर्षक तत्व (Push Factors)

देशान्तरण के प्रत्याकर्षक तत्व उन तत्वों को कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति को अपना मूल निवास स्थान छोड़ने को बाध्य करते हैं। दूसरे शब्दों में ये ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन तत्वों के अन्तर्गत मुख्यतः निम्न बातों का समावेश किया जाता है:

(1) अच्छे रोजगार के अवसरों का अभाव।

(2) स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा प्रावैधिक प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव।

(3) मनोरंजन के साधनों का अभाव।

(4) उन्नति के अवसरों का अभाव।

(5) राजनैतिक, धार्मिक तथा जातीय आधार पर भेदभाव।

(6) पुलिस का दुर्व्यवहार तथा आतंक।

(7) डाकुओं का आतंक।

(8) विशिष्ट समुदाय के व्यवहार, विश्वास तथा मान्यताओं से विरक्ति।

(9) सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़िवादिता।

(10) सामाजिक तिरस्कार तथा बहिष्कार।

3 देशान्तरण को प्रभावित करने वाले उपरोक्त आकर्षक एवं प्रत्याकर्षक तत्वों को अध्ययन की दृष्टि से निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है:

1. प्राकृतिक या भौगोलिक कारण (Natural or Geographical Factors)- प्राकृतिक अथवा भौगोलिक कारणों से प्रायः लोग प्रवास करते हैं। प्राकृतिक कारणों के अन्तर्गत जलवायु सम्बन्धी परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, सूखा, बाढ़, दुर्भिक्ष, महामारियाँ, भूकम्प, ज्वालामुखी आदि घटनाएँ आती हैं जो देशान्तरण को प्रोत्साहित करती है।

सामान्यतया लोग खराब जलवायु तथा दुर्गम भौगोलिक दशाओं वाले क्षेत्रों से स्वास्थ्य बर्द्धक जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रवासित होते हैं। कुछ परिस्थितियों में चिकित्सक भी रोगियों को स्वास्थ्यप्रद जलवायु के क्षेत्रों में प्रवास की सलाह देते हैं। इसी तरह, प्राकृतिक प्रकोप से लाखों व्यक्ति बेघर होकर भोजन की तलाश में भटकने लगते हैं।

कुछ विद्वानों का विचार है कि मध्य एशिया में जब शुष्कता बढ़ गयी तो वहाँ से आर्य लोग चारों दिशाओं की ओर जाने लगे। इन्हीं की एक शाखा तुर्किस्तान, अफगानिस्तान होते हुए भारत की ओर बढ़ गयी। इसी तरह यूरोप में भी प्लीस्टोसीन युग (Pleistosene Age) के अन्तिम चरण में जब बर्फ उत्तरी बाल्टिक खण्ड तक पहुँच गयी तब जनसंख्या धीरे-धीरे दक्षिणी यूरोप से उत्तर की ओर आने लगी।

जहाँ निरन्तर ज्वालामुखी फूटते रहते हैं तथा भूकम्प के झटके आते रहते हैं, वहाँ से जनसंख्या सुरक्षित स्थानों की ओर स्थानान्तरित होने लगती है। हवाई द्वीप, सिसली, फिलीपीन्स, आदि में ज्वालामुखी का उद्गार प्रारम्भ होने लगता है तो लोग वहाँ से स्थानान्तरित होने लगते हैं।

उपजाऊ मिट्टी भी जनसंख्या को आकर्षित करती है तथा अनुपजाऊ मिट्टी जनसंख्या के स्थानान्तरण को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि मानव सभ्यता का विकास एवं संकेन्द्रण नदियों की घाटियों एवं उपजाऊ दोनों क्षेत्रों में हुआ।

इसके अतिरिक्त खनिज पदार्थों की खोज भी देशान्तरण को प्रोत्साहित करती है। नए खनिजों का पता लगते ही खनिज केन्द्र में जनसंख्या का केन्द्रीकरण होने लगता है।

2. आर्थिक तत्व (Economic factors) देशान्तरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व आर्थिक तत्व है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता है किन्तु सुखी तथा समृद्ध जीवन को व्यतीत करने की अभिलाषा देशान्तरण को प्रोत्साहित करती है। यदि विश्व के विभिन्न देशान्तरित व्यक्तियों से उनके देशान्तरण के कारणों के सम्बन्ध में उनसे जानकारी

प्राप्त की जाए तो हमें ज्ञात होगा कि अन्य कारणों के अतिरिक्त सर्वाधिक देशान्तरण आर्थिक कारणों से हुए। देशान्तरण को प्रोत्साहित करने वाले कतिपय महत्वपूर्ण आर्थिक तत्व निम्नानुसार हैं:

i. **भूमि का अभाव -** सामान्यतः जनसंख्या के भूमि पर अधिक दबाव ने देशान्तरण को प्रोत्साहित किया है। पूर्व-औद्योगिक अवस्था में भूमि की कमी से प्रभावित होकर यूरोप से अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका की ओर बड़ी मात्रा में जनसंख्या का देशान्तरण हुआ। भारत में केरल तथा बंगाल से अन्य राज्यों की ओर देशान्तरण इसी प्रकार के अनेक कारणों से हुआ है।

ii. **औद्योगीकरण -** औद्योगीकरण भी देशान्तरण को प्रोत्साहित करता है। औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप पुराने उद्योगों का विघटन होता है तथा इन रोजगारों में संलग्न व्यक्तियों को नवीन उद्योगों में रोजगार की तलाश में शहरों की ओर देशान्तरित होना पड़ता है। भारतवर्ष में औद्योगीकरण के पूर्वारम्भ में ग्रामीण कुटीर उद्योगों का पतन हुआ तथा इन उद्योगों में लगे व्यक्तियों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाना पड़ा।

iii. **यातायात की सुविधाएँ -** सस्ते, सुगम तथा सुरक्षित यातायात की सुविधाएँ देशान्तरण को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त इसकी आवृत्ति को बढ़ाती हैं तथा दशाएँ निर्धारित करती हैं।

iv. **आर्थिक स्थिति में सुधार -** रोजगार के अवसर तथा अधिक धनोपार्जन की आकाँक्षा से लोग कठिनाइयों के बावजूद देशान्तरण के लिए प्रोत्साहित होते हैं। थाम्पसन तथा लुइस (Thompson and Lewis) के मतानुसार, ***"यह केवल उस तथ्य की स्वीकारोक्ति मात्र है कि यूरोप से महान उत्प्रवासन का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक स्तर में सुधार की आकांक्षा थी। (It is merely a recognition of the fact that far and away the most important cause of migration during the great emigration from Europe was the desire to improve economic status.)"***

वर्तमान समय में खाड़ी देशों (Gulf Countries) में उत्प्रवासन का प्रमुख कारण आर्थिक स्थिति में सुधार की आकाँक्षा है।

3. सामाजिक तत्व (Social Factors)- देशान्तरण के लिए आर्थिक तत्व ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, बल्कि सामाजिक रीति-रिवाज तथा प्रचलित परम्पराएँ भी जिम्मेदार हैं। विवाहोपरान्त लड़कियाँ अपने पति के घर चली जाती हैं तथा जहाँ-जहाँ पति जाता है वहाँ-वहाँ उसको भी जाना पड़ता है। संयुक्त परिवार प्रथा ने प्रारम्भ में प्रयास के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित की थीं किन्तु वर्तमान समय में इस संस्था में विघटन होने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है, जिसने प्रवास की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक अशान्ति तथा घरेलू झगड़ों के कारणों से भी व्यक्ति देशान्तरण करता है।

गाँवों से नगरों की ओर देशान्तरण में जहाँ आर्थिक कारणों ने प्रोत्साहन प्रदान किया है वहीं सामाजिक कारण भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की आकाँक्षा में अनेक व्यक्ति गाँवों से नगरों की ओर देशान्तरण करते हैं।

आज लोगों में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ है तथा इस प्रवृत्ति से प्रभावित अनेक व्यक्तियों ने गाँवों से नगरों की ओर प्रवास किया है।

4. जनांकिकी तत्व (Demographical Factors) - जिन स्थानों में जनसंख्या का दबाव अधिक है वहाँ से सामान्यतः कम दबाव की ओर जनसंख्या का प्रवास होता है। देशान्तरण सामान्यतः जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष पर निर्भर करता है। यदि किसी स्थान विशेष पर अधिक लोग हैं किन्तु किसी विशिष्ट कार्य के लिए अकुशल हैं तब वहाँ कुशल व्यक्तियों को प्रवासित करना आवश्यक हो जायेगा।

जन्म-दर तथा मृत्यु-दर भी देशान्तरण को प्रोत्साहित करती है। यदि पुरूष विशिष्ट जन्म-दर (Male specific birth rate) कम है तो सन्तुलन बनाये रखने की दृष्टि से पुरूषों के अन्तर्गमन (Immigration) में वृद्धि होगी। किन्तु इसके विपरीत यदि किसी देश अथवा स्थान में स्त्री-विशिष्ट जन्म-दर (Female specific birth rate) अधिक है तब स्त्रियों के बहिगर्मन (Emigration) में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी स्थान पर मृत्युदर अधिक है तो वहाँ से बहिर्गमन (Emigration) में वृद्धि होगी तथा अन्तर्गमन कम होगा। इसी प्रकार जिन देशों में जन्म-दर तथा मृत्यु-दर दोनों ही बहुत कम हैं तथा जन्म-दर में इतनी अधिक कमी हो चुकी है कि भविष्य में श्रम-शक्ति के अभाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है तब इस प्रकार का देश अन्तर्गमन को प्रोत्साहित करेगा तथा बहिर्गमन (Emigration) को हतोत्साहित करेगा।

देशान्तरण से देश की श्रम-शक्ति के गुणात्मक पक्ष को परिवर्तित किया जा सकता है। एक विकासशील देश सामान्यतः कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों के अन्तर्गमन को प्रोत्साहित करेगा किन्तु अकुशल श्रमिकों के बहिर्गमन (Emigration) को प्रोत्साहित करता है।

5. राजनीतिक कारक (Political factors) अनेक राजनीतिक निर्णय भी देशान्तरण को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना एक राजनैतिक निर्णय होता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास को कम किया जा सके।

युद्ध का प्रभाव भी देशान्तरण पर पड़ता है। युद्ध में जो विजयी होता है, वह जीती हुई भूमि पर बस जाता है और जो हारता है वह स्थान छोड़कर अन्यत्र बस जाता है। उदाहरण के लिए, जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर बढ़ना प्रारम्भ किया तो पोलैण्डवासी पूरब की ओर रूस में पलायन करने लगे। 1971 में बंगलादेश में स्वतंत्रता संग्राम के समय पाकिस्तान के सैनिकों की यातनाओं से पीड़ित होकर लाखों शरणार्थी भारत में चले आए और स्वतन्त्र बांग्लादेश के उदय होने पर बहुत वापस भी चले गए। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान यहूदियों को विश्व के अधिकांश देशों ने बाहर निकाल दिया तथा फिलीस्तीन में बसने के लिए मजबूर कर दिया।

उपनिवेशवाद तथा रंग-भेद की नीति भी देशान्तरण को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए गत् वर्षों में अफ्रीकी देशों ने भारतीय मूल के व्यक्तियों का निष्कासन कर दिया।

6. सांस्कृतिक एवं धार्मिक तत्व (Cultural and Religious factors)- सांस्कृतिक सम्पर्क एवं आदान-प्रदान से देशान्तरण की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है। सांस्कृतिक सम्पर्क एवं आदान-प्रदान में शिक्षा, यातायात की सुविधाओं तथा संचार व्यवस्था के माध्यम में वृद्धि होती है। सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराएँ तथा भाषा भी किसी देश अथवा स्थान के देशान्तरण की मात्रा तथा दिशा को प्रभावित करती है। जैसे हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोग सामान्यतः उन देशों में प्रवास करते हैं, जो हिन्दी भाषी प्रदेश हों अथवा

जहाँ विचार विनिमय की सुविधा हो। जिन देशों में सांस्कृतिक मित्रता है, वहाँ लोगों को देशान्तरण करने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है।

धार्मिक तत्व भी प्रवास को प्रोत्साहित करते हैं। धर्म प्रचार तथा धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से संचालित इस्लाम, बौद्ध तथा ईसाई आन्दोलनों से प्रभावित देशान्तरण के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर जीवन के अन्तिम दिनों में तीर्थ-स्थानों में बस जाने की प्रवृत्ति लोगों में होती है।

देशान्तरण के विभिन्न कारकों पर टिप्पणी करते हुए प्रो. थाम्पसन एवं लेविस ने लिखा है कि, ***"प्रवास के लिए उत्तरदायी कारक आर्थिक तथा गैर आर्थिक दोनों ही हो सकते हैं। सामान्यता आर्थिक प्रवास स्वैच्छिक होते हैं जबकि गैर आर्थिक प्रवास अनैच्छिक एवं बलात् (Forced Migration) होते हैं। जब व्यक्तियों को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी आधार पर यातना दी जाती है या परेशान किया जाता है तो वे इस यातना से बचने के लिए स्थान छोड़ना ही उपयुक्त समझते हैं। परन्तु इन दोनों प्रकार के कारकों में आर्थिक कारक ही अधिक महत्वपूर्ण हैं।(The motives leading to migration have probably varied but little in general character from age to age. The economic motives have probably been dominant at all times, although not of equal importance in all particular movements, clans, tribes, nomadic shepherds and other regularly migratory groups have always moved as seemed best to them in order to make a living although the force exerted on weaker by more powerful kinship groups and by military groups in search of better living has very frequently made necessary the migration of a weaker group in order to escape annihilation.)"***

10.5 देशान्तरण के मार्ग में बाधायें अथवा गतिरोध (Hurdles in Migration)

गतिशीलता के दृष्टिकोण से मनुष्य सबसे कम गतिशील है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास नही करना चाहता है। जिसके अनेक कारण हैं: जैसे किसी विशिष्ट स्थान से लगाव, सामाजिक समायोजन, सांस्कृतिक पम्पराएँ, विशिष्ट स्थान की जानकारी आदि। स्वदेश छोड़कर विदेश में बसने से व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः देशान्तरण के मार्ग में निम्नलिखित तत्व प्रमुखतः बाधाएँ उत्पन्न करते हैं:

1. **स्व-स्थान से दूरी** (Distance of Destination from Residence)- देशान्तरण में दूरी का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थान से दूसरे स्थान की दूरी में जैसे-जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे देशान्तरण की प्रेरणाएँ भी घटती जाती हैं। अधिक दूरी के स्थानों पर जाने में जोखिम तथा व्यय दोनों में वृद्धि हो जाती है। कम अवकाश पर अथवा किसी आकस्मिक कारण से घर वापस आना भी सम्भव नहीं होता है।
2. **प्रवास क्षमता** (Migration Capicity)- एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने के लिए विशेष प्रकार की क्षमता, निर्भीकता तथा प्रगतिशीलता की आवश्यकता होती है। सामान्यतः गाँव के लोगों में इसकी

कमी होती है जिसके अनेक कारण हैं, जैसे शहर के वातावरण में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाना, संकोची स्वभाव, अशिक्षा आदि। भारतवर्ष में प्रवासन क्षमता पंजाब के लोगों की अपेक्षाकृत अधिक है।

3. **वर्तमान व्यवसाय व स्थान से लगाव** (Attachment to Present Place and Work)- व्यक्तियों का अपने वर्तमान व्यवसाय, स्थान, परिवार, समाज तथा पास-पड़ोस के लोगों से इतना भावनात्मक लगाव होता है कि वे दूसरे स्थान या देश में प्रोन्नति एवं अधिक आय प्राप्त करने की सम्भावना के बावजूद प्रवास को पसन्द नहीं करते हैं। भारतीय श्रमिकों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखने को मिलती है। वे शहरों में मजदूरी करने जाते हैं, परन्तु वहां वे अपना काम चलाऊ आवास ही बनाते हैं, जब भी अवसर मिलता है या गाँव में घर पर कोई प्रयोजन पड़ता है या त्योहारों के अवसर पर वे अपने-अपने गाँवों को चले जाते हैं।
4. **भाषा, संस्कृति एवं रीति-रिवाज** (Languages, Culture and Social Customs)- स्थान परिवर्तन से भाषा, संस्कृति और सामाजिक रीति-रिवाज बदल जाते हैं। मानव का यह स्वभाव है कि वह अपनी बोली, भाषा, खान-पान, संस्कृति तथा सह-धर्मियों में ही उठना बैठना पसन्द करता है। अतः इन सबसे वंचित हो जाने तथा अपने आपको अलग या अकेला पाने का भय उसे देशान्तरित होने से रोकता है।
5. **प्रवास के नियम** (Migration Laws)- अन्तर्राष्ट्रीय देशान्तरण के मार्ग में सबसे अधिक गम्भीर समस्या प्रवास के नियमों के द्वारा उत्पन्न होती है। अधिकांश देशों के प्रवास के नियम इस प्रकार के होते हैं जो कि विदेशियों को अपने यहाँ देशान्तरण नहीं होने देते हैं। सामान्यतः आन्तरिक देशान्तरण पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय देशान्तरण की तुलना में आन्तरिक देशान्तरण अधिक होता है।
6. **मार्ग व्यय** (Travelling Expenses)- प्रवास के मार्ग में प्रमुख अवरोध मार्ग व्यय भी उत्पन्न करता है। यदि यात्रा व्यय बहुत अधिक है तो लोग प्रवास कम से कम करेंगे।

10.6 वैश्विक जनसंख्या में स्थानान्तरण की प्रवृत्तियाँ (Migration Trends in World Population)

स्थानान्तरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का प्रसारण हुआ है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक का मानव किसी न किसी कारण स्थानान्तरण करता रहा है। यह हो सकता है स्थानान्तरण की प्रवृत्तियों में अन्तर हो। सम्प्रति स्थानान्तरण की विश्वव्यापी प्रवृत्ति के आयाम व्यापक हो गये हैं। यातायात के साधन के कारण विश्व के किसी भूभाग में पहुँचना सुगम हो गया है। विभिन्न व्यापारिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से विश्व जनमानस स्थानान्तरण करता रहता है लेकिन स्थायी स्थानान्तरण बहुत ही कम हो रहे हैं। प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या को आवश्कतानुसार ही बढ़ने देना चाहता है। अनावश्यक जनसंख्या आकार बढ़ाना नहीं चाहता, लाभकर स्थिति में ही स्थायी बसाव अनुमन्य होता है। प्रागैतिहासिक (prehistoric) काल में मानव स्थानान्तरण प्रायः रिक्त एवं अनुकूल क्षेत्रों की ओर हुए। ऐतिहासिक मध्यकाल में स्थानान्तरण के राजनैतिक, आर्थिक कारण प्रमुख थे। आधुनिक काल में स्थानान्तरण के पक्ष और व्यापक होते जा रहे हैं। समयानुसार स्थानान्तरण के मूलभूत कारकों के प्रभावों में अन्तर दिखायी देता है। वास्तव में अध्ययन की दृष्टि से कालानुसार विश्वव्यापी स्थानान्तरण के तीन भाग किये जा सकते हैं:

(1) प्रागैतिहासिक स्थानान्तरण (Pre-Historic Migration),

(2) ऐतिहासिक स्थानान्तरण (Historic Age Migration)

(3) आधुनिक स्थानान्तरण (Modern Migration)

1 प्रागैतिहासिक स्थानान्तरण (Pre Historic Migration)

प्रागैतिहासिक स्थानान्तरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में लोग जाकर बसे। निश्चित ही ये स्थानान्तरण अकस्मात् नहीं हुए बल्कि कई चरणों में सम्पन्न हुए तथा इनके उददेश्य सीमित थे। भोजन प्राप्ति की इच्छा के साथ नये क्षेत्रों में बसने की मानव जिज्ञासा स्थानान्तरण के मूल में थी। विभिन्न प्रेक्षपणों एवं अनुसंधानों से मानव उत्पत्ति का आदि स्थान मध्य एशिया को ही बताया जाता है। अध्येताओं का मानना है कि प्रथम मानव स्थानान्तरण 10-5 लाख वर्ष ईसा पूर्व सम्पन्न हुए होंगे। इसी काल खण्ड में अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के ऊष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र बसे होंगे। द्वितीय स्थानान्तरण 5-2 लाख वर्ष ईसा पूर्व हुए थे तथा इस स्थानान्तरण के समय मानव समूह उत्तरी अमेरिका एवं आस्ट्रेलिया की ओर अग्रसर हुए तथा शीतोष्ण कटिबन्ध में बसाव हुआ। ज्ञातव्य है कि हिम प्रसार के कारण मानव का क्षेत्रीय प्रसार अवरूद्ध हो गया लेकिन ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हिम क्षेत्रों के संकुचन के साथ मानव प्रसार प्रारम्भ हो गया था तथा मानव प्रसार की प्रक्रिया ईसा से 5 हजार वर्ष पूर्व तक चलती रही। 5 हजार से 1500 वर्ष ईसा पूर्व तक नदी घाटियों में मानव विकसित अवस्था में पहुँच गया था तथा उसने आर्थिकी का विविधीकरण कर लिया था। व्यापार-यातायात, कृषि एवं पशुपालन की उन्नत प्रविधियाँ विकसित हो गयी थीं। नदी घाटी सभ्यता ने मानव अभ्युन्नति के विविध आयाम खोल दिये थे।

अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि अद्यतन मानव का अभ्युदय कैस्पियन सागर के निकट के क्षेत्रों से हुआ है। वस्तुतः यह भू-भाग मानव-पालना (Cradle of Mankind) कहा जाता है। इसी भू-भाग से मानव प्रसार विश्व के विभिन्न भागों की ओर सम्पन्न हुए। मानव प्रसार का प्रमुख कारण मानव जिज्ञासा एवं संसाधनों की खोज रही होगी, इसके साथ मध्य एशिया की बदलती जलवायु भी प्रमुख कारण थी। मानव को अपने गृह क्षेत्र से स्थानान्तरित होने का प्रमुख कारण बढ़ती हुई शुष्कता थी। शुष्कता के कारण भोजन का अभाव होने लगा। अनुकूल जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थितियों की खोज करता मानव विश्व के विभिन्न भागों में फैलता गया। इन नदी घाटियों में मनुष्य ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और अग्रणी क्षेत्र बनाने में जुट गया। उल्लेखनीय है कि नदी घाटियों में अनेक सांस्कृतिक सभ्यताओं का जन्म हुआ। मानव संस्कृति इन्हीं सभ्यताओं के चतुर्दिक फलीफूली और विकास की ओर अग्रसर हुई।

उद्भव क्षेत्र से मानव प्रसार के प्रथम चरण में विश्व के विभिन्न भागों में मानव स्थानान्तरण हुए। कैस्पियन सागर के पश्चिमी ओर यूरोप एवं अफ्रीका की ओर प्रसार हुआ। प्रथम यूरोपीय प्रसार उत्तर की ओर सम्पन्न हुआ। प्रसार की द्वितीय शाखा अफ्रीका के उत्तरी भाग को समेटती हुयी स्पेन तक गयी। इसी क्रम में नील नदी के मार्ग से होता हुआ मानव अफ्रीका के आन्तरिक भाग की ओर अग्रसर हुआ। नील नदी का प्रवसन मार्ग दो भागों में विभक्त हुआ। एक मार्ग तन्जानियाँ तथा इथोपिया की ओर बढ़ा तो दूसरा नाइजीरिया एवं घाना की ओर।

कैस्पियन सागर क्षेत्र से दक्षिण की ओर भी मानव प्रवास हुआ। दक्षिणोन्मुख मानव प्रवास की एक शाखा भारत वर्ष के दक्षिणी भाग की ओर अग्रसर हुई। दूसरी शाखा म्यांमार एवं थाईलैण्ड होती हुई मलाया तक पहुँच

गयी। मलाया से एक शाखा बोर्नियों तथा न्यूगनी द्वीप की ओर उन्मुख हुई तथा दूसरी ऑस्ट्रेलिया पहुँची। मानव प्रसार कैस्पियन क्षेत्र से पूर्व की ओर भी हुआ। पूर्व की शाखा उत्तरी चीन की ओर अग्रसर हुई। उत्तरी चीन से एक शाखा पूर्व की ओर तथा दूसरी शाखा उत्तरोन्मुखी हो गयी। उत्तरोन्मुखी शाखा का प्रवाह मंगोलिया से होता हुआ बोरिंग जल डमरू मध्य तक पहुँचा। तत्पश्चात् अलास्का होता हुआ उत्तरी अमेरिका में प्रवेश कर गया। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग से होते हुए उसने मध्य अमेरिका में प्रवेश किया तथा मध्य अमेरिका के पश्चात् दक्षिणी अमेरिका में मानव प्रवाह दो भागों में बँट गया। एक शाखा पश्चिम भाग से होती हुई अग्रसर हुई तो दूसरी शाखा पूर्वोन्मुखी होकर अर्जेन्टाइना तक पहुँची। उपरोक्त मानव प्रसार के तथ्य मानव के नये क्षेत्रों की बसने की जटिल प्रक्रिया का बोध कराते हैं। मानव विभिन्न भौगोलिक अनुकूलता एवं प्रतिकूलता को सहन करते हुए नये-नये क्षेत्रों की ओर अग्रसर हुआ होगा।

प्रागैतिहासिक स्थानान्तरण की विशेषताएँ:

1. मानव विकास की आदिम अवस्था में सम्पन्न स्थानान्तरण के उददेश्य सीमित थे। सामान्यतः यह काल खण्ड प्रसार की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था।
2. मानव प्रसार मुख्यतः मध्य एशिया से बाहरी क्षेत्रों की ओर हुआ।
3. स्थानान्तरण समूहों में सम्पन्न हुए। सामूहिक स्थानान्तरण के उद्देश्य एक जैसे होते थे।
4. मध्य एशिया की जलवायु की शुष्कता प्रागैतिहासिक स्थानान्तरण का मुख्य कारण थी। वनस्पति संकट एवं भोजन का अभाव स्थानान्तरण की गति को तीव्र किया।
5. प्रथम स्थानान्तरण निकटवर्ती क्षेत्रों के सुगम स्थानों पर हुआ।
6. स्थानान्तरण की अवधि लम्बी थी। ये स्थानान्तरण लाखों वर्षों में सम्पन्न हुए। मानव वर्ग ने प्राकृतिक बाधाओं को पार करते हुए पैदल ही समस्त यात्राओं को पूर्ण किया था।
7. पूर्व स्थानान्तरित मानव वर्ग तत्कालिक स्थानान्तरित मानव समुदाय द्वारा आगे की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित एवं बाध्य किये जाते रहे। फलतः प्रथम स्थानान्तरित मानव महाद्वीपों के छोरों पर जा बसा।
8. प्रथम स्थानान्तरण के कारण ही मानव प्रजातियों का अभ्युदय हुआ। विभिन्न प्राकृतिक पर्यावरण में मानव के बाह्य शारीरिक लक्षण परिवर्तित हुए और मानव प्रजातियों में वर्ग उत्पन्न हो गये।
9. प्रतिकूल क्षेत्रों में मानव स्थानान्तरित हुआ परन्तु मानव वहाँ रूक नहीं पाया।
10. स्थानान्तरण के कारण अनुकूल क्षेत्र बस गये। नदी घाटियों का बसाव सभ्यताओं का उदय स्थल बने। नील एवं सिन्धु घाटी में बसी सभ्यता इस तथ्य की पुष्टि करती है।
11. नये क्षेत्र में स्थानान्तरित मानव वर्ग स्थानीय वनस्पतियों, पौधों, संसाधनों में सामंजस्य बनाते हुए जीवनयापन करते रहे। प्राकृतिक तत्वों को पहचानते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा भी की। वस्तुतः ये मानव चेतना के कारण ही सम्भव हो सका।
12. स्थानान्तरण के कारण मानव समुदाय में क्षेत्रीय विभेद उत्पन्न हुए। स्थान एवं क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर विवाद हुए। आधुनिक रूप से राष्ट्र गोरे या काले, विकसित और विकासशील देखने को मिल रहे हैं।
13. प्रागैतिहासिक स्थानान्तरण की प्रकृति बर्हिमुखी थी। लोग लौटकर पुनः मध्य एशिया की ओर नहीं गये।

14. स्थानान्तरण के कारण ही मानव-प्रकृति में सामंजस्य स्थापित हो सका। मानव सम्पूर्ण पृथ्वी पर फैल गया और बस गया।
15. विभिन्न भौतिक परिवेश में रहता हुआ मानव वर्ग अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए सांस्कृतिक पर्यावरण का सृजन करता रहा। मानवीय चेतना के कारण सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संस्थाओं का जन्म हुआ। सम्पूर्ण विश्व में जनसंख्या का फैलाव प्रागैतिहासिक स्थानान्तरण के कारण सम्भव हुआ। मानव ने बसने योग्य समस्त क्षेत्रों का पता लगाया और स्थानीय प्राकृतिक दशाओं का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया तथा सांस्कृतिक तत्वों का सृजन किया। सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक प्रणालियों को जन्म दिया। मनुष्य की सृजनशीलता का परिचय विभिन्न सभ्यताओं के अभ्युदय से मिलता है। वस्तुतः प्रागैतिहासिक स्थानान्तरण के उददेश्य सीमित क्षेत्र तथा स्थानान्तर्गत जनसंख्या का एक समूह होता था और पूरे समुदाय का ध्येय भी एक होता था।

2 ऐतिहासिक स्थानान्तरण (Historic Migration)

मध्यकालीन स्थानान्तरण के मुख्य क्षेत्र भूमध्यसागरीय परिक्षेत्र, नील नदी की घाटी, सिन्धु गंगा का मैदान, ह्वांगहो घाटी एवं दजला-फरात की घाटी थे। ये क्षेत्र तत्कालीन सभ्यता के केन्द्र और धनधान्य से सम्पन्न थे। व्यापारिक केन्द्र होने के कारण ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न थे। इन वैभवशाली क्षेत्रों की ओर सबकी दृष्टि थी। व्यापारिक गतिविधियों के कारण स्थानान्तरण को बढ़ावा मिलता रहा। इसी कालखण्ड मे भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण की अधिकता रही। यूनान का सिकन्दर, मध्य एशिया एवं मध्य पूर्व के देशों से महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, चंगेज खां, बाबर, तैमूर एवं नादिर शाह आदि के आक्रमण उल्लेखनीय हैं। ये अपने सैनिकों को यहाँ बसा गये तथा बाबर एवं उसके वंशजों ने शासन भी किया। इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए भी लोग आते रहे। इस प्रकार मध्यकालीन स्थानान्तरण में दो प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है-

(1) बलात् स्थानान्तरण
(2) स्वैच्छिक स्थानान्तरण

1. बलात स्थानान्तरण - युद्ध एवं धर्म के प्रचार के कारण मध्यकाल में बलात् स्थानान्तरण हुए। सातवीं से बारहवीं शदी तक इस्लाम तथा ईसाई धर्म का युद्ध चलता रहा। पश्चिमी एशिया से यूरोप तक की जनसंख्या स्थानान्तरित होती रही। बहुत से लोग काल कवलित हुए तथा कुछ लोग लगातार भागते रहे या धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य हुए। धर्म रक्षा के लिए यहूदी लोग जर्मनी एवं सोवियत संघ मे जा बसे। दसवीं सदी में इस्लाम प्रचारक भारत की ओर अग्रसर हुए तो ईरान से बहुत से पारसी धर्मावलम्बी पलायित होकर गुजरात एवं महाराष्ट्र की ओर प्लायित हुए जो तत्कालीन स्थानान्तरण के प्रमुख कारण थे। उत्तर भारत की विकसित जातियाँ युद्ध के कारण जंगलों की शरण में चली गयीं तथा कालान्तर में आदिवासी बन गयीं। मुस्लिम आक्रमण से आक्रान्त क्षत्रिय जाति, जनजाति बन गयी। दक्षिण भारत में भी ऐसी घटनाएं घटीं। एशिया-अफ्रीका तथा दक्षिणी यूरोप मध्यकालीन स्थानान्तरण के क्षेत्र थे।

2. स्वैच्छिक स्थानान्तरण- मध्य काल में धर्म प्रचारकों, शासकों, सरदारों के निर्देशन में सैनिक, व्यापारी एवं कलाकार स्थानान्तरित हुए। इस कालखण्ड में इस्लाम धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु महती प्रयास हुए। भारी संख्या में प्रचारक अफ्रीका, यूरोप एवं एशिया की ओर अग्रसर हुए।

3 आधुनिक जनसंख्या स्थानान्तरण(Modern Population Migration)

खोजी यात्राओं के कारण आधुनिक स्थानान्तरण को प्रोत्साहन मिला। 15वीं शताब्दी के पश्चात् यूरोप में ज्ञान-विज्ञान ने खोजों को नई दिशा दी। व्यापारिक महत्वाकाँक्षा के कारण पश्चिमी नाविकों ने नये-नये क्षेत्रों को खोज निकाला। ये क्षेत्र यूरोपीय लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुए। यूरोप के लोग धन अर्जित करने, व्यापार की लालसा से स्थानान्तरित होने लगे और अनुकूल क्षेत्रों में बसने लगे। यूरोप महाद्वीप से अग्रेज, स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रान्सीसी, डच, वेलजियन आदि ने विभिन्न महाद्वीपों में अपनी बस्ती बनानी प्रारम्भ कर दी। नये-नये क्षेत्रों में यूरोपीय नागरिकों ने अपनी संप्रभुता को भी सुरक्षित कर लिया। जिन देशों में ये जाकर बसे, उन देशों के संसाधनों का उपयोग अपनी मातृभूमि के विकास एवं उन्नति के लिए करने लगे। कुशल राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिक यूरोपीय नये क्षेत्रों के शासक बन गये और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उपनिवेश बनाये। यूरोपीय देशों ने राजनीतिक विरोधियों तथा धन कमाने वाले व्यापारियों को नये क्षेत्र में बसाया। विदित है कि अंग्रेजों की बस्ती संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड में स्थायी रूप से बनी और ये देश अंग्रेजी मूल के लोगों से आबाद हैं। स्पेन तथा पुर्तगाल के लोगों ने दक्षिणी अमेरिकी में अपनी बस्ती बसायी। आधुनिक स्थानान्तरण में स्वैच्छिक एवं बलात् दोनों प्रकार के स्थानान्तरण हुए। उपनिवेशो से श्रमिकों का स्थानान्तरण प्रायः बलात् ही किया गया जबकि यूरोप से होने वाला अधिकांश स्थानान्तरण स्वैच्छिक रहा। 18वीं शताब्दी में अफ्रीकी नीग्रो का संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर स्थानान्तरण बलात् स्थानान्तरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जर्मनी के आतंक के कारण 10 लाख यहूदी यूरोप से पैलेस्टाइन एवं अमेरिका को स्थानान्तरित हो गये। पोलैण्ड की 20 लाख जनसंख्या सोवियत संघ को स्थानान्तरित हो गयी। आधुनिक स्थानान्तरण में अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्थानान्तरण दोनों हुए। युद्ध के कारण बलात् स्थानान्तरण भी सम्पन्न हुए। राजनीतिक कारणों से भी लोगों को स्थानान्तरित होना पड़ा। स्वैच्छिक स्थानान्तरण धन कमाने एवं व्यापार के कारण सम्पन्न हुए। स्थायी एवं अस्थायी स्थानान्तरण की प्रवृत्ति भी रही। इस युग में दासों का स्थानान्तरण उल्लेखनीय है। 20वीं शदी के मध्य तक जनसंख्या का प्रवाह अधिक रहा तथा प्रवाह के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ। विरल क्षेत्र सघन होने लगे। सर्वत्र संसाधनों का विदोहन प्रारम्भ हो गया। बसने योग्य प्रत्येक क्षेत्र में लोग जाकर बसे और क्षेत्र को उत्पादक बनाने का उपक्रम करने लगे। विदित हो कि आधुनिक समुदाय अग्रणी रहा है।

यूरोप में अमेरिकी (उत्तरी, मध्य, दक्षिणी) महाद्वीपों की ओर स्थानान्तरण-यूरोप से अमेरिकी महाद्वीप के देशों की ओर स्थानान्तरण आधुनिक युगीन स्थानान्तरण की महान घटना है। यूरोप के बढ़ते जातीय संघर्ष एवं धनाड्य बनने की कामना ने स्थानान्तरण के लिए प्रेरित किया। ज्ञातब्य है कि अमेरिका के क्षेत्र उर्वर, निवास योग्य तथा खनिजों से परिपूर्ण होने के कारण आकर्षण के कारण बन गये। रोजगार की प्रबल सम्भावनाओं ने लोगों को बसने के लिए बाध्य कर दिया और लोग स्वैच्छया बसे। सन् 1846 ई. से सन् 1932 ई. की अवधि में 5 करोड़ यूरोपीय नागरिक अमेरिकी महाद्वीपों की ओर स्थानान्तरित हुए परन्तु लगभग 80 प्रतिशत उत्तरी अमेरिका में बस

गये। उत्तरी अमेरिका का भौतिक परिवेश के सदृश रहा। वास्तव में यूरोपीय लोगों को बसने में असुविधा नहीं हुई। अंग्रेजों के प्रभुत्व के कारण उत्तरी अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश हो गया। दक्षिणी अमेरिका में लैटिन भाषी लोग आकर बस गये। ज्ञातव्य है कि लैटिन भाषी लोग दक्षिण यूरोप के निवासी रहे। आंग्लभाषी एवं लैटिन भाषी लोगों के संघर्ष के कारण अमेरिकी क्षेत्र समझौते के अनुरूप बसे। सम्पूर्ण अमेरिका में यूरोपीय संस्कृति का प्रचार हुआ है। अमेरिकी स्थानान्तरण धन कमाने की कामना से प्रेरित थे। इसलिए धनार्जन इसका प्रमुख लक्ष्य था। ये लोग प्रौद्योगिकी के उपयोग से खाद्य उत्पाद एवं कच्चे माल का उत्पादन करने लगे। उत्पाद अधिशेष को मातृ देशों को निर्यात करने लगे। यातायात तथा संचार के साधनों के विकास के कारण समस्त कार्य सुगम हो गये। यूरोपीय स्थानान्तरण के कारण दासों के बलात् स्थानान्तरण हुए। ज्ञातव्य है कि अफ्रीकी नीग्रों के साथ पशुवत् व्यवहार किया जाता था तथा ये क्रय एवं विक्रय किये जाते थे। एशिया के देशों से भी श्रमिकों को बलात् भेजा गया। यूरोप के लोगों का स्थानान्तरण स्वेच्छया था। उत्तरी अमेरिकी देश कृषि, खनन, पशुपालन एवं उद्योग आदि क्षेत्रों में विकसित होने लगे।

कालान्तर में विषय विज्ञ उत्तरी अमेरिकी देशों को अपनाने लगे, फलतः अमेरिकी देशों के गौरव में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय सरकारों ने उपनिवेशों को अपने अधीन कर लिया और स्वैच्छिक प्रवास को प्रोत्साहित किया। अतएव शदी के मध्य तक ग्रेट ब्रिटेन से प्रतिवर्ष 3 लाख व्यक्ति स्थानान्तरित हुए। हंगरी, आस्ट्रेलिया, इटली एवं जर्मनी से संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी की ओर प्रवास हुए। सन् 1840 से सन् 1880 ई. के मध्य 295 लाख व्यक्ति यूरोपीय देशों से संयुक्त राज्य अमेरिका को स्थानान्तरित हुए थे। सन् 1825-1920 ई. के मध्य ब्रिटेन से 1.7 करोड़ लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में जा बसे परन्तु 1930 के पश्चात् स्थानान्तरण की संख्या में ह्रास होने लगा। सन् 1820-1960 ई. के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बसे लोगों की संख्या सारणी 10.1 में दिखाया गया है।

सारणी 10.1

1820-1960 के मध्य संयुक्त अमेरिका में बसने वाली जनसंख्या

देश, जिससे स्थानान्तरण हुए	व्यक्ति
1. ग्रेट ब्रिटेन	90 लाख
2. जर्मनी	65 लाख
3. इटली	48 लाख
4. आस्ट्रिया हँगरी	42 लाख
5. अन्य यूरोपीय देश	90 लाख
योग	335 लाख

स्थानान्तरित जनसंख्या का बसाव उत्तरी अमेरिका के उसके पूर्वी तटों की ओर हुआ, जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप अपलेशिया की ओर बसाव प्रारम्भ हुआ तथा कालान्तर में लोग पश्चिमी भाग की ओर जाकर बसे। संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगीकरण के कारण पूरब से पश्चिम की ओर विकास और बसाव होता गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में आवासन (Immigration) के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

(1) यूरोपीय देशों से आवासन अधिक हुआ,

(2) आगन्तुक मानव वर्ग पूर्वी भाग में बसे,

(3) पश्चिमी भागों की ओर स्थानान्तरण पूर्वी भाग से सम्पन्न हुआ

(4) पूर्वी भाग में औद्योगीकरण से पश्चिमी भाग की ग्राम्य जनसंख्या पुनः नगरोन्मुख हो गयी,

(5) औद्योगीकरण पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर अग्रसर हुआ तदनुरूप जनसंख्या का स्थानान्तरण भी हुआ,

(6) आर्थिक खुशहाली के लिए स्थानान्तरिक लोगों की संख्या 90 प्रतिशत से अधिक थी,

(7) धार्मिक स्वतंत्रता की इच्छा से 5 प्रतिशत लोग स्थानान्तरित हुए थे,

(8) दास भी विभिन्न कार्यों के लिए दूसरे देशों से मँगाये गये थे तथा

(9) दास प्रथा की समाप्ति के पश्चात् विभिन्न देशों यथा भारत, चीन, जापान के श्रमिक भी स्थानान्तरित हुए थे।

उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के स्थानान्तरण में उल्लेखनीय स्थानान्तरण संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका विकास के विविध आयामों के प्रस्फुटन के कारण कुशल एवं प्रवीण लोगों का देश बन गया। सर्वग्राही राजनीतिक, आर्थिक विकास एवं संस्कृति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को गौरवमयी देश बना दिया।

यूरोप से अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया की ओर स्थानान्तरण- यूरोप से अफ्रीकी देशों की ओर स्थानान्तरण का मुख्य आकर्षण खनिज पदार्थों की प्राप्ति तथा कृषि उत्पादों की सुनिश्चित करना था। अफ्रीकी की ओर स्थानान्तरण का प्रमुख कारण खजिनों को व्यापक एवं बलात् दोहन भी था। अफ्रीकी जलवायु यूरोपीय लोगों के अनुकूल नहीं था फिर भी ये लोग इन देशों के प्राकृतिक वैभव का उपयोग कर धन अर्जित करना चाहते थे। कालान्तर में अफ्रीकी देश एक-एक कर उपनिवेश में बदल गये। सैकड़ों वर्ष तक यूरोपीय लोगों ने इनका दोहन किया तथा ये देश मात्र कच्चे पदार्थ भेजते रहे। विदित हो कि महाद्वीप का सुदूर दक्षिण भाग यूरोपीय वर्ग को बसने की दृष्टि से अनुकूल रहा। फलतः सर्वाधिक यूरोपीय जनसंख्या दक्षिणी अफ्रीकी संघ में बसी। उपनिवेशों के कारण यूरोपीय स्थानान्तरण अफ्रीका को होते रहे।

आस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में ख्याति प्राप्त किया। सन 1790 ई. में लाखों ब्रितानी आस्ट्रेलिया में बस गये। सोने के आकर्षण ने 1850-1860 के मध्य के दशक में 6 लाख यूरोपीय लोगों को आस्ट्रेलिया में बसने के लिए बाध्य कर दिया। 1914 तक लगभग एक लाख यूरोपीय प्रतिवर्ष आस्ट्रेलिया में आकर बसते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह संख्या घट कर 75 हजार हो गयी। युद्ध के कारण स्थानान्तरण कम हो गया। आस्ट्रेलिया में ब्रितानी मूल के लोग अधिक संख्या में बसे हैं। सम्प्रति इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या की 70 प्रतिशत है। 30 प्रतिशत जनसंख्या जर्मनी, यूगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, फ्रान्स, नीदरलैण्ड, इटली एवं ग्रीस मूल के लोगों की है।

एशियाई देशों में स्थानान्तरण- आदि मानव की उद्गम स्थली एशिया महाद्वीप से स्थानान्तरण प्रागैतिहासिक काल से ही होता चला आ रहा है। उल्लेखनीय है कि एशिया के देश पराभव के कारण ब्रितानियों के उपनिवेश बन गये तथा इन देशों से बलात् एवं स्वेच्छया स्थानान्तरण अन्य देशों को हुआ। 18वीं एवं 19वीं सदी में चीनी लोग कोरिया, मंचूरिया, हिन्दचीन, मलाया, कम्बोडिया, म्यांमार, भारत एवं इण्डोनेशिया में बस गये। ठेके पर मजदूरी करने के लिए हजारों श्रमिक संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर अग्रसर हुए। 1900-1910 के मध्य 2 लाख चीनी

श्रमिक दक्षिणी अफ्रीका को स्थानान्तरित हुए। 1922 तक 18 लाख चीनी जनसंख्या विश्व के अनेक भागों में स्थानान्तरित हो गयी। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व उत्तरी चीन में 12 लाख जनसंख्या प्रतिवर्ष की दर से मंचूरिया में बस गयी। 1950 तक चीन के 50 लाख लोग दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थानान्तरित हो गये। पूर्वी एशिया के देशों में जापान से भी स्थानान्तरण सम्पन्न हुआ। 1880 ई. में हजारों की संख्या में जापानी कोरिया में जाकर बसे। हवाई द्वीप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जापानी जनसंख्या स्थानान्तरित होकर बस गयी। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व 10 लाख से अधिक जापानी मंचूरिया, ब्राजील तथा कोरिया में प्रतिवर्ष बस जाते थे। मंचूरिया की जलवायु जापानियों के प्रतिकूल थी, फलतः बहुसंख्यक जापानी स्वदेश वापस भी आ गये। जापानी जिस देश में भी गये, वहाँ उन्होंने अपने सद्गुणों के कारण आदर पाया।

पश्चिमी एशिया में भी मानव स्थानान्तरण सम्पन्न हुआ है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् बड़ी संख्या में लेबनानी एवं तुर्क सम्पन्न अतिथि श्रमिक के रूप में स्थानान्तरित हुए थे। पश्चिमी एशिया की शुष्क जलवायु एवं कम संसाधन के कारण इरानी, इराकी, तुर्की, लेबनानी एवं यहूदी लोग यूरोप, अमेरिकी देशों, अफ्रीका एवं एशिया के उपभागों की ओर स्थानान्तरित हुए थे। ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना के पश्चात् भारत के लोगों को 'गिरमिटिया' श्रमिक के रूप में श्रीलंका, मलाया, फीजी, सूरीनाम, मारीशस, गुयाना, थाइलैण्ड एवं म्यांमार भेजा गया। कुछ तो वहीं बस गये तथा अन्य स्वदेश वापस आ गये। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन ने स्थानान्तरण को बढ़ावा दिया। बंगला देश के स्वतंत्र होने पर भी भारी संख्या में स्थानान्तरण हुए।

अफ्रीकी देशों से स्थानान्तरण- अफ्रीकी स्थानान्तरण की प्रवृत्ति बलात् स्थानान्तरण की रही है। 16 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में ही अफ्रीकी लोग दास के रूप में अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों, पश्चिमी द्वीप समूह ले जाये गये। उल्लेखनीय है कि दास के रूप में मानव व्यापार को जन्म देने में मुसलमानों एवं यूरोपियन लोगों की साझेदारी रही है। 16वीं शदी के मध्य से लेकर 17 वीं शदी के प्रारम्भिक वर्षों में 50 लाख नीग्रो अफ्रीकी देशों में स्थानान्तरित हो चुके थे। कैरेबियन एवं ब्राजील में बागाती कृषि को सम्पन्न करने के लिए 35 लाख दास आये थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1860 ई. तक 70 हजार अफ्रीकी दास बस गये थे। प्रेक्षणों से विदित होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीका नीग्रो की दास के रूप में संख्या 10 लाख से अधिक ही रही होगी। पशुओं के सदृश व्यवहार दासों के साथ किया जाता था तथा पशुओं के व्यापार जैसी ही प्रणाली भी उनके साथ अपनायी जाती थी। अफ्रीकी नीग्रो का दास के रूप में व्यापार मानव जाति के लिए कलंक साबित हुआ। आधुनिक काल के स्थानान्तरण में दासों का स्थानान्तरण एक उल्लेखनीय घटना है।

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त विश्व जनसंख्या का स्वरूप अपने-अपने देशों की ओर वापसी का रहा है। सारणी 10.2 में 1946-57 तथा 1960-70 के मध्य महाद्वीपों के अनुसार नये प्रब्रजन एवं 1970 में प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है।

सारिणी 10.2

महाद्वीपों के अनुसार शुद्ध प्रब्रजन एवं जनसंख्या वृद्धि

(जनसंख्या दस लाख में)

महाद्वीप	शुद्ध प्रब्रजन1946-57	शुद्ध प्रब्रजन1960-70	जनसंख्या वृद्धि (प्राकृतिक) 1970
एशिया	-0.51	-1.2	+47.7
अफ्रीका	+0.5	-1.6	+9.3
यूरोप	-5.4	+0.3	+3.2
लैटिन अमेरिका	+0.9	-1.9	+8.2
उत्तरी अमेरिका	+3.4	+4.1	+3.0
आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैण्ड	+1.0	+0.9	+0.4

Source: Sakharo,West Bengal,An Ethno-Demographic and Ethnographical Essay, Leningard, 1997.

सन् 1947 में भारत वर्ष के विभाजन के तत्काल बाद भारी संख्या में जनसंख्या का स्थानान्तरण प्रारम्भ हुआ। पाकिस्तान से 1 करोड़ हिन्दू भारत आये तथा यहाँ से 4 लाख मुसलमान पाकिस्तान गये। भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा पर जनसंख्या का यह आना-जाना तो समयबद्ध ढंग से था। परन्तु देश के पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भाग में यह आवागमन निरन्तर चलता रहा। पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) से अधिकांश बंगाली मुसलमान अनधिकृत घुसपैठ करके भारत के सीमावर्ती प्रान्तों व असम में आ बसे। इन्हीं को लेकर आज देश के समक्ष असम समस्या खड़ी है। 1951 की जनगणना के अनुसार 9 प्रमुख प्रान्तों में विदेशों से आये शरणार्थियों को बसया गया। जिसका विवरण सारणी 10.3 में दिया गया है:

सारणी 10.3

राज्य	शरणार्थी जनसंख्या (हजार)	राज्य की जनसंख्या%
1. पंजाब	3232	34.40
2. पश्चिमी बंगाल	2090	9.24
3. असम	274	3.13
4. बम्बई (महाराष्ट्र)	338	0.95
5. उत्तर प्रदेश	480	0.77
6. मध्य प्रदेश	113	0.53

Source: India: Spotlight on Population

10.7 प्रवासन या स्थानान्तरण या देशान्तरण के प्रभाव (Effects of Migration)

जब बहुत अल्प मात्रा में देशान्तरण होता है तो अधिक प्रभावकारी नहीं होता परन्तु जब कभी जनसंख्या का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण होता है तो यह अनेक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का कारण बनता है। एडवर्ड रास (Edward Ross) का मत है कि निरन्तर आवास तथा प्रवास ही किसी राष्ट्र के शरीर तथा आत्मा को सबल

बनाते हैं। जो जाति अपने निवास स्थान से जितनी ही अधिक दूर प्रवास करती है वह उतनी ही अधिक उन्नतिशील होती है।

अरब तथा मूअर (Moors) लोगों ने स्पेन में जाकर वहाँ सरासेन सभ्यता का विकास किया। यूरोपवासियों ने अमेरिका में प्रवास कर वहाँ की मूल सभ्यता को ही परिवर्तित कर दिया। औपनिवेशिक विकास के फलस्वरूप यूरोप का आर्थिक विकास तो हुआ ही साथ ही साथ संसार के कोने-कोने में यूरोपीय संस्कृति का भी विस्तार हुआ।

यद्यपि देशान्तरण के प्रभावों का ठीक-ठाक अध्ययन करना सहज नहीं है फिर भी निम्न बातों को दृष्टिगत् रखकर इसके प्रभावों का कुछ हद तक अध्ययन किया जा सकता हैः

1. **उस देश का दृष्टिकोण जहाँ से लोग प्रवासित हो रहे हैं** (Attitute of the country the migrants leave) - जिस देश से लोग प्रवासित हो रहे हैं यदि उस देश में जनाधिक्य की स्थिति है तो प्रवास को बुरा नहीं माना जाएगा। इसके विपरीत, यदि उस देश में श्रम शक्ति का अभाव है तो प्रवास को अच्छा नहीं माना जाएगा। साम्यवादी देश अपने नागरिकों का विदेशों में जाकर बसना अच्छा नहीं मानते। उनकी धारणा है कि विदेशों में लोग जाकर तभी बसते हैं जब उन्हें अपने देश में रोजगार तथा मजदूरी नहीं मिलती है।

   देशान्तरण से किसी देश की प्रतिभा का अन्य देशों में पलायन हो जाता है। कार्यशील व सशक्त व्यक्ति अन्य देशों में चले जाते हैं जिससे देश की जनसंख्या की आयु-संरचना में परिवर्तन हो जाता है। देश में वृद्धों तथा बच्चों की अधिकता हो जाती है। स्त्री-पुरूष अनुपात भी बदल जाता है, पुरूषों के अभाव में आर्थिक क्रियाकलापों के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ-जहाँ पुरूषों की कमी होती है वहाँ निर्माण उद्योग, जोखिमपूर्ण व्यवसाय आदि की कमी होती हैं। पुरूष विहीन परिवार सामान्यतया खाद्यानों का ही उत्पादन करते हैं जबकि पुरूषयुक्त परिवारों द्वारा व्यावसायिक फसलों यथा-कपास, गन्ना आदि का उत्पादन किया जाता है।

2. **उस देश का दृष्टिकोण जहाँ जाकर लोग बसते हैं** (Attitude of the Receiving Country) - विदेशों से आकर बसने वालों को प्रायः अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है क्योंकि उनके आने से देश के मूल निवासी अपनी भाषा, संस्कृति, खान-पान, रीति-रिवाजों तथा आर्थिक साधनों पर अतिक्रमण सा महसूस करते हैं। यदि किसी देश में साधनों की अल्पता है तो देशान्तरण से उस अभाव के और अधिक बढ़ने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी देश में कतिपय विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों का अभाव है और देशान्तरित होकर आने वाले लोगों में उक्त योग्यता विद्यमान है तब ऐसे व्यक्तियों के प्रति लोगों में दुर्भावना नहीं होगी।

   आर्थिक अभाव से भी अधिक महत्वपूर्ण कारक राजनैतिक, जातीय तथा धार्मिक होते हैं जो लोगों को विदेशी नागरिकों से दुर्भावनापूर्ण दृष्टिकोण रखने के लिए बाध्य करते हैं। प्रवासियों के आकर बसने से कई लाभ भी होते हैं। सामान्यतया प्रवासी व्यक्ति साहसी, प्रगतिशील, संघर्षशील, सहनशील तथा प्रतिभायुक्त होते हैं। अन्य देशों से आकर बसने वाली इस श्रेष्ठतम श्रम शक्ति से अच्छे परिणामों का प्राप्त होना स्वाभाविक है।

3. **प्रवासियों का व्यवहार एवं दृष्टिकोण** (Attitude and Behaviour of the migrants) - कोई प्रवासी व्यक्ति जब किसी नए स्थान पर जाकर बसता है तो नए स्थान पर उसे अनेक बातों से सामन्जस्य स्थापित करना पड़ता है। जिसके लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में आँकड़े सुलभ नही हो पाते हैं जिसके फलस्वरूप हमारा अध्ययन तर्क तथा परिकल्पनाओं पर ही आधारित रहता है। संक्षेप में , देशान्तरण के प्रभावों का अध्ययन दो शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है:

(क) देशान्तरण के सकारात्मक प्रभाव (Positive effects of theMigration)

(ख) देशान्तरण के नकारात्मक प्रभाव (Negative effects of theMigration)

(क) देशान्तरण के सकारात्मक प्रभाव - देशान्तरण के सकारात्मक अथवा अच्छे प्रभाव निम्नलिखित हैं:

(1) भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होना - ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है और भूमि का अपखण्डन एवं विखण्डन रूक जाता है। गाँवों में भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होने से बचत करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसा कि नर्क्स ने इंगित किया है कि छिपी हुई बेरोजगारी इस व्यवसाय की बचत की सम्भावित शक्ति (Saving Potential) की द्योतक है। अतः यदि उन्हें शहरों में व्यवसाय मिल जाता है तो ग्रामीण बचतें बढ़ जायेंगी।

(2) श्रमिकों की मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य - यह देखा जाता है कि किसी स्थान पर रोजगार के अवसर तो उपलब्ध होते हैं, परन्तु वहाँ श्रमिकों का अभाव रहता है। इसके विपरीत, कुछ स्थानों पर रोजगार के अवसर कम होते हैं, किन्तु वहाँ श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक रहती है। उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में उत्पादन की मात्रा कम होगी। देशान्तरण श्रमिकों की माँग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करके राष्ट्रीय आय की वृद्धि में सहायक होता है। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का सन्तुलित विकास होता है। देशान्तरण से उपयुक्त कार्य हेतु उपयुक्त व्यक्ति मिल जाता है।

(3) एकता की भावना का विकास - एक देश के अन्तर्गत जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाजों से परिचित होते हैं इससे उनमें भावनात्मक एकता का विकास होता है। इस तरह, देशान्तरण मनुष्य में मानवता तथा भाई-चारे की भावना को विकसित करता है तथा सामाजिक समरसता तथा सांस्कृतिक विस्तार को बढ़ावा देता है।

(4) नगरीकरण के लाभ - देशान्तरण से नगरीकरण के समस्त लाभ सुलभ हो जाते हैं। नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन एवं संचार आदि की सुविधाएँ अधिक होती हैं। तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण तक शोध की सुविधाएँ नगरों में सहजता से उपलब्ध रहती है। इसके अतिरिक्त, नगरीय क्षेत्रों में देश-विदेश के व्यक्तियों की शैक्षणिक प्रतिभा, साहित्य, कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र में उपलब्धियों का लाभ भी उठाया जा सकता है। इस तरह, नगरीकरण का लाभ देशान्तरण से ही प्राप्त किया जा सकता है।

(5) जनांकिकी की दृष्टि से लाभ - देशान्तरण जनांकिकी की दृष्टि से भी लाभकारी होता है। इसमें जन्म एवं मृत्यु दर में कमी आती है तथा स्वास्थ्य सुविधाओं आदि की सुलभता से जीवन-स्तर ऊँचा उठता है तथा अधिक समय तक जीवित रहने की सम्भावना बढ़ जाती है।

(ख) देशान्तरण के नकारात्मक प्रभाव –

देशान्तरण के जहाँ एक ओर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हें वहीं दूसरी ओर इसके नकारात्मक प्रभाव भी कम नहीं पड़ते। यह समाज में उथल-पुथल उत्पन्न कर देता है जिससे सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। कभी-कभी जब भारी मात्रा में देशान्तरण होता है तो जिस देश में देशान्तरण होता है उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। देशान्तरण के प्रमुख कुप्रभाव निम्नलिखित हैं

(1) मानसिक असन्तोष - जब कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर प्रवास करता है तो उसके मन में कुछ निश्चित उद्देश्य होता है तथा महत्वाकांक्षाएं होती हैं, परन्तु यदि वे उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते और वास्तविक उपलब्धियाँ आशानुरूप नहीं होती तो इससे प्रवासी व्यक्ति में मानसिक असन्तोष उत्पन्न होता है और मानसिक बीमारियाँ बढ़ती हैं। इस सम्बन्ध में **डेविड एम. हीर (David M. Heer)** का कथन है कि, ***"यदि प्रवासी एवं गैर-प्रवासी व्यक्तियों के बीच अन्य अन्तरों को स्थिर भी मान लिया जाय तो भी यह कहा जा सकता है कि प्रवासियों में मानसिक बीमारी का दबाव गैर-प्रवासियों की अपेक्षा अधिक होता है।"***

(2) अन्तर-व्यक्तिक सम्बन्धों का ह्रास - देशान्तरण परिवार-जनों, मित्रगणों तथा सगे-सम्बन्धियों के बीच परस्पर सम्बन्धों में कमी ला देता है। इससे सामाजिक घनिष्ठता में कमी आती है और सामाजिक अलगाव को बढ़ावा मिलता है। कभी-कभी नए स्थान पर प्रवासी को अपना कोई साथी नहीं मिल पाता है और वह अपने आपको अकेला महसूस करने लगता है। उसे मनोरंजन का कोई अच्छा साधन नहीं मिल पाता। गलत काम करने पर वहाँ उसे कोई रोकने वाला नहीं होता है फलतः वह जुआ, शराब तथा वेश्यावृत्ति आदि भयंकर बुराइयों का शिकार हो जाता है।

(3) वर्ग-भेद - देशान्तरण से समाज में वर्ग-भेद को बढ़ावा मिलता है। सामान्यतया प्रवासी व्यक्ति अपना अलग समुदाय बनाने लगते हैं। प्रायः प्रवासियों व स्थानीय व्यक्तियों में सामाजिक व सांस्कृतिक अलगाव बना रहता है। इस तरह, समाज के अन्दर ही समाज बनने लगता है। इन समाजों में भाषा, जाति, प्रान्तीयता तथा धर्म आदि के नाम पर कभी-कभी संघर्ष एवं तनाव का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इससे कभी-कभी बड़ी गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

(4) सामंजस्य स्थापित करने की समस्या - देशान्तरित व्यक्तियों में प्रायः नए स्थान के लिए लगाव नहीं रहता है। अतः वे उस स्थान के विकास में रूचि नहीं रखते हैं। वे अपने को स्थानीय समाज में अलग रखते हैं। इस तरह अलगाव की भावनाएं उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध होती हैं।

प्रो. एल्फ्रेड सौबे का विचार है कि देशान्तरण से प्रवासी व्यक्ति की मनोवृत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रवास से मनुष्य के जीवन में विस्थापित (displaced) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रवासित व्यक्ति को अपने चिर परिचित भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण को छोड़कर अचानक ऐसे नवीन

वातावरण में पदार्पण करना पड़ता है जिसके बारे में वह पूर्णतया अनभिज्ञ रहता है। इस नवीन वातावरण में न केवल उसकी आर्थिक स्थिति बदलती है वरन् उसे एक नए खान-पान, पहनावा, संस्कृति तथा जलवायु आदि में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। नया वातावरण प्रारम्भ में व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगता तथा प्रतिकूल प्रतीत होता है। यदि इस वातावरण से वह अपने आपको समायोजित नहीं कर पाता तो व्यक्ति धीरे-धीरे आत्म केन्द्रित हो जाता है।

टी. लिन स्मिथ (T. Lyn Smith) के शब्दों में, ***"(जब व्यक्ति प्रवासित होता है तब) वह अपने समस्त पूर्व प्राथमिक तथा विशिष्ट रूचिकर समूह से अलग हो जाता है। अपने वर्ग से उसकी पहचान समाप्त हो जाती है, व्यक्ति को नए समूह में अपना स्थान बनाना आवश्यक हो जाता हैं इसके अतिरिक्त उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह नए समाज में अपने लिए लम्बवत् अथवा नवीन समुदाय की वर्ग संरचना में स्थान बना लें। प्रवासित व्यक्ति की मूल स्थान की भूमिका समाप्त हो जाती है तथा वह नए स्थान पर अपरिचित रहता है। नए समाज में अपने को स्वीकार्य बनाने की वह भरपूर कोशिश करता है। परन्तु नवीन स्थान पर स्वीकार्य होने की प्रक्रिया अर्थात नए सामाजिक वर्गों में अपना स्थान सुनिश्चित करवाने की प्रक्रिया तथा वर्ग प्रणाली में स्थान प्राप्त करने की प्रक्रिया न तो सुखद होती है और न ही शीघ्रता से होती है।"***

(5) आवास एवं जन घनत्व में वृद्धि की समस्या- देशान्तरण आवास की समस्या को बढ़ा देता है। प्रवास से शहरी जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है जिसके कारण वहाँ अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं जैसे- यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा स्वच्छता आदि। इस तरह यदि परिव्रजन से कहीं जनसंख्या का दबाव घटता है तो अन्य स्थान पर उनके जाने से वहाँ भी कमोवेश वही समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं।

10.8 अभ्यास प्रश्न(Practice Questions)

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें-

1. प्रो. वेब का जनसंख्या परिवर्तन
2. प्रवासन के आकर्षक तत्व
3. प्रवासन के प्रत्याकर्षक
4. प्रवासन के कारक
5. देशान्तरण के मार्ग में बाधायें
6. प्रागैतिहासिक हस्तान्तरण
7. ऐतिहासिक स्थानान्तरण
8. बलात् तथा स्वैच्छिक स्थानान्तरण

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. प्रवास के प्राकृतिक और भौगोलिक कारक क्या हैं?

A. सूखा और बाढ़ B. भूमि की कमी
C. औद्योगिकीकरण D. परिवहन के साधन

2. निम्नलिखित में से कौन सा पलायन का आर्थिक कारक नहीं है?

A. सूखा और बाढ़ B. भूमि की कमी
C. औद्योगिकीकरण D. परिवहन के साधन

3. मजबूर और स्वैच्छिक प्रवास निम्नलिखित में से किसके आता है?

A. आधुनिक प्रवासन B. ऐतिहासिक युग प्रवासन

C. पूर्व ऐतिहासिक प्रवासन D. सभी विकल्प गलत है।

4. प्रवास का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है?

A. भूमि की जनसंख्या के दबाव में कमी B. मानसिक अशांति

C. वर्ग संघर्ष D. पारस्परिक संबंध का अवमूल्यन

5. प्रवास का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है?

A. वर्ग संघर्ष B. भूमि की जनसंख्या के दबाव में कमी

C. श्रम की मांग और आपूर्ति में समायोजन D. एकता की भावना का विकास

10.9 सारांश (Summary)

सर्वप्रथम इस इकाई के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए **प्रो. वेब** के जनसंख्या परिवर्तन के सिद्धान्तों को **'कोआर्डिनेट ग्राफ'** की सहायता से जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि तथा ह्रास से शुद्ध प्रवास तथा अप्रवास के बीच सम्बन्धों को स्थापित करते हुए जनसंख्या में वृद्धि तथा कमी के सभी 8 निष्कर्षों को बताया गया है। तत्पश्चात् देशान्तरण के आकर्षक तथा प्रत्याकर्षक तत्वों को समझाया गया है। आकर्षक कारक लोगों को प्रवास के लिए प्रोत्साहित करते है।

दूसरे शब्दों में, ये ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिससे मनुष्य अपना निवास स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर बसने के लिए प्रोत्साहित होता है। दूसरी तरफ प्रत्याकर्षण तत्व वे हैं जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने को बाध्य करते हैं। इस तरह प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी, राजनीतिक तथा सामाजिक तत्वों का अध्ययन किया गया है। इनका अध्ययन यह बताता है कि कैसे उक्त कारक प्रवासन को प्रोत्साहित तथा प्रत्याकर्षित करते हैं ?

पुनः देशान्तरण के मार्ग की बाधाओं का अध्ययन किया गया है। जिसके अन्तर्गत विशिष्ट स्थान से लगाव, सामाजिक समायोजन, सांस्कृतिक परम्परायें, विशिष्ट स्थान की जानकारी अन्य कारणों को बताया गया है जिनका स्वदेश छोड़कर विदेश में बसने वाले व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है।

वैश्विक जनसंख्या में स्थानान्तरण की प्रवृत्तियों के अध्ययन के अन्तर्गत प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक तथा आधुनिक स्थानान्तरण का विस्तृत करते हुए प्रागैतिक स्थानान्तरण की विशेषताओं, बलात् तथा स्वैच्छिक स्थानान्तरण, यूरोप से अमेरिकी महाद्वीपों की ओर स्थानान्तरण, यूरोप से अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया की ओर स्थानान्तरण, एशियाई देशों से स्थानान्तरण, अफ्रीकी देशों से स्थानान्तरण अन्य का अध्ययन किया गया है। तत्पश्चात् देशान्तरण के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इसके अन्तर्गत देशान्तरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं का अध्ययन किया गया है। संक्षेप में, इस इकाई-10 के अन्तर्गत देशान्तरण से सम्बन्धित प्रवासन के प्रभावी कारकों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया गया है।

10.10 शब्दावली (Glossary)

- **आकर्षक तत्व** Pull Factors
- **प्रत्याकर्षण तत्व** Push Factors
- **पुरूष-विशिष्ट जन्म दर** Male Specific Birth Rate
- **स्त्री विशिष्ट जन्म दर** Female Specific Birth Rate
- **बाँधायें अथवा गतिरोध** Hurdles

10.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Questions)

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. A 2. A. 3.B. 4.A 5.A

10.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- डॉ. डी. एस. बघेल एवं डॉ. किरण बघेल - 2012 - *जनांकिकी*, विवेक प्रकाशन
- डॉ. किरन बघेल (1984): *जनांकिकी और भारत में जनसंख्या*, पुष्पराज प्रकाशन, इलाहाबाद।
- डॉ. जय प्रकाश मिश्र: *जनांकिकी*, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
- मंगला सिंह: *मानव भूगोल के मूल तत्व*, मिश्रा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, वाराणसी
- डॉ. रामदेव: *जनसंख्या भूगोल*, बसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर
- डॉ. वि. कुमार: *जनांकिकी*, साहित्य भवन आगरा

10.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- Lee, E : A theory of Migration in Population Geography, A Reader edited by Demko. 1970, p. 288-293
- I.V. Sakharaov : West Bengal, An Ethnodemographic and Ethnographical Essay, Leningrad, 1997.
- Baker, O.E. (1933) Rural – Urban Migration and National Welfare, U.S.A. (The Geographical Review Vol 14. No. 2)
- Mahto, Kailash (1985) : Population Mobility and Economic Development in Eastern India, Inter – India Publications, New Delhi.
- Shrinivasan, K (1979) : Dynamics of Population and Family Welfare in India, Bombay.

- Sundaram, K.V. (1985) : Population Geography, Heritage Publishers, New Delhi.
- Agrawal SN (192) India's Population Problem. Tata Mcgrow Hill Co. Bombay.
- Choubey, P.K. (1972), Population Policy in India, Kausik Publication, New Delhi.
- Srinivasan, K. (1998), Basic Demographic Techniques and Applications : Sagar Publication, New Delhi.
- John I. Clark : Population Geography.
- G. W. Barclay : Technique of Population Analysis.
- Thompson & Lewis : Population.

10.14 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. प्रवासन के प्रभावकारी कारकों को स्पष्ट कीजिए तथा इनकी व्याख्या कीजिए।
2. वैश्विक जनसंख्या में स्थानान्तरण की प्रवृत्तियों पर निबन्ध लिखिए।
3. देशान्तरण के प्रभावों को बताइये।
4. आधुनिक जनसंख्या स्थानान्तरण पर निबन्ध लिखें।

इकाई 11 - आन्तरिक प्रवासन के सिद्धान्त
(Theories of Internal Migration)

11.1 प्रस्तावना

11.2 उद्देश्य

11.3 आन्तरिक प्रवासन या आन्तरिक देशान्तरण

11.4 आन्तरिक प्रवासन के सिद्धान्त

11.4.1 आकर्षण-प्रत्याकर्षण सिद्धान्त

11.4.2 प्रवास कटिबन्ध सिद्धान्त

11.5 अभ्यास प्रश्न

11.6 सारांश

11.7 शब्दावली

11.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

11.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

11.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

11.11 निबंधात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

इस इकाई में हम आन्तरिक प्रवासन से सम्बन्धित प्रवासन के सिद्धान्त का अध्ययन करेंगे। प्रवासन आन्तरिक तथा बाह्य दोनों रूपों में हो सकता है। जब प्रवासन देश की सीमा के अन्दर होता है तब इसे आन्तरिक प्रवासन तथा जब देश की सीमा से बाहर दूसरे देश में होता है तो इसे बाह्य प्रवासन कहते हैं। सैद्धान्तिक रूप में इनमें मौलिक अन्तर नहीं होता जबकि व्यवहारिक रूप में दोनों देशों की कानूनी औपचारिकताएं बहुत बड़ी बाधा हैं। यद्यपि कभी-कभी आन्तरिक प्रवासन में भी कानूनी औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती हैं। कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत (नागालैण्ड, अरूणांचल प्रदेश) हेतु प्रवासन में अनेक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। इस तरह उनमुक्त प्रवासन में कानूनी औपचारिकतायें बहुत बड़ी बाधा हैं।

प्रवासन मुख्यतः स्थान विशेष के आकर्षण-प्रतिकर्षण का परिणाम होता है। व्यवसाय, रोजगार, अधिक आय की इच्छा, शिक्षा, आवास, मनोरंजन, स्वास्थ्य, अपनों के साथ रहने की इच्छा, नगरीय जीवन की बढ़ती चकाचौध अन्य आकर्षण के मुख्य बिन्दु हैं। जो प्रवासन की गति तथा मात्रा को बढ़ाते हैं। जबकि इसके विपरीत इनका अभाव तथा सामाजिक वैमनस्यता अन्य प्रवासन के प्रतिकर्षण कारक हैं, जिनके कारण लोग प्रवासन मजबूरी में करते हैं। इसी तरह प्रवासन के अनेक ऐतिहासिक तथ्य भी हैं जिनके कारण प्रवासन की गति तथा मात्रा में परिवर्तन होता है। इस क्रम मे इस इकाई में प्रवासन सम्बन्धी सिद्धान्तों को बताया गया है।

11.2 उद्देश्य (Objectives)

- ✓ आन्तरिक तथा बाह्य प्रवासन (अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन) के अन्तर को समझना।
- ✓ प्रवासन को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण प्रभावों को जानना।
- ✓ प्रवासन से सम्बन्धित 'प्रो. ली. के आकर्षण-प्रत्याकर्षण सिद्धान्त' तथा **'प्रो. ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबन्ध सिद्धान्त'** के द्वारा प्रवासन को समझना।
- ✓ प्रवासन सम्बन्धी प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत होना।

11.3 आन्तरिक प्रवासन या आन्तरिक देशान्तरण (Internal Migration)

जब किसी देश के निवासी अपने देश की सीमाओं के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उनका यह स्थानान्तरण आन्तरिक देशान्तरण या आन्तरिक प्रवासन कहलाता है। जैसे - यदि कोई व्यक्ति इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) से जाकर मुम्बई (महाराष्ट्र) में बस जाता है तब इसे आन्तरिक देशान्तरण या प्रवासन कहा जाता है।

प्रो. डोनाल्ड जे. बोग (Donald J. Bouge) की धारणा है कि आन्तरिक प्रवास के अन्तर्गत अन्तर्गमन के लिए In-migration शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए जबकि बहिर्गमन के लिए Out-migration शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्तर्गमन से तात्पर्य ऐसे प्रवासी से है जो एक राष्ट्र की सीमाओं के अन्तर्गत अपने मूल निवास को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाता है, जबकि दूसरे देश से आकर बसने को अप्रवासन (Immigration) कहा जाता है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आकर मुम्बई में बस जाता है तो मुम्बई की दृष्टि से वह आन्तरिक प्रवासी (In-Migrant) कहलाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति इंग्लैंड से आकर लखनऊ में बसता है तब भारत में यह (Immigrant) कहलाएगा। यदि कोई किसी स्थान अथवा प्रदेश को छोड़कर दूसरे स्थान अथवा प्रदेश में जाकर बस जाता है, परन्तु वह स्थान या प्रदेश राष्ट्रीय सीमाओं के अन्तर्गत है तब इस प्रकार के बहिर्गमन को व्नज उपहतंजपवद कहा जायेगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र की सीमाओं को पार कर दूसरे राष्ट्र में चला जाता है तब उसे प्रब्रजक (Emigrants)कहा जाएगा।

आन्तरिक देशान्तरण का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है:

(क) वैवाहिक देशान्तरण (Marital Migration) - वैवाहिक देशान्तरण वर अथवा वधू के कारण घटित होता है। इस तरह का देशान्तरण गाँव से शहर, शहर से शहर, शहर से गाँव अथवा गाँव से गाँव को हो सकता है। कभी-कभी इस तरह का देशान्तरण अन्तर्राष्ट्रीय भी हो सकता है परन्तु इसकी संख्या नगण्य होती है।

(ख) अन्तर्प्रान्तीय देशान्तरण (Inter Provincial Migration)- इस तरह का देशान्तरण किसी देश की सीमा के अन्तर्गत एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को होता है। इस तरह के देशान्तरण का निर्धारण प्रान्तीय सीमाओं के अन्तर्गत होती है।

(ग) गाँव-शहर देशान्तरण (Rural-Urban Migration) - गाँव शहर देशान्तरण चार प्रकार के हो सकते हैं:

1. गाँव से शहरों की ओर देशान्तरण,
2. गाँव से गाँव की ओर देशान्तरण,
3. शहरों से गाँव की ओर देशान्तरण और
4. शहरों से शहरों की ओर देशान्तरण।

गाँव से गाँव को देशान्तरण रोजगार की तलाश में हो सकता है अथवा गांव की उन लड़कियों का होता है जो एक गाँव से दूसरे गाँव में ब्याह दी जाती हैं। शहर से शहर की ओर देशान्तरण नौकरी पेशा लोगों के स्थानान्तरण के कारण अथवा काम की तलाश में होता है। शहरी लड़कियों का विवाह भी इसका कारण होता है। गाँव से शहर की ओर देशान्तरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह विकास के परिणामस्वरूप होता है। यह शहर के खिंचाव (Pull) तथा गाँव के धक्के (Push) के कारण होता है।

शहरीकरण - गाँवों में जमीन व रोजगार की कमी पड़ने के बाद शहरों में बसना ही इसका कारण है। भारत जैसे विकासशील देशों में जब गाँवों में कृषि कार्य से लोग फुर्सत पा जाते हैं तब कार्य की तलाश में शहरों की ओर चले जाते हैं, परन्तु गाँवों में कृषि कार्य पुनः प्रारम्भ होता है तो वे पुनः गांवों में वापस आ जाते हैं। इसे Back Migration अथवा Reverse Flow भी कहते हैं।

(घ) सम्बद्धता जन्य देशान्तरण (Associated Migration) - इस तरह के देशान्तरण से अर्थ विदेश में नौकरी या व्यवसाय करने गए देशान्तरकारी के साथ उसके आश्रितों के देशान्तरण से है। कमाने वाले सदस्यों का देशान्तरण प्रायः एकांकी देशान्तरण के रूप में होता है। वे शहरों में रहकर धन कमाते हैं और

गाँव में रहने वाले आश्रितों को धनराशि भेजते रहते हैं। परन्तु एकांकी परिवारों में वृद्धि के साथ सम्बद्धताजन्य देशान्तरण की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है।

11.4 आन्तरिक प्रवासन के सिद्धान्त (Theory of In-Migration)

सामान्यतया आन्तरिक तथा बाह्य प्रवासन के सिद्धान्तों में कोई मूल अन्तर नहीं होता। दोनों ही तरह के सिद्धान्तों में जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की मूल प्रकृति लगभग समान है। आन्तरिक प्रवासन में एक देश या राज्य की सीमा में होने से प्रवासियों को सामान्यतया कानूनी कठिनाईयों - पासपोर्ट, वीजा अन्य की औपचारिकतायें नहीं पूरी करनी पड़ती हैं, जबकि बाह्य स्थानान्तरण या प्रवासन में प्रवासियों को पासपोर्ट, वीजा तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती है। इस तरह मूल रूप से आन्तरिक तथा बाह्य प्रवासन में कोई अन्तर नहीं होने से दोनों ही तरह के प्रवासन के सिद्धान्त समान माने जाते हैं। जनसंख्या प्रवासन या स्थानान्तरण या प्रब्रजन के कारणों (Causes) एवं प्रवासियों के चयन की प्रकृति के आधार पर निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं

11.4.1 आकर्षण-प्रत्याकर्षण सिद्धान्त (The Push-Pull Theory)

यह सिद्धान्त मनुष्य के निर्णय लेने की प्रक्रिया (decision making process) तथा स्थानान्तरण के कारणों (Causes of migration) से सम्बन्धित है। प्रायः मनुष्य निम्नलिखित दो कारणों से स्थानान्तरण के लिए विवश होता है -

1. मूल स्थायी निवास का अपकर्षण - प्रमुख कारण कम मजदूरी, बेरोजगारी, जातीय, धार्मिक, राजनीतिक उत्पीड़न, प्राकृतिक सहिष्णुता आदि हैं।

2. सम्भाव्य स्थलों के प्रति आकर्षण - प्रमुख कारण रोजगार के अवसर, सामाजिक-धार्मिक एवं राजनीतिक लाभ, धार्मिक सहिष्णुता आदि हैं।

आकर्षक कारक (Pull Factors) - प्रवासन के आकर्षक कारकों से तात्पर्य उनसे है जो मनुष्य को अपना निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र बसने को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्रमुख कारक निम्नवत् हैं:

1. रोजगार एवं व्यवसाय के श्रेष्ठ अवसर।
2. अधिक आय अर्जित करने के अवसर।
3. शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण तथा आवास की सुविधायें।
4. मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता।
5. स्वास्थ्यप्रद जलवायु।
6. सगे-सम्बन्धियों एवं इष्ट-मित्रों का आकर्षण।
7. उन्नत नगरीय जीवन।

प्रत्याकर्षण कारक (Push Factors)- प्रवासन के प्रत्याकर्षक कारकों से आशय उन परिस्थितियों से होता है जिनसे बाध्य होकर कोई व्यक्ति अपने स्वाभाविक निवास का परित्याग करता है। कुछ प्रमुख प्रत्याकर्षण कारक निम्नवत् हैं:

1. रोजगार के अवसरों का अभाव।
2. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा प्रशिक्षण का अभाव।
3. मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव।
4. आय प्राप्ति तथा उन्नति के अवसरों का अभाव।
5. सामाजिक तिरस्कार तथा बहिष्कार ।
6. वैमनस्य एवं शत्रुता।
7. असामाजिक तत्वों का आतंक।
8. राजनीतिक, जातीय तथा धार्मिक आधार पर भेदभाव।

प्रो. ली का सिद्धान्त - प्रो. ई. ली ने अपनी '**A Theory Of Migration In Population Geography**' में अपना सिद्धान्त दिया। **प्रो. ली (Lee)** ने इस सिद्धान्त की चित्रीय व्याख्या प्रस्तुत की है। इनके अनुसार अपेक्षित भावी प्रवास में भौतिक, आर्थिक, शैक्षिक व कानूनी बाधा का अनुभव किया जाता है।

ली ने स्थानान्तरण को 4 कारकों में विभक्त किया है –

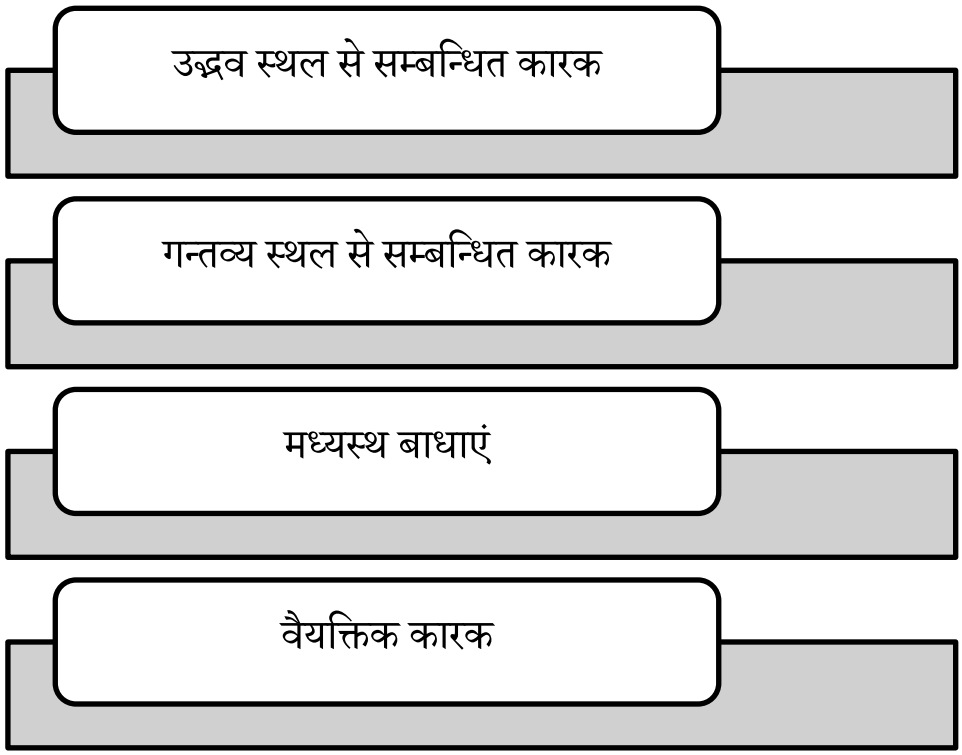

चित्र - 11.1

प्रो. ली का सिद्धान्त

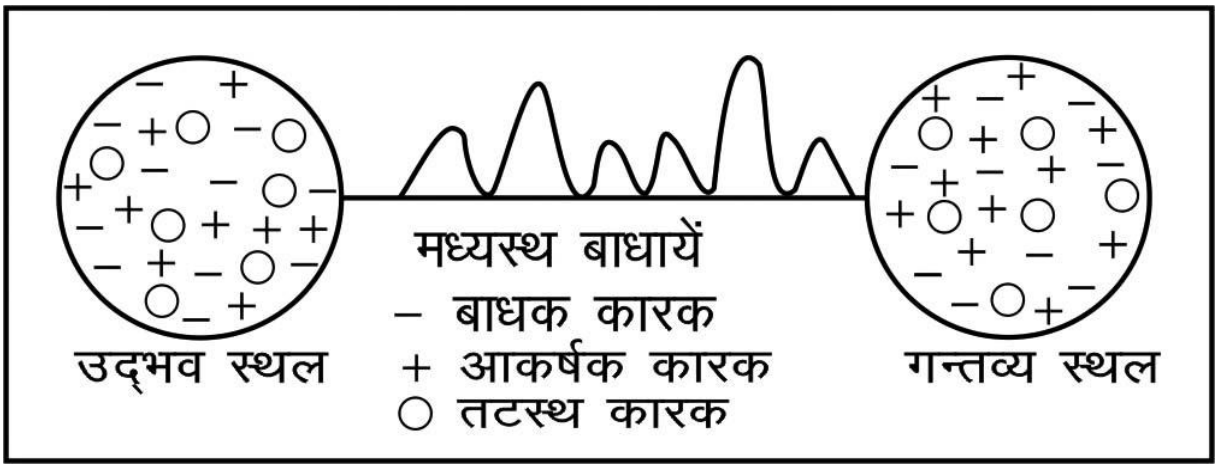

Lee, E. : A Theory of Migration in Population Geography, A Reader edited by Demko, 1970. p. 288-293.

चित्र 11.1 से आकर्षण उत्पन्न करने वाले कारकों को धन (+) बाधा उत्पन्न करने वालो कारकों को ऋण (-) तथा तटस्थ रखने वाले कारकों को शून्य (0) चिन्हों द्वारा दिखाया गया है।

प्रो. ली के अनुसार उद्भव और गन्तव्य स्थल दोनों पर धनात्मक (आकृष्ट करने वाले) कारक और ऋणात्मक (प्रतिकूल) कारक तथा तटस्थ कारक उपस्थित रहते हैं। यदि गन्तव्य स्थल में धनात्मक कारक अधिक और उद्भव स्थल पर ऋणात्मक कारक अधिक पाये जाते हैं, तो स्थानान्तरण अथवा प्रवास की दशायें बनती हैं। दोनों के मध्य भौतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं कानूनी बाधायें हो सकती हैं। ये मध्यस्थ बाधायें छोटी अथवा बड़ी हो सकती हैं। मध्यस्थ बाधायें यदि बड़ी या कठिन होती हैं तो स्थानान्तरण मध्य में ही स्थगित हो सकता है अथवा उसकी दिशा परिवर्तित हो सकती है।

(अ) परिकल्पनायें: प्रो. ली ने स्थानान्तरण की मात्रा, दर और प्रवाह से सम्बन्धित निम्नलिखित परिकल्पनायें की है -

1. पर्याप्त विभिन्नता वाले क्षेत्र में स्थानान्तरण अधिक होता है।
2. समान जाति, भाषा, आय, शिक्षा वाले लोगों में स्थानान्तरण अल्प और जनसंख्या में विभिन्नता वाले लोगों में स्थानान्तरण अधिक होता है।
3. मध्यस्थ, बाधायें जितनी अधिक होंगी, स्थानान्तरण उतना ही अल्प होगा।
4. आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का भी स्थानान्तरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक मन्दी होने पर स्थानान्तरण कम होता है।
5. किसी भी प्रदेश अथवा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के अनुरूप स्थानान्तरण की दर निर्भर होती है।
6. यदि स्थानान्तरण पर प्रभावी रोक न लगाई जाय तो उसकी संख्या व दर बढ़ती जाती है।

(ब) चयनात्मक पक्ष:

वस्तुतः प्रवासन या स्थानान्तरण सभी दशाओं में चयनात्मक होता है। विशिष्ट आयु वर्ग के पुरूष प्रवास पर अधिक जाते हैं। कुछ प्रवासी गन्तव्य स्थल पर धनात्मक कारक अधिक होने के कारण बेहतर अवसर की तलाश में प्रवास करते हैं। परन्तु उद्भव स्थल पर ऋणात्मक कारक प्रभावी होने पर प्रवासी का अपना कोई चुनाव नहीं होता, उसकी बाध्यता होती है। मध्यस्थ बाधाओं की कठिनाइयों के अनुरूप धनात्मक चयन बढ़ता है। उद्भव और गन्तव्य दोनों स्थलों के क्षेत्र और जनसंख्या के गुणों का मिश्रण प्रवासियों की विशेषताओं में परिलक्षित होता है।

(स) विभिन्न विद्वानों के विचार:

'फार' एवं **'हम्फरी'** आदि विद्वानों ने प्रब्रजन को बिना किसी का नियम के होने वाली घटना बताया है। परन्तु **'रोबेन्स्टीन'** (E.G. Reavenstein : The laws of Migration, Journal of R.S. Society, 48, Part 2, June 1985, P. 167-227) महोदय ने प्रब्रजन को नियम के तहत होने वाली घटना बताते हुए उसके कुछ नियम प्रतिपादित किये जो निम्नलिखित हैं:

1. **प्रब्रजन तथा दूरी:** प्रब्रजन की मात्रा दूरी बढ़ने पर घटती है और अधिक दूरी की ओर होने वाले प्रवास पर औद्योगिक व वाणिज्यिक केन्द्रों का प्रभाव पड़ता है।
2. **प्रब्रजन अवस्था:** औद्योगिक व वाणिज्यिक केन्द्रों की ओर प्रवासित जनसंख्या में स्थायित्व आ जाता है। बड़े नगरों अथवा तेजी से बढ़ रहे नगरों में सन्निकटवर्ती नगरीय केन्द्रों से लोग आकर बसते हैं।
3. **प्रवास-प्रवृत्ति में ग्रामीण व नगरीय भिन्नता:** प्रवास प्रवृत्ति के अनुसार नगरीय जनसंख्या में अपेक्षाकृत कम प्रब्रजन की प्रवृत्ति पायी जाती है।
4. **अल्प दूरी प्रवासन में महिलाओं का एकाधिकार:** महिलाएँ कम दूरी वाले प्रवास मे अधिक भाग लेती हैं।
5. **प्रवाह एवं उत्प्रवाह:** प्रब्रजन की मुख्य धारा या प्रवास के साथ उत्प्रवास भी होते रहते हैं।
6. **आर्थिक प्रवृत्ति का प्रभुत्व:** प्रब्रजन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है।
7. **तकनीकी एवं प्रब्रजन:** प्रब्रजन की मात्रा तकनीकी विकास से तो और भी बढ़ती है क्योंकि तकनीकी विकास आधुनिक विश्व के विकास की रीढ़ है।

11.4.2 प्रवास कटिबन्ध सिद्धान्त (Migration Zone Theory)

प्रवास के संदर्भ में ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबन्ध सिद्धान्त (Migration Zone Theory) ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रवास कटिबन्ध सिद्धान्त - इस सिद्धान्त का प्रतिपादन **प्रो. ग्रिफिथ टेलर** ने किया था। उन्होंने मानव जातियों के सम्बन्ध में इसका प्रतिपादन करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि मानव जाति का उद्गम प्रदेश मध्य एशिया कैस्पियन अरब सागर का समीपवर्ती क्षेत्र था। आदिकाल में मानव जाति इसी प्रदेश में रहती थी। बाद में

विकसित होने वाली नवीन मानव जातियाँ इस क्षेत्र में निवास करने वाली पूर्व विकसित जातियों को बाहर परिधि की ओर हटाती गई।

उदाहरणार्थ - पहले उद्भूत होने वाली मानव जाति नीग्रीटो को, उसके बाद आई नीग्रो जाति ने बाहर परिधि की ओर हटा दिया। तत्पश्चात् विकसित होने वाली आस्ट्रेलायड जाति ने पूर्व विकसित दोनों जातियों को बाहर हटाने का कार्य किया। इस प्रकार धीरे-धीरे बाद में विकसित होने वाली जातियाँ अपने पूर्व की जातियों को क्रमशः बाहर की ओर हटाती गई। फलस्वरूप पूर्व विकसित जातियाँ स्थानान्तरण करके महाद्वीपों के बाहरी कटिबन्धों में बसती गई तथा बाद में आई जातियाँ महाद्वीपों के आन्तरिक भागों में पाई जाती हैं।

विश्व में हुए मानव के प्रमुख प्रब्रजन या स्थानान्तरण को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, दो प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है:

(अ) प्रागैतिहासिक प्रब्रजन (Pre-Historic Migration)

(ब) ऐतिहासिक प्रबन्धन (18वीं से 20वीं शताब्दी तक Historic migration)

1 प्रागैतिहासिक (Pre-Historic Migration)

प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या का प्रमुख स्थानान्तरण मध्य एशिया से विश्व के अनेक क्षेत्रों अथवा देशों की ओर हुआ था। इसमें निम्नलिखित मुख्य रहे हैं:

1. मध्य एशिया से पूर्वी यूरोप में यूक्रेन प्रदेश, वोल्गा घाटी तथा पश्चिमी काला सागर तटीय भाग से होते हुए डेन्यूब घाटी तक।
2. मध्य एशिया से मंगोलिया एवं अनादिर प्रायद्वीप की ओर।
3. अनादिर प्रायद्वीप से भी कुछ जनसंख्या बेरिंग सागर होते हुुए उत्तरी अमेरिका गई। उस समय कनाडा की जलवायु आज जैसी कठोर नहीं थी।
4. मध्य एशिया से पूर्वी चीन की ओर।
5. मध्य एशिया से खैबर तथा अन्य दरों के रास्ते सिन्धु घाटी में आकर सम्पूर्ण उत्तर भारत में प्रसार हुआ।
6. मध्य एशिया से ईरान, दजलाफरात में उर्वर प्रदेश होते हुए मिस्र की नील घाटी की ओर।

2 ऐतिहासिक प्रब्रजन (18 वीं से 20 वीं शताब्दी तक (Historic Migration)

इस प्रकार के प्रब्रजन सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से कम आबादी वाले क्षेत्रों की ओर हुए है। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रब्रजन ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय व औद्योगिक केन्द्रो की ओर भी हुए हैं। इस प्रकार प्रब्रजन का स्वरूप अन्तर्महाद्वीपीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर्राज्यीय व स्थानीय स्तर पर देखा जा सकता है। विश्वस्तर पर निम्नांकित प्रब्रजन प्रमुख रहे हैं:

1. **यूरोपीय प्रब्रजन** – 17 वीं शताब्दी से लेकर 20 वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय देशों से उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, उत्तर व दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड तथा साइबेरिया की ओर अन्तर्महाद्वीपीय प्रब्रजन हुए हैं। सन् 1846 से 1932 तक 5 करोड़ लोग इन देशों की ओर स्थानान्तरित हुए थे। 19वीं व 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में यहाँ जनसंख्या प्रब्रजन गति बड़ी तीव्र रही। यहाँ की

जनसंख्या जहाँ भी स्थानान्तरित हुई वहाँ अपनी तकनीक क्षमता को भी ले गई। उन नये देशों की उर्वरशील, संसाधन - सम्पन्न भूमि पर यूरोपीय लोगों की अपनी वैज्ञानिक-तकनीकी क्षमता के उपयोग द्वारा कच्ची सामग्रियों का उत्पादन इतना अधिक बढ़ा लिया कि वे अधिकता वाले पदार्थों को अपने देशों में सस्ती दरों पर भेजने लगे।

19वीं व 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में परिवहन व संचार के साधनों में तीव्रतर विकास से प्रब्रजन को और भी बल मिला। यूरोप से प्रवास किये लोगों की अधिकांश संख्या (लगभग 4 करोड़) संयुक्त राज्य अमेरिका में बसी। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक केवल ब्रिटेन से ही 2.5 करोड़ लोग विदेशों में जाकर बस गये।

सन् 1870 ई. से 1950 ई. तक के 80 वर्षों के काल खण्ड में पोलैण्ड, जर्मनी व पूर्व सोवियत रूस से अधिक संख्या में लोग शरणार्थी के रूप में आकर ब्रिटेन में बस गये। द्वितीय महायुद्ध (1945) के बाद ब्रिटेन से प्रतिवर्ष लगभग 8.50 लाख लोग कामनवेल्थ के देशों में जाकर रहने लगे।

19वीं शताब्दी में ही यूरोपीय संस्कारों ने उपनिवेशों को अपने नियंत्रण में ले लिया। फलस्वरूप स्वतन्त्र रूप से प्रब्रजन को प्रोत्साहन मिला। सन् 1850 ई. तक ब्रिटिश द्वीपों से लगभग 3 लाख लोग प्रतिवर्ष बस जाते रहे परन्तु इसके पश्चात् प्रवासी संख्या में ह्रास दिखायी देने लगा। इटली, जर्मनी, हंगरी व आस्ट्रिया से भी अधिक संख्या में लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर बस गये।

ब्रिटिश उपनिवेश अफ्रीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, भारतवर्ष, म्यांमार, श्रीलंका, ब्रिटिश गुयाना, ट्रिनीडाड, मलाया, बोर्नियों, जमैका, फिजी व पापुआ द्वीप आदि में दूर-दूर तक विस्तृत था। फ्रांस के उपनिवेशों का विस्तार हिन्दचीन, मेडागास्कर, अफ्रीका के सहारा व सूडान प्रदेशों में रहा है। डच लोगों का उपनिवेश इण्डोनेशिया व गायना में विस्तृत था। इनके अतिरिक्त जर्मनी, इटली, बेल्जियम व स्पेन के उपनिवेश विश्व के अनेक भागों में फैले थे।

उपर्युक्त उपनिवेश अपने मातृ देशों के लिए आर्थिक स्तम्भ रहे हैं। उपनिवेशों से खाद्य सामग्री, कच्ची सामग्री, खनिज पदार्थ व अन्य उपयोगी वस्तुयें, मसाले आदि मातृ देशों को भेजी जाती थीं और उनके बदले में विनिर्मित तैयार माल अत्यधिक दरों पर उपनिवेशों को भेज दिये जाते थे। इन उपनिवेशों की मानवशक्ति का उपयोग युद्ध के समय मातृ देशों की रक्षा आदि के लिए सैन्य सेवा में किया जाता था।

सन् 1922 ई. में टर्की व बुल्गारिया से जनसंख्या का प्रवास यूनान की ओर हुआ। इसी प्रकार इटली, स्पेन व पूर्व सोवियत रूस में जनसंख्या का प्रवास शरणार्थी जनसंख्या के रूप में लगभग 20 लाख थी।

सन् 1945 (द्वितीय विश्व युद्ध) के पश्चात् लगभग 80 लाख यूरोपीय शरणार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से उनके स्वदेशों (इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैण्ड्स) में पुनर्स्थापित किये गये।

2. संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी प्रब्रजन - पिछली दो शताब्दियों में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या लगभग 190 गुनी बढ़ी है, जिसका प्रमुख कारण यूरोपीय लोगों का प्रब्रजन ही है। यहाँ की जनसंख्या प्रब्रजन के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें मुख्य हैं:

(i) यूरोपीय जनसंख्या का अप्रवासन ही इस देश की जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख कारण रहा है।

(ii) आने वाले यूरोपीय लोग सर्वप्रथम यहाँ के पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र में बसे। धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़े परन्तु वहीं तक गये जहाँ तक की प्राकृतिक दशायें उनके अनुकूल रहीं।

(iii) इस देश के पूर्वी भाग के सघन आबाद क्षेत्र में, औद्योगिक क्रान्ति के बाद पश्चिमी ग्रामीण जनसंख्या का अप्रवासन पूर्वी नगरों की ओर प्रारम्भ हुआ।

(iv) देश के पूर्वी औद्योगिक नगरीय क्षेत्रों में सघनता बढ़ जाने पर जनसंख्या व उद्योग दोनों का पश्चिम की ओर स्थानान्तरण हुआ।

(v) इस देश में आये अधिकांश (लगभग 90 प्रतिशत) लोग नवीन कृषि भूमि, खनिज व शक्ति के स्रोतों के भूदृश्य का उपयोग कर सुखी जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से आये थे।

(vi) ऐसे शरणार्थी जिन्हें शासन का भय व आतंक था, इस देश में आकर निवास करने लगे, जैसे - यहूदी आदि।

(vii) ब्रिटेन आदि देशों से निर्वासित लोगों ने यहाँ आकर शरण ली।

(viii) दास प्रथा के तहत अफ्रीका से नीग्रो लोग कृषि फार्मों पर कार्य करने के लिये यहाँ लाये गये।

(ix) दास-प्रथा समाप्त हो जाने पर चीन, भारत, जापान के लाखों श्रमिक यहाँ ठेके पर कार्य करने के लिए आया-जाया करते थे।

इनमें से अधिकांश संयुक्त राष्ट्र में ही स्थायी रूप से बस गये।

सन् 1860 ई. के पश्चात् प्रति दशक लगभग 1 करोड़ मनुष्य यहाँ अप्रवासन करते रहे। परन्तु यह संख्या सन् 1930 के बाद घटने लगी। इस देश में अप्रवासन करने वालों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि सन् 1880-1930 तक के 50 वर्षों की समयावधि में हुई। सन् 1900 ई. से 1919 तक के लघु कालखण्ड में ही लगभग 90 लाख मनुष्य इस देश में बाहर से आकर बस गये।

इस देश में औद्योगिक विकास सन् 1920 ई. के बाद अधिक तीव्रगति से हुआ। उस समय ग्राम्य नगरीय प्रव्रजन भारी संख्या में प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप 1920-30 के मध्य लगभग 80 लाख जनसंख्या ग्रामों में नगरों से आकर बस गई, जिनकी आयु की सीमा 25 वर्ष से कम थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में जल-विद्युत आदि शक्ति के विकास के परिणाम स्वरूप उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो रहा है, परिवहन के साधनों का फैलाव बढ़ रहा है। फलस्वरूप अब ग्रामीण क्षेत्र में भी उद्योगों का प्रसार हो रहा है। अतएव अब औद्योगिक केन्द्रों के लिए दैनिक प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस प्रवृत्ति में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि 1950-1970 के मध्य पायी गई है।

3. एशियाई प्रव्रजन - इस महाद्वीप से प्रागैतिहासिक कालों में जनसंख्या का प्रव्रजन भारी संख्या में अनेक बार हुआ। इस काल में प्रव्रजन प्रमुखतः मध्य एशिया से हुए हैं। ऐतिहासिक काल में (13वीं शताब्दी में) चंगेज खाँ आदि आक्रमणकारियों ने चीन के पूर्वी भाग की ओर आक्रमण किया, इन आक्रमणकारियों में से अधिकांश लोग चीन में ही बस गये। चीन से प्रवास करने वालों की सर्वाधिक संख्या 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में रही। हजारों की संख्या में चीनी इण्डोनेशिया, मलाया, कम्बोडिया, हिन्दचीन, कोरिया व मंचूरिया की ओर प्रवास कर गये। यहाँ से अधिकांश संख्या में लोग ठेके पर काम करने के लिए दक्षिण

अफ्रीका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका चले गये। सन् 1900 से 1910 के बीच लगभग 2 लाख चीनी मजदूर केवल दक्षिण अफ्रीका को प्रवास किये।

बीसवीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 50 लाख चीनी लोग दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में स्थानान्तरण किये। द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व एशिया महाद्वीप के पूर्वी प्रदेशों में भारी संख्या में स्थानान्तरण हुआ। उत्तरी चीन से लगभग 12 लाख लोग प्रति वर्ष मंचूरिया में जाकर स्थायी रूप से बसे। दक्षिणी चीन के सघन आबादी वाले क्षेत्रों से भी लाखों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष मलाया, वियतनाम, लाओस, सुमात्रा, बोर्नियों में जाकर बसते रहे।

उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम चरण में जापान से भारी संख्या में प्रवास हुआ। यहाँ से हजारों की संख्या में लोग कोरिया प्रवासित हुये। जापान से अधिक संख्या में लोग हवाई द्वीप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा में जाकर बस गये। सन् 1909 के आस-पास यहाँ की जनसंख्या का प्रवास ब्राजील, आस्ट्रेलिया, कोरिया, मंचूरिया में हुआ जिनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक थी। उत्तरी मंचूरिया की असहनीय अति ठण्डी जलवायु के कारण वहाँ से लोग जापान की ओर प्रवास किये। सन् 1915 के पश्चात् जापान में तीव्रतर औद्योगिक विकास के कारण यहाँ जनसंख्या में नगरीकरण की प्रबृत्ति अधिक बढ़ी। यहाँ की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत विगत् 50 वर्षों में 30 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत के लगभग हो गया। यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन अधिक रहा।

4. भारतीय प्रब्रजन - भारतवर्ष की उर्वरशील नदी घाटियों के कृषि क्षेत्रों ने बाहरी मानव वर्गों को समय-समय पर आकर्षित किया है। मध्य एशिया जलवायु के शुष्क होने के कारण शक, हूण आदि मानव वर्गों के अनेक आक्रमण उत्तरी भारत में हुए। विदेशी आक्रमणकारियों का मुख्य मार्ग प्रायः हिमालय के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित खैबर दर्रा रहा है। यूनान के एलेक्जेण्डर और मध्य पूर्वी देशों से तथा मध्य एशिया से महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, चंगेज खाँ, बाबर, नादिरशाह आदि के आक्रमण हुये थे। उनके साथ आये हुए सैनिकों में से अधिकाँश यहीं भारत में ही बस गये।

ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व मुख्यतः सम्राट अशोक के राज्यकाल में बहुत से भारतीय धर्म प्रचार के लिए मध्य एशिया, मंगोलिया, ईरान, म्यांमार चले गये थे। तत्पश्चात् ईसा के पश्चात् प्रारम्भिक शताब्दियों में हजारों भारतीय, श्रीलंका, म्यांमार, मलाया, कम्बोडिया, हिन्दचीन, सुमात्रा, जावा व बाली द्वीप को प्रवास किये। इस्लामी देशों से धर्म-प्रचारक लोग 12 वीं शताब्दी से 15 वीं शताब्दी तक आते रहे।

भारत में यूरोपीय लोगों का अप्रवासन समुद्री मार्ग से संभव हो पाया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज एवं 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व फ्रांसीसी व्यापारी यहाँ आये और इन देशों के लोगों ने अपनी-अपनी व्यापारिक कम्पनियाँ स्थापित कीं। समय-समय पर इन कम्पनियों के लोगों में संघर्ष भी हुआ। बाद में ब्रिटेन सरकार की सहायता से भारत की देशी रियासतों के आपसी फूट का लाभ उठाकर अंग्रेज व्यापारियों ने अपने कार्य का विस्तार किया। धीरे-धीरे भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित हो गया। 19वीं शताब्दी में अधिकांश अंग्रेज भारत आये, जिनमें मुख्य रूप से शासन के प्रबन्धक व सैनिक थे। तत्पश्चात् वहाँ से अनेक बड़े व्यापारियों का आगमन हुआ, जिन्होने भारत के चाय बागानों, जूट फार्मों,

उत्खनन एवं प्रमुख उद्योगों पर अपना विशेषाधिकार स्थापित कर लिया। ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भी अधिकांश लोगों का अप्रवासन होता रहा।

उन्नीसवीं शताब्दी (विशेषकर 1830 से 1900 तक) में अंग्रेजों ने लाखों भारतीयों को कुली बनाकर अपने अन्य उपनिवेशों जैसे - मारीशस, गुयाना, ट्रिनीडाड, नेटाल, कीनिया, फिजी, ब्राजील आदि देशों की ओर प्रवासित किया, जहाँ कृषि फार्मों पर उनसे मजदूरों का कार्य लिया जाता था। इतना ही नहीं, 20 वीं शताब्दी में प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भारी संख्या में भारतीयों को सैनिक बनाकर अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा अथवा अंग्रेजों के मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए युद्ध करने विदेशों में भेजा गया, जहाँ अधिकांश लोग मौत के घाट उतार दिये गये।

सन् 1940 ई. में भारत से लगभग 20 लाख जनसंख्या का प्रवास श्रीलंका को हुआ। यह जनसंख्या वहाँ की आबादी की 1/3 हो गई है। वहाँ रहने वाले भारतीयों में 1/3 से अधिक लोग बागान मजदूर के रूप में कार्य करते रहे। भारत से लगभग 10 लाख लोग म्यांमार गये, जिनकी संख्या का प्रतिशत वहाँ की जनसंख्या का 6 प्रतिशत रहा। मलाया में 8 लाख भारतीयों का प्रवास हुआ, जहाँ प्रत्येक सातवाँ व्यक्ति भारत का है। ब्रिटिश गुयाना, ट्रिनीडाड की लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या भारतीय हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त विश्व में प्रब्रजन का स्वरूप अपने-अपने देशों की ओर वापसी का रहा है।

सन् 1947 में भारतवर्ष के विभाजन के तत्काल बाद भारी संख्या में जनसंख्या का प्रब्रजन प्रारम्भ हुआ। पाकिस्तान से लगभग 1 करोड़ हिन्दू भारत आये तथा यहाँ से 4 लाख मुसलमान पाकिस्तान गये। भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा पर जनसंख्या का यह आना-जाना तो समयबद्ध ढंग से था। परन्तु देश के पूर्वी उत्तर-पूर्वी भाग में यह आवागमन निरन्तर चलता रहा। पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से अधिकाँश बंगाली मुसलमान अनधिकृत घुसपैठ करके भारत के सीमावर्ती प्रान्तों व असम में आ बसे। इन्हीं को लेकर आज देश के समक्ष असम समस्या खड़ी है। 1951 की जनगणना के अनुसार 9 प्रमुख प्रान्तों में विदेशों से आये शरणार्थियों को बसाया गया, जिसका विवरण सारणी 11.1 में दिया गया है।

सारणी - 11.1

राज्य	शरणार्थी जनसंख्या (हजार में)	राज्य की जनसंख्या (प्रतिशत)
पंजाब	3232	34.40
पश्चिम बंगाल	2090	9.24
असम	274	3.13
बम्बई (महाराष्ट्र - गुजरात)	338	0.95
उत्तर प्रदेश	480	0.77
मध्य प्रदेश	113	0.53

Source: India Spotlight on Population

इसी क्रम में अन्तर प्रदेशीय प्रब्रजन आर्थिक व राजनीतिक कारणों से हुआ है।

आर्थिक कारणों से कृषि भूमि का आकर्षण एवं उद्योगों में मजदूरों की माँग मुख्य कारण था। असम में चाय बागानों के लिए बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल व पूर्वी उत्तर प्रदेश से हजारों श्रमिक काम करने के लिए गये थे। इनमें से अधिकाँश असम में ही खेती करने के लिए बस गये।

बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की लाखों जनसंख्या पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा व हुगली घाटी में स्थित औद्योगिक केन्द्रों की ओर प्रवासित हुई। राजस्थान से हजारों लोग (मुख्यतः मारवाड़ी) उद्योग व व्यापार में प्रबन्धक अथवा पूँजीपति के रूप में पश्चिम बंगाल में जाकर बस गये हैं। मुम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर आदि केन्द्रों में श्रमिक, व्यापारी, उद्योगपति की हैसियत से लाखों व्यक्ति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब व राजस्थान आदि राज्यों में आकर बस गये। प्रायः देश के हर भाग में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों व कस्बों की ओर जनसंख्या उन्मुख दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए मुम्बई नगर की जनसंख्या को लिया जा सकता है। 1872 से 1941 के मध्य यहाँ की जनसंख्या की 3/4 जनसंख्या बाहर से आने वाली जनसंख्या रही है।

भारतीय जनगणना के आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि भारत में केवल असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल ही ऐसे प्रान्त हैं, जिनमें आने वालों की संख्या जाने वालों की संख्या से अधिक रही। इन्हीं प्रान्तों में चाय बागान, औद्योगिक केन्द्रों की ओर देश के विभिन्न क्षेत्रों से अधिसंख्य लोग स्थानान्तरण किये है। अन्य प्रान्तों में जाने वालों की संख्या की ही अधिकता रही। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक धनात्मक शुद्ध प्रवास बिहार +2.57 प्रतिशत का है, जबकि ऋणात्मक शुद्ध प्रवास वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल -4.71 प्रतिशत असम -31.5 प्रतिशत महाराष्ट्र -1.3 प्रतिशत मुख्य हैं।

11.5 अभ्यास प्रश्न(Practice Questions)

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:

1. प्रवासन का आकर्षण कारक
2. प्रवासन का प्रत्याकर्षण कारक
3. आकर्षण-प्रत्याकर्षण सिद्धान्त
4. प्रवासन का चयनात्मक पक्ष
5. प्रागैतिहासिक प्रवजन
6. ऐतिहासिक प्रवजन
7. यूरोपीय प्रवजन
8. भारतीय प्रवजन

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. आंतरिक प्रवासन किसे कहते हैं?

A. एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का पलायन

B. एक देश से दूसरे देश में लोगों का पलायन

C. एक ही देश में और एक देश से दूसरे देश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन

D. उपरोक्त सभी

2. निम्नलिखित में से किसे आंतरिक प्रवास कहा जाता है?

A. वैवाहिक प्रवास B. अंतर प्रांतीय प्रवास

C. ग्रामीण-शहरी प्रवास D. उपरोक्त सभी

3. "A Theory of Migration in Population Geography" नामक पुस्तक किसने लिखी हैं?

A. ज़िलिंस्की B. प्रो. ई ली

C. रेवेनस्टीन D. उपरोक्त में से कोई नहीं

4. प्रो ली. के अनुसार, प्रवासन कितने कारकों का परिणाम है?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

11.6 सारांश (Summary)

इस इकाई में सर्वप्रथम प्रवासन की व्याख्या के साथ आन्तरिक प्रवासन को स्पष्ट किया गया है। तत्पश्चात् आन्तरिक प्रवासन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए आन्तरिक प्रवासन के विभिन्न शीर्षकों - वैवाहिक देशान्तरण, अन्तर्प्रान्तीय देशान्तरण, गाँव-शहर देशान्तरण, सम्बन्धताजन्य देशान्तरण को स्पष्ट कर प्रवासन के दो मुख्य सिद्धान्तों (i) प्रो. ली के 'आकर्षण-प्रतिकर्षण सिद्धान्त' तथा (ii) प्रो. ग्रिफिथ टेलर के 'प्रवास कटिबन्ध सिद्धान्त' का विस्तृत वर्णन किया गया है।

प्रवासन के आकर्षण-प्रत्याकर्षण सिद्धान्त के अन्तर्गत आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण के विभिन्न कारकों को स्पष्ट किया गया है। उन्नत जीवन की अभिलाषा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन, सगे सम्बन्धियों अन्य का आकर्षण व्यक्ति को जहाँ प्रवासन के लिये आकर्षित करता है वहीं अभावों को पूरा करने की इच्छा व्यक्ति को प्रवासन हेतु बाध्य करती है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं अन्य का अभाव सामाजिक तिरष्कार, असामाजिक तत्वों का आतंक, राजनैतिक, जातीय तथा धार्मिक आधार पर भेदभाव व्यक्ति को अपने पुराने अधिवास के प्रति विकर्षण पैदा करता है। साथ ही इसे प्रब्रजन की दूरी, नगरी भिन्नतायें, तकनीकी ज्ञान अन्य भी प्रभावित करते हैं। इस हेतु 'प्रो. ली के प्रब्रजन सिद्धान्त' को उद्भव तथा गन्तव्य स्थल को माडल चित्र द्वारा समझाया गया है।

प्रब्रजन का एक सिद्धान्त प्रो. ग्रिफिथ टेलर ने भी अपने प्रवास कटिबन्ध सिद्धान्त के द्वारा दिया है। इसके अन्तर्गत प्रागैतिक प्रवजन तथा ऐतिहासिक प्रवजन का माडल दिया गया है। दोनों माडलों का मूल आधार जीवन की मूल आवश्यकता की पूर्ति एक मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति एवं महती इच्छा को संतुष्ट करना रहा है। इस हेतु यूरोपीय प्रवजन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी प्रवजन तथा भारतीय प्रवजन के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

इस तरह प्रवासन के विभिन्न पक्षों को आकर्षण-प्रतिकर्षण माडल तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष में समझने के लिए प्रयास किया गया है।

11.7 शब्दावली (Glossary)

- आन्तरिक प्रवासन या आन्तरिक देशान्तरण (राष्ट्रीय सीमा के अन्दर) – In Migration
- वहिर्गमन Out Migration (राष्ट्रीय सीमा के बाहर प्रवासन)
- वैवाहिक देशान्तरण Marital Migration
- अन्तर्प्रान्तीय देशान्तरण Inter Provincial Migration
- गाँव-शहर देशान्तरण Rural Urban Migration
- सम्बद्धता देशान्तरण Associated Migration
- आकर्षण सिद्धान्त Pull Theory
- विकर्षण सिद्धान्त Push Theory
- प्रवास कटिबन्ध सिद्धान्त Migration Zone Theory

11.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers forPractice Questions

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. A 2. D 3. B 4.D

11.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- डॉ. मिश्रा, जे. पी., जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा।
- डॉ. बघेल, डी. एस., जनांकिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
- डॉ. पन्त, जीवन चन्द्र, जनांकिकी, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
- अशोक कुमार, जनसंख्या, एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रयाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय*, भारत सरकार
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग*, भारत सरकार
- *भारतः 2013*, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

11.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- A.M. Carr Saunders : World Population, 1936, P.42
- Walter F. Willcox : Studies in American Demography, 1940 P. 40
- M.K. Bonnett: the world, 1954 3

- Ross, John, A (1982): International Encyclopedia of Population The Free Press. Macmillon Publishing co.New York.
- U.N. Determinantes and Consequences of Population Trends, 1953, P. 61
- UNFPA, The State of World Population, 1996
- United Nations Population Division , Word Population 2006.
- World Bank Atlas 1996
- Estimated from United Nations, 1986
- U.N. Demographic Year Book, 1950
- Selected World Demographic Inedicators by Region and Country or Area. 1970-75, Prepared by United Nations Population Division

11.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. आन्तरिक प्रवासन के सिद्धान्तों पर एक निबन्ध लिखो।
2. आन्तरिक प्रवासन के प्रो. ली के आकर्षण - प्रत्याकर्षण सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये।
3. प्रो. ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबन्ध सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

इकाई 12 - नगरीकरण: विकसित और विकासशील देशों में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की वृद्धि एवं वितरण

(Urbanization: Growth and Distribution of Rural and Urban Population in Developed and Developing Countries)

12.1 प्रस्तावना

12.2 उद्देश्य

12.3 नगरीकरण

- **12.3.1 नगरों की विकास की अवस्थाएँ**
- **12.3.2 नगरीय जीवन की विशेषताएँ**
- **12.3.3 भारत में नगरीकरण**

12.4 विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या, प्रक्षेपित जनसंख्या, औसत वृद्धि दर, प्रजनन दर एवं जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत

- **12.4.1 संयुक्त राज्य अमेरिका की जनांकिकीय संरचना**
- **12.4.2 चीन की जनांकिकीय संरचना**
- **12.4.3 पूर्व सोवियत रूस की जनांकिकीय संरचना**
- **12.4.4 ग्रेट ब्रिटेन की जनांकिकीय संरचना**
- **12.4.5 जापान की जनांकिकीय संरचना**

12.5 अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

12.6 सारांश (Summary)

12.7 शब्दावली (Glossary)

12.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers forPractice Questions)

12.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

12.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

12.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

12.1 प्रस्तावना (Introduction)

इस इकाई में विकसित एवं विकासशील देशों में ग्रामीण एवं नगरी जनसंख्या की वृद्धि तथा वितरण देखेंगे। इस हेतु नगरीकरण की संक्षिप्त व्याख्या के साथ नगरीय जीवन की विभिन्न विशेषताओं को जानने के साथ विश्व के कुछ विकसित एवं विकासशील देशों अमेरिका, चीन, पूर्व सोवियत रूस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान एवं भारत का अध्ययन करेंगे।

इस इकाई के अन्तर्गत उपरोक्त देशों में जनसंख्या वृद्धि , प्रक्षेपित जनसंख्या, औसतन वृद्धि दर, प्रजनन दर, जनसंख्या की नगरीय प्रवृत्ति तथा ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण जनसंख्या तथा प्रवासी जनसंख्या से नगरीकरण का प्रारूप कैसे बदलता है; महानगरों में बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते महानगरों की संख्या किस गति से बढ़ रही है; अन्य का अध्ययन करेंगे।

12.2 उद्देश्य (Objectives)

- ✓ नगरीकरण के अर्थ को समझना।
- ✓ नगरों के विकास की अवस्थाये तथा नगरीय अधिवासों के प्रकार को समझना।
- ✓ विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या, प्रक्षेपित जनसंख्या, औसत वृद्धि दर, प्रजनन दर एवं जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत जानना।
- ✓ अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, जापान तथा भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के साथ ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर को जानना तथा प्रवासन के महत्व को समझना।

12.3 नगरीकरण (Urbanization)

'नगरीकरण' शब्द का निर्माण नगर से हुआ है। नगरीकरण उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। जिसके माध्यम से नगरों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त नगरीकरण का अर्थ लोगों के द्वारा नगरीय सभ्यता को स्वीकार करना भी होता है। लगभग सभी देशों में गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या का देशान्तरण निरन्तर होता रहता है। सामान्यतः देशान्तरण छोटी प्रशासनिक इकाई से बड़ी प्रशासनिक इकाई की ओर होता है जैसे गांवों से कस्बों; कस्बों से तहसील मुख्यालय; तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय; जिला मुख्यालय से महानगरों की ओर होता है। देशान्तरण विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों से होता हुआ महानगरों में हो सकता है अथवा एक ही बार में गाँवों से महानगरों में हो सकता है। देशान्तरण वास्तव में कहाँ होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि देशान्तरण होने के साथ की दूरी कितनी है? यदि गाँव से महानगर की दूरी कम है तो सीधे गाँव से महानगरों में देशान्तरण हो जायेगा।

देशान्तरण की प्रवृत्ति सामान्यतः एकतरफा होती है। गाँवों से शहरों की ओर का प्रवास अधिकांशतः होता है, किन्तु शहरों से गाँवों की ओर प्रवास की घटनाएँ बहुत ही कम होती हैं।

विद्वानों ने नगरीकरण को भिन्न-भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। प्रमुख परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

प्रसिद्ध नगरीय समाजशास्त्री बर्गेल के अनुसार, ''ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हमें नगरीकरण कहना चाहिए। इस प्रक्रिया का गाँव की जनसंख्या की आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है।''

थॉम्पसन व लुइस (Thompson and Lewis) के शब्दों में, ***"नगरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अन्तर्गत किसी देश की जनसंख्या बढ़ती दर से शहरों में आकर बसने लगती है। 'नगरत्व' एक ऐसी जीवनयापन विधि है जो नगरों में अपनाई जाती है।"***

नगरीकरण को परिभाषित करते हुए एक अन्य स्थल पर **थॉम्पसन व लुइस (Thompson and Lewis)** ने लिखा है कि ***''नगरीकरण सम्बन्धित समुदायों से लोगों का गतिशील होना है जो मुख्यतः कृषि से अन्य समुदायों में होता है, जो सामान्यतः बड़े होते हैं, जिनकी गतिविधियाँ मुख्यतः सरकार, व्यापार, उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रों में केन्द्रित हैं।(Urbanisation is the movement of people from communities concerned chiefly with agriculture to other communities, generally larger, whose activities are primarily centered in government, trade, manufacture or allied interest.)''***

नगर की सर्वोत्तम परिभाषा प्रस्तुत करने का श्रेय इटली के भूगोलवेत्ता **विडाल डी ला ब्लाश (Vidal de la Blache)** को है। इनके शब्दों में, ***"नगर, एक सामाजिक संगठन है जिसका क्षेत्र अधिक विस्तृत है, यह सभ्यता के एक स्तर को प्रदर्शित करता है जिसको कुछ क्षेत्र प्राप्त नहीं कर पाए हैं तथा सम्भवतः वे उसे कभी भी नहीं प्राप्त कर पायेंगे। (A city is a social organisation of much greater scope, it is the expression of a stage of civilization which certain localities have not achieved and which they may perhaps never themselves attain.)"***

इस प्रकार **ब्लाश** का मत है कि नगर किसी भी देश के निवास का केन्द्र बिन्दु होता है। गाँव की ओर सभ्यता का प्रसारण नगरों से ही होता है। वास्तव में साहित्य, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, फैशन आदि का विकास नगरों में ही होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी नगरीय संस्कृति का अनुकरण करते हैं। किन्तु इस सांस्कृतिक अनुकरण में समयान्तराल होता है, अर्थात् जब तक ग्रामीण क्षेत्र नगरीय संस्कृति अथवा परिवर्तनों को आत्मसात कर पाते हैं। तब तक नगरीय संस्कृति में पुनः परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन तथा विकास एवं अनुकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व के नगरों की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि का एक तिहाई से भी अधिक भाग ग्रामीण-नगरीय स्थानान्तरण का परिणाम है। यह स्थानान्तरण मुख्य रूप से राजधानी नगरों एवं महानगरों की ओर होता है। जहाँ तक विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्ति का प्रश्न है तो यह समान नहीं है। विश्व में सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र क्रमशः ओशेनिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका हैं। विश्व की 50 (2008) प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है। मोनाको, नौरू, सिंगापुर हांग-कांग तथा वेटिकन सिटी की शत-प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है। विश्व में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत (90) बरूण्डी, पापुआ, न्यू गिनी, उगांडा, श्रीलंका, नाइजर, नेपाल तथा मलावी में है। विश्व के सभी विकसित देशों में नगरीकृत जनसंख्या का भाग 75 प्रतिशत से अधिक है जबकि विकासशील देशों में 50 प्रतिशत से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है।

भारत की नगरीय जनसंख्या 2001 में चीन को छोड़कर विश्व के समस्त देशों की कुल नगरीय जनसंख्या से अधिक थी।

सारणी-12.1

सार्क देशों में जनसंख्या स्थिति-2001

देश	नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में	साक्षरता प्रतिशत में
पाकिस्तान	35.0	37.8
बांग्लादेश	19.0	38.2
श्रीलंका	23.0	90.2
नेपाल	12.0	27.5
भूटान	06.0	42.2
मालद्वीव	27.0	93.2
भारत	29.0	74.04
	(2008)	(2011)

सारणी 12.2

विश्व के 10 सबसे बड़ी महानगरीय जनसंख्या (2008)

महानरीय क्षेत्र का नाम	अनुमानित जनसंख्या
1. टोकियो-याकोहामा	34400000
2. जाकार्ता	21800000
3. न्यूयार्क सिटी	20090000
4. सियोल-चीन	20010000
5. मनीला	19550000
6. मुम्बई	19530000
7. साओपोलो (ब्राजील)	19140000
8. मैक्सिको सिटी	18430000
9. दिल्ली	18000000
10. ओसाका-कोबे-क्योटो (जापान)	17470000

नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन मूलतः जनसंख्या आकार, संरचना और कार्यिक क्षेत्र में होता है। भारतीय जनगणना विभाग ने नगरीय बस्ती की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है:

(i) जनसंख्या 5000 या इससे अधिक हो।

(ii) जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से कम न हो।

(iii) कार्यिक जनसंख्या का 75 प्रतिशत पुरूष वर्ग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो।

(iv) नगरपालिका, टाउन एरिया या छावनी बोर्ड आदि में शामिल हो।

आधुनिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया में विकास का मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास रहा है। 20वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में विकसित देशों में नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र थी, परन्तु इसके उत्तरार्द्ध

में जनसंख्या विस्फोट एवं ग्रामीण-नगरीय स्थानान्तरण के कारण विकासशील देशों में यह प्रक्रिया तीव्र हो गई है। यह स्थानान्तरण मुख्य रूप से राजधानी नगरों एवं महानगरों की ओर होता है। इसे ही Secular Shift of Population कहा गया है। जहाँ विकसित देश नगरीय संतृप्तता को प्राप्त कर रहे हैं, वहीं विकासशील देशों में अभी भी नगरीकरण का स्तर अल्प है। अतः आगामी वर्षों में वहाँ नगरीकरण की प्रक्रिया और भी तीव्र होने की संभावना है।

12.3.1 नगरों की विकास की अवस्थाएँ (Stages of Evolution of Cities)

लुइस मम्फोर्ड ने 1938 ई. में नगरों के विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है:

1. **इयोपोलिस**-यह नगरीय विकास की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में कृषि एवं पशुपालन संबंधी कार्यों के विकास के कारण गाँवों का विकास हुआ। बड़े-बड़े एवं केन्द्रीय गाँवों में शिक्षा, संस्कृति एवं कला आदि का विकास हुआ।
2. **पोलिस**-इस शब्द का अर्थ नगर से है। इस अवस्था में बड़े गाँव कस्बे का रूप धारण करते हैं जिनमें व्यापारिक गतिविधियों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में गाँवों का नगरीय आकार में विकास प्रारम्भ हो जाता है।
3. **मेट्रोपोलिस**-इस अवस्था में नगर का आकार बृहद् हो जाता है। बृहद् स्तर पर कारखानों, शिक्षा संस्थानों, व्यापारिक संस्थानों आदि की स्थापना हो जाती है। इस अवस्था में नगर अपने आस-पास के नगरों से बड़ा हो जाता है एवं नगर का संबंध दूरवर्ती क्षेत्रों से भी हो जाता है।
4. **मेगालोपोलिस**-यह नगर की चरम अवस्था को बताती है। नगर में गन्दी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है एवं जीवन नारकीय रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। पूँजीवादी व्यवस्था का प्रसार, नैतिकता का पतन, नौकरशाही का विकास, मानव का शोषणयुक्त जीवन इस प्रकार के नगरों की विशेषता है। अमेरिका के पूर्वी तटीय मैदान में बोस्टन से स्पेरो प्वाइंट तक के नगरीय क्षेत्र इसका उदाहरण है। बर्मिघम, टोकियो, याकोहामा क्षेत्र, अर्मेस्टर्डम-रोटरडम क्षेत्र भी इस अवस्था में पहुँच गये हैं।
5. **टायरेनोपोलिस**-यह नगर विकास की पाँचवीं अवस्था है जिसमें मानव जीवन के आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य (perspective) में सर्वत्र पराश्रयता (dependency) का विकास हो जाता है। नगर की समस्याएं काफी अधिक बढ़ जाती हैं नगरों में खुले स्थान का अभाव, मकानों की कमी, सड़कों पर अनियंत्रित भीड़-भाड़ जैसी समस्याएं चरम अवस्था पर पहुँच जाती हैं। इस अवस्था में नगर के पार्श्व का पतन प्रारम्भ हो जाता है।
6. **नेक्रो पोलिस**-इस अवस्था में नगर का पतन प्रारम्भ हो जाता है। यह पतन किसी न किसी ऐसे कारण से होता है जो मानव की शक्ति से परे होता है। दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध आदि के फलस्वरूप नगर कब्रिस्तान के समान लगने लगता है। इस प्रकार इस अवस्था में नगर अपनी मृत्यु के करीब पहुँचता नजर आता है।

➢ ग्रिफिथ टेलर ने नगर के विकास की 7 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है:

i. पूर्व शैशवावस्था (Subinfantile Stage)
ii. शैशवावस्था (Infantile Stage)
iii. बाल्यावस्था (Juvenile Stage)
iv. किशोरावस्था (Adolescent Stage)
v. प्रौढ़ावस्था (Mature Stage)
vi. उत्तर प्रौढ़ावस्था (Late Mature State)
vii. वृद्धावस्था (Old Stage)

➢ नगरीय अधिवासों के प्रकार:

सामान्यतः नगरीय अधिवास निम्नलिखित रूप से विभाजित किये जा सकते हैं। जैसे की - अनुमार्ग बस्ती, नगरीय पुरवा, नगरीय गाँव, कस्बा, नगर, महानगर, सन्नगर एवं मैगालोपोलिस। इनको निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- ❖ कस्बा जनसंख्या 500 से 1000 या इससे अधिक हो।
- ❖ नगर-1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर। भारत की आधे से अधिक नगरीय जनसंख्या इसी प्रकार के नगरों में रहती है।
- ❖ महानगर (Metropolitan or Metropolis) की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है।
- ❖ मेगालो-पोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जीनगाटमैंन ने किया। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगालो-पोलिश कहा जाता है।
- ❖ सन्ननगर में दो अलग-अलग नगर एक-एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे- हैदराबाद- सिकन्दराबाद, टोकियो-याकोहामा।
- ❖ अमलैण्ड (Umland) - नगर अपने आस-पास कुछ क्षेत्रों की सेवा करता है और बदले में उस क्षेत्र की सेवायें प्राप्त करता है। जितने ग्रामीण क्षेत्र का नगर से सम्बन्ध होता है, उतने क्षेत्र को नगर का अमलैण्ड कहते हैं। ज्ञातव्य है कि **अमलैण्ड** शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम **आन्द्रे एलिक्स (1914)** द्वारा किया गया था।
- ❖ भारतीय जनगणना विभाग द्वारा भारतीय नगरों की जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है:

नगर वर्ग		जनसंख्या
I	प्रथम वर्ग	1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
II	द्वितीय वर्ग	50000 से 99000 तक की जनसंख्या
III	तृतीय वर्ग	20000 से 49000 तक
IV	चतुर्थ वर्ग	10000 से 19999 तक
V	पंचम वर्ग	5000 से 9999 तक
VI	षष्टम वर्ग	5000 से कम

- ❖ भारत में V एवं VI वर्ग के नगरों की निरन्तर गिरावट की स्थिति है।
- ❖ भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक भाग, प्रथम श्रेणी के नगरों में रहता है।
- ❖ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ग के नगरों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।

➢ **प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों का विभाजन:**

1. औद्योगिक नगर - जैसे जमशेदपुर (टाटानगर), कानपुर, नोएडा, दुर्गापुर आदि।
2. धार्मिक नगर - जैसे वाराणसी, मथुरा
3. प्रशासनिक नगर - जैसे राज्यों की राजधानियाँ
4. गैरिसन नगर - जहाँ सेना रहती हैं जैसे-इंदौर के पास के महानगर
5. नगर माल - ऐसे नगर जो काफी पास-पास होते हैं और उनकी स्थिति जुड़वे की तरह होती है, जैसे हैदराबाद-सिकन्दराबाद।

12.3.2 नगरीय जीवन की विशेषताएँ (Characteristics of Urban Life)

नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताओं को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है-

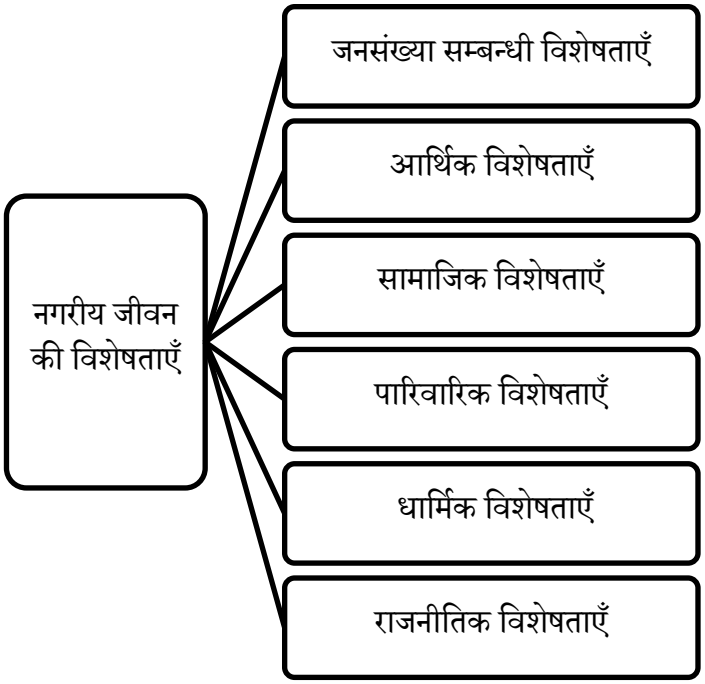

(1) जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ –

नगरीय जनसँख्या की प्रमुख विशेषताएँ अग्रलिखित होती है:

(अ) जनसंख्या की अधिकता के कारण भीड़भाड़ की समस्या रहती है।

(आ) जनसंख्या में विविधता पाई जाती है।

(इ) नगरीय जनसंख्या विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई होती है।

(ई) नगरीय जनसंख्या में सभी पहलुओं के समुचित विकास का प्रयास किया जाता है।

(उ) नगरीय जनसंख्या में गतिशीलता की मात्रा अधिक पाई जाती है और

(ऊ)नगरीय जनसंख्या को भूमि का अभाव रहता है।

(2) आर्थिक विशेषताएँ –

नगरीय जीवन की प्रमुख आर्थिक विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं:

(अ) व्यवसाय नगरीय आर्थिक जीवन के आधार पर होते हैं तथा विविध प्रकार के व्यवसाय पाये जाते हैं।

(आ) नगरीय व्यवसाय वंशानुगत न होकर योग्यता और कार्यों पर आधारित होते हैं।

(इ) नगरीय आर्थिक जीवन अत्यन्त ही जटिल और कसमकसपूर्ण होते हैं और

(ई) नगरीय व्यवसायों की प्रकृति जटिल तथा प्रतिस्पर्धापूर्ण होती है।

(3) सामाजिक विशेषताएँ –

नगरीय सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(अ) नगरों में सामुदायिक जीवन का अभाव पाया जाता है।

(आ) नगरीय सामाजिक जीवन विशिष्टता लिये हुए होता है।

(इ) नगरों में पड़ोस का कोई विशेष महत्व नहीं होता है।

(ई) नगरीय व्यक्ति विभिन्न मतों और विचारधाराओं के होते हैं, इसलिए सदस्यों में घनिष्टता का अभाव पाया जाता है।

(उ) नगरों में सामाजिक नियन्त्रण के औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे-कानून, पुलिस और न्यायालय आदि।

(ऊ) नगरीय जीवन में व्यक्तियों के सम्बन्ध अवैयक्तिक, व्यक्तिवाद से पूर्ण असहिष्णु और प्रतिस्पर्धापूर्ण होते हैं।

(ए) नगरों में रहने वाले व्यक्ति कर्मठ, आशावादी, कृत्रिम और प्रगतिशील विचारधाराओं वाले होते हैं।

(4) पारिवारिक विशेषताएँ –

नगरीय परिवार की विशेषताओं को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है:

(अ) नगरों में व्यक्तिगत परिवारों की अधिकता होती है।

(आ)नगरीय परिवारों में आत्मनिर्भरता पायी जाती है।

(इ) नगरीय विवाह पवित्र बन्धन की अपेक्षा स्त्री-पुरूष का एक समझौता मात्र होता है।

(ई) नगरीय परिवारों में स्त्री-पुरूष की स्थिति में समानता रहती है।

(उ) नगरीय परिवारों में शक्ति का अभाव पाया जाता है, इसलिए विघटन की प्रक्रिया तीव्र रहती है।

(5) धार्मिक विशेषताएँ:

नगरीय जीवन की धार्मिक विशेषताओं को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है:

(अ) नगरों में धर्म को कम महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही नगरों में धर्म के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की विचारधाराएँ होती हैं।

(आ) नगरों में धार्मिक कर्मकाण्ड का अभाव पाया जाता है।

(इ) नगरीय जीवन की संस्कृति अत्यन्त ही गतिशील होती है।

(ई) नगरीय संस्कृति भौतिकवादी, स्वार्थपूर्ण और परम्पराओं से परे होती है।

(6) राजनीतिक विशेषताएँ:

नगरीय जीवन की राजनैतिक विशेषताओं को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है:

(अ) नगरीय जनसंख्या राजनीति में अधिक रूचि लेती है।

(आ) नगरीय जीवन राजनीतिक विविधाओं में पूर्ण होता है।

(इ) नगरीय व्यक्तियों को शासकीय विधानों का ज्ञान रहता है।

- प्रसिद्ध समाजशास्त्री **किंग्सले डेविस (Kingsley Davis)** ने नगरीय समाज के निम्न लक्षण बतलाए हैं:

(1) सामाजिक विविधता (Social Heterogeniety)

(2) द्वैतीयक समितियाँ (Secondary Association)

(3) द्वैतीयक नियंत्रण (Secondary Control)

(4) ऐच्छिक समितियाँ (Voluntary Association)

(5) व्यक्तिवाद (Individualism)

(6) सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility)

(7) सामाजिक सहिष्णुता (Social Tolerance)

(8) क्षेत्रीय पृथकता (Spatial Segregation)

(9) सामुदायिक भावना का अभाव (Lack of Community Sentiment)

(10) गतिशील जीवन (Mobile Life)

12.3.3 भारत में नगरीकरण

भारत में नगरीकरण की प्रवृति को निम्न सारणी 12.3 द्वारा किया सकते हैं:

सारणी 12.3

भारत में नगरीकण की प्रवृति (1901-2001)

वर्ष	नगरों की संख्या	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	नगरीय जनसंख्या (करोड़ में)	कुल जनसंख्या में नगरीय जनंसख्या का प्रतिशत	दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर (प्रतिशत में)	नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर
1901	1.827	23.83	2.59	10.84	-	-
1911	1.815	25.21	2.59	10.29	0.35	0.03
1921	1.949	25.13	2.81	11.18	8.27	0.79
1931	2.072	27.89	3.35	11.99	19.12	1.75
1941	2.250	31.87	4.42	13.86	31.97	2.77
1951	2.843	36.10	6.24	17.29	41.42	3.47
1961	2.365	43.92	7.89	17.97	26.41	2.34

1971	2.590	54.82	10.91	19.91	38.23	3.21
1981	3.378	68.33	15.95	23.34	46.14	3.83
1991	3.768	84.06	21.82	25.72	36.19	3.09
2001	5.161	102.87	28.60	27.80	31.19	3.13

Source; Census of India 2001, Totals: Rural-Urban Distribution

जनगणना 2001 के अनुसार भारत की 27.8 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। जबकि 1901 में नगरी जनसंख्या का अनुपात मात्र 10.84 प्रतिशत था। 1991 में 25.72 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती थी। वर्ष 1991-2001 के दौरान जनसंख्या में हुई निबल वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में 113 मिलियन और शहरी क्षेत्रों में 68 मिलियन थी। 2001 के समाप्त दशक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि क्रमशः 17.9 और 31.7 प्रतिशत थी। पूर्ववर्ती दशक के दौरान देश की शहरी जनसंख्या में (27.8 प्रतिशत- 25.7 प्रतिशत)-2.1 प्रतिशत की निबल वृद्धि देखी गयी। उपर्युक्त आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि:

1. भारत के नगरीकरण में सर्वाधिक दशकीय वृद्वि दर (46.18 प्रतिशत) तथा अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर (3.83 प्रतिशत) 1971-81 के दशक में हुई।
2. 1941- 51 के नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का कारण देश विभाजन था। अधिकांश शरणार्थियों ने शहरों एवं कस्बों में आश्रय लिया था।
3. वर्ष 1991- 2001 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 3.13 तथा दशकीय वृद्वि 31.72 प्रतिशत थी।
4. भारत में 28.61 करोड़ जनसंख्या नगरों में रहती है, जबकि यू.एस.ए. की कुल जनसंख्या 28.41 करोड़ है।
5. 1901 में भारत में नगरों की संख्या 1827 थी, जो 2001 में 5161 हो गयी।

निम्नलिखित आँकड़ों से (सारणी 12.4) स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में नगरीकरण की गति बहुत मन्द थी। 1951-61 के दशक में नगरीकरण में कुछ तेजी आई लेकिन 1961-71 के दशक में भारत-चीन एवं भारत-पाकिस्तान के युद्व तथा 1966-67 में सूखे की स्थिति के कारण पुनः उसकी गति मन्द हो गई। 1971-91 के बीच नगरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई तथा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 19.91 से बढ़कर 25.72 हो गया। भारत में बड़े नगरों या एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई। 1901 में एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की कुल जनसंख्या 6.6 मिलियन या 26.0 प्रतिशत थी जो 1991 में बढ़कर 138.8 मिलियन या 65.2. प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत 50,000 से 99.999 की जनसंख्या वाले नगरों की आबादी 1901 से 1991 के बीच लगभग स्थिर रही जो 1901 और 1991 में क्रमशः 11.29 प्रतिशत तथा 10.95 प्रतिशत हो गयी। 20 हजार से कम आबादी वाले नगरों की जनसंख्या में 1901- 1991 के बीच तीव्र गति से हास हुआ। जो 1901 में 20.83 प्रतिशत थी वह 1991 में घटकर 7.7 प्रतिशत रह गई। 1951 के बाद प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। 1951 में प्रथम श्रेणी अर्थात् एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 76 थी जो 1991 में बढ़कर 296 हो गयी।

सारणी 12.4

भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि कस्बों के वर्गीकरण के आधार पर

'जनसंख्या मिलियन' में तथा' कोष्ठक में प्रतिशत जनसंख्या

कस्बों का वर्ग	1901	1951	1961	1971	1981	1991
(1) एक लाख और अधिक	6.661 (26.0)	27.507 (44.6)	39.883 (51.4)	61.226 (57.2)	94.504 (60.4)	138.802 (65.2)
(2) 50,000-99,999	2.892 (11.29)	6.137 (9.96)	8.713 (11.23)	11.680 (10.92)	18.190 (11.63)	23.309 (10.95)
(3) 20,000-0049,999	4.007 (15.64)	9.688 (15.72)	13.139 (16.94)	17.126 (16.01)	22.409 (14.33)	28.079 (13.19)
(4) 10,000-19,999	5.335 (20.83)	8.399 (13.63)	9.902 (12.77)	11.706 (10.94)	14.930 (9.54)	16.531 (7.77)
(5) 5,000-9,999	5.159 (20.14)	7.993 (12.97)	5.329 (6.8)	4.756 (4.45)	5.603 (3.58)	5.532 (2.60)
(6) 5,000 से कम	1.562 (6.10)	1.906 (3.09)	0.597 (0.77)	0.473 (0.44)	0.784 (0.50)	0.614 (0.29)
(7) सभी वर्ग	25.616 (100.00)	61.630 (100.00)	77.562 (100.00)	106.967 (100.00)	156.420 (100.00)	212.867 (100.00)
कुल जनसंख्या में केन्द्रीय जनसंख्या का प्रतिशत	10.84	17.29	17.97	19.91	23.34	25.72

स्त्रोत-भारत, 1998 प्रकाशन विभाग,पृ. 18

'मेगा सिटी' या **'मिलियन सिटी'** के नाम से जाने वाले अर्थात् 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 1991 में 23 थी वह 2001 में 35 पर जा पहुँची है। इनमें कुल नगरीय जनसंख्या का 33 प्रतिशत भाग निवास करता है। 1991 में 23 बड़े नगरों की कुल जनसंख्या 70.7 मिलियन थी, वहीं 2001 में 35 बड़े नगरों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई। 23 बड़े नगरों के नाम हैं -बृहत्तर मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, जयपुर, सूरत, कोचीन, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, इन्दौर, पटना, मदुराई, भोपाल, विशाखापट्नम्, वाराणसी एवं लुधियाना। 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 23 से बढ़कर 35 हो गई है।

सारणी 12.5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले 12 नगरों की जनसंख्या, (2001)

नगर	राज्य	जनसंख्या मिलियन में	नगर	राज्य	जनसंख्या मिलियन में
1. वृहत्तर मुम्बई	महाराष्ट्र	16.3	7. अहमदाबाद	गुजरात	4.5
2. कोलकाता	पश्चिमी बंगाल	13.2	8. पूणे	महाराष्ट्र	3.7
3. दिल्ली	दिल्ली	12.7	9. सूरत	गुजरात	2.8
4. चेन्नई	तमिलनाडु	6.4	10. कानपुर	उत्तर प्रदेश	2.6
5. बंगलौर	कर्नाटक	5.6	11. जयपुर	राजस्थान	2.3
6. हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	5.5	12. लखनऊ	उत्तर प्रदेश	2.2

यदि भारत के नगरीकरण की तुलना पाश्चात्य देशों के साथ की जाय तो भारत की स्थिति काफी पिछड़ी नजर आती है। जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में 74 प्रतिशत, जापान में 76 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में 86 प्रतिशत, यूनाइटेड किंगडम में 92 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है, वहीं भारत में केवल 27.8 प्रतिशत जनसंख्या ही नगरों में रहती है।

सारणी 12.6

राज्य	पूर्व की जनगणना के आधार पर नगरीय जनसंख्या की वृद्धि (प्रतिशत में)							नगरीकरण की मात्रा (प्रतिशत में)			
वर्ष	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1961	1971	1991	2001
आन्ध्र प्रदेश	17.7	1.0	23.2	36.1	47.9	15.7	33.9	117.44	19.31	27.00	27.08
असम	22.9	35.4	30.8	30.5	66.6	122.0	15.5	7.69	8.87	11.00	12.72
बिहार	1.7	8.2	22.0	33.7	38.1	48.7	44.0	8.42	10.00	13.83	10.47
गुजरात	7.1	8.7	14.9	38.4	35.8	20.1	41.0	25.77	28.08	34.50	37.50
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	35.6	-	17.66	24.51	29.00
हिमांचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	35.5	-	6.99	8.68	9.79
जम्मू कश्मीर	69.1	-0.3	18.7	21.6	18.3	28.3	44.7	16.66	18.59	24.00	24.88
केरल	15.4	29.8	34.6	30.5	52.7	39.3	35.7	15.11	16.24	28.00	28.97
मध्य प्रदेश	-10.9	10.9	23.0	32.8	33.2	47.9	46.6	14.29	16.29	23.18	26.67
महाराष्ट्र	1.0	18.7	15.5	27.1	62.4	21.3	40.8	28.22	31.17	38.67	42.40
कर्नाटक	4.6	17.7	21.6	23.0	61.7	18.4	35.2	22.33	24.31	30.90	33.98
उड़ीसा	8.0	2.3	12.7	30.0	44.0	88.1	66.3	6.32	8.41	10.30	14.97
पंजाब	-16.5	7.2	27.1	36.1	27.0	33.2	24.9	20.13	23.13	29.50	33.85
राजस्थान	-4.8	-0.03	17.2	22.4	39.6	10.8	38.5	16.28	17.63	22.90	23.38
तमिलनाडु	15.6	8.9	23.4	22.3	41.7	22.7	38.6	26.69	30.26	34.00	43.86
उत्तर प्रदेश	-9.0	0.6	12.8	26.0	22.9	9.9	30.7	12.85	14.02	20.00	20.78
पश्चिम बंगाल	13.7	7.2	15.0	63.7	32.5	36.0	28.4	24.45	24.75	27.50	28.03
नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	9.95	17.22	17.74
मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	13.19	27.54	27.88
मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	14.55	18.60	19.63
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	10.43	11.90	17.02
भारत	0.35	8.29	19.12	31.95	41.43	26.43	38.21	17.97	19.91	25.72	27.78

12.4 विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या, प्रक्षेपित जनसंख्या, औसत वृद्धि दर, प्रजनन दर एवं जनसंख्या का नगरीय (Population of Different Areas of the world, Projected Population, Average Growth Rate, Fertility Rate and Population Percentage of the Cities)

जनसंख्या प्रक्षेपणों तथा विश्व की यदि वास्तविक जनसंख्या की प्रवृत्तियों पर नजर डाली जाये तो यह स्पष्ट होता है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म व मृत्यु दर भिन्न-भिन्न हैं। जहाँ कुछ लोगों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है वहीं कुछ भागों में कम है। इसका मूल कारण स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि , महामारियों-बीमारियों की रोकथाम तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम में वृद्धि व सफलता तथा असफलता है। किसी देश की जन-वृद्धि की दर का निर्धारण साधारणतः उस देश विशेष की जन्मदर, मृत्युदर व देशान्तरण दर पर निर्भर है। विकसित राष्ट्रों में जन्मदर और मृत्युदर दोनों नीची हैं तथा वहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ जन्मवृद्धि दर नीची है जबकि कम विकसित राष्ट्रों में परिस्थितियाँ इसके विपरीत होती हैं अतः वहाँ जनवृद्धि दर ऊँची रहती है।

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की प्रवृत्तियों को आगे सारणी 12.7 में दर्शाया गया है:

सारणी - 12.7

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ

क्षेत्र	कुल जनसंख्या (मिलियन) 1996	प्रक्षेपित जनसंख्या (मिलियन) 2025	औसत वृद्धि दर: 1995-2000	नगरीय प्रतिशत 1995	प्रजनन दर 2000
विश्व	5804.1	8294.3	1.5	45	2.98
अधिक विकसित क्षेत्र	1170.7	1238.4	0.3	75	1.71
कम विकसित क्षेत्र	4633.4	7055.9	1.8	38	3.29
अविकसित देश	591.8	1162.3	2.7	22	5.27

Source:UNFPA, The state of World Population, 1996

विश्व के कुछ विकसित एवं विकासशील देशों में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्न तालिका 12.7 में दिखाया गया है। जिससे यह पता चलता है कि विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। कुछ चुने हुए विकसित एवं विकासशील देशों में नगरीकरण का प्रतिशत निम्न सारणी 12.8 में दिखाया गया है।

सारणी 12.8

कुछ चुने हुए देशों में नगरीकरण का प्रतिशत

देश	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
अमेरिका	80.5
जापान	65.7
ऑस्ट्रेलिया	88.0
न्यूजीलैण्ड	86.0
चीन	39.5
थाईलैण्ड	32.0
श्रीलंका	15.2
पाकिस्तान	34.5
नेपाल	15.3
भूटान	24.7
बांग्लादेश	18.0
भारत	28.5

Source: Human Development Report, 2006

विश्व के कुछ प्रमुख विकसित एवं विकासशील देशों - संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पूर्व सोवियत रूस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, चीन एवं भारत में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण के क्रम को निम्नानुसार समझा जा सकता है।

12.4.1 संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) दुनिया का सबसे विकसित व शक्तिशाली राष्ट्र है। जनसंख्या के आधार पर चीन तथा भारत के बाद विश्व में तीसरा स्थान अमेरिका का ही है। यदि यहाँ की जनांकिकीय विशेषताओं पर विचार किया जाये तो यह स्पष्ट होगा कि अन्य देशों की भाँति यहाँ भी जनसंख्या बढ़ती रही है पर यह वृद्धि की दर अन्य देशों से भिन्न रही है। ऐसा अनुमान है कि 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर 35 प्रतिशत रही है। 1750 से 1850 के बीच अमेरिका की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वह केवल जन्मदर वृद्धि के कारण ही नहीं वरन् इसका प्रमुख कारण जनसंख्या का भारी मात्रा में अप्रवास रहा है। केवल 1820 से 1950 के मध्य अर्थात् 130 वर्षों में अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या लगभग 4.10 करोड़ रही है।

1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी में विवाह दर में कमी होने से जन्म दर में भी कमी देखी गयी जो 19वीं शदी के चौथे दशक में घटकर 7.2 हो गयी परन्तु पाँचवे दशक में पुनः बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गयी जबकि 1991-2000 की दशक में केवल 9 प्रतिशत रही। निम्न सारणी 12.9 में 1750 से 2025 के बीच जनसंख्या की मात्रा तथा सारणी 12.10 में जनसंख्या वृद्धि को दिखाया गया है। अमेरिका की खोज के साथ वहाँ अप्रवासियों

की संख्या बढ़ने के साथ ही नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रादुर्भाव माना जाता है। इसी क्रम में वहाँ ग्रामीण जनसंख्या का प्रवाह भी नगरों की ओर शुरू हुआ।

सारणी 12.9

संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या, 1750-2025

वर्ष	जनसंख्या (लाखों में)
1750	11
1800	53
1850	232
1900	760
1950	1,520
1960	1,800
1970	2,100
1977	2,280
1991	2,530
1995	2,630
2000 प्रक्षेपित	2,740
2025 प्रक्षेपित	3,190

सारणी-12.10

संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि दर (1991-1981)

दशक-वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	प्रति दशक वृद्धि दर (% में)	वार्षिक वृद्धि दर (% में)
1901-10	9.2	2.10	0.21
1911-20	10.5	14.9	1.49
1921-30	12.3	16.1	1.61
1931-40	...	7.2	0.72
1941-50	15.1	14.5	1.45
1951-60	17.8	18.4	1.84
1961-70	22.8	17.0	1.70
1971-80	24.45	16.0	1.60
1981-90	25.8	100	1.00
1991-2000	28.0	8.5	0.85

Source: UN Demographic Year Book

(अ) संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवास (Immigration in USA)

सन् 1610 ई. से प्रथम विश्वयुद्ध तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासियों का ताँता लगा रहा। यहाँ प्रारम्भ में सस्ती एवं पर्याप्त भूमि की उपलब्धता ने आप्रवासियों को आकर्षित किया। अधिकाँश आप्रवासी यहाँ कृषि-कार्य की दृष्टि से आये। सन् 1820 ई. तक तो यहाँ की जनसंख्या यूनाइटेड किंगडम से भी कम थी। 19वीं शताब्दी के पश्चात् कृषि योग्य भूमि की समाप्ति के कारण यहाँ अटलांटिक तटीय नगर एवं औद्योगिक केन्द्रों में बाहर से जनसंख्या आने लगी। सन् 1930 की आर्थिक मंदी के कारण आप्रवासियों की संख्या में ह्रास हुआ। परन्तु उसके बाद उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। पुनः द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भी आप्रवासन में भारी कमी हुई। परन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद पुनः बाहर से जनसंख्या आने लगी, जिसकी संख्या पहले की अपेक्षा कम रही।

अमेरिका में 1610 में मात्र 210 आप्रवासी ही थे। इसके बाद आप्रवासियों की संख्या समय के साथ ही बढ़ती गई। जिसे आगे की सारणी 12.7 में प्रदर्शित किया गया है। 1830 के पश्चात् आप्रवासियों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। 1830-40 के बीच प्रति वर्ष औसतन 60 हजार आप्रवासी अमेरिका में आये। 1901 से 10 के बीच यह औसत 8.8 लाख प्रति वर्ष रहा। यद्यपि आप्रवासियों का कोटा निर्धारण नीति 1921-24 में अपनाई गई जिसमें कुल आप्रवासियों की संख्या 1.5 लाख निश्चित कर दी गई लेकिन इसके पूर्व 1882 में ही सर्वप्रथम चयन करके आप्रवास नीति अपना ली गई थी। 1801 से 1935 के बीच कुल मिलाकर अमेरिका में शुद्ध आप्रवास 2.65 करोड़ व्यक्ति का था। इस दृष्टि से यूरोप से प्रवासी होने वाले 60 प्रतिशत व्यक्तियों का आप्रवास अमेरिका में हुआ।

यद्यपि इस काल में 4 करोड से अधिक अप्रवासी यहाँ आये पर इसी बीच कुछ व्यक्ति अमेरिका से प्रवास कर गये इसलिए शुद्ध अप्रवास 2.65 करोड़ ही रहा। 1924 के कोटा नियमों के अन्तर्गत जहाँ प्रत्येक देश से आने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित कर दी गई। साथ ही यह भी निर्धारित कर दिया गया कि कोई अमरीकी नागरिक इस बात की गारन्टी दे कि आने वाला व्यक्ति देश की समस्या नहीं बनेगा और रोजगार प्राप्त कर सकेगा। 1930 की मन्दी के बाद इन नियमों का कड़ाई से पालन किया गया। अनेक देशों के आप्रवासियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये और आप्रवासी कर भी लगाये गये। सारणी 12.11 में अमेरिका में आप्रवासियों की संख्या तथा सारणी 12.12 में विभिन्न देशों के आप्रवासियों की संख्या देखी जा सकती है।

सारणी 12.11

संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या का आप्रवास (1610-1980)

वर्ष	आप्रवासियों की संख्या	वर्ष	आप्रवासियों की संख्या	वर्ष	आप्रवासियों की संख्या
1610	210	1851-61	25.98 लाख	1911-20	17.37 लाख
1660	85 हजार	1861-70	23.15 लाख	1921-30	41.07 लाख
1750	12.1 लाख	1871-80	28.12 लाख	1931-40	5.28 लाख
1820-30	1.52 लाख	1881-90	52.47 लाख	1941-45	1.71 लाख
1831-40	5.99 लाख	1891-1900	36.88 लाख	1946-70	1.00 करोड़
1841-50	17.73 लाख	1901-1910	87.95 लाख	1971-80	1.65 करोड़

सारणी 12.12

संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवास

मूल देश	आप्रवासियों की संख्या (लाखों में)	प्रतिशत
ब्रिटेन	99	23.0
जर्मनी	65	16.0
इटली	48	12.0
आस्ट्रिया	42	11.0
यूरोप के अन्य देश	90	31.5
मध्य दक्षिण अमरीका	49	12.0
एशिया के देश	10	2.5

(ब) संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या

सन् 1790 ई. में यहाँ एकमात्र नगर न्यूयार्क था। उस समय इस देश में कुल जनसंख्या की मात्र 5 प्रतिशत जनसंख्या ही नगरीय थी जो बढ़कर सन् 1960 ई. में 70 प्रतिशत हो गई। आज सम्पूर्ण देश की 75.2 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है शेष 24.8 प्रतिशत से कम गाँवों में निवास करती है। वहाँ पर 50 हजार से कम आबादी वाला क्षेत्र शेष गाँव की श्रेणी में रखा जाता है अतः यदि हम अर्द्धविकसित देशों की दृष्टि से विचार करें तो यह कहना आवश्यक न होगा कि अमेरिका में 90 प्रतिशत के आसपास जनसंख्या 10 हजार से अधिक आबादी वाले नगरों में निवास करती है।

1990 की जनसंख्या के आधार पर अमेरिका की 24.87 करोड़ जनसंख्या में से 18.70 करोड़ शहर में तथा 6.16 करोड़ गाँव में रहते थे। शहरों में 903.7 लाख पुरूष तथा 966.7 लाख महिलायें थी। 1790 में न्यूयार्क ही अमेरिका का एकमात्र ऐसा नगर था जहाँ कुल आबादी का 5 प्रतिशत भाग निवास करता था और इस समय तक अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी। पर इसके बाद नगरीकरण-औद्योगीकरण की वृद्धि के साथ ही गाँव से जनसंख्या नगरों की ओर बढ़ती गई और 1920 में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात लगभग बराबर हो गया। लेकिन नगर की ओर जनसंख्या का प्रवाह चलता रहा और 1960 तक नगर की आबादी बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 1960 में अमेरिका के नगरों की कुल जनसंख्या 12.53 करोड़ तथा गाँवों की कुल जनसंख्या 5.3 करोड़ थी। यहाँ के गाँवों में प्रायः सभी शहरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

निम्न सारणी 12.13 में 1790 से 2000 के बीच नगरीकरण के विकास को दिखाया गया है।

सारणी 12.13 संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीकरण का विकास (1790-2000)

वर्ष	प्रतिशत जनसंख्या		प्रति दशक वृद्धि -दर		नगरीय ग्रामीण जनसंख्या अनुपात
	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	
1790	94.9	05.1	...	....	....
1800	93.9	06.1	33.8	59.9	1.8
1810	92.7	07.3	34.7	63.0	1.8
1820	92.8	07.2	33.2	31.9	0.9
1830	91.2	8.8	31.2	62.6	2.0
1840	89.2	10.8	29.7	63.7	2.1
1850	84.7	15.3	29.1	92.1	3.2
1900	60.3	39.7	12.2	36.4	3.0
1910	54.3	45.7	09.2	39.3	4.4
1920	48.8	51.2	03.2	29.9	9.1
1930	43.8	56.2	04.4	27.3	6.2
1940	43.5	56.5	06.4	27.9	1.2
1950	36.0	64.0	06.5	20.6	3.2
1960	30.1	69.9	00.8	29.3	...
2000	23.0	77.0	...	...	....

Thompson and Lewis: The Population Problems

(स) तीव्र गति से नगरीकरण के विकास का कारण

अमेरिका में तीव्र गति से होने वाले नगरीकरण का मुख्य कारण गाँवों से नगरों की ओर भारी मात्रा में जनसंख्या का प्रवास हो रहा है। यह प्रवास निम्न कारणों से हुआ:

(1) अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक उन्नतिशाली क्षेत्र था। अतः अधिकांश जनसंख्या इसी क्षेत्र की ओर प्रवासी हुई।

(2) जनसंख्या का सर्वाधिक प्रवास लगभग 20 लाख प्रतिवर्ष दक्षिण क्षेत्र से उत्तर की ओर होता रहा है।

(3) अमेरिका की अन्तर्क्षेत्रीय प्रवासिता की एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही है कि नीग्रो जन समुदाय दक्षिण से उत्तर क्षेत्र और पूर्व से पश्चिमी क्षेत्र एवं गाँवों से नगरों की ओर काफी मात्रा में प्रवास हुआ है।

(4) अमेरिकन जनसंख्या की प्रवासिता का सबसे अन्तिम लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा है कि गांवों से बड़े नगरों की ओर ही जनसंख्या आकर्षित होकर प्रवासी हुई है। फलतः संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े नगरों में जनसंख्या का केन्द्रीकरण हुआ है। यदि आबादी की दृष्टि से अमेरिका के नगरों पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि सन् 1970 ई. में यहाँ दस लाखीय नगरों की संख्या 30 थी, जिसमें न्यूयार्क (114 लाख), लॉस एंजिल्स (68 लाख), शिकागो (67 लाख), फिलाडेल्फिया (47 लाख), डेट्रायट (40 लाख) सनफ्रास्किो

(30 लाख), पिट्सबर्ग (24 लाख) तथा वाशिंगटन डी0सी0 (23 लाख) प्रमुख थे। यहाँ के नगरीकरण की इस तीव्र प्रक्रिया में ग्राम्य-नगरीय प्रवास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

12.4.2 चीन की जनांकिकीय स्थिति (Demographic Situation of China)

जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में प्रथम स्थान तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात् तीसरा स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिलेखों के अनुसार सन् 2004 में चीन की संख्या 130.8 करोड़ तक पहुच गई थी। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग एक- चौथाई भाग चीन में निवास करता है। विश्व का प्रति छठा व्यक्ति चीनी माना जाता है।

निम्न सारणी 12.14 में चीन की जनसंख्या वृद्धि की आधुनिक प्रवृतियों को प्रदर्शित किया गया है:

सारणी 12.14

चीन में जनांकिकीय प्रवृत्ति

वर्ष	जन्म दर (प्रति हजार)	मृत्यु दर (प्रति हजार)	वृद्धि पर (प्रतिशत)	कुछ जनसंख्या (मिलियन में)
1972	29.9	7.7	2.0	867.27
1973	28.1	7.1	2.10	887.61
1975	23.1	7.3	1.58	919.70
1976	20.0	7.3	1.27	932.67
1978	18.3	6.3	1.20	958.09
1979	17.9	6.2	1.17	970.92
1991	21.1	6.7	1.44	1170.56
1993	20.0	7.0	1.30	1205.18
1997	18.0	7.0	1.1	1227.0
2004	-	-	-	1308.0
2025(अनुमानित)	14	8.7	5.3	1526.1

Source: Collected from United Nations Population Data Charts and Human Development Report,2006 and also (source:Hou Wenrou: Population policy P.68,World Bank Atlas) 1996

(अ) चीन की जनसंख्या का ग्रामीण एवं शहरी अनुपात

चीन में भी ग्राम और नगर के मध्य सीमा निर्धारण का आधार जनसंख्या एवं व्यवसाय है। **श्री एस. चन्द्रशेखर** के अनुसार, ***"चीन में जनगणना की परिभाषा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ उस क्षेत्र से है जहाँ 2000 या इससे कम जनसंख्या है और वे स्थान जहाँ 2000 से अधिक जनसंख्या है पर 50 प्रतिशत लोग कृषक हो या कृषि कार्य में संलग्न हों।"*** इस दृष्टि से नगर से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहाँ 2000 से अधिक जनसंख्या हो तथा 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में कार्यरत हो। 1995 में चीन में कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत भाग शहरों में तथा 70 प्रतिशत भाग ग्रामों में निवास कर रही थी। शहर में जनसंख्या का विकास 3.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो रहा है जबकि भारत में यह दर 3.0 है। यहाँ की जनसंख्या के

आन्तरिक प्रवास या ग्राम्य-प्रवास सम्बन्धी आँकड़ों का अभाव है। फलस्वरूप नगरीकरण की प्रवृति का प्रमाणिक विश्लेषण करना असम्भव है। यही, नहीं चीन के प्रकाशित आँकड़े सत्य से परे एवं अशुद्व माने जाते हैं। उनकी जनगणना में केवल चार स्थानीय निवास आयु लिंग जातीय संरचना को ही सम्मिलित करते हैं। अत: ग्रामीण-शहरी जनसंख्या सम्बन्धी अन्य तथ्यों को पूर्णतया ज्ञात नही किया जा सकता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से अधिक सघन क्षेत्र शहरी तथा वीरान क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के रूप में माने जा सकते हैं। इस दृष्टि से इनका वर्णन निम्न रूप में किया जा सकता है:

1. **सघन जनसंख्या का क्षेत्र -** चीन के पूर्वी मैदानी भाग में अधिकतम जनसंख्या पायी जाती है, जहाँ की मिट्टी व जलवायु की दशायें कृषि के अनुकूल हैं। इस मैदानी भाग के 6 प्रान्तों (होपी, शांतुंग, होनान, अह्नवी, सीक्यांग, क्यांगशू) में यहाँ की 40 प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है, जबकि इन प्रान्तों का क्षेत्रफल जनसंख्या लगभग 10 प्रतिशत है। ह्वांगहो का कुछ भाग ऊँचाई पर होने के बावजूद अधिक जनसंख्या वाला है, क्योंकि वहाँ पर कृषिगत् दशाएँ अनुकूल हैं।

   यहाँ के अद्यौगिक नगरों में जनसंख्या का अत्यधिक संकेन्द्रण पाया जाता है। इन नगरों में इनके चतुर्दिक क्षेत्रों से कृषिगत् व औद्योगिक कच्ची सामग्रियाँ आती है। यहाँ के यांग्टीसीक्यांग बेसिन में 30 करोड़ व्यक्ति रहते हैं, जो सोवियत रूस व ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है।

2. **विरल जनसंख्या का क्षेत्र -** चीन के उत्तर- पश्चिमी सीमा की ओर घनत्व में गिरावट दिखाई देता है। मंगोलिया व सिक्यांग में जनसंख्या का घनत्व 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी तथा तिब्बत के पठारी भाग मे घनत्व 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी भी समान रूप में नहीं पाया जाता।

   पश्चिमी चीन का मरूस्लीय भाग विश्व का प्रसिद्व जनशून्य क्षेत्र है। यहाँ की 2 मिलियन वर्ग किमी. क्षेत्रफल इसी प्रकार का है। इस भाग में ऊँटों का काफिला विचरण करता रहता है, जिसकी भेंट अनेक दिनां तक मानव समुदाय से नहीं होती।

   चीन में विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों की निम्नकिंत दशाएँ पायी जाती हैं -

   1. तापमान की अधिकता,
   2. वर्ष की न्यूनता,
   3. पर्वतीय एवं वीरान पठारी भाग,
   4. परिवहन व यातायात के साधनों की कमी।

12.4.3 पूर्व सोवियत रूस की जनांकिकीय संरचना

सोवियत रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 करोड़ 24 लाख वर्ग किमी है। इसका क्षेत्रफल उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के लगभग बराबर तथा ग्रेट ब्रिटेन व फ्रांस के क्षेत्रफल के योग का लगभग 28 गुना है। इस देश की जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुपात में बहुत कम है। यद्यपि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा (चीन तथा भारत के बाद) बड़ा देश है। सन् 1985 में इस देश की जनसंख्या 27.7 करोड़ थी जो 2000 में लगभग 33.3 करोड़ अनुमानित की गयी थी।

यदि जनसंख्या की वृद्धि दर पर विचार किया जाये तो वर्तमान में रूस में लगभग 1.12 प्रतिशत अर्थात 11.2 प्रति हजार दर से जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे प्रतिवर्ष 30 लाख अतिरिक्त वृद्धि रूस की जनसंख्या में होती है। जहाँ भारत में प्रतिदिन 60,000 बच्चे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा होते हैं वहाँ रूस में प्रतिदिन पैदा होने वाले बच्चों की संख्या 9 हजार है अर्थात यहाँ 7 बच्चे प्रति मिनट पैदा होते हैं।

(अ) रूस में जनसंख्या की वृद्धि -

द्वितीय विश्वयुद्व के समय लगभग सोवियत संघ को 3 करोड़ जनसंख्या की हानि उठानी पड़ी। 1917 से 1926 के मध्य इन 9 वर्षों में रूस के जहाँ 50 लाख व्यक्ति युद्व में मारे गये; 160 लाख व्यक्ति सामान्य रूप से मृत्यु का शिकार हुए वहीं इसी अवधि में 100 लाख कम बच्चे पैदा हुए। इस तरह कुल मिलाकर जनसंख्या में 2.8 करोड़ की कमी आई। थाम्पसन तथा लेविस का कथन है कि रूस में इन 12 वर्षो में 3.5 करोड जनसंख्या की कुल मिलाकर वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन जनसंख्या केवल 70 लाख ही बढ़ी। इस जन - हानि की तुलना समस्त यूरोप से 40 प्रतिशत अधिक थी। इसी तरह द्वितीय युद्व काल में रूस में 3 करोड़ की जनहानि उठानी पड़ी। रूस में 1913 में कुल जनसंख्या 14.92 करोड़ थी, वह 1926 में घटकर 14.70 करोड़ रह गयी। इसके बाद जनंसख्या में जो वृद्धि हुई है वह बहुत अधिक नहीं रही है।

जन्म-दर - पूर्व सोवियत रूस में निरन्तर जन्म- दर में ह्रास आ रहा है। यहाँ सन् 1897 में जन्म-दर 47 प्रति हजार थी,जो गिरकर सन् 1928,1950,1955,1965,1980 में क्रमशः 44.3, 26.7, 25.7 18.4 17.0 प्रति हजार हो गई। इस देश मे 50 वर्षो की जन्म - दर में लगभग 61 प्रतिशत का ह्रास हुआ है, निम्न जन्म-दर की सारणी 12.15 से स्पष्ट हो जाता हैः

सारणी 12.15

पूर्व सोवियत रूस में जन्म-दर की प्रवृत्ति (1897-1980 ई0)

वर्ष	जन्म-दर(प्रति हजार)	वर्ष	जन्म-दर(प्रति हजार)
1897	47.0	1960	24.9
1913	47.0	1965	18.4
1928	47.3	1970	17.6
1937	38.7	1975	17.5
1940	31.3	1980	17.0
1950	26.7	1985	16.9
1955	25.7	1990	16.9

मृत्यु-दर - पूर्व सोवियत रूस में जन्म- दर के साथ मृत्यु-दर में भी गिरावट आई है। सन् 1897 में यहाँ मृत्यु -दर 32 प्रति हजार थी जो घटकर सन् 1931 में 30; सन् 1952 में 8.4; सन् 1965 में 7.2 तथा सन् 1980 में 6.5 प्रति हजार हो गई। यहाँ सन् 1913 से 1965 के मध्य मृत्यु-दर में 75 प्रतिशत की गिरावट हुई है जो विश्व में एक अकेला उदाहरण है।

सारणी 12.16

पूर्व सोवियत रूस में मृत्यु-दर की प्रवृति

वर्ष	मृत्यु-दर (प्रति हजार)	वर्ष	मृत्यु – दर (प्रति हजार)
1897	32.0	1961	7.2
1913	30.0	1965	7.2
1952	8.4	1980	6.5
1958	8.2	1990	6.0

Source: World Development Report,2003

यहाँ मृत्यु- दर में तीव्र ह्रास का कारण स्वास्थ्य व चिकित्सकीय सुविधाओं में आशातीत वृद्धि रही है। इस देश में समानता के सिद्वान्त के आधार पर हर नागरिक को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं। जनसंख्या वृद्धि को सारणी 12.17 में दिखाया गया है।

सारणी 12.17

रूस की जनसंख्या 1913-85 (जनसंख्या मिलियन में)

वर्ष	जनसंख्या	वर्ष	जनसंख्या
1913	159.2	1960	214.0
1926	147.0	1970	243.0
1945	166.0	1980	266.0
1950	180.0	1985	277.0

जनसंख्या प्रक्षेपणों के अनुसार 2000 में रूस की जनसंख्या 33.3 करोड़ हो जाने की सम्भावना है।

(ब) ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या

सोवियत संघ की क्रान्ति के पूर्व 1 लाख से अधिक की आबादी वाले केवल 29 नगर ही थे जबकि क्रान्ति के बाद नियोजन अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत संचालित औद्योगीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नगरों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। जैसे- जैसे औद्योगीकरण की गति तीव्र होती गई वैसे-वैसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में जनसंख्या का प्रवास बढ़ा है। 1966 में रूस के नगरों की संख्या 192 थी जिसमें निवास करने वाले नागरिकों की संख्या लगभग 7 करोड़ थी। इसके पूर्व 1960 में नगरों और ग्रामों की जनसंख्या लगभग बराबर थी लेकिन इसके बाद शहरी जनसंख्या का अनुपात निरन्तर बढ़ा है। 1961 में ग्रामीण बस्तियाँ कुल मिलाकर 7 लाख 5 हजार थीं, जिनमें लगभग 2.84 लाख ग्रामों में औसतन 10 व्यक्ति प्रति गाँव निवास करते थे। इसी तरह 1.37 ग्रामों में निवासियों का औसत 11 से 50 के मध्य, 80,924 ग्रामों में 51 से 100 व्यक्ति, 1.83 लाख ग्रामों में 101 से 1000 व्यक्ति, 1950 प्रतिशत ग्रामों में 1001 से 5000 व्यक्ति एवं 675 ग्रामों में लगभग 5000 से कुछ अधिक व्यक्ति निवास करते थे। सोवियत संघ में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के वितरण को निम्न सारणी 12.18 में दिखाया गया है।

सारणी 12.18

रूस में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या (जनसंख्या करोड़ में)

वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	ग्रामीण प्रतिशत	शहरी प्रतिशत
1913	13.11	2.81	82	18.0
1926	12.08	2.62	82	18.0
1939	13.39	5.61	67	33.0
1960	10.80	10.90	50	50.0
1970	10.60	13.60	47	53.5
1980	9.36	16.40	42	58.0
1983	9.70	17.60	36	64.0

उक्त सारणी 12.24 से स्पष्ट है कि 1960 के पूर्व रूस में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक था लेकिन 1960 के बाद शहरों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

प्रान्तों की जनसंख्या- जनसंख्या की दृष्टि से प्रान्तों में सबसे अधिक घनी आबादी रूस की है। इसकी जनसंख्या 1993 में 149 मिलियन थी तथा क्षेत्रफल कुल 17.075 हजार वर्ग किलोमीटर है।

निम्न सारणी 12.19 में सोवियत संघ के विभिन्न प्रान्तों की जनसंख्या को दिखाया गया है:

सारणी 12.19

सोवियत संघ के विघटन के समय विभिन्न प्रान्तों की जनसंख्या

(जनसंख्या मिलियन में)

प्रान्तों का नाम	जनसंख्या	प्रान्तों का नाम	जनसंख्या
रूस रूसियन	149	मोल डेवियन	4
यूक्रेन	52	लैटवियन	3
कजाख	17	किरघिज	5
उजबेक	22	ताजिक	6
ब्यालोरूसिन	10	अरमेनियन	4
जिओरजियन	5	तुर्कमैन	4
अजरवाजेयन	7	स्टोनियन	2
लिथूनियन	4	मोल डेवियन	4

इस प्रकार सर्वाधिक आबादी वाला प्रान्त रूस है जबकि सबसे कम आबादी वाला प्रान्त स्टोनियन है। घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाले प्रान्त रूस, यूक्रेन, कजाक तथा उजबेक आदि हैं। सबसे कम घनत्व वाले प्रान्त क्रमशः किरघिज, ताजिक आदि हैं। संक्षेप मे, हम यह कह सकते हैं कि पूर्व सोवियत रूस में नगरीकरण की तीव्र गति के कारण यहाँ नगरीय क्षेत्रों का विकास हुआ है। इस देश के प्रमुख नगरीय क्षेत्र (Urban Zone) निम्नाँकित है –

1. मास्को क्षेत्र
2. लेनिनग्राड क्षेत्र
3. गोर्की से आस्ट्रेनखान का विस्तृत क्षेत्र
4. यूराल क्षेत्र

5. यूक्रेन से डोनवास तक का क्षेत्र
6. कुजबास क्षेत्र
7. मध्य एशियाई कृषि प्रधान नगरीय क्षेत्र
8. सुदूर पूर्व के तटीय क्षेत्र

पूर्व सोवियत रूस के कुछ क्षेत्रों की ग्रामीण जनसंख्या में कमी आ रही है। ऐसे क्षेत्रों में बाल्टिक राज्य, डोनेत्स प्रदेश, ओमस्क, वोल्गा क्षेत्र प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसे क्षेत्र देश के मुख्यतः पूर्वी भागों में स्थित हैं जिनमें कजाखिस्तान, मध्य एशिया, सुदूर पूर्व के क्षेत्र उल्लेखनीय हैं।

12.4.4 ग्रेट ब्रिटेन की जनांकिकीय संरचना

ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या इग्लैण्ड, वेल्स, स्काटलैण्ड, आयरलैण्ड तथा चैनल द्वीपसमूहों में वितरीत है। सन् 2004 में इस देश की जनसंख्या 6 करोड़ थी तथा जनसंख्या का घनत्व 244 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। सन् 2000 ई. में इस देश की जनसंख्या 6 करोड़ थी। इस देश को प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्व में अधिक हानि उठानी पड़ी। यहाँ के जनांकिकीय इतिहास का विधिवत् श्रीगणेश सन् 1801 ई. से प्रारम्भ होता है। इसके पूर्व भी सैन्य-शक्ति एवं राजकीय वित के आँकलन के लिए व्यक्तियों की गणना की जाती थी। परन्तु उनके आँकड़े अव्यवस्थित व अप्रामाणिक होते थे।

ग्रेट ब्रिटेन में प्रथम जनगणना सन् 1801 ई. में हुई जिसके बाद से प्रति दस वर्षो में यह कार्य सम्पन्न हो रहा है। सन् 1801 के बाद की जनसंख्या वृद्धि दर को सारणी 12.20 में दिखाया गया है। जिसके अनुसार पिछले 200 वर्षो में जनसंख्या में लगभग 6 गुनी वृद्धि होकर सन् 2000 में कुल जनसंख्या 6 करोड़ हो गयी है.

सारणी 12.20

ग्रेट ब्रिटेन में जनसंख्या वृद्धि (1801-2000)

(जनसंख्या मिलियन में)

वर्ष	कुल जनसंख्या इंग्लैण्ड व वेल्स	स्काटलैण्ड	उत्तरी आयरलैण्ड	ब्रिटेन	वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में
1801	8.9	1.6	1.4	10.5	1.4
1821	12.0	2.1	1.4	14.1	1.4
1841	15.9	2.6	1.6	18.5	1.2
1861	20.1	3.0	1.4	23.1	1.2
1881	26.0	3.6	1.3	29.6	1.1
1901	32.5	4.5	1.3	37.0	0.7
1921	37.9	4.9	1.3	42.8	0.4
1941	42.2	5.0	1.2	47.2	0.4
1961	47.0	5.3	1.4	52.3	0.4
1971	48.6	5.4	1.5	54.0	0.4
1981	49.2	5.1	1.5	55.8	0.4
2000	49.0	5.0	-	60.0	0.4
2004	-	-	-	60.0	0.4

Source: UN Population Demographic Year Book and Human Development Report,2006

(अ) ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या

ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या इंग्लैण्ड, वेल्स, स्काटलैण्ड, आइले ऑफ मैन तथा चैनल द्वीप समूहों में वितरित है। ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या का सामान्य वितरण 245 व्यक्ति प्रति किमी है। ग्रेट ब्रिटेन में सघन आबादी वाले भाग कोयला क्षेत्रों पर पाये जाते हैं। यहाँ का लन्दन क्षेत्र ही ऐसा आबाद क्षेत्र है जो कोयला पर आधारित नहीं है। लंकाशायर कोयला क्षेत्र में दो बड़े औद्योगिक व व्यापारिक केन्द्र मैनचेस्टर व लिवरपूल हैं। यार्कशायर क्षेत्र में लीड्स, बेडफोर्ड और शेफील्ड मुख्य केन्द्र हैं। मिडलैण्ड्स क्षेत्र में बर्मिघम, स्टोक आदि औद्योगिक केन्द्र पाये जाते हैं।

ग्रेट ब्रिटेन के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक पाया जाता है। यहाँ नगरीय क्षेत्रों में तो 1600 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक पाये गये हैं। उत्तर- पूर्वी इंग्लैण्ड में सर्वाधिक घनत्व नार्थम्बरलैण्ड डरहम क्षेत्र के टाइन, टीज नदी घाटियों में प्राप्त है जहाँ कोयला व लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। दक्षिणी वेल्स कोयला क्षेत्रों में स्वान्सी व कार्डिफ बड़े केन्द्र है। स्काटलैण्ड में जनसंख्या के घने क्षेत्र ग्यास्गो कोयला क्षेत्र तथा क्लाइड नदी घाटी में पाये जाते हैं। सन् 1961 ई. की जनगणना के अनुसार इंग्लैण्ड व वेल्स की जनसंख्या में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 20 व 80 था जो सन् 1991 ई. में 21.9 तथा 78.1 हो गया। नगरीय जनसंख्या में कमी का प्रमुख कारण नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक संख्या में स्थानान्तरण रहा है। विकसित देशों में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से अधिक ग्रस्त होने के कारण नगरीय जनसंख्या में अब हरित पेटी की ओर प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख नगरीय केन्द्रों में लंकाशायर,लंदन, मिडिल सेक्स, ईसेक्स, डरहम, केण्ट, हेम्पशायर मुख्य हैं। इन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है।

(ब) देशान्तरण (Migration)

ब्रिटेन की जनसंख्या देशान्तरण से बहुत अधिक प्रभावित रही है। 17 वीं तथा 18 वीं शताब्दी में अंग्रजों ने उपनिवेशों की स्थापना की इसी क्रम में 17 वीं शताब्दी में लगभग 5 लाख तथा 18 वीं शताब्दी में लगभग 15 लाख लोग ब्रिटेन से विदेशों में जा बसे। 19 वीं शताब्दी के अन्त में बाहर जाने वालों की संख्या बहुत कम हो गयी थी। 1930-31 तक यहाँ से लोगों का बहिर्गमन होता रहा। 1931 से 1950 के मध्य बहुत से शरणार्थी यूरोप, वेस्टइण्डीज तथा दक्षिण अफ्रीका से इस देश में आ बसे। इसके अतिरिक्त 1930 के उपरान्त ब्रिटेन के उपनिवेश समाप्त होने लगे। फलतः बहुत के लोग ब्रिटेन वापस लौट आये। साथ ही विकासशील देशों से भी बहुत से व्यक्ति आकर यहाँ बस गये।

12.4.5 जापान की जनांकिकीय संरचना

उगते सूर्य का देश (Land of Rising Sun) जापान, एशिया महाद्वीप का एक विकसित देश है। यहाँ की जनसंख्या 12.7 करोड़ हो गई है। जापान का कुल क्षेत्रफल 370 हजार वर्ग किमी है, जो चार द्वीपों (होकैडो, होन्शू, शिकोकू क्यूशू) में बँटा है। इन चारों द्वीपों में मुख्य द्वीप होन्शु है जिसका क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का लगभग 63 प्रतिशत है। देश का अधिकांश भाग पहाड़ी है। फलस्वरूप यहाँ का केवल 16 प्रतिशत भूभाग ही कृषि योग्य है।

यहाँ की 40 प्रतिशत जनसंख्या मात्र 1 प्रतिशत क्षेत्र में ही संकेन्द्रित है, जिसमें देश के 6 प्रमुख महानगरों की स्थिति पायी जाती है। यहाँ का औसत जनघत्व 376 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जापान में जनगणना सर्वप्रथम 1920 में शुरू हुई। जापान की जनसंख्या का विकास, जन्म व मृत्युदर निम्न सारणी 12.17 से स्पष्ट है:

सारणी 12.21

12.21

जापान में जनसंख्या का विकास, जन्म व मृत्यु-दर

वर्ष	जनसंख्या(करोड़ में)	जन्म-दर (प्रति हजार)	मृत्य-दर वृद्धि दर (प्रति हजार)
1872	3.48	-	-
1878	3.62	24.5	19.0
1888	3.90	29.6	19.0
1908	4.80	33.7	20.9
1920	5.59	36.2	25.4
1930	6.45	32.4	18.2
1940	7.19	26.8	17.3
1950	8.32	28.1	10.9
1960	9.34	17.7	7.7
1964	9.67	17.66	6.9
1970	10.37	18.83	6.9
1971	10.87	14.0	6.0
1980	11.63	18.0	7.0
1990	12.51	18.0	9.0
2000	12.70	15.0	9.0
2002	12.70	-	-
2004	12.79	-	-

(अ) ग्रामीण नगरीय जनसंख्या –

विश्व में जापान (जर्मनी को छोड़कर) ही एक ऐसा देश है जहाँ नगरीकरण की प्रवृति इतनी अधिक तीव्र पाई जाती है कि आगामी कुछ ही वर्षो में यहाँ 2/3 से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करेगी। 1920-40 के मध्य यहाँ नगरीय जनसंख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है। द्वितीय विश्व युद्व के बाद यहाँ तीव्र औद्योगिक विकास हुआ। फलस्वरूप नगरीकरण की प्रवृर्ति भी तीब्रता से बढ़ी। जापान की लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या चार बड़े नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। जापान में 10 बड़े नगर हैं जिनमें जापान की अधिकांश नगरीय आबादी रहती है। ये नगर जनसंख्या वृद्धि को समस्या से ग्रसित हैं। सारणी 12.22 में जापान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का विकास दिखाया गया है:

सारणी 12.22

जापान में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या

(जनसंख्या करोड़ में)

वर्ष	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या
1920	5.59	82.0	18.00
1930	6.45	76.0	24.0
1940	7.10	62.3	37.7
1950	8.32	43.9	56.1
1960	9.34	43.8	56.2
1970	10.87	43.6	56.4
1980	11.88	39.2	60.8
1995	12.50	37.1	62.9
2004	12.79	34.5	65.5

उक्त सारणी 12.28 से स्पष्ट है कि ग्राम्य नगरीय प्रवास के कारण ग्रामीण जनसंख्या में लगातार गिरावट हो रही है। यहाँ के महानगरों में रहने वाली जनसंख्या कुल जनसंख्या का 65.5 प्रतिशत है।

12.5 अभ्यास प्रश्न(Practice Questions)

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:

1. नगरों के विकास की अवस्थायें।
2. नगरीय जीवन की विशेषतायें।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवास।
4. संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या
5. चीन की जनसंख्या वृद्धि में ग्रामीण-शहरी अनुपात
6. रूस में जनसंख्या वृद्धि ।
7. ग्रेट ब्रिटेन की जनांकिकी संरचना
8. भारत में नगरीय जनसंख्या

12.6 सारांश (Summary)

इस इकाई में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए नगरीकरण के विभिन्न अर्थों को समझा गया है। इसी क्रम में वैश्विक परिवेश में सार्क देशों तथा विश्व के 10 सबसे बड़ी महानगरीय जनसंख्या के चार्ट द्वारा जनसंख्या घनत्व एवं बड़ी जनसंख्या के क्रम में जापान के टोकियो को पाया गया है। भारत का मुम्बई तथा दिल्ली भी क्रमशः छठवें तथा नौवें स्थान पर है। नगरों के विकास क्रम को समझाते हुए इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस के साथ-साथ ग्रिफ्रिथ टेलर के विकास क्रम- शैशवावस्था, बाल्यावस्था किशोरावस्था पौढ़ावस्था तथा वृद्वावस्था को समझाया गया है। तत्पश्चात् नगरीय जीवन की विशेषताओं का अध्ययन किया गया है जिसके अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा धार्मिक अन्य विशेषताओं को बताया गया है।

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की प्रवृतियों को स्पष्ट करते हुए विकसित, विकासशील एवं अविकसित क्षेत्रों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। जिसके अन्तर्गत सारणी द्वारा कुछ चुने हुए देशों में नगरीकरण के प्रतिशत को दिखाया गया है। विकसित तथा विकासशील देशों विशेष रूप में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पूर्व सोवियत रूस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, चीन,एवं भारत में जनसंख्या-वृद्धि , वितरण एवं ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या को विभिन्न सारणियों द्वारा दिखाया गया है। विकसित देशों में विशेष रूप से अमेरिका में जनसंख्या बढ़ने तथा शहरीकरण का मुख्य कारण आप्रवासन रहा है। चीन तथा रूस में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र से शहरीकरण का कारण मुख्यत आन्तरिक प्रवास रहा है, इस तरह नगरीकरण के विकास में आकर्षण तथा प्रतिवर्षण के साथ-साथ वाह्य तथा आन्तरिक प्रवासन की भी बड़ी भूमिका रही है।

भारत में नगरीकरण की प्रवृति में सबसे अधिक वृद्धि 1971-81 के दशक के बीच 46.18 प्रतिशत, लगभग 3.83 प्रतिशत वार्षिक थी। इसका मुख्य कारण बंगलादेशियों का भारत में प्रवासन था। भारत में बड़े नगरों या एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। 1991 में 23 बड़े नगरों की कुल जनसंख्या 70.7 मिलियन थी वही 2001 में 35 बड़े नगरों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक हो गयी थी। वृहत्तर मुम्बई, कोलकाता तथा दिल्ली तो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सम्मिलित हैं। संक्षेप में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कम हो रहा है जबकि जनगरीकरण प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि देखी जा रही है।

12.7 शब्दावली (Glossary)

- **जनसंख्या का स्थानान्तरण** Shift Of Population
- **शैशवावस्था** Infantile Stage
- **बाल्यावस्था** - Juvenile Stage
- **किशोरावस्था** - Adolescent Stage
- **प्रौढ़ावस्था** - Mature Stage
- **वृद्धावस्था** - Old Stage
- **सामाजिक सहिष्णुता** - Social Tolerance

12.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers for Practice Questions)

12.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- डॉ. मिश्रा, जे. पी., जनांकिकी, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा।
- डॉ. बघेल, डी. एस., जनांकिकी, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
- डॉ. पन्त, जीवन चन्द्र, जनांकिकी, गोयल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

- अशोक कुमार, जनसंख्या, एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन, हिन्दी ग्रंथ अकादमी प्रयाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय*, भारत सरकार
- वार्षिक रिर्पोट, 2012-13: *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग*, भारत सरकार
- *भारतः 2013*, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

12.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful/Helpful Text)

- A.M. Carr Saunders : World Population, 1936, P.42
- Walter F. Willcox : Studies in American Demography, 1940 P. 40
- M.K. Bonnett: the world, 1954 3
- Ross, John, A (1982): International Encyclopedia of Population The Free Press. Macmillon Publishing co.New York.
- U.N. Determinantes and Consequences of Population Trends, 1953, P. 61
- UNFPA, The State of World Population, 1996
- United Nations Population Division , Word Population 2006.
- World Bank Atlas 1996
- Estimated from United Nations, 1986
- U.N. Demographic Year Book, 1950
- Selected World Demographic Inedicators by Region and Country or Area. 1970-75, Prepared by United Nations Population Division .

12.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. नगरीकरण से आप क्या समझते हो ? नगरों के विकास की अवस्थायें समझाइये।
2. विश्व में नगरीय विकास के इतिहास पर संक्षिप्त निबन्ध लिखें।
3. अमेरिका की जनसंख्या में वृद्धि दर को स्पष्ट कीजिये तथा जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारणों को स्पष्ट कीजिये।